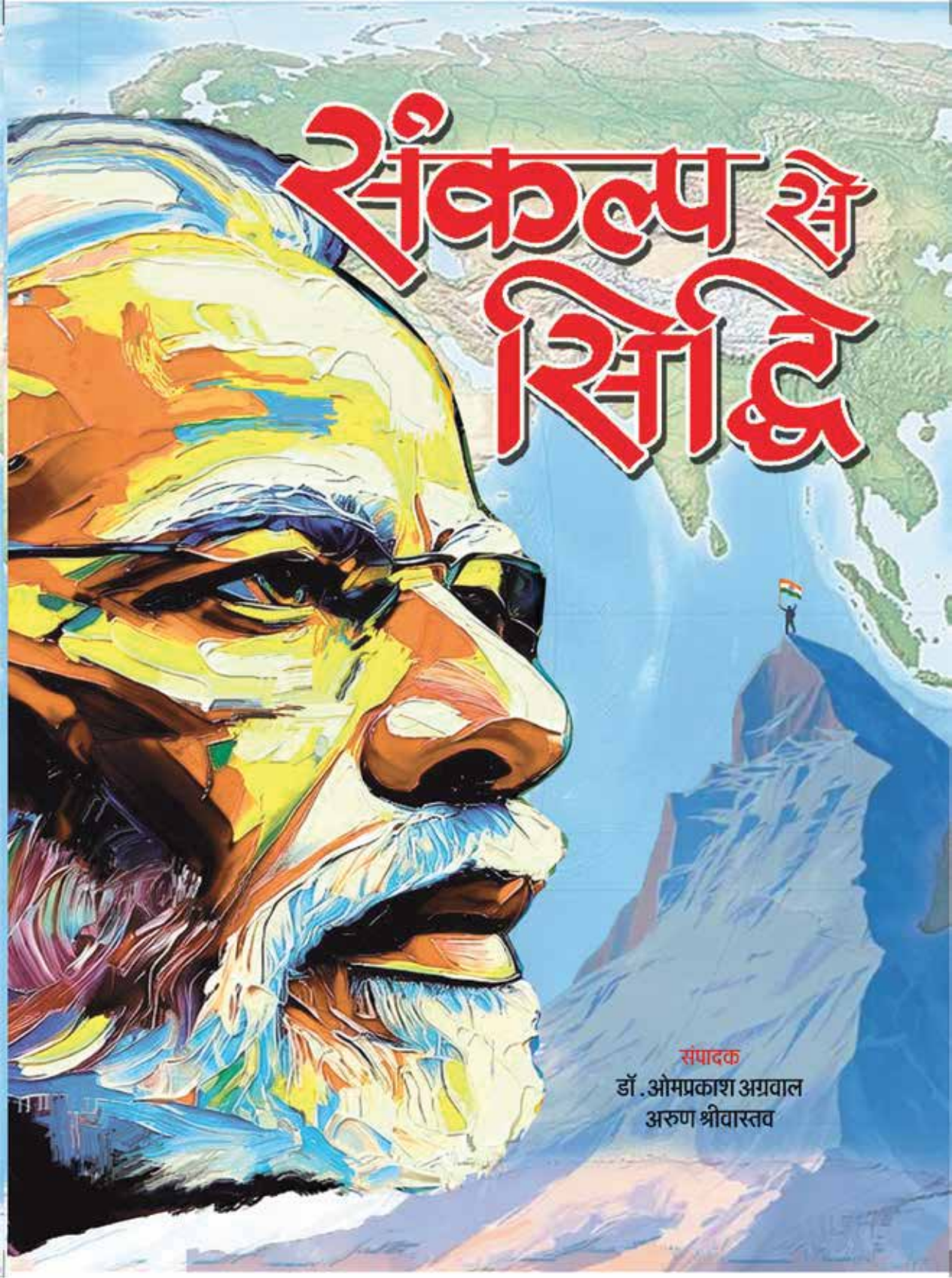




संकल्प से सिद्धि

संपादक

डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल
अरुण श्रीवास्तव

रैंकल्प श्रे सिद्धि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व, विचारों,
नीतियों, उपलब्धियों का समग्र आकलन

सौजन्य
एनआईडीटी, ग्रेटर नोएडा

संपादक
डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल
अरुण श्रीवास्तव



एनएलएम वेलफेयर ट्रस्ट

• दिल्ली • गाजियाबाद • लखनऊ • गोरखपुर

www.nlmwelfaretrust.com

प्रकाशक : एनएलएम वेल्फेयर ट्रस्ट

• दिल्ली • गाजियाबाद • लखनऊ • गोरखपुर

www.nlmwelfaretrust.com

सर्वाधिकार : सुरक्षित

संस्करण : प्रथम

मूल्य : छह सौ एक रुपये (रु. 601)

मुद्रक : मित्तल प्रिंट एन पैक, पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92

SANKALP SE SIDHI

Editor : **Dr. Om Prakash Agarwal, Arun Srivastava**

Published By NLM welfare Trust

अपनी बात

सं

कल्पना के स्तर पर जब इस पुस्तक के प्रारूप को लेकर विमर्श चल रहा था, तब बार-बार यह बात जेहन में आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन, उनकी सरकार, शासन-प्रशासन के तरीकों को लेकर अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। बड़ी संख्या में किताबें भी आ चुकी हैं। ऐसे में चुनौती यह थी कि आखिर इस किताब को उनके किस पहलू पर केंद्रित किया जाए, जिसमें समग्रता के साथ नयापन भी हो। ऐसे में काफी विचार-विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित ऊर्जावान-कर्मठ प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व, विचारों, सरकार की नीतियों के पीछे उनकी प्रेरणा, उपलब्धियों, शासन-प्रशासन के तरीकों, नागरिकों से उनके जुड़ाव आदि लगभग सभी पहलुओं को लेकर समग्रता में एक ऐसी संग्रहणीय पुस्तक तैयार की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में पिछले करीब 12 वर्षों में उनकी सरकार का लेखा-जोखा भी सामने आ सके। बहुत छानबीन से यह भी पता चला कि संपूर्णता में इस तरह का आकलन हिंदी में संभवतः पहले नहीं हुआ है। इसके बाद यह सोचा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और कार्यों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर किसी एक विशेषज्ञ से लिखवाने के बजाय उन विद्वानों से लिखने का आग्रह किया जाए, जिनकी देश-विदेश में अलग पहचान है और जो अपने-अपने क्षेत्र के ख्यातिप्राप्त विद्वान हैं। इसके बाद विषय तय करके उन विद्वान लेखकों-पत्रकारों से संपर्क किया गया। सुखद आश्चर्य की बात यह है कि जिन अनुभवी विद्वानों से संपर्क किया गया, लगभग सभी ने पुस्तक की विषयवस्तु को देखते हुए अपने लिए सुझाए गए विषय पर लिखने का आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बारे में न केवल मूल्यवान सुझाव दिए, बल्कि बहुत कम समय में ही अपने आलेख उपलब्ध करा दिए। कुछ लेखकों के आलेख में नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी अब तक की यात्रा का रोचक विश्लेषण भी है। इनमें से कई लेखकों/पत्रकारों ने नरेन्द्र मोदी के जीवन और उनके कार्यों को नजदीक से देखा और महसूस भी किया है, जिसकी झलक उनके आलेख में मिलती है। इसके लिए इस पुस्तक में शामिल सभी विद्वतजन के प्रति हम हृदय से आभारी हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुस्तक की संकल्पना और प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने तक लगभग हर चरण में प्रख्यात पत्रकार व लेखक तथा नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय रामबहादुर राय साहब का नियमित सान्निध्य, बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पुस्तक के अनूठे कवर से लेकर विषय और लेखकों पर भी उनसे लगातार चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक का प्रारंभिक आलेख स्वयं उनका ही है, जो आपातकाल के दिनों में संघर्ष के एक सेनानी के रूप में नरेन्द्र मोदी की सक्रियता को लेकर उनके गहन शोध पर आधारित है। इस आलेख में ऐसे कई प्रसंग हैं, जिनके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी सामने आई थी। इसके लिए हम उनके प्रति हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने अपनी व्यस्तता के बीच समय निकालकर हमसे अपने अमूल्य विचार साझा किए। उन्होंने हिंदी में ऐसी पुस्तक का अभाव बताते हुए इसे जल्द प्रकाशित करने के लिए प्रेरित भी किया था।

इस पुस्तक की संकल्पना, तैयारी, संयोजन से लेकर प्रकाशन तक में एनआईईटी (ग्रेटर नोएडा) का जो सहयोग मिला, वह अकल्पनीय है। इससे तत्परता और लगन के साथ इस पुस्तक की तैयारी को त्वरित गति से आगे बढ़ाने में मदद मिली। हम इसके लिए एनआईईटी प्रबंधन के प्रति भी बहुत आभारी हैं।

उम्मीद है कि यह पुस्तक आप सभी को पसंद आएगी।

विनम्र आभार के साथ,

डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल
अरुण श्रीवास्तव

अनुक्रम

अपनी बात	5
1. इमरजेंसी की लड़ाई के एक सक्रिय सेनानी : रामबहादुर राय	10
2. प्रभावी और प्रेरक नेतृत्व : युगांतकारी कार्यकाल : आचार्य राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी	20
3. न दैन्यं न पलायनम् : डॉ. सच्चिदानंद जोशी	28
4. अध्यात्म, राजनीति और प्रबंध कौशल का संगम : प्रो. हिमांशु राय	32
5. मोदी और मीडिया के रिश्ते : डॉ. गोविंद सिंह	40
6. राजनीति का मोदी युग : राजीव सचान	46
7. भारतीयता का वैश्विक जयघोष : उमेश चतुर्वेदी	50
8. व्यक्तित्व एवं विचार : मनोवैज्ञानिक विश्लेषण : डॉ. आलोक मिश्रा	58
9. डिजिटल भारत का बढ़ता कारवां : बालेन्दु शर्मा दाधीच	64
10. विरासत के साथ विकास की यात्रा : कुमार रोहित	74
11. राजनीति-प्रशासन का कौशलयुक्त प्रबंधन : डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी	82
12. क्रांतिकारी बदलाव की ओर दूरस्थ-ऑनलाइन शिक्षा : डॉ. नागेश्वर राव	88

13. संवाद में प्रभाव भी और प्रेरणा भी : सौरभ श्रीवास्तव	96
14. गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का अभियान : विवेक शुक्ला	102
15. दूरदर्शी सोच के अप्रतिम नायक : कुमार पंकज	114
16. स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की राह : मिलन सिन्हा	120
17. दुनिया में बढ़ाया भारत का मान : जितेंद्र तिवारी	128
18. योग का वैश्विक पुनर्जागरण : मनीष त्रिपाठी	138
19. आध्यात्मिक-वैज्ञानिक चेतना के विरल साधक : डॉ. राजेंद्र नाथ त्रिपाठी	146
20. मुझे मां गंगा ने बुलाया है : प्रो. रामनारायण द्विवेदी	152
21. सांस्कृतिक चेतना और कवि मन : प्रो. रवींद्र नाथ श्रीवास्तव 'परिचय दास'	158
22. अनुशासन, कर्म व ऊर्जा का संगम : डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल	166
23. खाड़ी संकट : असर बेअसर : अरुण श्रीवास्तव	172



विशेष खंड : नारी-शक्ति वंदन	179
24. आधी आबादी को पूरा अधिकार : डॉ. सरोजिनी अग्रवाल	180
25. सशस्त्र बलों में नारी-शक्ति की उड़ान : जया तारे	186
26. मन के जीते जीत : डॉ. नीमा अग्रवाल	194
27. नये भारत में नेतृत्व की राह पर नारी शक्ति : यशा माथुर	200

विनम्र समर्पण
विकसित भारत के प्रति संकल्पित
देश के सुधी-समर्पित नागरिकों को...





विकसित भारत



रामबहादुर राय

वरिष्ठ पत्रकार व लेखक,
अध्यक्ष-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

इमरजेंसी की लड़ाई के

एक सक्रिय सेनानी

न रेन्द्र मोदी, जो 2014 से प्रधानमंत्री हैं, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ऐसे विलक्षण राजनेता ने क्यों देश-दुनिया को 'संविधान हत्या दिवस' का अनोखा उपहार दिया? यह प्रश्न अगर कोई पूछता है तो इसे किसी भी तरह अस्वाभाविक नहीं मानना चाहिए। इसे स्वाभाविक मानने के अनेक कारण हैं। कुछ कारणों का यहां उल्लेख कर देने मात्र से समाधान मिल सकता है। 2025 में इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। पहली बार इमरजेंसी को एक पहचान प्राप्त हुई। वह संविधान की हत्या की संज्ञा से जानी जाएगी। इसमें ही इमरजेंसी का पूरा महाभारत उपस्थित हो जाता है। इसे समझने के लिए अतीत की यात्रा जरूरी है। वह अतीत जो 1975 में घटित हुआ, लेकिन उसका प्रारंभ तो कुछ साल पहले ही हो गया था।

इमरजेंसी के कुराज से दो-दो हाथ करने वाले लोकतंत्र के सेनानी कहलाए। कुछ तो ऐसे सेनानी रहे, जो बिना लड़े वीरगति को प्राप्त हो गए। इस श्रेणी में वे आएंगे, जिन्हें पुलिस ने औचक पकड़ा। कुछ तो मैदान में उतरे, पर मुखबिरों के शिकार हो गए। कुछ ऐसे भी लोकतंत्र सेनानी हुए, जो लड़ते हुए



‘इमरजेंसी कैसे आई, इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, परंतु इमरजेंसी हटी कैसे, इस बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। इस स्थिति से ही इस पुस्तक का जन्म हुआ। चुनाव आए। जनता पक्ष की विजय हुई। क्या यह निरा चमत्कार था!’...‘वास्तविकता यह है कि लक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए लगातार 21 माह तक सुनियोजित ढंग से संघर्ष करना पड़ा।...‘यह मेरी प्रथम पुस्तक है।’...‘भूमिगत संघर्ष के बारे में अब तक अनुत्तरित रहे, कुछ कठिन प्रश्नों की कुंजी स्वरूप यह पुस्तक मैंने किसी लेखक की तरह नहीं, वरन् लड़ाई के एक सिपाही की हैसियत से लिखी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखित
‘आपातकाल में गुजरात’ पुस्तक से



धरे गए, लेकिन जिन्हें पुलिस पूरे इमरजेंसी में अपनी हरचंद कुचालों के बावजूद नहीं पकड़ पाई। ऐसे लोकतंत्र सेनानियों की संख्या भी काफी बड़ी थी। उनमें सबसे ज्यादा संख्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की रही। इन्हीं लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी को हटवाया और लोकतंत्र को वापस लाए। इमरजेंसी के कुराज से शायद ही कोई अपरिचित हो। जितना सच यह है, उतना ही यह भी एक सच है कि बहुत थोड़े ही लोग हैं, जो यह जानते हों कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकतंत्र की पुनःस्थापना के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अहिंसक प्रतिरोध को हर तरह से संगठित किया था। उसी प्रतिरोध का सफल परिणाम निकला कि इमरजेंसी अंततः हटानी पड़ी।

इमरजेंसी का मतलब था, इंदिरा की तानाशाही। उस दौर में इंदिरा की तानाशाही का ताना-बाना मजबूत दिखता था। शासन तंत्र में पुलिस हरावल दस्ता थी। संजय ब्रिगेड कंट्रोल रूम में बैठी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हरावल दस्ते के लिए मुखबिरी करती थी। कांग्रेस के ज्यादातर नेता, कार्यकर्ता और सांसद-विधायक लोकतंत्र सेनानियों को जेल में बंद कराने के लिए रात-दिन एक करते थे। ऐसी थी विषम परिस्थिति। ‘रावण रथी विरथ रघुवीरा’- चरितार्थ हो रहा था।

इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जिस युवा ने एक क्षण भी नहीं गंवाया, वे थे नरेन्द्र मोदी। इमरजेंसी को गुजरे 50 साल हो गए हैं। इमरजेंसी में नरेन्द्र मोदी 25 साल की जीवन रेखा के करीब थे। घर-बार छोड़कर समाज कार्य में दो-तीन साल पहले से ही सक्रिय थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। इमरजेंसी की घोषणा से पहले की रात का जैसा सजीव वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, उसे पढ़कर कोई भी अपनी आंखों में वह चित्र बना सकता है, जो तब इंदिरा गांधी के निवास के आदेश से घटित हो रहा था। पुस्तक है- ‘आपातकाल में गुजरात’। इसके लेखक नरेन्द्र मोदी हैं। यह गुजराती में लिखी गयी थी। इस पुस्तक को गुजराती साहित्य की अमूल्य धरोहर श्रेणी में स्थान मिला है। स्वभाषा का भाव जो नरेन्द्र मोदी में पाया जाता है, उसकी यह पहली झलक भी है। इस पुस्तक को जैसे ही कोई हाथ में लेगा और पढ़ने से पहले उस पर नजर दौड़ाएगा तो दो बातें उसे सोचने के लिए ठहरने का संकेत देंगी। पहली कि दंतोपंत ठेंगडी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। दंतोपंत ठेंगडी के बारे में जो जानते हैं, वे प्रस्तावना के हर शब्द के जादू को अनुभव कर सकेंगे। जो नहीं जानते, उन्हें यह जानना चाहिए कि वे राष्ट्रीय नेताओं में बड़े नेता, संगठनकर्ताओं में सबसे कुशल संगठनकर्ता, विचारकों में शिखर विचारक और डॉ. आंबेडकर के एक निकट सहयोगी भी थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के

आजीवन प्रचारक थे। उनका बड़ा सम्मान था। यह भी जानने की बात है कि इमरजेंसी में वे नानाजी देशमुख, रवीन्द्र वर्मा की गिरफ्तारी के बाद लोक संघर्ष समिति के महासचिव का दायित्व संभाले रहे। फिर भी पुलिस से बचे रह सके। पूरी इमरजेंसी में भूमिगत संघर्ष के एक सूत्रधार थे।

उन्होंने नरेन्द्र मोदी की पुस्तक- 'आपातकाल में गुजरात' की प्रस्तावना में एक जगह लिखा है- 'जब इमरजेंसी घोषित हुई, उस समय तीन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें थीं, किंतु इनमें से गुजरात सरकार ने ही तानाशाही का खुलकर विरोध किया और लोकतंत्र सेनानियों को अभय क्षेत्र प्रदान किया। इस प्रदेश में उस समय साहित्य-निर्माण आदि ऐसे कार्य हुए, जो अन्य प्रदेशों में करना संभव नहीं था। 'साधना' तथा 'भूमिपुत्र' पत्रिकाओं ने देश के अखबारी इतिहास में एक नए गौरवशाली अध्याय का निर्माण किया। इस संघर्ष के अहिंसात्मक तंत्र में गुजरात प्रारंभ से ही प्रशिक्षित था, क्योंकि महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की यह भूमि रही है। अखिल भारतीय स्तर पर लोक संघर्ष समिति ने जितने भी कार्यक्रम दिए, उन सबका कार्यान्वयन गुजरात ने बहुत अच्छे से किया। इस दृष्टि से संघर्ष की अखिल भारतीय पृष्ठभूमि पर इस प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों की समग्र कारवाइयों का इतिहास सुसूत्र तथा प्रसंगबद्ध ढंग से लिखना एक कठिन कार्य था, किंतु यह कार्य इस कृति के लेखक नरेन्द्र मोदी ने संतोषजनक ढंग से किया है। इस तरह का लेखन किस ढंग से किया जाए, इसका नमूना भी इस पुस्तक में लेखक ने प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक इतिहास लेखकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।'

दूसरी, बात पुस्तक के परिशिष्ट-4 में है। उसका शीर्षक है- 'कुछ निजी बातें'। नरेन्द्र मोदी लिखते हैं- 'इमरजेंसी कैसे आई, इस बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, परंतु इमरजेंसी हटी कैसे, इस बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। इस स्थिति से ही इस पुस्तक का जन्म हुआ। चुनाव आए। जनता पक्ष की विजय हुई। क्या यह निरा चमत्कार था!...' वास्तविकता यह है कि लक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए लगातार 21 माह तक सुनियोजित ढंग से संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष से संबंधित छोटे प्रकार के अनेक सूक्ष्म, ज्ञात-अज्ञात पहलुओं की अपनी एक भव्य गाथा है। इस प्रकार से इस दूसरे स्वातंत्र्य संघर्ष का अंग्रेजों के विरोध में हुए स्वातंत्र्य संघर्ष से लेशमात्र कम महत्व नहीं है। गुजरात ने भी इस संघर्ष के प्रारंभ से ही जमकर लोहा लिया है।'... 'यह मेरी प्रथम पुस्तक है।'... 'भूमिगत संघर्ष के बारे में अब तक अनुत्तरित रहे, कुछ कठिन प्रश्नों की कुंजी स्वरूप यह पुस्तक मैंने किसी लेखक की तरह नहीं, वरन् लड़ाई के एक सिपाही की हैसियत से लिखी है।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'कुछ मूक सेवकों की उनके बारे में कुछ न लिखे जाने की इच्छा के वश होकर मुझे संयमित रहना पड़ा है। इसके अलावा सफल भूमिगत जीवन के गुर, युक्तियाँ-प्रयुक्तियाँ एवं कुछ योजनाओं के बारे में आज कुछ भी कहना समय से पहले कही गई बात होगी।'

इमरजेंसी का सीधा-सपाट मतलब है, इंदिरा गांधी की तानाशाही। उस दौर को बहुविध पीड़ा से इस समय याद किया जा रहा है। यह सर्वथा उचित है। यही वह सही समय है, जब यह भी जानना चाहिए कि उसी तानाशाही के दौर में भारतीय लोकतंत्र का पुनर्जन्म हुआ। उसके एक नायक आज भारत के स्वराजी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। इमरजेंसी के सफल योद्धा नरेन्द्र मोदी की उन सच्ची गाथाओं को पुनः स्मरण करना चाहिए। इसके दो कारण हैं। पहला कि पिछले वर्ष इमरजेंसी के पचास साल हुए। दूसरा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस संघर्ष गाथा का एक नायक आज भारत का प्रधानमंत्री हैं। दूसरे शब्दों में, इमरजेंसी में जो लोकतंत्र का सेनानी था, वह भारत के जीवंत लोकतंत्र का आज प्रथम पुरुष है। यह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता के लिए दीप-स्तंभ सरीखा आशवासन है।

इन दोनों कारणों का एक वैचारिक और सैद्धांतिक आधार है। वह यह कि जो समाज अपने लोकतंत्र के पुनर्जन्म का इतिहास भूल जाता है, उसका भविष्य भयंकर तानाशाही के खतरे में पड़ा रहता है। यह खतरा कैसे बड़ी चुनौती है और उससे पार पाने का रास्ता क्या है, इसे ही एक इतिहास बोध से सुलझाया जा सकता है। इस लेख में जो-जो गाथाएं आप पढ़ेंगे, वे डींग हांकने के लिए नहीं लिखी जा रही हैं। इसलिए लिखी जा रही हैं कि भविष्य में कोई स्वार्थी, पदलोलुप तानाशाह लोकतंत्र को फांसी पर न लटकाए। उसे वही काला इतिहास दोहराने की हिम्मत न हो।



नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल के दौरान
संघर्ष को सफल बनाने के लिए
भूमिगत रहकर रात-दिन काम किया।
तब वे 24 साल के युवा थे। राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। भूमिगत
रहकर उन्होंने लोकतंत्र की मशाल
जलाए रखी। इसके लिए वे कभी साधु
वेश में होते थे तो कभी सरदार का
बाना अपना लेते थे। जरूरत पड़ने
पर अगरबत्ती बेचने वाले बन जाते थे।
उन्होंने इमरजेंसी के दिनों में अखबार के
हॉकर का भी काम किया।



इमरजेंसी में एक तिकड़ी काम कर रही थी। उसका जाल पूरे देश में था। वह तिकड़ी कौन सी थी? उसका स्वरूप क्या था? उसका काम क्या था? ये तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर इमरजेंसी के अनुभवों में समाया हुआ है। जिन्होंने भी इमरजेंसी का दौर देखा और लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयास करने की सक्रियता दिखाई, वे भली-भांति जानते हैं कि उन्हें उस तिकड़ी से बड़ा खतरा था।

आमतौर पर विद्वान लोग जब इमरजेंसी के बारे में अपनी कलम चलाते हैं तो वे पुलिस राज की चर्चा तक ही सीमित रहते हैं। किताबी अध्ययन की अपनी सीमा है। इसलिए उन लोगों का कोई दोष नहीं है, जो पुलिस की ज्यादातियों के आधार पर इमरजेंसी की तानाशाही का वर्णन करते हैं। इसमें दो तत्व और उस समय सक्रिय थे। उनकी अनदेखी करके चलेंगे तो तस्वीर अधूरी रहेगी। पुलिस के अलावा जो दो तत्व थे, उन्हें बर्बर पुलिस की दूसरी और तीसरी कतार कह सकते हैं। कांग्रेस की संजय ब्रिगेड और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआइ) के लोग बढ़-चढ़ कर पुलिस की आंख, नाक, कान, हाथ और पांव का काम कर रहे थे। इसी से तिकड़ी बनी थी। पुलिस को कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों से जो मदद मिली, वह इमरजेंसी के दौर में बर्बर घटनाओं में बदली।

ऐसे भयावह वातावरण में युवा नरेन्द्र मोदी ने लोकतंत्र के लिए चेतना जगाने का बीड़ा उठाया। संकल्प करना एक बात है और उसे हर विपरीत परिस्थिति में पूरा कर लेना एक असंभव को संभव बनाना जैसा होता है। सोचिए, नरेन्द्र मोदी तब अपना सामाजिक-सार्वजनिक जीवन शुरू ही कर रहे थे। यह नहीं कह सकते कि उन्हें उस संग्राम का अनुभव था, जिसमें वे कूद पड़े थे। नरेन्द्र मोदी संघ के युवा प्रचारक थे। इंदिरा गांधी और उनकी तिकड़ी का सबसे प्रबल प्रहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर था। परिस्थितियां विपरीत और भयावह थीं। चुनौती बड़ी थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध घोषित हो गया था। इमरजेंसी लगाये जाने के एक सप्ताह बाद ही संघ पर प्रतिबंध लगा। चार जुलाई, 1975 की तारीख थी। उसी रात माधव कोडोपंत मुले ने एक बैठक बुलाई। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह थे। उसमें मोरोपंत पिंगले, भाऊराव देवरस, प्रो. राजेन्द्र सिंह (रजू भैया), बापूराव मोघे थे। बेहतर समन्वय के लिए उस बैठक में सुंदर सिंह भण्डारी, दत्तोपंत ठेंगडी और नानाजी देशमुख भी उपस्थित थे। नानाजी देशमुख उस समय लोक संघर्ष समिति के महासचिव थे। इन नेताओं ने परिस्थिति को समझा, आंका और कार्ययोजना बनाई।

एक संगठनात्मक संरचना बनाने का निर्णय हुआ। जो इमरजेंसी में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष चला सके। पूरे देश को छह क्षेत्रों में बांटकर उसके क्षेत्रीय प्रमुख बनाए गए। हर क्षेत्र का एक केंद्र था। इस तरह दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता (अब कोलकाता), बंगलोर (बेंगलुरु), बंबई (मुंबई) और नागपुर केंद्र निर्धारित हुए। बंबई केंद्र से महाराष्ट्र (विदर्भ को छोड़कर), गोवा तथा गुजरात में संघर्ष को संचालित करने की जिम्मेदारी लक्ष्मणराव इनामदार पर आई। लक्ष्मणराव इनामदार कौन थे? उनका यहां जरूरी परिचय इन शब्दों में पढ़िये। ये शब्द नरेन्द्र मोदी के हैं, 'लक्ष्मण माधव इनामदार' नाम गुजरात में कितने लोग जानते होंगे? लेकिन 'वकील साहब' कहो तो गुजरात के केवल शहरों में ही नहीं, गांवों में भी वे लोकप्रिय थे।... लक्ष्मणराव इनामदार हमारे 'वकील साहब' बने, इसमें उनकी तपस्या, अथक परिश्रम और कार्य तथा कार्यक्षेत्र के साथ संपूर्ण समरसता का इतिहास है।'

जैसे रामकृष्ण परमहंस की कथा बिना स्वामी विवेकानंद के पूरी नहीं होती, जैसे महात्मा गांधी की कथा बिना सरदार पटेल और महादेवभाई देसाई के पूरी नहीं होती, वैसे ही लक्ष्मण राव इनामदार (वकील साहब) की कथा नरेन्द्र मोदी की पुस्तक, 'आपातकाल में गुजरात' के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस पुस्तक में परिशिष्ट-1 है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें वह पत्र है, जिसे लक्ष्मणराव इनामदार ने बंदी लोकतंत्र सेनानियों को लिखा था। यह पत्र लंबा है। उस पर 31 मई, 1976 की तारीख है। इस पत्र में बंदी लोकतंत्र सेनानियों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ बातें कही गई हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात पत्र में वह है, जिसे आज पढ़ने पर अचंभा होता है। वह बात क्या है? उस अंश को पढ़ें और अनुभव करें, 'संभवतः अक्टूबर 1976 से मार्च 1977 के बीच इंदिरा बहन अपनी अनुकूलता के अनुसार चुनाव घोषित करेंगी।' यह बात लक्ष्मणराव इनामदार के पत्र में है। इस सूचना के बाद पूरी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका एक खाका वे अपने पत्र में उन लोगों के लिए बनाते हैं, जिन्हें समझना है और जानना है। वे लिखते हैं कि चुनाव में धांधली हो सकती है। लेकिन इस कारण चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। उस समय लोकतंत्र सेनानियों में दो मत थे। कुछ लोग चुनाव के बहिष्कार के पक्षधर थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव को पूरी शक्ति से लड़ने और जीतने के लिए कटिबद्ध था। यह बात इस पत्र में भी है। यह पत्र आज दो बातें बताता है। एक, इंदिरा गांधी के तानाशाही ताने-बाने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी व्यूह रचना से भेद लिया था। जो ताना-बाना मजबूत दिखता था, वह खोखला साबित हुआ। दो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व को इंदिरा गांधी के निवास से ही यह पता चल गया था कि वे लोकसभा चुनाव कराने जा रही हैं।

लक्ष्मणराव इनामदार के एक सहयोगी युवा नरेन्द्र मोदी थे। उन पर यह जिम्मेदारी आयी कि वे उस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में संघर्ष के लिए एक संगठनात्मक ढांचा बनाएं। संघ पर प्रतिबंध का व्यावहारिक अर्थ यह था कि उसके कार्यालयों पर ताले लगा दिये गए थे। लेकिन पुलिस की विफलता यह थी कि उसे कार्यालयों से कार्यकर्ताओं की सूची और नाम नहीं मिले। उसे यह कार्य अलग से करना पड़ा। पुलिस को दोहरी मेहनत करनी पड़ी। उसे पहले तो यह पता करना पड़ा कि संघ के नए केंद्र कौन से हैं। दूसरा कि कहां कौन सक्रिय है। संघ के लोकतंत्र सेनानियों ने पुलिस को खूब छकाया। संघ की योजना में जो कार्य होना था, वह पुलिस और इंदिरा गांधी की तिकड़ी से नजर बचाकर ही किया जा सकता था। इसके लिए हर सक्रिय नायक ने अपना नाम बदला। नरेन्द्र मोदी बने बटुक भाई।

लोकतंत्र सेनानी नरेन्द्र मोदी ने अपने लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए। एक कि गुजरात और पूरे देश में जहां जरूरत पड़ेगी, वहां जाएंगे और लोकतंत्र के लिए अलख जगाते रहेंगे। दो कि किसी भी कीमत पर पुलिस से बचे रहेंगे, लेकिन सक्रियता में कोई कमी नहीं आने देंगे। इमरजेंसी के 21 महीने का इतिहास साक्षी है कि नरेन्द्र मोदी ने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया, उसे वे पूरा कर सके।



नरेन्द्र मोदी के लिए आपातकाल के दिनों में नाम बदलकर काम करना आसान नहीं था। उन्हें कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता था। नाम और पहचान बदलकर रहने के बावजूद ऐसा नहीं था कि गिरफ्तारी का संकट टल गया था। दूसरे देश में रहने के बावजूद यह खतरा लगातार बना रहता था कि कहीं से कोई पुलिस को यह जानकारी न पहुंचा दे कि नरेन्द्र मोदी फलां देश में फलां नाम के साथ घूम रहे हैं।

ऐसे उदाहरण विरले हैं। इसे जानने-समझने के लिए यह अंश पढ़िए, 'नरेन्द्र मोदी के लिए आपातकाल के दिनों में नाम बदलकर काम करना आसान नहीं था। उन्हें कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता था। नाम और पहचान बदलकर रहने के बावजूद ऐसा नहीं था कि गिरफ्तारी का संकट टल गया था। दूसरे देश में रहने के बावजूद यह खतरा लगातार बना रहता था कि कहीं से कोई पुलिस को यह जानकारी न पहुंचा दे कि नरेन्द्र मोदी फलां देश में फलां नाम के साथ घूम रहे हैं।' इस खतरे के बीच वे अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। गिरफ्तारी से भी बच सके। ऐसा इसलिए हो सका, क्योंकि नरेन्द्र मोदी ने जोखिम के साथ सूझबूझ को बनाए रखा। जो चूके, वे पकड़े गए। आज किसी के लिए यह कल्पना करना भी कठिन होगा कि इमरजेंसी के दिन कैसे बीतते थे। जब मुखबिर चारों ओर फैले हों वैसे ही जैसे अभिमन्यु कौरवों के बीच फंसा था।

गुजरात के वरिष्ठ साहित्यकार और राज्य साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विष्णु पंड्या का यह कथन एक गवाही है, 'एक बैठक में मैं, नरेन्द्र मोदी, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी केशवराव देशमुख, शंकर सिंह वाघेला और नाथालाल झगड़ा उपस्थित थे। उस बैठक में हम सभी लोगों को साहित्य, संगठन और संघर्ष की जिम्मेदारी दी गई। दुर्भाग्य से सबसे पहले पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला भी पकड़े गए। मोदी और देशमुख नहीं पकड़े गए थे। ... मोदी ने जिस तरह का बेहतरीन कार्य गुजरात में किया था, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो 'लोक संघर्ष समिति' बनी थी, उसमें उन्हें शामिल किया गया। इसमें संघ के नानाजी देशमुख जैसे बड़े लोग भी थे। सरदारजी का वेश धारण करके मोदी काफी जोखिम लेते हुए कुछ मौकों पर हम लोगों से मिलने जेल भी आए। प्रकाशन, प्रतिरोध और संगठन को चलाए रखने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मोदी जैसे उन लोगों के कंधों पर आ गईं, जो जेल से बाहर थे।

नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर संघर्ष को सफल बनाने के लिए रात-दिन काम किया। तब वे 24 साल के युवा थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। भूमिगत रहकर उन्होंने लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी।

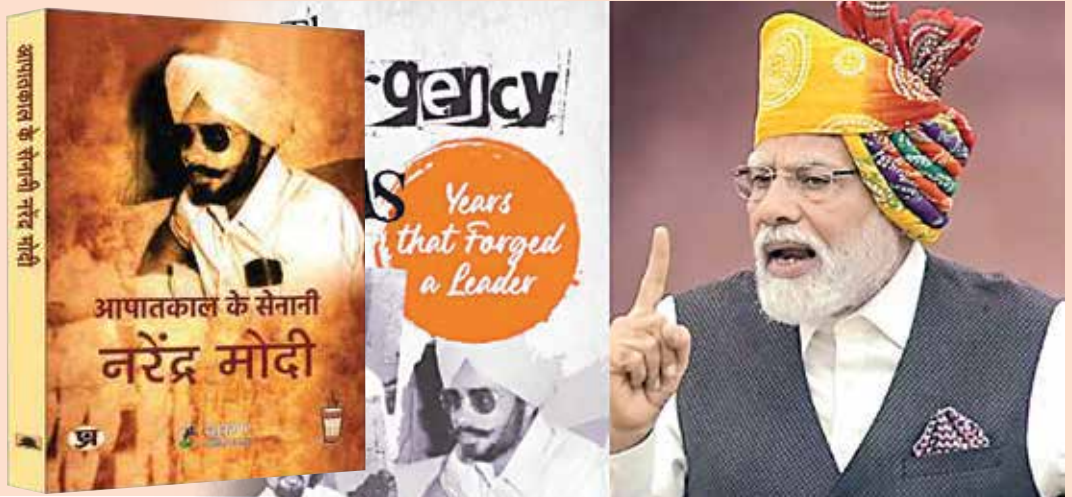
आचार्य जे.बी. कृपलानी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीस साल के शासन के बाद आधुनिक भारतीय इतिहास के त्रासद अध्याय (इमरजेंसी) की शुरुआत 1975 में आपातकाल की घोषणा के साथ ही नहीं हुई। यह काफी पहले ही शुरू हो गया था, जब 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कार्यसमिति से भी पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने

आर्थिक मामलों पर 'कुछ फुटकर विचार' नाम से चर्चा कराई। अफसोस है कि उनकी इस मनमानी को कांग्रेस नेतृत्व ने मान लिया था। उनके मनमाना काम-काज और फैसलों की शुरुआत यहीं से हुई, जो आगे चलकर नियमित चीज बन गई।' कृपलानी जी की आत्मकथा में यह अंश उस अध्याय के प्रारंभ में है जिसका शीर्षक है, 'तानाशाही'।

कृपलानी जी को जो जानते हैं, वे मानेंगे कि नरेन्द्र मोदी ने 'संविधान हत्या दिवस' को सुनिश्चित कर 'दूसरी आजादी' के सभी सेनानियों को एक उपहार दिया है। प्रकांतर से हर देशवासी को लोकतंत्र का ककहरा थमाया है। कुछ लोग इसे उपहार नहीं भी मानेंगे। ऐसे लोग अनुभव करेंगे कि यह उपहार जले पर नमक छिड़कने जैसा है? ऐसे लोगों को खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। वे हमारे आस-पास मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो इसे प्रतिहिंसा की भावना का द्योतक समझ सकते हैं। कौन क्या समझता है, कैसे समझता है, क्यों समझता है? यह प्रश्न व्यक्ति, समूह, संस्था, संगठन, समाज के विभिन्न समुदायों की उस समझ से संबंधित है जिसका गहरा नाता इतिहास दृष्टि से होता है। क्या यह सर्वसामान्य सिद्धांत है? इसका उत्तर इसमें छिपा हुआ है कि इमरजेंसी को किस तरह समझा गया है। 'संविधान हत्या दिवस' ने हर भारतीय की इतिहास दृष्टि में एक नए आकाश की रचना कर दी है। उसे नया इतिहास बोध मिला है। इस आधार पर इतिहासकार नरेन्द्र मोदी को मौलिक चित्त का मालिक मानेंगे।

अगर ऐसा न होता तो 1977 में ही 'संविधान हत्या दिवस' घोषित कर दिया जाता। जो जनता सरकार बनी थी, वह 'दूसरी आजादी' की लड़ाई के अच्छे परिणाम का प्रतीक थी। यह प्रश्न यहां अप्रासंगिक नहीं होगा कि क्यों उस सरकार ने यह फैसला नहीं किया। इसका उत्तर भी सीधा-साधा है। वह एक बेमेल समसामयिक संकट में बना अस्थायी गठजोड़ था। वह भी ढीला-ढाला। उस समय भी जनता पार्टी में कोई यह नहीं मानता था कि इमरजेंसी ठीक थी। कांग्रेस में अवश्य आवाजें उठने लगी थीं कि इमरजेंसी लगाना अनुचित था। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता में यह हिम्मत नहीं थी कि वह जनता लहर में यह कहे कि इमरजेंसी सही थी। इमरजेंसी के लिए दोषी कौन है? इस पर कांग्रेस में बहस तब भी थी और आज भी है।

प्रणब मुखर्जी ने अपने संस्मरण में इसके लिए सिद्धार्थ शंकर रे को दोषी ठहराया है। 'संविधान हत्या दिवस' से स्पष्ट हो गया है कि दोषी अगर कोई है तो वह इंदिरा गांधी स्वयं हैं। क्या कोई है, जो आज यह मानता हो कि इमरजेंसी की घोषणा सही थी? शायद ही कोई ऐसा मूढ़ खोजने पर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष 29 जून को अपने 'मन की बात' रेडियो पर कही। इसमें वे इमरजेंसी पर भी बोले। उससे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के भाषण का एक अंश सुनाया। 'मन की बात' के श्रोताओं और दर्शकों ने सुना कि मोरारजी भाई देसाई कह रहे हैं, 'आखिर ये जो जुल्म हुआ दो साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था। मगर वो शिखर पर पहुंच गया है दो साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर थोप दी गई और अमानुषीय बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही। न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए। जिस ढंग से एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया और फिर राज की ओर से अपनी मनमानी होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है।' इसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आडियो भी सुनाया। उसमें वाजपेयी जी कह रहे हैं, 'देश में जो कुछ हुआ, उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोकशक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है।' इस कथन में 1977 के चुनाव परिणाम की एक व्याख्या है। इन कथनों को याद दिलाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि, 'हम देशवासियों ने 'संविधान हत्या दिवस' मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए, जिन्होंने



इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है।' अगर किसी को जानना हो कि 'संविधान हत्या दिवस' क्यों घोषित हुआ तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन बार-बार पढ़ना चाहिए।

इससे पहले 25 जून, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, 'आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन, भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था, जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था।'

यह आकस्मिक नहीं है। संविधान में आस्था की जड़ें किसी को खोजना हो तो उसे अनेक प्रमाण मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः सिर्फ चिन्हित किया है। शुरुआत उन्होंने बहुत पहले की थी। जो इतिहास का आज एक सुनहरा पृष्ठ बन गया है। संविधान के 60 साल पूरे होने पर गुजरात के सुरेंद्र नगर में नरेंद्र मोदी ने तब कहा था, 'संविधान हमें शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, जोड़ता है, हमें सीमाओं में बांधता है। ये बंधन मुक्ति के मार्ग होते हैं।' नरेंद्र मोदी के ये उद्गार सहज हैं। दूसरी आजादी की लड़ाई के इतिहास में गहरे पैठकर इसे जाना जा सकता है। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन में नरेंद्र मोदी सूत्रधार थे, लेकिन पृष्ठभूमि में थे। उन्होंने नवनिर्माण आंदोलन को सफल बनाने में अपना खून पसीना बहाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता और इस समय बड़े वकील अरुण ओझा याद करते हैं कि नवनिर्माण आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय सम्मेलन कराया, जिसमें मशहूर वकील वी.एम. तारकुंडे भी शामिल हुए। एक दूसरा आयोजन अहमदाबाद के टाउन हॉल में हुआ, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने संबोधित किया।

इमरजेंसी की रेडियो पर घोषणा से पहले ही गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 25 जून की रात जो कुछ सूचनाएं मिल रही थीं, उनका वर्णन अपनी पुस्तक, 'आपातकाल में गुजरात' में नरेंद्र मोदी ने सूत्रवत किया है। 'आपातकाल के सेनानी नरेंद्र मोदी' दूसरी पुस्तक है जो अपने पाठकों को इन शब्दों में उस संघर्ष की एक झलक देती है, 'गुजरात के आपातकाल विरोधी संघर्ष को संघ के बड़े

लोगों ने नेतृत्व दिया था, जिसमें लक्ष्मणराव इनामदार (वकील साहब), केशवराव देशमुख, वसंत गजेंद्रगड्कर आदि शामिल थे। इनके नेतृत्व में नरेन्द्र मोदी, शंकर सिंह वाघेला और नाथालाल झगड़ा जैसे लोग कार्य करते थे। गुजरात का अनुकरण बिहार में बहुत प्रचलित हुआ। सरदार पुत्री मणिबेन पटेल ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। संघ के कार्यकर्ताओं ने साइकिल पर 'मुक्ति यात्रा' निकाली थी, जिसे मणिबेन ने झंडा दिखाकर रवाना किया था।'

'आपातकाल के दिनों में गुजरात में सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा था। इसकी शुरुआत 14 नवंबर, 1975 से होनी थी। इस दिन गुजरात के सभी जिला मुख्यालयों पर आपातकाल के विरोध में सत्याग्रह का आयोजन हुआ। इस दौरान पूरे गुजरात में 'तानाशाही मुर्दाबाद' और 'लोकशाही जिंदाबाद' के नारे लगे। हजारों कार्यकर्ता आपातकाल विरोधी संघर्ष में जुटे और जेल भी गए।' इसी पुस्तक में यह वर्णन भी है कि, 'अहमदाबाद जिले का सत्याग्रह धोलका में हुआ। वहां क्रांतिभाई कपाड़िया के नेतृत्व में आठ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। इन सत्याग्रहियों को अहमदाबाद की साबरमती जेल में लाकर कैद किया गया। साबरकांठा जिले का सत्याग्रह हिम्मत नगर में बल्लभ भाई दोशी के नेतृत्व में हुआ। वहां सत्याग्रह करने से पहले जे.पी. के स्वास्थ्य लाभ हेतु सामूहिक प्रार्थना की गई। एकत्र विशाल जन समुदाय ने सत्याग्रहियों को जेल के लिए विदा किया। मेहसाणा में जिले के अलग-अलग सात गांवों से आए हुए सत्याग्रहियों का नेतृत्व श्यामा प्रसाद शास्त्री ने किया था। जिन गांवों से ये सत्याग्रही आए थे, उन सभी गांवों में उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किए गए थे।' अलग-अलग स्थानों पर सत्याग्रह करने वाले लोगों के बारे में नरेन्द्र मोदी लिखते हैं, 'सत्याग्रह की खबर पाकर आबू में गुप्तवास कर रहे कपिलदेव स्वामी नामक एक साधक अपनी साधना को छोड़कर जन-जागृति हेतु लोगों के बीच आ पहुंचे। भगवा वस्त्रधारी, इकहरे शरीर, मुंडित मस्तक, लंबी शिखा और नुकीली नाक वाले इन स्वामी जी की वाणी आग बरसाती थी। बनासकांठा जिले के पालनपुर में भैरू प्रताप शास्त्री के नेतृत्व में आठ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। कच्छ जिले में सत्याग्रह का आरंभ भुज से हुआ। 78 वर्षीय नारायण गोस्वामी तथा रतन सिंह भाई सेजपाल सहित कुल सात सत्याग्रहियों ने सविनय कानून भंग किया और गिरफ्तार हुए। जामनगर जिले के दस सत्याग्रहियों ने श्री दिनेश कुमार व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। राजकोट में डॉ. पी.वी. दोशी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुजरात प्रांत के संघचालक रहे थे, के नेतृत्व में 15 सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। जूनागढ़ जिले में कर्मठ कार्यकर्ता भानू भाई शुक्ल के नेतृत्व में छह सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया।'

'अमरेली में मनभाई रणछोड़ भाई, सुरेंद्र नगर में प्रभुदास परमार, भावनगर में विधायक मणि भाई गांधी, खेड़ा में प्रसिद्ध डॉ. अरविंद भाई व्यास, गोधरा में हर्षद भाई व्यास और वासुदेव भाई और बड़ोदरा में डॉ. भोगी भाई पटेल ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। भरूच की कमान अजय भाई जोशी ने संभाली तो सूरत में सत्याग्रह का नेतृत्व वहां के व्यापारी इंद्रकांत भाई शाह





ने किया। वलसाड़ में सत्याग्रह के अगुआ संघ के जिला संघचालक बलवंत भाई बने। 'आपातकाल में गुजरात' पुस्तक का यह अंश है। इसके लेखक नरेन्द्र मोदी हैं। इस वर्णन का सार यह है कि नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल में गुजरात लोक संघर्ष समिति के संघर्ष का भूमिगत रह कर सफल और सार्थक संयोजन किया।

इसीलिए बीते वर्ष 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' पर गृहमंत्री अमित शाह ने त्यागराज इनडोर स्टेडियम की बड़ी सभा में कहा कि, 'हम यहां आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो काला अध्याय था, उसे याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि 25 जून, 1975 को संविधान की हत्या की गई थी। इसे याद रखने से वह पुनः दोहराया नहीं जाएगा।' उसी अवसर पर उन्होंने कहा कि, '(नरेन्द्र) मोदी जी ने उस दौरान संघर्ष को सफल बनाने के लिए रात-दिन एक किया। तब वे 24 साल के युवा थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। भूमिगत रहकर उन्होंने लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी। इसके लिए वे कभी साधु वेश में होते थे तो कभी सरदार का बाना अपना लेते थे। जरूरत पड़ने पर अगरबत्ती बेचने वाले बन जाते थे। उन्होंने इमरजेंसी के दिनों में अखबार के हॉकर का भी काम किया।'

(साभार : युगवार्ता)

(पद्मभूषण और पद्मश्री से सम्मानित लेखक प्रख्यात पत्रकार, बहुभाषी न्यूज एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार व उसके प्रकाशनों के समूह संपादक और नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। वे अनेक चर्चित पुस्तकों के लेखक और संपादक हैं।)



विकसित भारत



आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी
कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

प्रभावी और प्रेरक नेतृत्व

युगांतकारी कार्यकाल

भारतीय इतिहास के कालक्रम में कुछ दशक ऐसे हैं जो सदियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2014 से अब तक का समय भारत के लिए वैसा ही 'टर्निंग पॉइंट' है, जैसा 1947 या 1991 था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व केवल एक राजनीतिक दल की जीत नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस की उस सुषुप्त आकांक्षा का प्रकटीकरण है, जो अपनी पहचान और अस्मिता के लिए छटपटा रही थी। नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व शैली स्पष्ट और निर्णायक है। वे तेजी से निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए जाने जाते हैं। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से ही उनका यह कौशल स्पष्ट था, जब उन्होंने राज्य में कई सर्वांगीण विकासात्मक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी सशक्त और निर्णायक नेतृत्व शैली ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक अतिविशिष्ट राजनेता के रूप में स्थापित किया। वैश्विक संकटों और चुनौतियों के समय उनके कठिन निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें एक भरोसेमंद और सक्षम जननेता के रूप में पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल राजनीति के व्याकरण को बदला,



प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल राजनीति के व्याकरण को बदला, अपितु उन्होंने 'तुष्टीकरण' के स्थान पर 'संतुष्टीकरण' और 'अधिकार' के स्थान पर 'कर्तव्य' को स्थापित किया। उनका यह कहना कि 'मैं प्रधान सेवक हूँ' गांधीजी के 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धांत का आधुनिक संस्करण है।



अपितु उन्होंने 'तुष्टीकरण' के स्थान पर 'संतुष्टीकरण' और 'अधिकार' के स्थान पर 'कर्तव्य' को स्थापित किया। उनका यह कहना कि 'मैं प्रधान सेवक हूँ' गांधीजी के 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धांत का आधुनिक संस्करण है।

सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा का केंद्र 'राष्ट्र प्रथम' है। उनकी यह विचारधारा मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर टिकी है। जिनमें पहला स्तंभ है सभ्यतागत राष्ट्रवाद। जहां पश्चिमी राष्ट्रवाद सामान्यतः 'नस्ल' या 'भाषा' पर आधारित होता है, वहीं नरेन्द्र मोदी का राष्ट्रवाद 'संस्कृति' पर आधारित है। उनका मानना है, कि भारत केवल एक 75-76 वर्ष पुराना स्वतंत्र देश ही नहीं है, बल्कि एक सर्वसमावेशी सभ्यता है। उनके इन विचारों का स्रोत निश्चित रूप से श्रीअरविंदो, वीर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शोधित दृष्टि है, जिसमें भारत को एक 'पुण्यभूमि' और 'पितृभूमि' माना गया है। साथ ही, पीएम मोदी जब केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाते हैं या काशी में तमिल संगमम का आयोजन करते हैं, तब वे वर्षों से खंडित की गई भारतीय पहचान को, एक सूत्र में पिरो कर सांस्कृतिक एकीकरण को मजबूती प्रदान करते हैं। उनके द्वारा उद्धोषित नारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' सर्वसमावेशी विकास का मूल मंत्र है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तावित एकात्म मानववाद को भी एक नया रूप दिया है। पंडित दीनदयाल जी का यह दर्शन पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का 'मध्यम मार्ग' है। क्योंकि पूंजीवाद केवल 'अर्थ' पर केंद्रित है और साम्यवाद केवल 'राज्य' को ही सर्वोच्च मानता है, जबकि एकात्म मानववाद कहता है कि मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा—इन चारों का विकास होना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो मोदी जी की योजनाएं, जैसे—'स्वच्छ भारत' (तन की शुद्धि), 'योग' (मन और आत्मा की शुद्धि), 'शिक्षा नीति' (बुद्धि का विकास) इसी दर्शन का विस्तार हैं। 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मान्यता दी। 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी के परिणामस्वरूप आज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित अनेक देशों में योग को स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल किया गया है। हजारों विदेशी नागरिक भारत आकर ऋषिकेश, कर्नाटक,

केरल जैसे योग-आश्रमों में योग का प्रशिक्षण लेते हैं। विश्व की प्रमुख हस्तियां, जैसे-माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो योग के नियमित अभ्यासी हैं।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने संवाद और नेतृत्व का एक नया उदाहरण भावी पीढ़ियों के लिए पेश किया है। उन्होंने अपने 'मन की बात' नामक कार्यक्रम से संवाद का लोकतंत्रीकरण किया है। रेडियो जैसा पुराना माध्यम मोदी जी के हाथों में एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। इसके 100 से अधिक प्रसारणों के माध्यम से उन्होंने राजनीति को 'सत्ता' से हटाकर 'समाज' पर केंद्रित कर दिया है। इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता जानते हैं कि इसमें वे राजनीतिक विरोधियों पर हमला नहीं करते, बल्कि गांव के किसी उद्यमी किसान, किसी नवाचारी छात्र या किसी स्वयं सहायता समूह की महिला की कहानी सुनाते हैं। यह उनके द्वारा की गई 'सोशल इंजीनियरिंग' का सबसे सशक्त माध्यम बना है।

कोविड-19 महामारी के दौरान उनका नेतृत्व विश्व के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। कोविड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। इस बीमारी ने जितना लोगों के शरीर को कष्ट पहुंचाया, उससे कहीं अधिक लोगों को मानसिक संताप भी दिया, लेकिन पीएम मोदी ने उस दौरान कुछ ऐसे निर्णय लिए, जिससे उन्होंने देश का मनोबल ऊंचा उठाया और सबको एकजुट किया। उनके द्वारा किये गए 'ताली-थाली' बजाने या 'दीया जलाने' के आह्वान का कुछ विरोधियों द्वारा भले ही मजाक उड़ाया गया, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसने 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांध दिया, जिससे लॉकडाउन का पालन करना संभव हुआ। यह दिखाता है कि एक नेता कैसे जनशक्ति को नयी दिशा दे सकता है। इसी बीच 'वैक्सीन मैत्री' के माध्यम से 100 से अधिक देशों को मुफ्त टीका पहुंचाकर भारत ने प्राचीन सिद्धांत "सर्वे सन्तु निरामयाः" को चरितार्थ किया।

बात यदि आर्थिक मोर्चे की करें तो प्रधानमंत्री मोदी का आर्थिक दर्शन 'प्रो-पुअर' और 'प्रो-मार्केट' का अनूठा मिश्रण है। अपने डिजिटल इंडिया मिशन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। 2014 से पहले करोड़ों भारतीयों के पास बैंक खाते नहीं थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इन लोगों को बैंक से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने जनधन, आधार कार्ड और जागरूकता के द्वारा भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार किया। आज डी.बी.टी.(डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है, जिससे बिचौलियों का 'खूनी खेल' खत्म हो गया है। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। सिंचाई परियोजनाओं और फसल बीमा योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता कम करके समृद्धि में बढ़ावा दिया है। 2019





मोदी युग में भारत 'पॉलिसी ऑफ हेजिटेशन' से निकलकर 'पॉलिसी ऑफ कॉन्फिडेंस' में आ गया है। तभी तो भारत एक तरफ 'क्वाड' (QUAD) का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ 'ब्रिक्स' (BRICS) में भी सक्रिय है। रूस से तेल खरीदना और अमेरिका के साथ रक्षा सौदे करना—यह भारत के राष्ट्रीय हितों की सर्वोच्चता को दर्शाता है।

में शुरू हुआ जल जीवन मिशन हर ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। चार साल के भीतर 2023 तक बारह करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना ने प्रवासी श्रमिकों और गरीबों को कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की। अब तक इक्यासी करोड़ से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिला है।

साथ ही भारत यूपीआई क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज भारत दुनिया का 46% डिजिटल रियल-टाइम ट्रांजैक्शन अकेले करता है। यह तकनीक के लोकतंत्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहीं प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना सरकारी विभागों के बीच के अवरोधों को खत्म करती है। प्रतिदिन 30-40 किलोमीटर सड़क निर्माण और रेलवे का 100% विद्युतीकरण भारत की गति को बढ़ा रहा है।

एक समय इस देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती गई। आज पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय को नारों से निकालकर 'वास्तविकता' तक पहुंचाया है। उनके विकसित भारत के मॉडल में देश की स्त्रियों की अग्रणी भूमिका है। इसका प्रमाण उनकी योजनाओं और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में भी दिखता है। उज्ज्वला योजना द्वारा 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शनों ने ग्रामीण महिलाओं को न केवल धुएं से मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके समय की बचत की, जिसे वे अब उत्पादक कार्यों में लगा रही हैं। साथ ही, उनकी सरकार में ही तीन तलाक खत्म हुआ। यह केवल एक कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को संवैधानिक समानता और सामाजिक सुरक्षा देने का एक साहसी कदम है। वहीं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने महिला शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया। अब बेटियों की शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ी है। वे देश-विदेश में शीर्ष संस्थाओं का नेतृत्व कर रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं में सदैव वंचितों को वरीयता दी गयी है। तभी तो देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों पर विशेष ध्यान देकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ केवल महानगरों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों तक अवश्य पहुंचे। ध्यातव्य है कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पचास करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। 2023 तक इस योजना के तहत पांच करोड़ से अधिक लोग मुफ्त इलाज करा चुके थे। मिशन इंद्रधनुष 2.0

के तहत टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा मिला है। इन योजनाओं द्वारा लोगों के स्वास्थ्य में तो सुधार होता ही है, स्वस्थ होने से उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है।

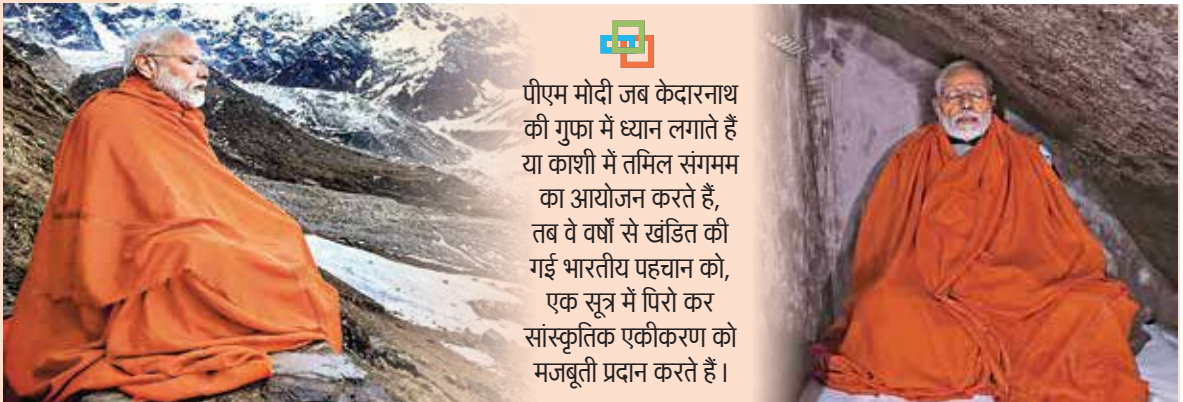
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने यह धारणा तोड़ी कि आधुनिक होने के लिए अपनी पहचान छोड़ना आवश्यक है। उनके कार्यकाल में 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना दिया। आगे चलकर आदित्य L-1 मिशन और गगनयान जैसी परियोजनाओं के माध्यम से भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है। इन उपलब्धियों से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वैश्विक मान्यता पुष्ट हुई है।

2023 में ही भारत ने सफलतापूर्वक जी-20 की अध्यक्षता की, जिसमें विकासशील देशों की आवाज को प्राथमिकता दी गई। "वसुधैव कुटुंबकम्" के सिद्धांत का प्रसार करते हुए भारत ने हरित विकास और डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया। इसी जी-20 बैठक में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया।

इन वैश्विक उपलब्धियों के साथ ही सनातन नगरी अयोध्या और काशी के गौरव की वापसी भी हुई है। अयोध्या में हुआ राम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि यह भारत के 'राष्ट्रीय गौरव' की पुनर्स्थापना है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक ने धर्म को अर्थव्यवस्था और पर्यटन से जोड़ दिया, जिससे स्थानीय रोजगार में भारी वृद्धि के साथ ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मनोभावना बलवती हुई है।

इस सरकार का जोर औपनिवेशिक प्रतीकों के अंत पर भी रहा है, इसलिए राजपथ का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' करना, नौसेना के ध्वज से शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेना और अंडमान के द्वीपों का नामकरण शहीदों के नाम पर करना—यह सब भारतीय मानस के वि-औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता पर भी कई शिक्षाशास्त्री वर्षों से चर्चा कर रहे थे। मोदी सरकार ने उनकी बातों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा शिक्षा प्रणाली में कई सुधार किए, जिसके अंतर्गत मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा और आधुनिक तकनीक का समावेश किया गया। यही नहीं, 2040 तक भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सोलर अलायंस और हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने का बीड़ा उठाया है। साथ ही 2070 तक भारत का नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है। ऐसा कहा जाने लगा है कि सेमीकंडक्टर भविष्य के विकास की कुंजी है। इसलिए समय की नब्ज पहचानते हुए भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र



पीएम मोदी जब केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाते हैं या काशी में तमिल संगमम का आयोजन करते हैं, तब वे वर्षों से खंडित की गई भारतीय पहचान को, एक सूत्र में पिरो कर सांस्कृतिक एकीकरण को मजबूती प्रदान करते हैं।



पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय को नारों से निकालकर 'वास्तविकता' तक पहुंचाया है। उनके विकसित भारत में मॉडल में देश की स्त्रियों की अग्रणी भूमिका है। इसका प्रमाण उनकी योजनाओं और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में भी दिखता है। उज्ज्वला योजना द्वारा 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शनों ने ग्रामीण महिलाओं को न केवल धुएं से मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके समय की बचत की, जिसे वे अब उत्पादक कार्यों में लगा रही हैं।



में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण उद्योग भी है।

विदेश नीति के हवाले से कहा जाए तो मोदी युग में भारत 'पॉलिसी ऑफ हेजिटेशन' से निकलकर 'पॉलिसी ऑफ कॉन्फिडेंस' में आ गया है। तभी तो भारत एक तरफ 'क्वाड' (QUAD) का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ 'ब्रिक्स' (BRICS) में भी सक्रिय है। रूस से तेल खरीदना और अमेरिका के साथ रक्षा सौदे करना—यह भारत के राष्ट्रीय हितों की सर्वोच्चता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक कूटनीति और व्यक्तिगत संपर्क को अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे उनके वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों को बल मिला। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय प्रवासियों के साथ गहरे संबंध बनाए, जिससे विश्वभर में भारत की छवि को सुधारने में मदद मिली। उनकी विदेश यात्राओं के दौरान उनके सार्वजनिक भाषण और रैलियां उनके नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में प्रभावी रही हैं।

हमारे समय के सबसे ज्वलंत विषय यानी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर पहल की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत के नेतृत्व में 2015 में पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) की स्थापना के माध्यम से भारत ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। साथ ही, 'एक पेड़ मां के नाम' के माध्यम से उन्होंने देश को हरा-भरा बनाने का भी प्रयास किया है।

अनुच्छेद-370 हटाने का निर्णय भारत के संघीय ढांचे में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। राष्ट्रहित की दृष्टि से इसे राष्ट्रीय एकीकरण, समान नागरिक अधिकार, विकास और सुरक्षा को मजबूत करने वाले कदम के रूप में मान्यता मिली है। सर्जिकल स्ट्राइक (2016), एयर स्ट्राइक (2019) और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भी कड़े संदेश दिए। उनके कार्यकाल में ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 200 से अधिक रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। आज मेड इन भारत के मिशन को ध्यान में रखकर अपने रक्षा-उपकरण देश में ही बनाने पर

बल दिया जा रहा है।

वैश्विक स्तर पर निरंतर मिलने वाले सम्मान ने भी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की स्वीकृति पर मुहर लगाई है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 'स्वच्छ भारत अभियान' के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में प्रदान किया गया। ऐसे ही भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने और मध्य पूर्व में कूटनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को सुधारने के लिए सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उन्हें मिला। यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिग्विशड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ जॉर्जिया, बहरीन द्वारा ऑर्डर ऑफ किंग हमाद, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ अलायंस द्वारा वर्ल्ड लीडर अवार्ड, दक्षिण कोरिया द्वारा सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया जाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर्मठ और चमत्कारिक व्यक्तित्व का परिचायक है।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" की उक्ति को चरितार्थ करते हुए भारतीय राजनीति में आधी आबादी की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री की पहल पर लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) भारतीय राजनीति में मातृशक्ति को समुचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। उनका नेतृत्व 'परिवर्तनकारी' एवं 'सुधारात्मक' सिद्ध हुआ है। उन्होंने अपने कई अभिभाषणों में देश के समक्ष अपना लक्ष्य स्पष्ट किया है और कहा है कि हम सबको मिलकर 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में ला खड़ा करना है। हमें डिजिटल रूप से एक ऐसे सशक्त समाज का निर्माण करना है जहां हर नागरिक को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। देश के युवाओं को अपनी मेधा के द्वारा नई औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और 5-G प्रौद्योगिकी के तीव्रगामी विकास के लिए अभी से कटिबद्ध हो जाना चाहिए।

उनका कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि यदि नेतृत्व के पास स्पष्ट विचारधारा, अटूट संकल्प और राष्ट्र एवं जनता के प्रति समर्पण हो, तो सदियों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। पीएम मोदी के नेतृत्व का मूल्यांकन केवल जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास से होगा



"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" की उक्ति को चरितार्थ करते हुए भारतीय राजनीति में आधी आबादी की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री की पहल पर लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) भारतीय राजनीति में मातृशक्ति को समुचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक बड़ी पहल है।





पीएम नरेन्द्र मोदी ने संवाद और नेतृत्व का एक नया उदाहरण भावी पीढ़ियों के लिए पेश किया है। उन्होंने अपने 'मन की बात' नामक कार्यक्रम से संवाद का लोकतंत्रीकरण किया है। रेडियो जैसा पुराना माध्यम मोदी जी के हाथों में एक शक्तिशाली माध्यम बन गया। इसके 100 से अधिक प्रसारणों के माध्यम से उन्होंने राजनीति को 'सत्ता' से हटाकर 'समाज' पर केंद्रित कर दिया है।



जो आज एक साधारण भारतीय की आंखों में झलकता है। यह 'अंधकार से प्रकाश की ओर' बढ़ते हुए भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास की यात्रा की महागाथा है, जिसमें विराम लगना राष्ट्रहित में नहीं होगा। वन्दे मातरम्।



(लेखक संप्रति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा में कुलपति हैं। इससे पूर्व साढ़े पांच वर्ष तक डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मप्र (वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सदस्य एवं बेंगलुरु स्थित नैक (NAAC) की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 26 जुलाई, 2024 से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का निदेशक पद भी संभाल रहे हैं। साथ ही, वर्तमान में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, पनवेल, मुंबई की शासी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने लगभग 31 वर्षों तक मिजोरम विश्वविद्यालय में सेवाएं दी हैं। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 100 से अधिक शोधपत्र प्रकाशित हैं। दो पुस्तकों का संपादन भी किया है। भारतीय भूस्तर विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान हेतु इन्हें 2012 में भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी, बेंगलुरु द्वारा 'एल. रामाराव शताब्दी जन्म पुरस्कार' और 2014 में 'डॉ. एस.एम. नक्रवी स्वर्ण पदक' से सम्मानित किया जा चुका है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय पृष्ठ पर नियमित रूप से इनके लेख प्रकाशित होते हैं।)



विकसित भारत



डॉ. सच्चिदानंद जोशी

सदस्य सचिव-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला
केंद्र, कुलपति-भारतीय विरासत संस्थान

न दैन्यं

न पलायनम्

महाभारत में अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण इस उक्ति के साथ किया जाता है, "अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्"। पूरे महाभारत के घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में भगवान श्रीकृष्ण का गीता का उपदेश और अर्जुन की यह प्रतिज्ञा प्रेरणा के केंद्र में हैं। वर्तमान परिदृश्य में ये प्रतिज्ञा कदाचित् विस्मृत हो जाती, यदि हमारे सामने नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जैसा व्यक्तित्व नहीं होता। अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण और अपने ध्येय के प्रति अडिग रहकर संघर्ष करते रहने और अंततः ध्येय को प्राप्त करने का भाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में साक्षात् अवतरित होता दिखाई देता है।

जब हम उनके जीवन को, उनके कार्यकलापों को और उनकी चुनौतियों को देखते हैं तो एक ही प्रश्न हमारे मन में उभरता है कि यह आदमी आखिर किस मिट्टी का बना है, जो न आलोचनाओं से हतोत्साहित होता है और न आरोपों से विचलित होता है, जो न व्यंग्य बाणों से आहत होता है और न षड्यंत्रों से भ्रमित होता है। कैसे यह व्यक्ति अपने ध्येय की ओर अपने लक्ष्य की ओर अविचल बढ़ता जाता है "स्थितप्रज्ञ" का भाव लिए।



श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण और गुण बताए हैं। मूल रूप से स्थितप्रज्ञ के उन गुणों को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जो कामनाओं का त्याग करे, जो आत्म-संतुष्ट हो, जो सम भावी हो, जो वीतरागी हो और जो इन्द्रिय निग्रह का पालन करता हो और इन सबसे बढ़कर जो विरोध, षड्यंत्र और मिथ्या कथन से विचलित हुए बिना अपना काम करता हो, वही स्थितप्रज्ञ है।

यह शायद मानव समाज का स्वभाव है जो व्यक्ति आम जीवन से हटकर कुछ देश हित में या समाज हित में करना चाहता है, उसे उस काल में कड़ी निंदा और विरोध का सामना करना पड़ता है, जिस काल में वह स्वयं कार्य कर रहा होता है। इसके अनेक उदाहरण प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक में मिल जाएंगे। जिस काल में ऐसे व्यक्तित्व अवस्थित होते हैं, उस समय का समाज उन्हें सहज मान्य नहीं करता और उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उनके कार्य का और उनके जीवन का मूल्यांकन तथा महत्व तो बाद में आने वाले काल में होता है।

नरेन्द्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं और हम सब उनके समकालीन समाज हैं। यह हमारे भाग्य में भी है कि हम एक इतिहास घटित होता देख रहे हैं। साथ ही, यह हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम समकालीन समाज में नरेन्द्र मोदी की आलोचना, विरोध और भर्त्सना को भी देख रहे हैं। तकनीक के आडंबर ने ऐसी आलोचनाओं और षड्यंत्रों को और मुखरता प्रदान की है। पिछले कुछ समय में जैसी भाषा और शब्दावली का प्रयोग उनकी आलोचना में हो रहा है, उसे देख सुनकर एक साधारण व्यक्ति तो कब का अपना मानसिक संतुलन खो दे, लेकिन यह नरेन्द्र मोदी ही हैं जो वह सब भी निर्विकार भाव से देख सुन पा रहे हैं, अडिग, अविचल होकर।

अगर हम पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो यह देखकर और सोचकर हमें निश्चित ही खेद और लज्जा होगी कि समकालीन समाज ने उन्हें किस-किस तरह से प्रताड़ित, अपमानित और कुंठित करने का प्रयास किया है। उनके लिए कैसे अपमानजनक और घृणित शब्दों का प्रयोग किया गया है। कैसे उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को संदेह और षड्यंत्र के जाल में खड़ा किया है। कैसे उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक पर विभिन्न लांछन लगा कर कलंकित करने का प्रयास किया गया है। ये षड्यंत्र सिर्फ राजनैतिक उद्देश्य से किए गए नहीं थे, ये उनके समूचे व्यक्तित्व और कृतित्व का समूल नाश करने की नीयत से तथाकथित सभ्य समाज द्वारा रचे गए थे। उन्हें झूठा कहना, पलायनवादी कहना, उन्हें हत्यारा कहना, यहां तक कि लाशों का सौदागर तक कह डालना, ये सब इसी सभ्य समाज के प्रयास हैं। शायद ही होगा कि नरेन्द्र मोदी ने इनका

कोई सीधा-सीधा उत्तर दिया होगा। वे अपने काम को, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ते रहे। पुरानी आलोचनाएं, पुराने षड्यंत्र समाप्त होते रहे और नये की रचना होती रही। समाज शायद यह महसूस ही नहीं कर पाया कि एक इतिहास रचा जा रहा है, जिसके भागीदार वे सभी हैं जो इस काल में हैं। नरेन्द्र मोदी आगे बढ़ते रहे, एक ऐसे विकसित भारत की संकल्पना लेकर जो आत्मनिर्भर हो और जो पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो।

अपने उद्देश्य में सफलता न मिल पाने की हताशा में ऐसे लोगों ने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर दूसरे देशों की षड्यंत्रकारी शक्तियों को भी साथ लाने का प्रयास किया। नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी षड्यंत्र रचे गए, उनकी आलोचनाओं के नये बिंदु खोजकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपमानित करने के प्रयास किए गए, लेकिन इन सबका परिणाम अंततः यही हुआ कि उनकी स्वीकार्यता अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी लगातार बढ़ती रही। वे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता तो बने ही, विश्व के सर्व स्वीकार्य नेता भी बन गए।

श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण और गुण बताए हैं। मूल रूप से स्थितप्रज्ञ के उन गुणों को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जो कामनाओं का त्याग करे, जो आत्म-संतुष्ट हो, जो सम भावी हो, जो वीतरागी हो और जो इंद्रिय निग्रह का पालन करता हो और इन सबसे बढ़कर जो विरोध, षड्यंत्र और मिथ्या कथन से विचलित हुए बिना अपना काम करता हो, वही स्थितप्रज्ञ है। आज जिस तरह देश और विदेश से अपने निहित स्वार्थों के लिए संचालित और अपने अस्तित्व के लिए खतरा देख प्रायोजित कुटिल कारगुजारियों से जूझते हुए नरेन्द्र मोदी अनवरत अपने कर्तव्यों का पालन करने में जुटे हैं तो सचमुच लगता है कि उन्होंने अर्जुन की प्रतिज्ञा "न दैन्यं न पलायनम्" को शिरोधार्य कर लिया है। इसी श्लोक की अगली पंक्ति है जो उनके लिए और हम सबके लिए भी आशा की किरण और उत्साह का द्योतक है :

आज जिस तरह देश और विदेश से अपने निहित स्वार्थों के लिए संचालित और अपने अस्तित्व के लिए खतरा देख प्रायोजित कुटिल कारगुजारियों से जूझते हुए नरेन्द्र मोदी अनवरत अपने कर्तव्यों का पालन करने में जुटे हैं तो सचमुच लगता है कि उन्होंने अर्जुन की प्रतिज्ञा "न दैन्यं न पलायनम्" को शिरोधार्य कर लिया है।





नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी षड्यंत्र
रचे गए, उनकी आलोचनाओं
के नये बिंदु खोजकर उन्हें
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी
अपमानित करने के प्रयास किए
गए, लेकिन इन सबका परिणाम
अंततः यही हुआ कि उनकी
स्वीकार्यता अंतरराष्ट्रीय फलक
पर भी लगातार बढ़ती रही। वे
भारत के सबसे लोकप्रिय नेता तो
बने ही, विश्व के सर्व स्वीकार्य नेता
भी बन गए।



"आयु रक्षती मार्याणी भाग्यं फलती सर्वदा"

वे अपनी प्रतिज्ञा पर ऐसे ही अडिग बने रहें और उनकी आयु में, उनके यश में और उनकी कीर्ति में सदा वृद्धि होती ही रहे, इसी में भारत का और विश्व का कल्याण है।



(लेखक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA), नई दिल्ली के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख के साथ भारतीय विरासत संस्थान के कुलपति भी हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के संस्थापक कुलपति भी रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के संस्थापक रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। मीडिया, संचार, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, नीति और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर लिखा है। प्रकाशन प्रभाग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों का संपादन किया है। उनके चर्चित प्रकाशित कार्यों में 'सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियाँ' (2017); 'पुत्रिकामेष्टि' (2021), 'लो हैंगिंग फ्रूट्स' (2024), चार लघु-कथा और तीन कविता संग्रह शामिल हैं। उन्होंने नए संसद भवन के लिए कलाकृति की परिकल्पना की और उसे क्रियान्वित किया। वे भारत मंडपम में दुनिया के सबसे बड़े नटराज की स्थापना में भी सहायक रहे। उन्होंने हिंदी व मराठी में 25 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। उन्हें नाट्य तपस्वी, जनार्दन राय नागर सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय सम्मान जैसे कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं।)



विकसित भारत



प्रो. हिमांशु राय
निदेशक, आईआईएम-इंदौर

अध्यात्म, राजनीति और प्रबंधन कौशल का संगम

इतिहास के कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जो केवल घटनाओं का क्रम नहीं होते, बल्कि वे एक राष्ट्र की आत्मा को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं। भारत के लिए वर्ष 2014 के बाद का समय माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा ही स्वर्णिम युग सिद्ध हुआ है, जिसमें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक नए दृष्टिकोण से समझा और संचालित किया गया। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अध्यात्म, राजनीति और प्रबंधन कौशल के त्रिकोण को केंद्र में रखकर एक समग्र राष्ट्रीय परिवर्तन की दिशा निर्धारित करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। यदि इस पूरे परिवर्तन को समझना हो, तो यह आवश्यक है कि हम इसे केवल योजनाओं और आंकड़ों के माध्यम से न देखें, बल्कि उस वैचारिक आधार को समझें, जिसने इन सभी प्रयासों को दिशा प्रदान की।

अध्यात्म : राष्ट्र की चेतना का पुनर्जागरण

2014 के पश्चात भारत में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, उसकी आधारशिला अध्यात्म में निहित है। यहां अध्यात्म का आशय किसी संकीर्ण



प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का विराट स्वरूप उल्लेखनीय है, जहां विश्वभर से करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने यह सिद्ध किया कि भारत का अध्यात्म केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि जनजीवन में गहराई से रचा बसा है। यह आयोजन प्रशासनिक दक्षता और आध्यात्मिक आस्था के अद्वितीय समन्वय का उदाहरण बना, जहां परंपरा और आधुनिक प्रबंधन एक साथ दिखाई दिए। इस प्रकार के आयोजन यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में अध्यात्म केवल व्यक्तिगत साधना का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का माध्यम भी है।

पंथवादी पहचान से नहीं, अपितु उस व्यापक भारतीय जीवनदृष्टि से है, जो समावेशिता, संतुलन, कर्तव्यबोध और आत्मानुशासन को केंद्र में स्थापित करती है। दीर्घकाल तक भारत ने अपनी इस सभ्यतागत चेतना को या तो सीमित रूप में प्रस्तुत किया अथवा आधुनिकता के दबाव में उसे गौण मान लिया। परंतु पिछले वर्षों में यह बोध स्पष्ट हुआ कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास के बिना कोई भी राष्ट्र दीर्घकालिक प्रगति का आधार निर्मित नहीं कर सकता।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत थी, जिसने जगद्गुरु भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। इसके पश्चात काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास, अयोध्या में श्रीरामलला जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार तथा उज्जैन में महाकाल लोक का विस्तार, ये सभी स्थापत्य या पर्यटन के आयाम होने के साथ-साथ भारतीय चेतना के पुनर्संयोजन के प्रयास भी थे। वर्ष 2024 में अयोध्या में श्रीराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारतीय समाज की सामूहिक स्मृति, आस्था और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक बनकर उभरा।

इसी क्रम में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का विराट स्वरूप भी उल्लेखनीय है, जहां विश्वभर से करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने यह सिद्ध किया कि भारत का अध्यात्म केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि जनजीवन में गहराई से रचा बसा है। यह आयोजन प्रशासनिक दक्षता और आध्यात्मिक आस्था के अद्वितीय समन्वय का उदाहरण बना, जहां परंपरा और आधुनिक प्रबंधन एक साथ दिखाई दिए। इस प्रकार के आयोजन यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में अध्यात्म केवल व्यक्तिगत साधना का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का माध्यम भी है।

भारत की आधुनिकता उसकी जड़ों से विच्छिन्न होकर नहीं, बल्कि उन्हीं से शक्ति अर्जित करके विकसित हो रही है, और यह प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक नेतृत्व से ही संभव हो सका है। उनके द्वारा प्रारंभ की गई पहलों ने भारतीय समाज में एक नवीन आत्मविश्वास का संचार किया है,

जहां अपनी पहचान को लेकर संकोच का स्थान स्वाभिमान ने ग्रहण कर लिया है। यह स्वाभिमान आक्रामक नहीं, अपितु आत्मनिष्ठ है और यह वर्चस्व की नहीं, बल्कि आत्मबोध की अभिव्यक्ति है।

यह अध्यात्म शासन की नीतियों में भी परिलक्षित हुआ है। “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” जैसे सूत्र से उन्होंने नीति निर्माण को एक नैतिक अधिष्ठान प्रदान किया। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का जो सतत प्रयास दिखाई देता है, वह इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विस्तार है। यह एक प्रकार का कर्तव्य आधारित शासन है, जिसमें राज्य स्वयं को केवल शक्ति के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि लोककल्याण के दायित्व से युक्त संस्था के रूप में स्थापित करता है।

अध्यात्म का यह पुनर्जागरण भारत की वैश्विक छवि को भी रूपांतरित कर रहा है। आज भारत तीव्र गति से उभरती अर्थव्यवस्था तो है ही, साथ ही इसे एक ऐसी प्राचीन किंतु जीवंत सभ्यता के रूप में देखा जा रहा है, जो विश्व को संतुलन, सहअस्तित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश प्रदान करने में सक्षम है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की यह छवि उसके सांस्कृतिक आत्मविश्वास का ही विस्तार है। यह परिवर्तन सूक्ष्म अवश्य है, परंतु अत्यंत प्रभावकारी है, क्योंकि यह राष्ट्र की आत्मा को पुनः जाग्रत करता है। जब कोई समाज अपनी जड़ों से पुनः जुड़ता है, तब उसकी प्रगति केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक व्यापक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का रूप धारण कर लेती है। यही इस कालखंड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जहां अध्यात्म वर्तमान का मार्गदर्शक और भविष्य का आधार बनकर उभरा है।

राजनीति : निर्णय क्षमता और संरचनात्मक परिवर्तन

अध्यात्म ने जहां दिशा प्रदान की, वहीं राजनीति ने उसे क्रियाशील रूप दिया और उसे ठोस राष्ट्रीय संकल्प में परिवर्तित किया। वर्ष 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में जो सबसे व्यापक और





काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास,
अयोध्या में श्रीरामलला जन्मभूमि
मंदिर का निर्माण, केदारनाथ धाम
का पुनरुद्धार तथा उज्जैन में महाकाल
लोक का विस्तार, ये सभी स्थापत्य या
पर्यटन के आयाम होने के साथ-साथ
भारतीय चेतना के पुनर्संयोजन के
प्रयास भी थे। वर्ष 2024 में अयोध्या में
श्रीराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह
भारतीय समाज की सामूहिक स्मृति,
आस्था और सांस्कृतिक निरंतरता का
प्रतीक बनकर उभरा।



निर्णायक परिवर्तन हुए हैं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता, स्पष्टता और साहस का पुनर्स्थापन भी शामिल है। पूर्ववर्ती दशकों में जहां नीतिगत जड़ता, अनिर्णय तथा प्रक्रियात्मक विलंब शासन की पहचान बन चुके थे, वहीं इस कालखंड में एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई जिसमें जटिल और दीर्घकालिक प्रभाव वाले निर्णयों को लेने और उन्हें लागू करने का साहस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इस परिवर्तन का प्रारंभ वित्तीय समावेशन और प्रशासनिक पारदर्शिता के माध्यम से हुआ। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया और शासन का केंद्र अंतिम व्यक्ति को बनाया गया। यह समावेशी राजनीति का व्यावहारिक रूप था, जिसमें विकास को अधिकार के रूप में देखा गया, न कि सुविधा के रूप में। इसके पश्चात् वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण का निर्णय भारतीय राजनीति की निर्णयात्मकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया। इसका उद्देश्य औपचारिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना था। यद्यपि इस निर्णय पर विभिन्न स्तरों पर विमर्श हुआ, तथापि यह निर्विवाद है कि इसने शासन की उस प्रवृत्ति को रेखांकित किया जिसमें कठिन निर्णयों से परहेज करने के स्थान पर उन्हें अपनाने का साहस प्रदर्शित किया गया।

इसी क्रम में वर्ष 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का क्रियान्वयन तथा वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर का लागू होना, भारतीय आर्थिक संरचना के पुनर्गठन की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुए। वस्तु एवं सेवा कर ने विविध कर व्यवस्थाओं को एकीकृत करते हुए भारत को एक समेकित बाजार के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि दिवाला संहिता ने वित्तीय अनुशासन को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। यह स्पष्ट संकेत था कि राजनीतिक नेतृत्व अब दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध है।

इन सुधारों को केवल आंकड़ों के माध्यम से नहीं, बल्कि उनके व्यापक प्रभावों के आलोक में समझना अधिक समीचीन है। कर व्यवस्था में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन की स्थापना तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार, ये सभी परिवर्तन इस बात के द्योतक हैं कि राजनीति अब अल्पकालिक लाभों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है।

राजनीति का यह रूप सामाजिक क्षेत्र में भी समान रूप से सक्रिय रहा। स्वच्छ भारत अभियान के

माध्यम से स्वच्छता को एक राष्ट्रीय संकल्प में परिवर्तित किया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना तथा जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना – ये सभी उस राजनीतिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं जिसमें शासन का उद्देश्य केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार करना है।

गौरतलब है कि इन्हीं वर्षों में राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित निर्णय भी राजनीतिक इच्छाशक्ति के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में उभरे। संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक पुनर्गठन का निर्णय यह दर्शाता है कि राजनीति अब जटिल और संवेदनशील विषयों पर भी स्पष्ट और निर्णायक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम है। यह राष्ट्रीय एकात्मता के विचार को सुदृढ़ करने का प्रयास भी था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की राजनीति अधिक आत्मविश्वासी, संतुलित और सक्रिय हुई है। वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति एक निर्णायक और प्रभावशाली स्वर के रूप में उभरी है। विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार, वैश्विक संकटों के समय संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण तथा बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम है। मोदी युग की राजनीति केवल प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि पहल करने वाली; केवल प्रबंधकीय नहीं, बल्कि दृष्टिसंपन्न है; और केवल वर्तमान तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाली है। यही वह परिवर्तन है जिसने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक नई गति और एक नई गंभीरता प्रदान की है।

प्रबंधन : दृष्टि से क्रियान्वयन तक की यात्रा

यदि अध्यात्म दिशा प्रदान करता है और राजनीति संकल्प का संचार करती है, तो प्रबंधन वह सशक्त माध्यम है जो इन दोनों को यथार्थ में परिणत करता है। वर्ष 2014 के पश्चात भारत की शासन प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक परिवर्तन है, वह है व्यापक स्तर पर योजनाओं के प्रभावी, समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन की क्षमता का विकास। यह एक गहन प्रबंधकीय



अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की
स्थापना इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण
का प्रारंभिक और अत्यंत
महत्वपूर्ण संकेत
थी, जिसने जगद्गुरु
भारत की आध्यात्मिक परंपरा को
वैश्विक विमर्श के केंद्र में स्थापित
किया।



जब अध्यात्म दिशा देता है,
राजनीति संकल्प प्रदान करती है
और प्रबंधन कौशल उसे धरातल
पर उतारता है, तब एक ऐसा
राष्ट्र बनता है जो केवल अपने
लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के
लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता
है। यही इस दशक की सबसे
बड़ी उपलब्धि है, और यही उस
भारत की पहचान है जो निरंतर
आगे बढ़ रहा है, विकसित हो
रहा है और अपने सामर्थ्य को
पहचान रहा है।



टूटिकोण का परिणाम है, जिसमें नीति निर्माण के साथ-साथ उसके धरातलीय निष्पादन को समान महत्व प्रदान किया गया।

इस परिवर्तन का मूलाधार डिजिटल इंडिया अभियान में निहित है, जिसने शासन की कार्यप्रणाली को मूल रूप से रूपांतरित किया। तकनीक को केवल सुविधा का उपकरण न मानकर, उसे शासन के केंद्रीय तंत्र के रूप में स्थापित किया गया। आधार, जन धन और मोबाइल के त्रिसंयोजन ने एक ऐसा सुदृढ़ डिजिटल ढांचा निर्मित किया, जिसने राज्य और नागरिक के मध्य की दूरी को न्यूनतम कर दिया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाखों करोड़ रुपये की राशि बिना किसी मध्यस्थ के सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की गई, जिससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित हुई, बल्कि शासन के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हुआ। यह प्रबंधन का वह रूप है, जिसमें दक्षता और नैतिकता एक साथ समाहित होती है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेषतः यूपीआई, इस प्रबंधकीय नवाचार का अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण है। जिस प्रकार यह प्रणाली अल्प समय में देश के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने में सफल हुई, उससे सिद्ध होता है कि जब तकनीक को सरलता और सुलभता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तब वह व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। छोटे व्यापारियों से लेकर सामान्य नागरिक तक सभी के लिए लेनदेन को सहज बनाना यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्कृष्ट प्रबंधन कौशल का परिणाम है।

सरकारी प्रक्रियाओं में भी इसी प्रकार का रूपांतरण देखा गया है। सरकारी खरीद के लिए डिजिटल मंचों का उपयोग, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली तथा ई-गवर्नेंस के विस्तार ने प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया है। अब निर्णय केवल अनुमान या परंपरा के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्य और विश्लेषण के आधार पर लिए जा रहे हैं। यह आधुनिक प्रबंधन की उस पद्धति का संकेत है, जिसमें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

कोविड महामारी के दौरान यह प्रबंधन मॉडल अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्रत्यक्ष हुआ। यह एक ऐसा काल था, जब संपूर्ण विश्व अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा था। भारत जैसे विशाल

और विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान का क्रियान्वयन, ये सभी कार्य अत्यंत जटिल थे, तथापि डिजिटल प्लेटफार्मों, समन्वित प्रशासन और समयबद्ध निर्णयों के माध्यम से इस चुनौती का सामना किया गया।

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी प्रबंधन की यह दक्षता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गति शक्ति जैसी एकीकृत पहल यह दर्शाती है कि अब विकास को अलग-अलग परियोजनाओं के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे एक समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत समन्वित किया जा रहा है। सड़क, रेल, बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क के विकास को परस्पर जोड़कर एक ऐसी संरचना तैयार की जा रही है, जो आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करती है और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करती है। यह दीर्घकालिक योजना और सूक्ष्म क्रियान्वयन का समन्वित उदाहरण है।

यहां यह भी स्पष्ट होता है कि प्रबंधन केवल तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक विस्तार भी है, जिसका आधार भारतीय अध्यात्म में निहित है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा सदैव संतुलन, समन्वय और कर्तव्यनिष्ठा पर बल देती रही है। यही तत्व आधुनिक शासन के प्रबंधन ढांचे में भी परिलक्षित होते हैं। जब प्रशासन स्वयं को सेवा का माध्यम मानता है और प्रत्येक निर्णय को लोककल्याण के दृष्टिकोण से देखता है, तब प्रबंधन केवल कार्य निष्पादन नहीं रह जाता, बल्कि वह एक नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है।

वर्ष 2014 के पश्चात भारत में प्रबंधन ने केवल शासन की गति को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी परिवर्तित किया है। यह वह चरण है जहां दृष्टि, नीति और क्रियान्वयन के मध्य समन्वय स्थापित हुआ है। अध्यात्म से प्रेरित मूल्य, राजनीति से उत्पन्न संकल्प और प्रबंधन से सुनिश्चित परिणाम, इन तीनों का संगम ही उस राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का आधार बना है, जिसने भारत को एक नए आत्मविश्वास और नई दिशा के साथ आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि भारत ने स्वयं को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ किया है। यह दृष्टिकोण केवल विकास के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, पहचान और उद्देश्य की स्पष्टता पर आधारित है।





अध्यात्म से प्रेरित मूल्य, राजनीति से उत्पन्न संकल्प और प्रबंधन से सुनिश्चित परिणाम, इनका संगम ही उस राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का आधार बना है, जिसने भारत को एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की है।



अध्यात्म, राजनीति और प्रबंधन कौशल का यह संगम एक व्यापक राष्ट्रीय दर्शन का संकेत है। यह बताता है कि जब कोई राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिकता की ओर बढ़ता है, तब वह केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी समृद्ध होता है।

राष्ट्र निर्माण की यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। यह एक सतत यात्रा है, जिसमें प्रत्येक चरण नए अवसर और नई चुनौतियाँ लेकर आता है। लेकिन यह निश्चित है कि पिछले दशक ने भारत को एक नई दिशा और एक नई गति प्रदान की है। जब अध्यात्म दिशा देता है, राजनीति संकल्प प्रदान करती है और प्रबंधन कौशल उसे धरातल पर उतारता है, तब एक ऐसा राष्ट्र बनता है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। यही इस दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही उस भारत की पहचान है जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है।



(लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के निदेशक हैं। उनके कार्यकाल में आईआईएम इंदौर ने प्रतिष्ठित ट्रिपल क्राउन मान्यता : AMBA, AACSB और EQUIS भी प्राप्त की, जो विश्व के एक प्रतिष्ठित से भी कम बिजनेस स्कूलों को प्राप्त है। वे एसडीए बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (भारत परिसर) के डीन भी रह चुके हैं और भारत व विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन कर चुके हैं। उन्होंने कई चर्चित पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें नेगोशिएशन, ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर (स्टीवन मैकशेन और मैरी ऐन वॉन गिलनो के साथ), प्रवाह तथा ब्रांड इंडिया शामिल हैं। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित प्रशिक्षक और परामर्शदाता हैं, जो अब तक 100,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, जिनमें वरिष्ठ नौकरशाह, राजनयिक और सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल हैं। वे पर्वतारोहण, योग और संस्कृति के प्रति भी गहरी रुचि रखते हैं।)



विकसित भारत



डॉ. गोविंद सिंह

वरिष्ठ पत्रकार व लेखक, अध्यक्ष-मीडिया
सलाहकार समिति (मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड)

मोदी और

मीडिया के रिश्ते

नरेन्द्र मोदी ने जब जून 2014 में सत्ता संभाली थी, तो कोई यह कल्पना तक नहीं कर सकता था कि यह व्यक्ति एक दिन भारत का भाल ऊंचा करेगा। ऐसा इसलिए कि उससे पहले राष्ट्रीय मीडिया में मोदी एक तिरस्कृत नाम था। वे लुटियन की दिल्ली के आदमी नहीं थे। उनके प्रति राष्ट्रीय मीडिया के उपेक्षा भाव को देखकर ही उन्होंने कहा भी था कि, 'मैं लुटियन की दिल्ली का आदमी नहीं हूँ, मैं पूरे देश का हूँ'। वर्ष 2002 में गोधरा दंगों के बाद राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें इकतरफा दोषी करार दिया था। उनके खिलाफ इतना दुष्प्रचार हुआ कि दुनिया भर का मीडिया उन्हें एक खलनायक की तरह देखने लगा। इसीलिए अमेरिका ने उन्हें वीसा तक देने पर रोक लगा दी थी।

ऐसा नहीं कि मोदी के साथ भारतीय मीडिया हमेशा ही पूर्वाग्रही रहा हो। अक्टूबर 2001 में नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब उनकी उम्र 51 वर्ष की थी। राजनीतिक रूप से सक्रिय तो वे 16-17 वर्ष की उम्र में ही हो गए थे, लेकिन 1971 में संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बनने के बाद उन्होंने पूरी तरह से सामाजिक जीवन के लिए गृह त्याग कर दिया। तब से वे मीडिया



के प्रभाव का गहराई से अध्ययन करने लगे। वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। भारतीय जीवन का बड़ी गहराई से अध्ययन किया। हिमालय उन्हें बरबस आकर्षित करता रहा। उन्होंने देशभर के धर्म स्थानों का भी भ्रमण किया। तब उन्हें पता चला कि वास्तविक जीवन और मीडिया द्वारा चित्रित समाज में कितना अंतर है! 1985 में जब देश में राजनीति नई करवट ले रही थी, तब संघ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। 1998 में वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाये गए। पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर वे देश-विदेश भी घूमे। इस बीच वे पार्टी के प्रवक्ता भी रहे। उनके ज़माने में पार्टी मुख्यालय में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग काफी लोकप्रिय होती थी। तब भी अधिकतर मीडिया संघ-भाजपा की विचारधारा का विरोधी था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मीडिया के साथ मोदी के रिश्ते बुरे नहीं थे। मुझे याद है 2001 में एक बार आजतक के दो पत्रकारों की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। संवाददाता रंजन झा के पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया गया, जबकि कैमरामैन गोपाल सिंह बिष्ट की अंत्येष्टि दिल्ली के निगमबोध घाट पर हुई। गोपालदा को मोदी जी बहुत अच्छा मानते थे। वे वहां आए और लगभग 30 मिनट चुपचाप एक कोने में खड़े रहे।

2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्हें विपक्षी दलों का विरोध तो सहना ही पड़ा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कोप भी कम नहीं झेलना पड़ा। फरवरी 2002 में अचानक से गुजरात के गोधरा से दंगे भड़के। इन दंगों के बाद नरेन्द्र मोदी के प्रति राष्ट्रीय मीडिया का रुख काफी कड़ा, आलोचनात्मक और ध्रुवीकृत हो गया। भाजपा विरोधी राष्ट्रीय मीडिया ने दंगों को कुछ इस तरह से चित्रित किया कि जैसे मोदी ने ही आदेश दिया हो कि मुसलमानों के घर जला डालो, उन्हें मार डालो। भाजपा का भी एक धड़ा इस आग में घी डालने का काम कर रहा था। उस दौर को भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। दंगों के तुरंत बाद, अधिकतर राष्ट्रीय समाचार पत्रों और चैनलों (जैसे NDTV, CNN-IBN और प्रमुख अंग्रेजी अखबारों) ने मोदी की प्रशासनिक विफलता पर तीखे सवाल उठाए। मीडिया का एक बड़ा वर्ग उन्हें 'राजधर्म' का पालन न करने और दंगों को रोकने में नाकाम रहने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहा था। उन्हें पूरी तरह से सांप्रदायिक करार दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ संघ समर्थक और क्षेत्रीय मीडिया ने उन्हें एक हिंदू हित रक्षक

नेता के रूप में देखना शुरू किया। पर दूसरी तरफ राष्ट्रीय और अंग्रेजी मीडिया ने मोदी को लगातार खलनायक बनाए रखा। 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने केंद्रीय विकास योजनाओं के राज्यों में प्रयोग को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें यह पता चला कि विकास की दृष्टि से सबसे अच्छा काम गुजरात सरकार कर रही है। उसके बाद 'गुजरात मॉडल' की छिटपुट चर्चा होने लगी। 2010 के बाद मीडिया के रुख में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा। फिर गुजरात में होने वाले निवेश उत्सवों- 'वाइब्रेंट गुजरात' ने भी धारणा बदलने में मदद की। मीडिया का दक्षिणपंथी धड़ा उनके "सुशासन" और "विकास पुरुष" वाली छवि पर ध्यान केंद्रित करने लगा। प्रवासी भारतीयों ने भी साथ दिया, खास कर सोशल मीडिया ने उनके विकास मॉडल को सिर आंखों पर बिठाया। कुल मिलाकर मुख्यधारा के मीडिया ने 2014 से पहले नरेन्द्र मोदी को बहिष्कृत ही रखा। मोदी अक्सर यह बोलते रहे हैं कि 2002 के बाद मीडिया ने उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की।

2014 का चुनाव प्रचार अभियान और मीडिया

संभवतः यही कारण है कि मोदी ने मुख्यधारा के मीडिया पर बहुत भरोसा नहीं किया। लुटियन दिल्ली को चलाने में जो मीडिया सबसे आगे रहता था, उसे उन्होंने बाहर ही रखा। 'द वायर' में प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि, '2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान, भाजपा ने डिजिटल और सोशल मीडिया के क्षेत्र में अभूतपूर्व रणनीति अपनाई। नरेन्द्र मोदी ने ट्विटर (अब एक्स) और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। उनकी 'चाय पे चर्चा' जैसे अभियान न केवल मतदाताओं तक पहुंचने में प्रभावी रहे, बल्कि पारंपरिक मीडिया की मध्यस्थता को कम करने में भी सफल रहे... मोदी की सोशल मीडिया रणनीति में उनकी छवि को एक 'विकास पुरुष' और 'मजबूत नेता' के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया गया। 2014 में उनकी रैलियों की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, 3डी होलोग्राम तकनीक का उपयोग हुआ, जिसने उन्हें एक साथ कई स्थानों पर 'उपस्थित' होने की क्षमता दी। इसने उनकी छवि को जन-केंद्रित नेता के रूप में प्रचारित



2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने केंद्रीय विकास योजनाओं के राज्यों में प्रयोग को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें यह पता चला कि विकास की दृष्टि से सबसे अच्छा काम गुजरात सरकार कर रही है। उसके बाद 'गुजरात मॉडल' की छिटपुट चर्चा होने लगी। 2010 के बाद मीडिया के रुख में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा। फिर गुजरात में होने वाले निवेश उत्सवों- 'वाइब्रेंट गुजरात' ने भी धारणा बदलने में मदद की।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने बिचौलिया मीडिया की जगह डायरेक्ट मीडिया संचार का इस्तेमाल किया। पुराने घाघ पत्रकारों का वर्चस्व तोड़ा और फिजूल के बहस-मुबाहिसे में उलझने की जगह अपने काम पर फोकस किया। उनके सामने राष्ट्र प्रथम का ध्येय वाक्य है। इसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए वे मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं।



किया'। इसी चुनाव में पहली बार सोशल मीडिया को केवल एक सहायक टूल नहीं, बल्कि वार रूम की तरह इस्तेमाल किया गया। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर सक्रियता कहीं ज्यादा बढ़ी। मोदी ने पारंपरिक मीडिया के औजारों-प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि को बाईपास करके सीधे जनता से संवाद किया। पहली बार भाजपा ने एक विशाल स्वयंसेवक नेटवर्क और आईटी सेल बनाया, जिसने हैशटैग्स और संदेशों को वायरल करने का काम किया। यह चुनाव भारतीय लोकसभा चुनावों के इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों की तरह लड़ा गया, इसलिए मीडिया रणनीति भी उसी तरह की रही, जिसका मकसद मोदी को एक अपराजेय ब्रांड की तरह उभारना था। और इस काम में यह रणनीति काफी हद तक कामयाब भी हुई। इस चुनाव के मुख्य नारे "अबकी बार मोदी सरकार" और "अच्छे दिन आने वाले हैं" जैसे नारों ने एक सकारात्मक भविष्य की तस्वीर पेश की। भारतीय राजनीति के इतिहास में इस रणनीति को एक "वॉटरशेड मोमेंट" (निर्णायक मोड़) माना जाता है। इस अभियान ने पारंपरिक राजनीति को एक कॉरपोरेट-शैली की मार्केटिंग और हाई-टेक संचार रणनीति में बदल दिया।

नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया के साथ-साथ पारंपरिक मीडिया पर भी पकड़ मजबूत रखी। टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों में बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिए गए। चुनिंदा और प्रभावी इंटरव्यू के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाई। 2014 के चुनावों में "सोशल मीडिया वार रूम" का इस्तेमाल एक अत्यंत संगठित और सैन्य-स्तर की सटीकता के साथ किया गया था। यह केवल पोस्ट करने का केंद्र नहीं था, बल्कि रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण और प्रतिक्रिया का मुख्यालय था। अहमदाबाद और दिल्ली में मुख्य वार रूम बनाए गए थे, जहां डेटा वैज्ञानिकों, डिजिटल मार्केटर्स, कंटेंट राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनरों की एक पेशेवर टीम चौबीसों घंटे काम करती थी। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों- मसलन वाराणसी में भी वार रूम बनाए गए। अपनी बात कहने और प्रतिपक्षियों की बात को काटने के लिए डिजिटल मीडिया की तमाम विधाओं का प्रयोग किया गया। वार रूम में गढ़े गए संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लाखों स्वयंसेवक-कार्यकर्ताओं का जोश और समर्पण था यानी उनके हथियार एकदम ताजे और कारगर थे, जबकि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के औजार एकदम भोथरे हो चुके थे। इसमें कोई दोराय नहीं कि दो वरिष्ठ राजनेताओं का दिमाग भी इन रणनीतियों को बनाने में लगा रहता था। ये थे अरुण जेटली और अमित शाह। जहां शाह राजनीतिक रणनीति बनाते थे, वहीं जेटली मीडिया की रणनीति बनाते थे। यों भी 1998 के बाद से भाजपा ने अरुण जेटली के नेतृत्व में अपने प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था, जिससे वे कॉंग्रेसी प्रवक्ताओं पर भारी पड़ते गए।

2014 के बाद भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मीडिया के साथ अपने रिश्तों में खास बदलाव नहीं किया। हां, पहले की सरकारों की मीडिया नीति में जरूर आमूल बदलाव देखने को मिला। जहां पहले की सरकारों में पत्रकार और सत्ता के बीच एक पारंपरिक संवाद होता था, वहीं 2014 के बाद यह रिश्ता पत्रकारों के जरिये संवाद की जगह जनता से 'सीधे संवाद' की दिशा में मुड़ गया। मोदी ने पारंपरिक मीडिया (खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और लुटियंस दिल्ली के पत्रकारों) को "बिचौलिया" माना और उन्हें दरकिनार कर दिया। उन्होंने बरसों से सुप्त पड़े रेडियो को जगाया और 'मन की बात' नाम का मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम ने रेडियो को भी नया जीवन दान दिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने आरंभ में तो अपने मन के विचार श्रोताओं से साझा किए, लेकिन कुछ ही अंकों के बाद जनता से भी विचार मांगे गए। चूंकि यह एक अभिनव कार्यक्रम था, इसलिए तमाम टीवी समाचार चैनल, सरकारी चैनल भी इसे प्रसारित करने लगे। यह कार्यक्रम कभी अवरुद्ध नहीं हुआ। अब इसे बारह वर्ष होने को आए हैं, फिर भी चल रहा है। जनता में इसका आकर्षण निरंतर बना हुआ है। डायरेक्ट संचार की यह एक अद्भुत मिसाल है। टिवटर (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक का उपयोग करके अपनी बात सीधे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, जिससे पत्रकारों के 'फिल्टर' की जरूरत खत्म हो गई। अब पत्रकार सीधे टिवटर से खबर उठा लेते हैं। मंत्रालयों में हमेशा पत्रकारों की भीड़ नहीं लगी रहती। न ही बात-बात में प्रेस सम्मेलनों की जरूरत पड़ती है। साथ ही, सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं के लिए अलग-अलग एप बना दिये हैं, जिनसे सीधे सूचनाएं ली जा सकती हैं। इन एप को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।

हालांकि मीडिया हमेशा ही दो धड़ों में बंटा रहा है, लेकिन 2014 के बाद यह ध्रुवीकरण और स्पष्ट हो गया है। सरकार समर्थक मीडिया को गोदी मीडिया और बाकियों को विरोधी मीडिया कहा जाने लगा है। कई समाचार पत्र और वेब पोर्टल सरकार की कड़ी आलोचना भी करते हैं। कई मीडिया समूहों पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया में भी खुलकर सरकार के समर्थन और विरोध में अभियान चलाए जाते हैं।

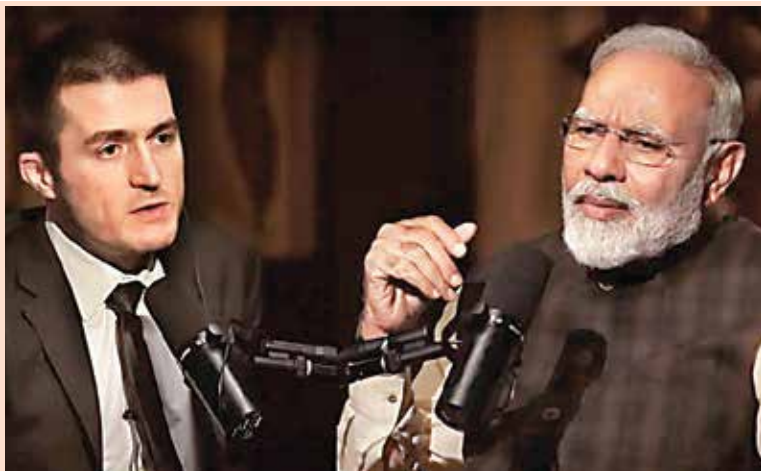
ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रेस से बोलना बंद ही कर दिया है। उन्होंने इंटरव्यू की भी एक नई शैली अपनाई है। कुछ चुनिंदा पत्रकारों या कभी-कभी गैर-पत्रकार हस्तियों (जैसे-अक्षय कुमार, प्रसून जोशी) को इंटरव्यू-पॉडकास्ट के लिए चुना। इन साक्षात्कारों में अक्सर तीखे सवाल के बजाय उनके निजी जीवन, आदतों और विजन पर चर्चा अधिक दिखी। पिछले वर्ष यानी मार्च 2025 में चर्चित अमेरिकी इन्फ्लुएंसर लेक्स फ्रिडमैन के साथ तीन घंटे से अधिक का उनका पॉडकास्ट काफी चर्चा में रहा। खास बात यह है कि इस इंटरव्यू से पहले फ्रिडमैन ने 45 घंटे का उपवास भी रखा था, जिससे पीएम मोदी खासे प्रभावित हुए।

पहले प्रधानमंत्री के हर दौर में पत्रकारों का एक बड़ा दल उनके साथ देश-विदेश जाता था, लेकिन 2014 के बाद केवल आधिकारिक मीडिया (दूरदर्शन/ANI) को ही साथ ले जाने की परंपरा शुरू हुई। अन्य मीडिया घरानों के पत्रकार भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्च पर। इस तरह मोदी ने बड़े पैमाने पर होने वाली फिजूलखर्ची पर रोक लगा दी। दरअसल, मोदी यह समझते हैं कि आज पारंपरिक मीडिया की वास्तविक ताकत क्या है। उन्होंने 2002 और 2014 के बीच मुख्यधारा के भारतीय मीडिया के चरित्र को भी अच्छी तरह से परखा है। संभवतः उन्हें 2014 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद लगा भी हो कि फिजूल में मीडिया से उलझने के बजाय अपने काम पर फोकस किया जाए। इसके लिए उन्होंने मध्यस्थ के जरिये किए जाने वाले संचार के बजाय डायरेक्ट संचार का सहारा लिया।

यहां मोदी के प्रति पश्चिमी या विदेशी मीडिया के रुख को जानना-समझना भी जरूरी है। जैसा कि हमने आरंभ में कहा था कि गुजरात दंगों के बाद भारतीय मीडिया के एकतरफा मीडिया ट्रायल के कारण विदेशी मीडिया भी प्रभावित रहा। यूरोप-अमेरिका के तमाम बड़े समाचार पत्र-पत्रिकाओं में भारत के वही पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें लुटियन दिल्ली का पत्रकार समझा जाता था और जो हमेशा से ही मोदी के विरोधी रहे हैं, इसलिए इन पत्रकारों ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा, जब मोदी की कड़ी आलोचना का थोड़ा सा भी मौका मिला। पश्चिमी मीडिया ने अप्रैल 2014 में चुनाव अभियान के



पिछले वर्ष यानी मार्च 2025 में चर्चित अमेरिकी इन्फ्लुएंसर लेक्स फ्रिडमैन के साथ तीन घंटे से अधिक का उनका पॉडकास्ट काफी चर्चा में रहा। खास बात यह है कि इस इंटरव्यू से पहले फ्रिडमैन ने 45 घंटे का उपवास भी रखा था, जिससे पीएम मोदी खासे प्रभावित हुए।



दौरान नरेन्द्र मोदी की धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाए थे। इनमें 'द इकोनॉमिस्ट' और 'द गार्डियन' प्रमुख हैं। 'द इकोनॉमिस्ट' ने मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर कहा था कि भारत इससे "बेहतर का हक़दार" है। पत्रिका ने आगे लिखा था कि वे 'हमें अगर ग़लत साबित करते हैं तो हमें खुशी होगी'। कई वर्षों तक पत्रिका का यही रुख रहा, हालांकि अब उसमें कुछ बदलाव जरूर दिखता है। 'द इंडिपेंडेंट' में जॉन इलियट ने लिखा, "भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दक्षिणपंथी विचारधारा वाले संगठनों की ओर से राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा मिलना चिंता का विषय है। 'सभी भारतीय हिंदू हैं', जैसे बयान ने हालात और बदतर बना दिए हैं।" ऐसे शीर्षकों से लगता है कि उनकी क्या मंशा है। वे भारत को अब भी पुराने चश्मे से ही देखते हैं। उनसे भारत की तरक्की नहीं देखी जाती। कोविड के दौरान भी उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा, जब मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया जा सकता हो। लाशों के बहते चित्रों को अतिशयोक्ति के साथ दिखाना इसी का प्रमाण है।

समग्रता में देखा जाये तो बदले हुए परिदृश्य में मोदी ने नए मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने बिचौलिया मीडिया की जगह डायरेक्ट मीडिया संचार का इस्तेमाल किया। पुराने घाघ पत्रकारों का वर्चस्व तोड़ा और फिजूल के बहस-मुबाहि़सों में उलझने की जगह अपने काम पर फोकस किया। उनके सामने 'राष्ट्र प्रथम' का ध्येय वाक्य है। इसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए वे मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं।



(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और संप्रति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। वे नवभारत टाइम्स, स्पैन, आउटलुक, आजतक, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे मीडिया हाउस में वरिष्ठ संपादकीय पदों पर रह चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली में प्रोफेसर व डीन के अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग के डीन भी रह चुके हैं।)



विकसित भारत



राजीव सचान

वरिष्ठ पत्रकार-लेखक, एसोसिएट
एडिटर-दैनिक जागरण

राजनीति का

मोदी युग

22

मार्च, 2026 को नरेन्द्र मोदी एक ऐसे शासनाध्यक्ष बन गए, जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के तौर पर सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का रिकार्ड स्थापित किया। जब 2001 में वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब न तो इस पद के दावेदार थे और न ही किसी ने इसकी आशा की थी कि वे मुख्यमंत्री के रूप में इतना लंबा कार्यकाल व्यतीत करेंगे और फिर प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। वे मुख्यमंत्री बनने के पहले न तो विधानसभा के सदस्य रहे थे और ना ही प्रधानमंत्री बनने के पूर्व संसद के सदस्य। जैसे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर छाप छोड़ी और उसी कारण प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने गहरी छाप छोड़ी है। इसे उनके आलोचक भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि नकारात्मक भाव में ही सही, वे यह कहते रहते हैं कि मोदी ने देश की राजनीति बदल दी। उनके समर्थक तो यह कहते और मानते ही हैं कि 2014 के बाद देश की राजनीति बदल गई। वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से 2014 के बाद का समय मोदी का युग है। इसका कारण उनकी और उनके सरकार की रीति-नीति



ही नहीं, उनकी राजनीतिक शैली भी है, जिसने राजनीति की दिशा-दशा बदली। यही कारण है कि इस दौर को मोदी युग कहा जा रहा है।

मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले की भाजपा अटल-आडवाणी की पार्टी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज की भाजपा मोदी और अमित शाह की पार्टी के रूप में जानी जाती है। अंतर केवल इतना ही नहीं है। तब की भाजपा और आज की भाजपा की कार्यशैली में भी बहुत अंतर आ चुका है। अब चाल, चरित्र और चेहरे की बात नहीं होती। अब येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतना ही एकमात्र ध्येय है। मोदी युग की भाजपा कहीं अधिक आक्रामक है और उसकी रणनीतियां भी बदल चुकी हैं। आज की भाजपा प्रत्येक चुनाव को कहीं अधिक तैयारी और शिद्दत के साथ लड़ती है। स्थानीय निकायों के चुनाव में भी वह पूरा जोर लगाती है और सफलता मिलने पर वैसे ही सेलिब्रेट करती है, जैसे विधानसभा चुनाव में मिली जीत को। यही कारण है कि भाजपा के बारे में यह कहा जाने लगा है कि वह चुनाव मशीन में बदल गई है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं वर्तमान गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दौरान एक दूसरे रूप में दिखते हैं तो सामान्य दिनों में बदले हुए अवतार में। चुनाव के समय वह अपने विरोधियों पर तीखे से तीखे हमले करने में कोई संकोच नहीं करते, लेकिन जब चुनाव नहीं हो रहे होते हैं तो अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति उनका व्यवहार बदला हुआ दिखाई देता है। इसी कारण वह अपने तमाम विरोधियों को अपने समर्थक में तब्दील कर चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कभी उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन आज या तो उनके प्रशंसक हैं अथवा उनके प्रति नरम हैं या फिर वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे नेताओं की एक बड़ी संख्या है, जिन्होंने मोदी के बारे में अपने विचार बदले हैं। इस युग की भाजपा की एक विशेषता यह भी है कि वह हर क्षण अपने राजनीतिक हितों की रक्षा में लीन दिखती है।

मोदी सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के छोटे से छोटे निर्णय में दूरगामी राजनीतिक हित साधने का भाव निहित होता है। यहां तक कि उनके परिधान भी कोई न कोई राजनीतिक संदेश दे रहे होते हैं। यदि वह दिल्ली में हैं और असम से संबंधित किसी मामले पर चर्चा कर रहे हैं तो उनके गले में असमिया गमछा नजर आएगा। इसी तरह यदि वह देश के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां से भाजपा या फिर स्वयं अपना कोई न कोई जुड़ाव स्थापित करते दिखते हैं। चूंकि एक कार्यकर्ता

के रूप में उन्होंने देश का कहीं व्यापक भ्रमण किया है, इसलिए वे छोटे से छोटे जिलों के बारे में भी जानकारी रखते हैं अथवा उसकी विशेषता से परिचित हैं। इसका वह उल्लेख भी करते हैं और यह तो सब जानते ही हैं कि वे स्थानीय भाषा और लहजे में अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं। नरेन्द्र मोदी की राजनीति की एक खासियत यह भी है कि वे राजनीतिक विफलता और उससे उपजी निराशा को कभी भी अपने कार्यकर्ताओं पर हावी नहीं होने देते। वह वक्त और हालात को देखते हुए अपनी रणनीति बदलते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने नई राजनीतिक सहयोगी भी तलाश लेते हैं। राजग का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। मोदी अपनी रणनीति बदलने में किस तरह माहिर हैं, इसका प्रमाण यह है कि जहाँ कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव उनके नाम पर लड़े गए, वहीं कुछ राज्यों में स्थानीय नेताओं को आगे किया गया और साथ ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के स्थान पर स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता प्रदान की गई। मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जो किसी भी विषय पर संबोधन के पहले यह प्रतीति कराते हैं कि उन्होंने उस पर गहन अध्ययन, मनन और चिंतन किया है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहले दिन से अपनी अलग राजनीतिक शैली विकसित की और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का शुभारंभ करना। उन्होंने अपनी राजनीति से कुछ पुरानी राजनीतिक धारणाओं को भी बदला है। उन्होंने अपनी राजनीति से परंपरागत राजनीतिक समीकरणों के विपरीत जाकर चुनावी सफलताएं हासिल की हैं। इनमें से कुछ सफलताएं ऐसी हैं, जो चौंकाने वाली रहीं। उदाहरणस्वरूप त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाना और पश्चिम बंगाल में वाम दलों एवं कांग्रेस को कहीं पीछे धकेल कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करना। मोदी युग की भाजपा न तो उत्तर भारतीय पार्टी बनकर रह गई है और ना ही शहरी मतदाताओं की पार्टी। मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद जाति की राजनीति भी बदली है। उन्होंने भाजपा के लिए नया जनाधार तैयार किया है। उन्होंने वर्गों के रूप में भाजपा समर्थक तैयार किए हैं। उदाहरणस्वरूप युवा और महिलाएं भाजपा समर्थक के रूप में उभरी हैं। यह स्पष्ट ही है कि न तो युवा की कोई जाति होती है और ना ही महिलाओं की।

जैसे अटल और आडवाणी के समय भाजपा ने दूसरी पीढ़ी के कई प्रभावशाली नेता तैयार किए, वैसे ही मोदी और शाह की भाजपा भी यही काम तेजी से कर रही है। कई राज्यों में ऐसे नेता मुख्यमंत्री अथवा भाजपा अध्यक्ष बने, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ तो ऐसे भी रहे, जो स्वयं भी इन पदों को हासिल करने की नहीं सोच रहे थे, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मोदी की राजनीतिक शैली ने केवल राष्ट्रीय राजनीति पर ही असर नहीं डाला है, बल्कि उनकी शैली ने देश की कूटनीति को भी प्रभावित किया है और यही कारण है कि आज भारत का अंतरराष्ट्रीय कद कहीं अधिक बढ़ गया है। मोदी ने अपनी राजनीति से केवल पार्टी को ही नहीं

जैसे अटल और आडवाणी के समय भाजपा ने दूसरी पीढ़ी के कई प्रभावशाली नेता तैयार किए, वैसे ही मोदी और शाह की भाजपा भी यही काम तेजी से कर रही है।





‘इसे नरेन्द्र मोदी के आलोचक भी स्वीकार करते हैं कि मोदी ने देश की राजनीति बदल दी। उनके समर्थक तो यह कहते और मानते ही हैं कि 2014 के बाद देश की राजनीति बदल गई। वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से 2014 के बाद का समय मोदी का युग है। इसका कारण उनकी और उनके सरकार की रीति-नीति ही नहीं, उनकी राजनीतिक शैली भी है, जिसने राजनीति की दिशा-दशा बदली। यही कारण है कि इस दौर को मोदी युग कहा जा रहा है।’

बदला है, बल्कि शासन के तौर-तरीकों में भी व्यापक बदलाव लाने में सक्षम हुए हैं। वे साहसिक और अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं। एक समय औसत भाजपा कार्यकर्ता भी इसे लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा के तीन में से दो मुख्य एजेंडे पूरे हो जाएंगे। ये दो एजेंडे हैं जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। समान नागरिक संहिता के निर्माण का तीसरा कोर एजेंडा भी आगे बढ़ रहा है। मोदी ने अपनी राजनीति से केवल भाजपा को ही नहीं बदला है, उनकी राजनीति का असर विपक्ष की राजनीति पर भी पड़ा है। विपक्षी दलों और विशेष रूप से राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस के लिए भाजपा का सामना करना मुश्किल हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के 240 सीटों पर सिमट जाने और कांग्रेस के 99 तक पहुंच जाने के बाद ऐसा कुछ संदेश उभरा था कि भाजपा ढलान पर आ गई है, लेकिन एक साल के अंदर ही और विशेष रूप से हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरी तौर पर बदल गया। जो यह मान रहे थे कि जदयू और तेलुगू देसम पर निर्भर मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में कुछ बदली-दबी हुई सी नजर आएगी, वह वैसे ही तेवर के साथ दिख रही है, जैसे पहले और दूसरे कार्यकाल में थी। अपने बलबूते बहुमत की सरकार न बना पाने के बावजूद मोदी सरकार पूरी प्रखरता से काम कर रही है और यह मानने का कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में इस प्रखरता में कोई कमी आने वाली है।



(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर तीन दशक से अधिक से उनके लेख नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं।)



विकसित भारत



उमेश चतुर्वेदी

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक
टिप्पणीकार

भारतीयता का

वैश्विक जयघोष

मै

गनाकार्टा की संधि ही वह प्रस्थान बिंदु है, जहां से आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। यूं तो भारत में अपनी तरह का लोकतंत्र प्राचीन काल से ही रहा है, जहां राजा राजव्यवस्था में सर्वोच्च होने के बावजूद लोकाचार, लोक व्यवस्था और लोक मर्यादा से ऊपर नहीं था। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में जो धर्म रहा है, वह आधुनिक अर्थों में संकुचित नहीं रहा, बल्कि वह बहुत व्यापक रहा है। यही धर्म और सांस्कृतिक परंपरा सर्वोच्च रही है, राजाज्ञा या कानून उसी का विस्तार और कई अर्थों में पूरक रहे हैं। इसके बरक्स आधुनिक लोकतंत्र ने धर्म और शासन तंत्र के बीच नई तरह की परिभाषा गढ़ी। उसने शासन तंत्र को सेकुलर बनाने की नींव रखी। इस सेकुलरवाद में राजव्यवस्था को धर्म से निरपेक्ष रखने की चिंता है। हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता राजव्यवस्था को धर्म से अलग करते-करते भारत के बहुसंख्यकों की सांस्कृतिक परंपरा और धर्म की उपेक्षा करने लगा। लेकिन यह उपेक्षा अल्पसंख्यकों की धार्मिक परंपराओं तक पहुंचते-पहुंचते संरक्षणवादी हो जाती है, जिसे आज एक वर्ग अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के तौर पर भी जानता-समझता है। इसी तुष्टीकरण



जिस वाराणसी की भूमि से नरेन्द्र मोदी चुनकर संसद पहुंचते हैं, उसी काशी की भूमि के रक्षक बाबा विश्वनाथ के मंदिर का न सिर्फ पुनर्विकास किया गया है, बल्कि विश्वनाथ कॉरिडोर का भी विकास किया गया है। मोदी के ही काल में अयोध्या की उस जन्मभूमि पर सनातन परंपरा के सबसे मर्यादित पुरुष अयोध्या के राजा राम के भव्य मंदिर का निर्माण और लोकार्पण हुआ है। इसके साथ ही उज्जैन के महाकाल मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है। इसी तरह असम के कामाख्या मंदिर, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम और गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। इससे भारत की आध्यात्मिक आत्मा को नई ऊर्जा मिली है।

ने भारत के बहुसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को हेय मानने की सोच को भी विकसित किया है। इस संदर्भ में आधुनिक लोकतंत्र की जन्मभूमि इंग्लैंड को देखते हैं तो पाते हैं कि राजव्यवस्था धर्म से उस हद तक अलग नहीं है, जिस तरह अपने देश में रही है। बेशक राज्य का अपना कोई धर्म वहां नहीं है, लेकिन राज्य धार्मिक परंपराओं से दूर भी नहीं है। वह निरपेक्ष नहीं, धार्मिक समभाव में भरोसा करता है।

इतनी बड़ी भूमिका का अपना संदर्भ है। इस संदर्भ में अगर हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्भव और विकास काल को देखते हैं तो साफ तौर पर पता चलता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी स्वीकृत मानकों और संवैधानिक मर्यादाओं के बीच उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। नरेन्द्र मोदी के कई कदमों को अगर हम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के निकष पर कसेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने सचमुच अलग ढंग से काम किए हैं। सरकारी तंत्र, संवैधानिक मर्यादा और परंपरा के आधार पर देखें तो ये कदम क्रांतिकारी, कम भारतीयता के सहज आधार हैं। केंद्रीय सत्ता में मोदी के उभार के बाद किसी अल्पसंख्यक धर्म की अवहेलना नहीं हुई, लेकिन बहुसंख्यकों के धर्म को प्रतिष्ठा मिली है।

नरेन्द्र मोदी ने जब 2014 के आम चुनावों के दौरान वाराणसी पहुंच कर चुनावी ताल ठोंकी, तब उन्होंने महामना मालवीय की मूर्ति के सामने जो कहा था, एक तरह से उसके जरिए उन्होंने भावी भारत की अपनी सांस्कृतिक सोच का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, 'मां गंगा ने उन्हें बुलाया है।' गंगा की पुकार का मतलब सिर्फ पतित पावनी धारा की पुकार नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पुकार थी। काशी के गंगा घाट पर कबीर ने सांस्कृतिक जड़ता पर प्रहार किया तो तुलसी दास ने अस्सी घाट पर बैठकर प्रचलित धारणा के इतर रामगाथा के रूप में सनातन समाज के लिए नवमंत्रों का सृजन किया। बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी काशी नगरी बौद्ध लोगों का ही शहर नहीं है, बल्कि नव सृजन और सांस्कृतिक परंपरा से नाभिनाल जुड़ने का नगर है। वाराणसी की माटी से जुड़कर प्रधानमंत्री ने संस्कृति, धर्म और सामाजिक चेतना के साथ भारतीयता की अजस्र धारा का जो प्रतिपादन किया है, वह अभूतपूर्व है। इसी धारा का ही प्रभाव कह सकते हैं कि मोदी के शासन काल

में भारतीयता का नवउद्गोष सर्वत्र दिखता है।

मोदी के शासन काल में भारतीय संस्कृति की धरोहर मंदिरों और तीर्थ स्थलों का बहुत तेजी से और अभूतपूर्व पुनर्विकास हुआ है। जिस वाराणसी की भूमि से नरेन्द्र मोदी चुनकर संसद पहुंचते हैं, उसी काशी की भूमि के रक्षक बाबा विश्वनाथ के मंदिर का न सिर्फ पुनर्विकास किया गया है, बल्कि विश्वनाथ कॉरिडोर का भी विकास किया गया है। मोदी के ही काल में अयोध्या की उस जन्मभूमि पर सनातन परंपरा के सबसे मर्यादित पुरुष अयोध्या के राजा राम के भव्य मंदिर का निर्माण और लोकार्पण हुआ है। इसके साथ ही उज्जैन के महाकाल मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है। इसी तरह असम के कामाख्या मंदिर, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम और गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। इससे भारत की आध्यात्मिक आत्मा को नई ऊर्जा मिली है। ध्यान रहे कि जब कोई मंदिर बनता है और वहां श्रद्धालु आने लगते हैं तो उस शहर की अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने लगता है। भारतीय मंदिरों की अपनी आर्थिकी रही है। नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारतीयता की सोच को जहां नया पोषण मिला है, वहीं मंदिरों से जुड़ी आर्थिकी के जरिए मंदिरों, कॉरिडोर वाले शहरों और आसपास के इलाकों का आर्थिक भाग्य भी चमक उठा है।

केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन और सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण ने एक तरह से देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दी है। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से भारत के लाखों सिख लोगों की धार्मिक भावनाओं को नया संबल मिला है। उनकी श्रद्धा को जैसे नए पंख मिल गए हैं। मुख्यमंत्री काल में साबरमती रिवरफ्रंट, डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन और कृषि क्षेत्र में दो अंकों की वृद्धि ने गुजरात को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया। ग्रामीण सड़क क्रांति, ज्योतिग्राम योजना और सौनी परियोजना ने गांवों और किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किए।

भारत में विशेषकर सनातन परंपरा वाली तीर्थयात्राओं और तीर्थ यात्रियों की सहूलियत और सुविधा का ध्यान सरकारी तौर पर कम ही रखा जाता रहा है। कुंभ जैसे आयोजन इसके अपवाद रहे हैं, लेकिन मोदी के शासन काल में प्रशासनिक अमले की यह सोच बदली है। इसी काल में केंद्र सरकार की पहल पर चार धाम राजमार्ग परियोजना न सिर्फ बनी, बल्कि उसे लागू भी किया गया है। इसी तरह हेमकुंड साहिब रोपवे और बौद्ध सर्किट का भी विकास तेजी से किया जा रहा है। पाकिस्तानी सीमा स्थित सिख समुदाय के तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब के लिए विशेष कॉरिडोर परियोजना ने





मोदी शासन काल में ही आकार लिया। अब भारतीय सिख श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भारत-पाक सीमा पर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू और सिख तीर्थस्थलों का ही विकास किया गया, बल्कि प्रसाद योजना के तहत मस्जिदों, चर्चों और अन्य धर्मों के पवित्र एवं पूजा स्थलों का भी पुनर्विकास किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं, राष्ट्र के सांस्कृतिक आत्माभिमान का प्रतीक बन चुका है। सांस्कृतिक स्थलों का विकास सिर्फ धार्मिकता का उभार नहीं है, बल्कि भारतीयता से जुड़ने का अनुपम संयोग है।

मोदी सरकार की सनातनोमुखी इन योजनाओं से तीर्थ स्थल वाले नगरों और राज्यों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसमें योग देने में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन और हृदय योजना का भी बड़ा योगदान रहा है। तीर्थस्थलों के विकास और इन योजनाओं के माध्यम से विरासत और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध शहरों में सैलानियों और तीर्थ यात्रियों की चहल-पहल बढ़ी है। इसका असर विदेशी सैलानियों की भारत यात्रा के आंकड़ों में बढ़ोतरी पर साफ नजर आता है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में भारत में 96 लाख 60 हजार विदेशी पर्यटक आए। इससे देश को करीब दो लाख 77 हजार 842 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में आय हुई है।

अतीत में भारत के तस्कर और कतिपय राजनेताओं की मिलीभगत से देश की बहुमूल्य धरोहर चुराकर या तस्कारी करके विदेश भेजी जाती रही हैं। नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने खोई हुई या विदेशी संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही भारत की अनमोल धरोहरों को वापस लाने की कोशिशें शुरू कीं। मोदी के 12 साल के शासन में इन धरोहरों की स्वदेश वापसी के अभियान में तेजी आई है। इस तेजी को आंकड़ों से समझा जा सकता है। साल 2013 से पहले तक भारत को विदेश में चोरी गई सिर्फ तेरह धरोहरें ही वापस आ पाई थीं, लेकिन मोदी सरकार की कोशिशों के बाद साल 2014 से लेकर अब तक करीब 642 प्राचीन वस्तुएं विभिन्न देशों से वापस लाई गई हैं। इनमें अकेले अमेरिका ने 578 अमूल्य कला कृतियां लौटाई हैं। यह सिर्फ भारत सरकार की सफलता ही नहीं है, बल्कि भारतीय गौरव बोध की वैश्विक स्वीकार्यता भी है।

मोदी के शासन के पहले तक भी देश अपने निर्माताओं का सम्मान करता रहा है, लेकिन इस पर वैचारिकी का असर भी दिखता रहा है। विशेषकर राष्ट्रवादी वैचारिक धारा वाले राष्ट्र निर्माताओं को यथोचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन मोदी सरकार ने इस परिपाटी को भी बदला। मोदी सरकार की नजर में राष्ट्र निर्माताओं की एक ही पहचान रही है, देश के प्रति उनका योगदान। इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने राष्ट्र-निर्माताओं को उचित सम्मान देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। दिल्ली के दिल में स्थित नेहरू स्मृति संग्रहालय सिर्फ पंडित नेहरू की ही विरासत के लिए प्रसिद्ध था, मोदी सरकार ने इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दिया। अब यहां देश के हर प्रधानमंत्री से जुड़ी स्मृतियां और महत्वपूर्ण तथ्यों को संजोया गया है। इसी तरह सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले बलिदानियों को भी विशेष रूप से सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने इंडिया गेट पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के गृहमंत्री के नाते बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की कल्पना की थी, उसे भी मोदी सरकार ने संवारकर देश के प्रति पुलिस के योगदान और त्याग को नई पहचान दी है। भारतीय स्वाधीनता इतिहास में शहादत के स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में विख्यात पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग स्मारक को भी नया रूप दिया गया है। इसके साथ ही देश भर में अलग से 11 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी बनाए गए हैं। इन संग्रहालयों के जरिए मोदी सरकार ने एक तरह से राष्ट्र निर्माताओं के योगदान को न सिर्फ अक्षुण्ण बनाया है, बल्कि बलिदानियों का राष्ट्र की ओर से आभार जताया है।

राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार के दौरान बहुत निर्माण हुए हैं। आने वाले दिनों में जब इतिहासकार दिल्ली के स्थापत्य का इतिहास लिखेंगे तो वे स्वीकार करेंगे कि मुगलों और अंग्रेजों के बाद सबसे ज्यादा निर्माण मोदी सरकार के दौरान ही हुआ। कभी जिसे देश दिल्ली के प्रमुख कारोबारी और प्रदर्शन स्थल को प्रगति मैदान के रूप में जानता था, वहां मोदी के प्रयासों से अब भारत मंडपम



मोदी सरकार की नजर में राष्ट्र निर्माताओं की एक ही पहचान रही है, देश के प्रति उनका योगदान। इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने राष्ट्र-निर्माताओं को उचित सम्मान देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। दिल्ली के दिल में स्थित नेहरू स्मृति संग्रहालय सिर्फ पंडित नेहरू की ही विरासत के लिए प्रसिद्ध था, मोदी सरकार ने इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दिया।





कभी जिसे देश दिल्ली के प्रमुख कारोबारी और प्रदर्शन स्थल को प्रगति मैदान के रूप में जानता था, वहां मोदी के प्रयासों से अब भारत मंडपम बनकर खड़ा है। इसी तरह नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के नए प्रतीक के रूप में उभरा है।

बनकर खड़ा है। इसी तरह नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के नए प्रतीक के रूप में उभरा है।

भारत की विशेषता को लेकर जब भी चर्चा होती है, कहा जाता है कि भारत की सांस्कृतिक धारा एक है। हमारी संस्कृति को विविधता में एकता का प्रतीक बताया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस एकता को प्रदर्शित करने के लिए अतीत में सार्वजनिक स्तर पर कम ही कोशिशें नजर आती हैं। हमारे संतों और सांस्कृतिक महापुरुषों ने भले ही ऐसी कोशिशें की हों, लेकिन आधुनिक भारत में ऐसा प्रयास कम ही दिखता है। भारत के तीर्थ, मेले और विरासत शहर एक तरह से भारतीय एकता के सूत्र रहे हैं, जिनके जरिए देश जुड़ता रहा है। भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करने को लेकर ज्ञात इतिहास में पहली बार गंभीर प्रयास शंकराचार्य के रूप में दिखता है, जिन्होंने देश के चार कोनों में चार शंकराचार्य पीठें बनाईं। मोदी सरकार इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ती नजर आती है। मोदी सरकार ने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने, इस प्रतिष्ठा और महानता से देश के नागरिकों को सीधे तौर पर जोड़ने के लिए 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' अभियान चलाया। भारत में उत्तर और दक्षिण का विभाजन खूब दिखता रहा है। इस विभाजन को पाटने की दिशा में आने वाले दिनों में काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन बहुत बड़े सहयोगी होंगे। कहना न होगा कि यह योजना भी नरेन्द्र मोदी के मानस की उपज है।

भारत की सांस्कृतिक और भाषायी विविधता के बीच सेतु बनाने के कई अन्य काम भी मोदी सरकार ने किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को महत्ता दी गई है। अगर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में नहीं होते तो शायद ये योजनाएं और ऐसी सोच जमीनी हकीकत नहीं बन पातीं। प्रयाग के 2025 के कुंभ की व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने भी भरपूर सहयोग दिया। यही वजह है कि इस आयोजन में रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जुटे, उन्होंने गंगा या त्रिवेणी स्नान करके सिर्फ पुण्य फल ही नहीं हासिल किया, बल्कि राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार भी बने। ये लोग जब अपने घरों को लौटते तो अपने साथ 'राष्ट्र एक' के भाव को लेकर नए उत्साह से लौटते। भारतीय विरासत और ऐतिहासिक परंपराएं विश्व में अनूठी हैं। मोदी सरकार के दौर में भारतीय धरोहर स्थलों का रख-रखाव तो बढ़ा ही है, उसमें वैश्विक दिलचस्पी

भी बढ़ी है। इसकी वजह से भारत के विश्व धरोहरों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई। हर साल इन धरोहरों की नई सूची यूनेस्को जारी करता है। जुलाई 2024 में असम के मोइदम्स को इस सूची में शामिल किया गया, जिससे अब भारत के पास 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें पंद्रह अमूर्त धरोहर हैं। इस अमूर्त धरोहर में बिहार का लोक पर्व छठ भी शामिल होने जा रहा है। यह सब मोदी सरकार की नई सांस्कृतिक नीति का ही परिणाम माना जा सकता है।

दुनिया में चिकित्सा को लेकर आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर ही दुनिया को सबसे ज्यादा भरोसा रहा है। दुनिया तो छोड़िए, आयुर्वेद की जन्मभूमि भारत में भी इसे अपनाने से लोग न सिर्फ हिचकते रहे, बल्कि इसे दकियानूसी मानते रहे। भारत में कहावत है, नीम-हकीम खतरा-ए-जान यानी नीम हकीम से जान को खतरा हो सकता है। ऐसे माहौल में भारतीय आयुर्वेद को वैश्विक मान्यता दिलाने में मोदी सरकार की सफल कोशिशें पीढ़ियों तक याद की जाएंगी। भारत में अब आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए अलग से आयुष मंत्रालय काम कर रहा है। अतीत में आयुर्वेद की व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय ही देखता था। मोदी सरकार की दृष्टि में आयुर्वेद की स्थिति क्या है, इसे अलग आयुष मंत्रालय की व्यवस्था से ही देखा और समझा जा सकता है। भारतीय आयुर्वेद ने कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरह की भूमिका निभाई, उसने उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा स्थापित की है। वैश्विक स्तर पर अब भारतीय आयुष चिकित्सा पद्धति और आयुष उत्पाद सहज स्वीकार्य हो रहे हैं।

आयुष मंत्रालय के प्रयासों से दुनिया के 24 देशों के साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौते हो चुके हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 35 देशों में आयुष सूचना केंद्र स्थापित किए हैं। भारत ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति और मानकों के लिहाज से आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने और उनके लिए शोध करने के लिए विशेष तौर पर गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना की गई है। इसके साथ ही भारत सरकार ने "हील इन इंडिया" व "आयुष वीजा" जैसी पहल शुरू की है। इसकी वजह से देश समग्र चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। इसके साथ ही भारत की अनूठी विरासत योग को भी मोदी सरकार ने वैश्विक मान्यता दिलाई है। समावेशी चिकित्सा में आयुर्वेद के साथ योग का प्रयोग भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा है। मोदी सरकार के प्रयासों से ही वैश्विक स्तर पर 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के देश और उनके निवासी शामिल होते



गंगा की पुकार का मतलब सिर्फ पतित पावनी धारा की पुकार नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पुकार थी। काशी के गंगा घाट पर कबीर ने सांस्कृतिक जड़ता पर प्रहार किया तो तुलसी दास ने अरस्सी घाट पर बैठकर प्रचलित धारणा के इतर रामगाथा के रूप में सनातन समाज के लिए नवमंत्रों का सृजन किया।



प्रयाग के 2025 के कुंभ की व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने भी भरपूर सहयोग दिया। यही वजह है कि इस आयोजन में रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जुटे, उन्होंने गंगा या त्रिवेणी स्नान करके सिर्फ पुण्य फल ही नहीं हासिल किया, बल्कि राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार भी बने। ये लोग जब अपने घरों को लौटे तो अपने साथ राष्ट्र एक के भाव को लेकर नए उत्साह से लौटे।



हैं। योग के प्रति वैश्विक मान्यता बढ़ी है। इसकी वजह से योग के जरिए स्वास्थ्य लाभ और मानसिक संतुलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, “मैं सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आया हूँ।” उनका यह कथन राजनीति ही नहीं, सांस्कृतिक जीवन और सनातन के प्रति उनकी सोच का प्रतीक है। इसी सोच के तहत वैश्विक नेतृत्व देने के लिए वे देश को सक्षम बनाने की दिशा में लगातार सक्रिय हैं। वैश्विक मंच पर आज अगर भारत का स्वर ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है तो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत तो है ही, सनातन और सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत के प्रति मोदी सरकार का प्रेम और सम्मान का प्रदर्शन भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अब तक के कार्यकाल की यात्रा केवल राजनीतिक घटनाओं का सिलसिला नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का महाकाव्य है।



(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक/टिप्पणीकार हैं। करीब तीन दशक से अधिक के अपने लंबे करियर में वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े विभिन्न संस्थानों में वरिष्ठ संपादकीय पदों पर रहे हैं। इनमें अमर उजाला, दैनिक भास्कर, सकाल, बीएजी फिल्मस, इंडिया टीवी, जी न्यूज, महुआ, लाइव इंडिया आदि शामिल हैं। हिंदी के सुपरिचित स्तंभकार के रूप में प्रमुख अखबारों में नियमित लेखन। अब तक करीब साढ़े छह हजार आलेख और टिप्पणियां प्रकाशित। इसके अलावा, बाजारवाद के दौर में मीडिया, राजभाषा हिंदी एवं अस्तित्वबोध और सवालियों का अक्स नाम से पुस्तकें प्रकाशित।)



विकसित भारत



डॉ. आलोक कुमार मिश्रा

संयुक्त सचिव-भारतीय विश्वविद्यालय संघ,
नई दिल्ली एवं ग्रेन विहेवियर एनालिस्ट

व्यक्तित्व एवं विचार

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

भारत के राजनीतिक इतिहास में नरेन्द्र मोदी एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने न केवल सत्ता के समीकरणों को बदला, बल्कि जनमानस के मनोविज्ञान को भी गहराई से प्रभावित किया है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनने तक की उनकी यात्रा मात्र राजनीतिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह निरंतर आत्म-विकास, अटूट संकल्प और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का एक अनूठा उदाहरण है। नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व के मनोविज्ञान को समझने के लिए उनके शुरुआती जीवन के 'इकोसिस्टम' को समझना अनिवार्य है। गुजरात के वडनगर की गलियों और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के अनुभव ने उनके भीतर 'सर्वाइवल इंस्टिंकट' (अस्तित्व रक्षा की प्रवृत्ति) और 'ऑब्जर्वेशनल लर्निंग' (अवलोकन द्वारा सीखने) को जन्म दिया।

लचीलापन : मनोविज्ञान में इसे 'ग्रिट' कहा जाता है। अभावों के बीच पलने वाले बालक ने यह सीखा कि परिस्थितियाँ आपको परिभाषित नहीं करतीं, बल्कि आप परिस्थितियों को परिभाषित करते हैं।



जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि "मैं देश नहीं झुकने दूंगा", तो यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं होता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह 'मैसनिक कॉम्प्लेक्स' का सकारात्मक रूप है, जहां व्यक्ति खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित मानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में बिताए गए दशकों के समय ने उनके भीतर 'कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग' पैदा की यानी हर काम को एक निश्चित ढांचे और अनुशासन में करने की आदत। यही कारण है कि उनकी कार्यशैली में 'थकावट' शब्द का अभाव दिखता है।



अकेलापन और चिंतन : किशोरावस्था में हिमालय की यात्रा और गृह-त्याग उनके भीतर के 'अंतर्मुखी' व्यक्तित्व को 'चिंतनशील' बनाने की प्रक्रिया थी। यहां से उनके भीतर 'स्व-नियमन' का गुण विकसित हुआ, जो आज उनके कठिन समय में भी शांत रहने की क्षमता में दिखता है।

पीएम मोदी के मनोविज्ञान का एक बड़ा हिस्सा 'आइडेंटिटी थ्योरी' से जुड़ा है। उन्होंने अपनी पहचान को व्यक्तिगत लाभ से हटाकर 'राष्ट्र' के साथ एकाकार कर लिया है। जब वे कहते हैं कि "मैं देश नहीं झुकने दूंगा", तो यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह 'मैसनिक कॉम्प्लेक्स' का सकारात्मक रूप है, जहां व्यक्ति खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित मानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में बिताए गए दशकों के समय ने उनके भीतर 'कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग' पैदा की यानी हर काम को एक निश्चित ढांचे और अनुशासन में करने की आदत। यही कारण है कि उनकी कार्यशैली में 'थकावट' शब्द का अभाव दिखता है।

प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों का विश्लेषण करें तो उनमें 'हाई रिस्क-हाई रिवॉर्ड' का मनोवैज्ञानिक पैटर्न दिखता है। वे 'यथास्थिति' को बनाए रखने के बजाय उसे तोड़ने में विश्वास रखते हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट : ये निर्णय उनके 'प्रोएक्टिव साइकोलॉजी' को दर्शाते हैं। उन्होंने रक्षा के मनोविज्ञान को 'रक्षात्मक' से बदलकर 'आक्रामक' बनाया। यहां मनोविज्ञान 'डर' को खत्म कर 'आत्मविश्वास' भरने का था।

स्वच्छ भारत अभियान : यह निर्णय शुद्ध रूप से 'बिहेवियरल इकोनॉमिक्स' और 'नज थ्योरी' पर आधारित था। गंदगी के प्रति भारतीयों की उदासीनता को उन्होंने 'सम्मान' और 'स्वास्थ्य' से जोड़कर एक मनोवैज्ञानिक आंदोलन बना दिया।

डिजिटल इंडिया : जब देश में इंटरनेट की पहुंच कम थी, तब डिजिटल क्रांति का विचार रखना उनके 'विजनरी इंटेलिजेंस' का प्रमाण है। उन्होंने यह भांप लिया था कि भविष्य का मनोविज्ञान 'कनेक्टिविटी' पर आधारित होगा।

जन-संवाद और सामूहिक चेतना : विश्व के सबसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति बनने के पीछे उनका 'कम्युनिकेशन साइकोलॉजी' पर असाधारण नियंत्रण है। 'मन की बात' कार्यक्रम सीधे जनता के साथ

एक 'भावनात्मक सेतु' बनाता है। मनोविज्ञान में इसे 'पैरा-सोशल इंटरैक्शन' कहते हैं, जहां जनता को लगता है कि प्रधानमंत्री सीधे उनसे बात कर रहे हैं।

प्रतीकों का प्रयोग : योग, चरखा, झाड़ू या पारंपरिक वेशभूषा—ये सभी 'विजुअल एंकर' हैं, जो जनता के अवचेतन मन में सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाते हैं। उन्होंने देश को 'आशावादी मनोविज्ञान' की ओर मोड़ा है। 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य देना मनोविज्ञान के 'गोल सेटिंग थ्योरी' का बेहतरीन प्रयोग है, जो पूरी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित कर देता है।

विपरीत परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक स्थिरता : एक छोटे से स्थान से चलकर वैश्विक मंच तक पहुंचने में उन्हें कई व्यक्तिगत और राजनीतिक हमलों का सामना करना पड़ा। यहां उनकी 'इमोशनल इंटेलिजेंस' की भूमिका अहम है। उन्होंने आलोचनाओं को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें 'फीडबैक' की तरह इस्तेमाल किया। यह एक 'ग्रोथ माइंडसेट' का लक्षण है। उनके मनोविज्ञान का आधार भारत की प्राचीन जड़ें हैं। वे आधुनिक तकनीक और प्राचीन मूल्यों के बीच एक 'कॉग्निटिव बैलेंस' बनाकर चलते हैं, जो उन्हें वैश्विक नेताओं के बीच विशिष्ट बनाता है।

विकसित भारत का संकल्प : पीएम मोदी का 'विकसित भारत' का संकल्प किसी आर्थिक डेटा मात्र पर आधारित नहीं है, बल्कि यह 'सामूहिक आत्मविश्वास' के मनोविज्ञान पर खड़ा है। गुलामी के प्रतीकों को हटाना और अपनी भाषा-संस्कृति पर गर्व करना, राष्ट्र के मनोविज्ञान को 'हीनभावना' से बाहर निकालने की प्रक्रिया है।

महिला नेतृत्व : 'महिलाओं के विकास' से 'महिला नेतृत्व वाले विकास' की ओर बढ़ना समाज के आधे हिस्से के मनोविज्ञान को सशक्त बनाना है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र का कोई भी हिस्सा मानसिक रूप से कटा हुआ महसूस न करे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक हम उनके 'आंतरिक दर्शन' और उन व्यक्तिगत पहलुओं को न समझें जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण नेतृत्व की ओर ले जाते हैं। यहां पर उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख आयाम दिए जा सकते हैं :

वैराग्य और जुड़ाव का संतुलन : पीएम मोदी के मनोविज्ञान में एक गहरा विरोधाभास दिखता है जो उन्हें संतुलित बनाता है—वह है 'अनासक्ति'।

साधु मनोविज्ञान : युवावस्था में उनके द्वारा किया गया भ्रमण और एकांतवास उनके भीतर एक 'साक्षी भाव' विकसित कर चुका है। राजनीति की आपाधापी और व्यक्तिगत हमलों के बीच भी वे विचलित नहीं होते। वे कर्म में पूरी तरह संलग्न होते हैं, लेकिन उसके परिणामों या आलोचनाओं से मनोवैज्ञानिक रूप से अलग रहने की कला जानते हैं।

समय का सूक्ष्म प्रबंधन : मनोविज्ञान में इसे 'कॉग्निटिव डिसिप्लिन' कहा जाता है। पीएम मोदी के लिए समय केवल एक इकाई नहीं, बल्कि एक 'संसाधन' है, जिसे वे व्यर्थ नहीं होने देते। बिना छुट्टी लिए काम करना उनकी मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है। उनका मनोविज्ञान 'आराम' को आलस्य नहीं, बल्कि 'कार्य के स्वरूप में परिवर्तन' मानता है। यही कारण है कि वे योग और ध्यान के माध्यम से अपने मानसिक 'सॉफ्टवेयर' को रोज रीसेट करते हैं।

'शून्य' से 'सृजन' की शक्ति : मनोवैज्ञानिक रूप से जो व्यक्ति अभावों में पला-बढ़ा होता है, उसके पास दो रास्ते होते हैं : हीन भावना या फिर असाधारण सृजन क्षमता। पीएम मोदी ने 'स्कासिटी माइंडसेट' को 'एबंडेंस माइंडसेट' में बदल दिया।

संसाधनों का सम्मान : वे छोटी-छोटी चीजों (जैसे पानी बचाना या डिजिटल ट्रंजैक्शन) पर जो जोर देते हैं, वह उनकी उसी बुनियादी समझ से आता है जहां 'बचत ही सृजन' है। यह उनके बचपन के संघर्षों का एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक रूपांतरण है।

संवेगालयक बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता : अक्सर उन्हें एक कठोर प्रशासक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके व्यक्तिगत व्यवहार में 'एम्पैथी' (समानुभूति) का एक गहरा स्तर है।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण भारत को एक 'आधुनिक शक्ति' बनाने का है, लेकिन अपनी 'जड़ों' को खोए बिना। वे भारत को केवल सिलिकॉन वैली की नकल करते हुए नहीं देखना चाहते। उनका विजन है कि भारत के पास एक हाथ में 'उपग्रह का रिमोट कंट्रोल' हो और दूसरे हाथ में 'उपनिषदों का ज्ञान'। उनके लिए राम मंदिर का निर्माण और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आत्मिक गौरव और भौतिक प्रगति के मनोविज्ञान को बताता है।



मानवीय जुड़ाव : 'परीक्षा पर चर्चा' के दौरान छात्रों से बात करना हो या किसी आपदा के समय भावुक होना—यह दिखाता है कि उनका मनोविज्ञान केवल 'लॉजिक' (तर्क) पर नहीं, बल्कि 'इमोशन' (भावना) पर भी टिका है। वे जानते हैं कि जब तक आप लोगों के 'दिल' से नहीं जुड़ते, आप उनके 'दिमाग' को प्रेरित नहीं कर सकते। 70 वर्ष से अधिक की आयु में भी तकनीक, सोशल मीडिया और आधुनिक वैश्विक रुझानों के प्रति उनकी सहजता उनके 'न्यूरोप्लास्टिसिटी' (मस्तिष्क की सीखने की क्षमता) को दर्शाती है। इसके साथ ही वे खुद को समय के साथ बदलने में संकोच नहीं करते। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह 'अहंकार' की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जहां सीखने की भूख पद की गरिमा से बढ़ी होती है।

मौन और एकांत का मनोविज्ञान : अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद पीएम मोदी साल में कुछ समय पूर्ण मौन और एकांत (जैसे केदारनाथ की गुफा में ध्यान) में बिताते हैं। मनोविज्ञान में इसे 'सेल्फ-एक्चुअलाइजेशन' की प्रक्रिया माना जाता है। यह एकांत उन्हें भीड़ से अलग हटकर आत्म-निरीक्षण करने और आने वाली चुनौतियों के लिए मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार करने में मदद करता है।

'भारत' एक मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में : उनके लिए भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक 'जीवंत इकाई' या 'मां' है। इसलिए उनके हर निर्णय के पीछे एक गहरा सांस्कृतिक मनोविज्ञान होता है। चाहे वह काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हो या अयोध्या में राम मंदिर, ये निर्णय केवल धार्मिक नहीं बल्कि भारत के 'सामूहिक अवचेतन' को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाने के मनोवैज्ञानिक प्रयास हैं।

'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' (लोकतंत्र की जननी) का भाव : पीएम मोदी ने वैश्विक पटल पर भारत की छवि को केवल 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र' से बदलकर 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में स्थापित किया है। उनका मानना है कि लोकतंत्र भारत के लिए कोई पश्चिमी आयात नहीं है, बल्कि यह हमारे डीएनए और वेदों में समाहित है। यह दृष्टिकोण भारतीयों के भीतर एक 'बौद्धिक श्रेष्ठता' और आत्मविश्वास का संचार करता है कि हमें दुनिया से सीखने की ज़रूरत तो है, पर हम दुनिया को सिखाने की क्षमता

भी रखते हैं।

'सबका साथ, सबका विकास' का सर्वव्यापी दर्शन : मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह दृष्टिकोण 'इंक्लूसिव साइकोलॉजी' का परिचायक है। वे भारत को एक ऐसे परिवार के रूप में देखते हैं जहां विकास का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) तक पहुंचना चाहिए। उनके लिए भारत का अर्थ भौगोलिक सीमाओं से परे 'भारतीयता' से है, जिसमें जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर विभाजन के बजाय 'एकता' मुख्य सूत्र है।

विरासत भी और विकास भी : पीएम मोदी का दृष्टिकोण भारत को एक 'आधुनिक शक्ति' बनाने का है, लेकिन अपनी 'जड़ों' को खोए बिना। वे भारत को केवल सिलिकॉन वैली की नकल करते हुए नहीं देखना चाहते। उनका विजन है कि भारत के पास एक हाथ में 'उपग्रह का रिमोट कंट्रोल' हो और दूसरे हाथ में 'उपनिषदों का ज्ञान'। उनके लिए राम मंदिर का निर्माण और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रनों की शुरुआत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आत्मिक गौरव और भौतिक प्रगति के मनोविज्ञान को बताता है।

'विश्व मित्र' और 'विश्व गुरु' की भूमिका : वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक 'संतुलनकारी शक्ति' के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि भारत की प्रगति में पूरे विश्व का कल्याण निहित है। 'वसुधैव कुटुंबकम्' (दुनिया एक परिवार है) उनके लिए केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि विदेश नीति का आधार है। चाहे कोविड के समय 'वैक्सीन मैत्री' हो या पर्यावरण के लिए 'इंटरनेशनल सोलर एलायंस', वे भारत को एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में देखते हैं जो संकट के समय दुनिया को रास्ता दिखाता है।

युवा भारत-डेमोग्राफिक डिविडेंड का मनोविज्ञान : पीएम मोदी भारत को 'युवाओं के सपनों का देश' मानते हैं। वे भारत की विशाल युवा जनसंख्या को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक 'अवसर' के रूप में देखते हैं। उनका 'स्टार्टअप इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' का विजन इसी विश्वास पर टिका है कि भारतीय युवाओं की मेधा वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सकती है। वे भारत को दुनिया की 'स्किल कैपिटल' बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मनोविज्ञान : भारत को देखने का यह उनका सबसे क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। सदियों की गुलामी ने भारतीयों के मन में जो 'निर्भरता' का भाव भर दिया था, प्रधानमंत्री मोदी उसे 'स्वावलंबन' में बदलना चाहते हैं। उनके लिए भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जो रक्षा से लेकर तकनीक तक, अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे का मुंह न ताके। यह दृष्टिकोण देश को 'उपभोक्ता' से 'उत्पादक' बनाने की दिशा में है।

महिला नेतृत्व : पीएम मोदी के दृष्टिकोण में भारत का भविष्य उसकी 'नारी शक्ति' में सुरक्षित है। वे महिलाओं को केवल 'लाभार्थी' के रूप में नहीं, बल्कि 'विकास के इंजन' के रूप में देखते हैं। ड्रोन दीदी से लेकर सेना में महिलाओं की भागीदारी तक, उनका मानना है कि जब भारत की नारी सशक्त होगी, तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के प्रावधान की कोशिश भी इसी दिशा में उनका बड़ा प्रयास है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो, अपनी शक्ति पर विश्वास करता हो और जो 21वीं सदी को 'भारत की सदी' बनाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। उनके लिए भारत एक 'विजयी राष्ट्र' है जिसे उसकी नियति—परम वैभव—तक पहुंचाना ही उनका जीवनोद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तिगत मनोविज्ञान 'राजर्षि' (राजा और ऋषि का मेल) की प्राचीन भारतीय अवधारणा के आधुनिक स्वरूप जैसा है। जहां एक ओर वे आधुनिकता और राजनीति के स्वामी हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी जड़ें व्यक्तिगत सादगी, अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना में गहराई तक धंसी हुई हैं। यही वह आधार है जिस पर उनके 'विकसित भारत' के संकल्प का भव्य महल खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र



मोदी का व्यक्तित्व एक ऐसे 'आर्किटेक्ट' का है जो केवल भवन नहीं, बल्कि राष्ट्र की सोच का निर्माण कर रहा है। उनका मनोविज्ञान 'त्याग', 'तपस्या' और 'तर्क' का संगम है। उन्होंने सिद्ध किया है कि यदि इच्छाशक्ति को निःस्वार्थ उद्देश्य से जोड़ दिया जाए, तो वह न केवल एक व्यक्ति का भाग्य बदलती है, बल्कि पूरे राष्ट्र के दर्शन और दिशा को पुनर्जीवित कर देती है। आज भारत जिस स्थान पर खड़ा है, वह पीएम मोदी के इसी 'ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप' (परिवर्तनकारी नेतृत्व) का परिणाम है, जिसने 140 करोड़ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि 'यही समय है और सही समय है'।



(लेखक भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU-इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया), नई दिल्ली में संयुक्त सचिव हैं और ब्रेन बिहेवियर एनालिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एम्स, दिल्ली से मन-शरीर चिकित्सा तथा दर्शनशास्त्र में दोहरी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ब्रिटेन से एलएलएम, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय कानून में विशेष अध्ययन तथा आईआईएम से एमबीए किया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, दलाई लामा, विराट कोहली, किरण बेदी तथा कमल हासन जैसी शख्सियतों के मस्तिष्क व्यवहार का विश्लेषण किया है। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड (2019), इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी द्वारा इनोवेटिव साइंटिस्ट अवार्ड (2017), अमेरिकन सायकोसोमैटिक सोसायटी, पोर्टलैंड, यूएसए के ग्लोबल आउटरीच अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है।)



विकसित भारत



वालेन्दु शर्मा दाधीच
सीईओ, एल्गो टेक्नोलॉजीज

डिजिटल भारत का

बढ़ता कारवां

प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया ने भारत यात्रा के बाद 'वाशिंगटन पोस्ट' में एक लेख लिखा। भारत का आर्थिक माहौल देखकर चकित जकारिया ने लिखा कि जहाँ अमेरिका और यूरोप में मुद्रास्फीति और संभावित मंदी के चलते चिंता का वातावरण है वहीं भारत के लोग अपने भविष्य को लेकर रोमांचित हैं। ऐसा इसलिए कि भारत तमाम चुनौतियों और रुकावटों के बावजूद तरक्की के रास्ते से भटका नहीं है और भले ही उसकी विकास दर बीस साल पहले के नौ प्रतिशत जैसी न हो लेकिन वह चीन के बाद सर्वाधिक प्रगति करने वाली दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जकारिया की नजर में भारतीय अर्थव्यवस्था तीन बड़ी क्रांतियों के कारण प्रगति कर रही है—आधार नामक 12-अंकों वाली व्यक्तिगत पहचान प्रणाली क्रांति, जियो क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति जिसके चलते भारत में दनादन नई सड़कें, पुल, इमारतें, मेट्रो लाइनें, सुरंगें आदि बन रही हैं।

जकारिया ने अपनी भारत यात्रा में जिन तीन क्रांतियों का जिक्र किया, उनमें से दो सीधे-सीधे आईटी और दूरसंचार से जुड़ी हुई हैं। तीसरी क्रांति में भी



आईटी की भूमिका है, हालांकि जकारिया से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करना छूट गया जो कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि भारत के बदलावों पर विदेशी मीडिया का आकलन अमूमन नाकाफी रहा है और भारत के बदलावों पर उसकी दृष्टि में समग्रता का अभाव है, फिर भी जकारिया ने बखूबी समझ लिया कि भारत के लिए आईटी की अहमियत क्या है।

आईटी के क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि भारत ने इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया है। देश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का लक्ष्य हासिल करने की शुरुआत हमारी सोच के ट्रांसफॉर्मेशन से हुई है। यह सोच जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के समय की गई टिप्पणी से जाहिर होती है- "मैं ऐसे डिजिटल इंडिया का सपना देखता हूँ जहां पर तेज-रफ्तार डिजिटल हाइवे देश को एक कर रहे हों, 1.4 अरब कनेक्टेड भारतीय नवाचार में जुटे हों और टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित कर रही हो कि नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क का माध्यम भ्रष्ट न किया जा सके।"

जकारिया ने अपनी बात को सिर्फ तीन क्रांतियों तक सीमित रखा- आधार क्रांति, रिलायंस जियो क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, किंतु प्रधानमंत्री मोदी की उपरोक्त टिप्पणी हमारी सोच को अधिक समग्रता से स्पष्ट करती है। वे डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हैं जिसका उद्देश्य देश में आईटी का व्यापक ईको-सिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) तैयार करना है। फिर वे डिजिटल हाइवे का जिक्र करते हैं जिसका एक हिस्सा रिलायंस जियो हो सकता है किंतु वह गांव-गांव में ब्रॉडबैंड, 4जी-5जी, मोबाइल कनेक्शनों के प्रसार, दूरसंचार उपग्रहों के संजाल, सक्षम इंटरनेट तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की मौजूदगी आदि की ओर संकेत करता है। पीएम मोदी की इसी टिप्पणी में 1.4 अरब कनेक्टेड भारतीयों का जिक्र है यानी तकनीक का फल हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जरूरी तंत्र की स्थापना। आज भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या 90 करोड़ और मोबाइल कनेक्शनों की संख्या 117 करोड़ हो गई है। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 95 प्रतिशत से भी अधिक गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। शायद ही कोई और सुविधा इतने बड़े पैमाने पर आम भारतीयों तक पहुंची हो, शायद बिजली भी नहीं।

डिजिटल विकास की लंबी यात्रा

आज 2026 में भारत का सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र देश की जीडीपी में 10% से अधिक का योगदान दे रहा है। करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है और वैश्विक तकनीकी आपूर्ति शृंखलाओं में भारत को एक महत्वपूर्ण हितधारक बना चुका है, लेकिन यह यात्रा सरल नहीं रही।

1950 और 60 के दशक में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने उस मानव पूंजी को तराशा जो बाद में वैश्विक तकनीकी मंचों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में कामयाब रही। सन् 1963 में जब पहला कंप्यूटर (आयातित आईबीएम 1620) आईआईटी बॉम्बे पहुंचा, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे जाकर भारत सूचना प्रौद्योगिकी की वैश्विक शक्ति बनने वाला है। उसके बाद सन् 1980 के दशक में भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के काल में नीतिगत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति को प्रोत्साहित किया गया और धीरे-धीरे प्रौद्योगिकी की दुनिया में भारत की उपस्थिति बढ़ती चली गई।

सन् 1991 में उदारीकरण के आने पर हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ गहरा तालमेल हुआ, जिसका सबसे प्रमुख लाभ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मिला। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में अपने आपको भरोसेमंद और मजबूत संस्थानों के रूप में स्थापित किया। इस दौरान बेंगलुरु जैसे शहरों का उभार हुआ जो भारत की 'सिलिकॉन वैली' में तब्दील हो गया। देश में आईटी पार्क खड़े हो रहे थे, हजारों इंजीनियर उनमें अपनी जगह बना रहे थे और अमेरिकी कंपनियां यह देख रही थीं कि भारत में वही काम एक-चौथाई लागत में होता है जिस पर उन्हें चार गुना खर्च करना पड़ता है।

फिर आया 1999 का वाई2के संकट जब भारतीय आईटी वैश्विक मानचित्र पर स्थायी रूप से अंकित हो गया। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इस विकराल समस्या का किफायती और विश्वसनीय समाधान प्रदान किया। नतीजा यह हुआ कि 2000 तक सॉफ्टवेयर निर्यात 6.2 अरब डॉलर को पार कर गया। इस दशक में आईटी के क्षेत्र ने 30-40% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। 1988 में स्थापित आईटी उद्योग के हितों के लिए कार्यरत संस्था नास्कॉम ने नीतिगत पैरवी और कौशल विकास में अहम भूमिका निभाई, जिससे यह क्षेत्र एक सुसंगठित उद्योग का रूप ले सका। यह सिलसिला सन् 2000 के दशक में भी आगे बढ़ता रहा।



सन् 2015 के बाद डिजिटल भारत के निर्माण की रफ्तार और तेज हुई, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' की घोषणा की। यह एक सरकारी योजना भर नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। नौ स्तंभों वाले इस कार्यक्रम के तीन मुख्य स्तंभ उल्लेखनीय हैं—पूरे देश में ब्रॉडबैंड हाईवे का निर्माण, डिजिटल सेवाओं तक सर्वत्र पहुंच, और ई-गवर्नेंस के माध्यम से शासन में पारदर्शिता।



मैं ऐसे डिजिटल इंडिया का सपना देखता हूँ जहाँ पर तेज-रफतार डिजिटल हाईवे देश को एक कर रहे हों, 1.4 अरब कनेक्टेड भारतीय नवाचार में जुटे हों और टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित कर रही हो कि नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क का माध्यम भ्रष्ट न किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



2010 के दशक ने भारत की डिजिटल यात्रा में नया युग शुरू किया। इस दशक में दो सबसे बड़े बदलाव हुए- पहला, मोबाइल स्मार्टफोन का हर हाथ में पहुंच जाना, और दूसरा सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार। सन् 2015 के बाद डिजिटल भारत के निर्माण की रफतार और तेज हुई, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' की घोषणा की। यह एक सरकारी योजना भर नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। नौ स्तंभों वाले इस कार्यक्रम के तीन मुख्य स्तंभ उल्लेखनीय हैं-पूरे देश में ब्रॉडबैंड हाईवे का निर्माण, डिजिटल सेवाओं तक सर्वत्र पहुंच, और ई-गवर्नंस के माध्यम से शासन में पारदर्शिता। ये तीनों एक तरफ तो डिजिटल तकनीकों के प्रभाव और प्रसार को सुनिश्चित करते हैं तथा दूसरी ओर इस क्रांति में आम आदमी की उपस्थिति को रेखांकित करते हैं।

2016 में लॉन्च हुए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने वित्तीय लेन-देन की दुनिया को ही बदल दिया। नोटबंदी ने डिजिटल भुगतान को एक विकल्प से आवश्यकता में बदल दिया और रिलायंस जियो ने मोबाइल डेटा को हर घर तक पहुंचा दिया। भारत रातोंरात विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता बन गया। करोड़ों लोग जो कभी इंटरनेट एक्सेस की कीमत नहीं चुका सकते थे, अचानक डिजिटल दुनिया के नागरिक बन गए। इधर, भारतनेट परियोजना ने 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा।

गांव-गांव कनेक्टिविटी

भारत के गांव-गांव में आम लोगों को अपने मोबाइल फोन पर वेबसाइटों, सोशल मीडिया, संचार सेवाओं और वीडियो का आनंद लेते देखना अब हमारे लिए बहुत आश्चर्य पैदा नहीं करता। यह भारत में सूचना क्रांति की कामयाबी का एक आयाम है। देश में आईटी सेक्टर का विकास अब सेवाओं से इतर क्षेत्रों में भी हो रहा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी विकास। यह हमारी सूचना क्रांति की सफलता का दूसरा आयाम है। सरकारी सेवाओं, शिक्षा तथा कारोबारी सेवाओं की समाज के निचले स्तर तक डिजिटल माध्यमों से डिलीवरी होना इसका तीसरा आयाम माना जा सकता है।

डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में हमारी यात्रा के विभिन्न पड़ाव और पहलू इस बात की पुष्टि करते

हैं कि देश की विविध सीमाओं, चुनौतियों और रुकावटों के बीच तकनीकी क्षेत्र में कुछ अच्छा घटित हुआ है। यह अच्छा काम 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों की बदौलत भी घटित हुआ है और इसके पीछे निजी क्षेत्र की कारोबारी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। हमारा आम नागरिक आर्थिक, तकनीकी और जागरूकता के स्तर पर इस तरह की सेवाओं को ग्रहण करने की स्थिति में है, यह भी कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को डिजिटल सुविधाएं देना, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन पहुंचाना और देश को एक ज्ञान-आधारित समाज बनाना रहा है, काफी हद तक नतीजे दिए हैं। तकनीक ने जिस तरह से आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है, वह किसी क्रांति से कम नहीं है। हम गांव-गांव तक इंटरनेट तथा दूसरे संचार साधनों को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। इनके जरिए डिजिटल सुविधाएं भी वहां तक पहुंची हैं। हालांकि सामान्य लोग इनका भरपूर लाभ उठा सकें, उसके लिए जिस किस्म के कौशल विकास की ज़रूरत है, वहां चुनौतियां बरकरार हैं। डिजिटल डिवाइड की चुनौती पहले की तुलना में सिकुड़ी है, लेकिन आज भी एक हकीकत है। ज्ञान समाज की स्थापना के लिए हमें आने वाले वर्षों तथा दशकों में प्रयास जारी रखने होंगे।

अलबत्ता, डिजिटल क्षेत्र में हमारी प्रगति की बानगी इस तथ्य में देखी जा सकती है। सन् 2015 में जब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तब देश में सिर्फ 19% लोग इंटरनेट से जुड़े थे और 15% के पास मोबाइल था। आज हमारी दो तिहाई आबादी इंटरनेट से जुड़ी है जबकि 78 फीसदी से ज्यादा लोग मोबाइल फोन रखते हैं।

डिजिटल इंडिया के बाद

डेटा क्रांति की बदौलत आज भारत के गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं, जहां लोग जन्म प्रमाणपत्र, पेंशन, बैंकिंग और बिजली बिल जैसी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन आसानी से ले सकते हैं। डिजिलॉकर, आधार और यूपीआई जैसी सुविधाएं हममें से हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हैं। सैकड़ों सरकारी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन हो गया है तथा वे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोग घर बैठे ही सरकारी दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, आयकर तथा जीएसटी के रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस तरह की चीजों से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), जिसके तहत आधार, यूनिफाइड पेमेंट



सन् 2015 में जब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तब देश में सिर्फ 19% लोग इंटरनेट से जुड़े थे और 15% लोगों के पास ही मोबाइल फोन था। आज हमारी दो तिहाई आबादी इंटरनेट से जुड़ी है, जबकि 78 फीसदी से ज्यादा लोग मोबाइल फोन रखते हैं।





इंटरफेस (यूपीआई), डिजिटल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) को गिना जाता है, आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर 1.4 अरब लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ता है। यूपीआई की सफलता तो अभूतपूर्व है। यह न केवल वैश्विक रीयल-टाइम पेमेंट वॉल्यूम का 50% से अधिक हिस्सा संभालता है, बल्कि इसका विस्तार अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस और अन्य देशों में भी हो चुका है। जिस देश में आजादी के दशकों बाद भी करोड़ों लोग बैंक खाते से वंचित थे, वहां आज एक क्यूआर कोड से मिनटों में अंतरराष्ट्रीय भुगतान संभव है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ही इस मॉडल को विकासशील देशों के लिए एक मानक के रूप में देख रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक-आधारित बदलाव आ रहा है। फिलहाल 'स्वयम्', नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और 'पीएम विद्या' जैसी योजनाओं से लाखों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का मौका मिला है। कोविड-19 के समय जब स्कूल बंद थे, तब डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का सिलसिला टूटने नहीं दिया। हालांकि शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव एकदम से नहीं आ जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ सेवाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा लेने वालों की मन:स्थिति, तैयारी, कौशल, जागरूकता, शिक्षा, सुविधा, आर्थिक स्वीकार्यता तथा इच्छाशक्ति जैसे पहलू भी इनकी सफलता में भूमिका निभाते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि अंततः ये उसी तरह घर-घर पहुंचेंगी जैसे कि सोशल मीडिया पहुंचा है। जरूरी है कि ये प्रयोग में आसान हों और ठोस नतीजे दें।

डिजिटल इंडिया ने उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है। कनेक्टिविटी और सूचनाएं उपलब्ध हैं तो छोटे-छोटे गांवों में भी लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वे ऐसा कर भी रहे हैं। शहरों में डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग ने गति पकड़ी है तो गांवों में स्थानीय हुनर को ऑनलाइन बाजारों तक लाने के हजारों उदाहरण उपलब्ध हैं। कॉल सेंटर शहरों के साथ-साथ गांवों तक जा पहुंचे हैं।

आईटी में बढ़त का अवसर

नए भारत को इस बात का अहसास है कि आईटी के क्षेत्र में उसके पास बढ़त लेने का अवसर मौजूद है। सरकार खुद अपने आपको डिजिटल सरकार में तब्दील करने में लगी हुई है जो नागरिकों

के लिए तो लाभ का विषय है ही, प्रौद्योगिकी में रोजगार और उद्यम के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा, ई-प्रशासन, ई-स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई है, खासकर कोविड के संकट के बाद। दुनिया में भारत के ऑनलाइन बाजार को चीन के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है।

हमारी पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन के कारण अतीत में हमने बहुत से कीमती मौके खोए हैं। लेकिन आईटी में स्थितियां अलग हैं- भारत स्टेम (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) के ग्रेजुएट पैदा करने में विश्व में लगातार पहले या दूसरे नंबर पर चला आ रहा है। हमारी 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है और यह वह वर्ग है जो टेक्नोलॉजी के प्रति मैत्रीपूर्ण है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहां हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे उन्नत शिक्षण संस्थानों की शिक्षा का स्तर तो जगजाहिर है ही, स्टार्टअप क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटर और टिकरिंग लैब्स संचालित किए जा रहे हैं जिनसे सचमुच में कामयाब स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं।

भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना चुका है। डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त 1,10,000 से अधिक स्टार्टअप्स देश में सक्रिय हैं। काबिल स्टार्टअप्स के लिए कर्ज, वेंचर कैपिटल, बाजार और प्रोत्साहन की कमी नहीं है जो लगभग 500 अरब डॉलर के कुल बाजार मूल्य वाले 121 यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर या 9200+ करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाले स्टार्टअप) की सूची से जाहिर हैं। तकनीकी शोध और विकास के क्षेत्र में भी स्थितियां बेहतर हो रही हैं। हालांकि इस मामले में हम आज भी अमेरिका और चीन से काफी पीछे हैं। आईटी में कौशल विकास का तंत्र विकसित हो चुका है जो इन कौशलों को आईटी से इतर पृष्ठभूमि रखने वालों तक भी पहुंचा रहा है।

एक दशक पहले तक भारत में बिकने वाले लगभग सभी स्मार्टफोन चीन से आयात होते थे। पर आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया है, जहां वित्त वर्ष 2025-26 में 35 करोड़ मोबाइल फोन का विनिर्माण हुआ। इसके पीछे सरकार की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसने 15 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात आकर्षित किया है।





हम पांच ट्रिलियन (50 खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के तात्कालिक लक्ष्य में से एक ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी आईटी की मानकर चल रहे हैं। इसके आसार इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि मौजूदा सरकार नए अवसरों के प्रति पहले की तुलना में अधिक चौकस और तैयार दिखाई देती है।



एपल को देखिए। जो कंपनी कभी अपने सभी आईफोन केवल चीन में बनाती थी, उसने अब अपने वैश्विक आईफोन उत्पादन का 14-20% भारत में स्थानांतरित कर दिया है। इसी तरह, सैमसंग का नोएडा स्थित संयंत्र 12 करोड़ मोबाइल फोन के विनिर्माण की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादन केंद्र बन चुका है। देसी ब्रांड भी अपनी जगह और पहचान बना रहे हैं।

यदि मोबाइल विनिर्माण भारत की पहली बड़ी औद्योगिक छलांग थी, तो अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) क्षेत्र में प्रवेश उससे भी बड़ी और अधिक जटिल चुनौती एवं अवसर है। चिप निर्माण दुनिया के सबसे कठिन तकनीकी उद्यमों में से एक है, जिस पर ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका का दशकों से दबदबा रहा है। भारत इस क्षेत्र में 100% आयात पर निर्भर रहा है। हर स्मार्टफोन, कार, चिकित्सा उपकरण और सैन्य प्रणाली में लगी चिप बाहर से आती थी। लेकिन 2024-26 में इस तस्वीर को बदलने की शुरुआत हुई है। भारत सरकार ने छह प्रमुख सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को अनुमोदित किया, जिनका कुल निवेश 20 अरब डॉलर से अधिक है। अनेक भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने स्वदेशी चिप डिजाइन में भी कदम रखा है। शक्ति आरआईएससी-वी प्रोसेसर सेमीकंडक्टर संप्रभुता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की वैश्विक दौड़ में भारत की सशक्त उपस्थिति है। वैश्विक एआई प्रतिभा पूल में शीर्ष-3 स्थान पर खड़े भारत में 50 लाख से अधिक एआई पेशेवर हैं। 2024 में घोषित इंडिया एआई मिशन, जिसका बजट 1.25 अरब डॉलर है, पुणे, दिल्ली सहित सात शहरों में एआई केंद्र स्थापित कर रहा है। सर्वम एआई के रूप में भारत की सॉवरेन (संप्रभु) एआई का विकास काफी आगे बढ़ चुका है। इधर, 'भाषिणी' एक और क्रांतिकारी कदम है, जिसने 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में एआई मॉडल विकसित किए हैं। यह भारत जैसे बहुभाषीय देश में एआई को वास्तव में समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जब एआई हिंदी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु में बात कर सकता है, तो तकनीक का लाभ केवल अंग्रेजी जानने वाले शहरी वर्ग तक सीमित नहीं रह जाता।

वैश्विक तकनीकी दिग्गजों का भारत में निवेश एआई के क्षेत्र में हमारे यहां मौजूद संभावनाओं में उनके विश्वास की पुष्टि करता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, एनवीडिया जैसे वैश्विक दिग्गज

एआई से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए (डेटा सेंटर आदि) देश में 50 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रहे हैं।

स्पष्ट नीतियां और दिशा

भारत सरकार ने डिजिटल तकनीक, दूरसंचार, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाई हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एआई मिशन और डिजिटल इंडिया एक्ट जैसी नीतियां काबिले गौर हैं। डिजिटल प्रगति के लिए अक्सर एस्तोनिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन भारत की कामयाबी यह है कि उसने इतनी बड़ी जनसंख्या को डिजिटल बनाया है। हमारी ऑनलाइन वित्तीय भुगतान प्रणालियां तो दुनिया में अक्वल हैं ही।

ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ पा लिया है और चुनौतियां बची ही नहीं। हालांकि डिजिटल इंडिया ने साबित किया है कि हमारे जैसे देश में इतनी विविधताओं तथा असमानताओं के बावजूद डिजिटल दुनिया में भी ठोस उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। देश को आत्मनिर्भर, समावेशी और ज्ञान-आधारित समाज में तब्दील करने की हमारी जद्दोजहद में डिजिटल इंडिया की भूमिका अहम है और यह आगे भी बनी रहेगी।

मैंने अक्सर अपनी विदेश यात्राओं के दौरान लोगों को भारत की आईटी-सफलता की तारीफ करते हुए सुना है। यह साख बहुत लंबे समय से चले आए प्रयासों और भरोसेमंद सेवाएं देने की वजह से मिली है। यह साख लगातार बेहतर हुई है, खासकर आधार, जनधन, डिजिटल लेनदेन क्रांति और कोविड संकट के प्रबंधन के चलते। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण, पराग अग्रवाल और अरविंद कृष्ण जैसे दिग्गजों ने वैश्विक स्तर पर भारतीय आईटी प्रतिभा की काबिलियत और अहमियत को स्थापित किया है।

भारत की आईटी क्रांति का छोटा हिस्सा घटित हो चुका है जबकि बड़ी क्रांति होनी अभी बाकी है। मोदी सरकार ने मौजूदा दशक को 'टेकेड' (तकनीकी दशक) का नाम दिया है और हम पांच ट्रिलियन (50 खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के तात्कालिक लक्ष्य में से एक ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी आईटी की मानकर चल रहे हैं। इसके आसार इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि मौजूदा सरकार नए अवसरों के प्रति पहले की तुलना में अधिक चौकस और तैयार दिखाई देती है। सन् 2025





में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आईटी और आईटी आधारित सेवाओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंच गई जो 1998 में मात्र 1.2 प्रतिशत थी। मौजूदा दशक में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक ले जाया जा सका तो वह एक बहुत बड़ी सफलता होगी।

भारत के लिए तीन बहुत बड़े अवसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनुफैक्चरिंग और क्वान्टम कंप्यूटिंग से आने के आधार हैं। अतीत की परिपाटी पर चलते तो शायद विकसित देशों में बहुत कुछ हो जाने के बाद हमने इन पर ध्यान दिया होता, लेकिन आज ये सभी सरकार की प्राथमिकताओं में से हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा पर काम शुरू हो चुका है। मैनुफैक्चरिंग में मोबाइल और सेमीकंडक्टर के रूप में दो बड़ी पहल हमारे सामने हैं जो न सिर्फ अन्य देशों पर हमारी निर्भरता खत्म कर सकती है बल्कि नए बाजार भी खोलने वाली है। क्वान्टम कंप्यूटिंग आईटी के समूचे परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। भारत के राष्ट्रीय क्वान्टम मिशन की स्थापना एक दूरदर्शिता वाला कदम है।

आईटी और दूरसंचार क्षेत्र में अनुकूल और दूरदर्शितापूर्ण माहौल, बढ़ते सरकारी-निजी निवेश, स्टार्टअप के कामयाब नेटवर्क, कुशल युवाओं की विशाल संख्या, तेज-रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था, परिपक्व डिजिटल तंत्र की मौजूदगी जैसे पहलू भारत को आईटी की वैश्विक महाशक्ति बना सकते हैं। जैसे चीन ने खुद को दुनिया की मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्री में तब्दील कर दिया, हम खुद को आईटी-हब में बदल सकते हैं। सब ठीक रहा तो मौजूदा 'टेकडे' (तकनीकी दशक) हमारी उस वैश्विक यात्रा का 'टेक-ऑफ' सिद्ध हो सकता है।



(राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बालेंद्र शर्मा दाधीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की जानी मानी शख्सियत हैं। भारतीय भाषाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। लंबे समय तक माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय भाषा प्रमुख रहे दाधीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ हैं। संप्रति वे दुबई स्थित एल्गो टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इंटरनेट के संचालन से जुड़ी वैश्विक संस्था ICANN के यूनिवर्सल एक्सेस अंबेसडर हैं।)



विकसित भारत



कुमार रोहित

निदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय
सामाजिक सुरक्षा अकादमी (श्रम एवं
रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

विरासत के साथ

विकास की यात्रा

क

ल्पना कीजिए कि सुदूर उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों के घने जंगलों के बीच, जहां कल तक बिजली की कल्पना भी एक स्वप्न थी, वहां आज सुबह की पहली किरण के साथ एक 'ड्रोन दीदी' अपने गांव के खेतों के ऊपर एक अत्याधुनिक ड्रोन उड़ा रही है। वह न केवल तकनीक का प्रदर्शन कर रही है, बल्कि वह उन सदियों पुरानी रूढ़ियों को भी तोड़ रही है, जिन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज को विकास की दौड़ में पीछे कर दिया था। वहीं मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर माहेश्वर में नर्मदा के तट पर बैठी एक रेहड़ी-पटरी वाली महिला मछलियों का दाना बेचने वाली अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहक से सहजता के साथ कहती है-"साहब, क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए।" उसके मोबाइल पर होने वाली वह 'बीप' मात्र एक वित्तीय सूचना नहीं है, बल्कि वह भारत के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के भीतर जागी उस असीम शक्ति और आत्मविश्वास की पुकार है, जिसने वैश्विक परिदृश्य पर भारत की पहचान बदल दी है।

यह वह भारत है जो पिछले एक दशक में पुनर्जीवित हुआ है। वर्ष 2014 का



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 'नीतिगत जड़ता' (Policy Paralysis) के कुहासे को चीरकर 'संकल्प से सिद्धि' के मार्ग पर चलना सीखा है। यह उस भव्य रोडमैप का जीवंत चित्रण है, जो भारत को 2047 तक एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने की अटल आधारशिला रख रहा है।

वह कालखंड, जिसे वैश्विक विश्लेषक 'फ्रेजाइल फाइव' (Fragile Five) अर्थव्यवस्थाओं के पतन के रूप में देख रहे थे, आज इतिहास के पन्नों में बहुत पीछे छूट चुका है। पिछले करीब बारह वर्षों की यह यात्रा केवल आर्थिक आंकड़ों या विकास दर का संकलन नहीं है, बल्कि यह 1.4 अरब भारतीयों के 'राष्ट्रीय गौरव' की पुनर्प्राप्ति की महागाथा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 'नीतिगत जड़ता' (Policy Paralysis) के कुहासे को चीरकर 'संकल्प से सिद्धि' के मार्ग पर चलना सीखा है। यह उस भव्य रोडमैप का जीवंत चित्रण है, जो भारत को 2047 तक एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने की अटल आधारशिला रख रहा है।

विकसित भारत का स्वप्न : साझा राष्ट्रीय चेतना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन में "विकसित भारत" केवल गगनचुंबी इमारतों या विशाल जीडीपी का नाम नहीं है। यह एक ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना है, जहां विकास की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए भी देश अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा रहे। प्रधानमंत्री इसे 'विरासत भी, विकास भी' के मंत्र से परिभाषित करते हैं। 2047 का लक्ष्य-स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना-आज एक सरकारी योजना मात्र नहीं रह गया है, बल्कि यह एक 'साझा राष्ट्रीय संकल्प' बन चुका है। यह संकल्प चार अविभाज्य स्तंभों पर टिका है : युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और अन्नदाता (किसान)। जब राष्ट्र की ये चार इकाइयां सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी, तभी भारत की वैश्विक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस विजन का लक्ष्य 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति 18,000 से 20,000 डॉलर की आय प्राप्त करना है, ताकि भारत न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि मानव विकास सूचकांक (HDI) के मामले में भी दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो सके।

परिवर्तन की आधारशिला : शासन शैली और प्रशासनिक सक्षमता

2014 के बाद से भारत ने शासन की एक नई परिभाषा देखी है। प्रधानमंत्री का मंत्र "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" (Minimum Government, Maximum Governance) केवल एक नारा नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली का नया डीएनए बन गया है। यह शासनशैली निर्णयों में

'साहस' और क्रियान्वयन में 'गति' का प्रतिनिधित्व करती है।

इस प्रशासनिक सक्षमता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) प्लेटफॉर्म है। कल्पना कीजिए एक ऐसे 'वर्चुअल वार रूम' की, जहां प्रधानमंत्री स्वयं हर महीने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठकर उन परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं जो दशकों से फाइलों के ढेर के नीचे दबी हुई थीं। अब तक 85 लाख करोड़ (1 ट्रिलियन डॉलर) से अधिक की 382 मेगा परियोजनाओं को इस तकनीक आधारित नेतृत्व ने गति प्रदान की है। बोगीबिल पुल, जिसका सपना 1997 में देखा गया था या नवी मुंबई हवाई अड्डा-ऐसी सैकड़ों परियोजनाओं का साकार होना इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व जब व्यक्तिगत रुचि लेकर बाधाओं को दूर करता है, तो शासन जनता के प्रति जवाबदेह बन जाता है।

प्रशासनिक सुधारों की इसी कड़ी में सरकार ने औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागते हुए न केवल 1,500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त कर दिया, बल्कि संसद से जन विश्वास बिल पारित करके 79 विभिन्न कानूनों से जुड़े 1000 प्रावधानों को बदला जा रहा है। इसके तहत छोटी-मोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए उसके लिए सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस तरह के अपराधों से जुड़े पांच करोड़ से अधिक मामले देशभर की आदालतों में लंबित हैं। यह 'लीगल क्लीन-अप' न केवल व्यापार की सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाता है, बल्कि एक नागरिक के रूप में 'Ease of Living' को भी सुनिश्चित करता है।

प्रमुख उपलब्धियां : सशक्तिकरण का नया प्रतिमान

(क) वित्तीय समावेशन : अंतिम व्यक्ति का आर्थिक उदय

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने भारत के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी और अभेद्य दीवार को ढहा दिया है। दशकों तक बैंकिंग व्यवस्था केवल संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार मानी जाती थी, लेकिन आज भारत का सबसे निर्धन नागरिक भी गर्व से अपना 'रुपे कार्ड' दिखाता है। मार्च 2025 तक 56 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले जा चुके थे, जिनमें से 55% से अधिक महिलाओं के नाम पर हैं।

इन खातों और 'JAM ट्रिनिटी' (जन-धन, आधार और मोबाइल) के एकीकरण ने भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से अब तक 43 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई गई है। इस व्यवस्था ने सरकारी खजाने से 3.5 लाख करोड़ की 'लीकेज' रोकी है, जो पहले बिचौलियों की भेंट चढ़ जाती थी। यह केवल वित्तीय बचत नहीं है, बल्कि यह करोड़ों नागरिकों का अपनी सरकार पर पुनः स्थापित हुआ अटूट विश्वास है।

(ख) डिजिटल क्रांति और UPI : वैश्विक सॉफ्ट पावर

आज भारत की सड़कों पर एक रेहड़ी-पटरी वाला भी वैश्विक डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। यूनिफाइडेपेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने लेन-देन के तरीके को ही बदल दिया है। जून 2025 में UPI ने 18.4 बिलियन लेन देन का ऐतिहासिक शिखर छुआ, जो प्रति दिन 613 मिलियन लेन देन के बराबर है। भारत का यह 'डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा' (DPI) आज दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है।

सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश आज भारतीय UPI को अपना रहे हैं, जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का डंका बजा रहा है। इंटरनेट डेटा की लागत, जो 2014 में 308/GB थी, अब गिरकर मात्र 9.34 रह गई है, जिसने डिजिटल लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है।



प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से अब तक 43 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई गई है। इस व्यवस्था ने सरकारी खजाने से 3.5 लाख करोड़ की 'लीकेज' रोकी है, जो पहले बिचौलियों की भेंट चढ़ जाती थी।



(ग) सामाजिक कल्याण: संतुष्टि से सम्मान तक

मोदी सरकार की नीतियों का मूल दर्शन 'अंत्योदय' है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आवास, बिजली, स्वास्थ्य और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार बनें।

आयुष्मान भारत : विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में इसने 55 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज प्रदान कर उन्हें बीमारी की आर्थिक विभीषिका से बचाया है।

स्वच्छ भारत मिशन : 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण ने न केवल स्वच्छता का स्तर सुधारा, बल्कि करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को वह सुरक्षा और गरिमा प्रदान की, जिसकी वे हकदार थीं।

जल जीवन मिशन : 'हर घर जल' अभियान के माध्यम से 15.59 करोड़ ग्रामीण घरों तक पहली बार नल से स्वच्छ पानी पहुंचा है, जिससे ग्रामीण जीवन की एक बड़ी पीड़ा का अंत हुआ है।

(घ) बुनियादी ढांचा: आधुनिक भारत की धमनियां

भारत का भौतिक स्वरूप पिछले एक दशक में पूरी तरह बदल गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति 2014 के 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर अब 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। रेलवे में 'वंदे भारत' जैसी आधुनिक ट्रेनों और 'उड़ान' (UDAN) योजना के तहत 164 से अधिक सक्रिय हवाई अड्डों ने आम भारतीय की यात्रा को सुगम बनाया है। बंदरगाहों की क्षमता का दोगुना होना और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का पूरा होना भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में मजबूत कदम हैं।

अयोध्या : सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

भारत के इस विकास पथ पर अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक मुक्ति का क्षण है। 22 जनवरी, 2024 को हुई प्राण-प्रतिष्ठा और 25 नवंबर, 2025 को मंदिर के पूर्ण होने पर किया गया 'ध्वजारोहण' भारतीय जनमानस के लिए 500 वर्षों के संघर्ष और अटूट आस्था की विजय का प्रतीक है।

आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव का संचार

श्रीराम मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के लिए एक 'मनोवैज्ञानिक मरहम' की तरह है। यह उस हीन-भावना के अंत की घोषणा है जो सदियों की दासता ने भारतीय मन पर अंकित कर दी थी। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में 'ध्वजारोहण' किया, तो वह केवल एक मंदिर का पूर्ण होना नहीं था, बल्कि वह "अमृत काल" में एक आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी भारत के उदय का जयघोष था। इस घटना ने आम भारतीयों के भीतर यह विश्वास जगाया है कि यदि राष्ट्र एक होकर संकल्प करे, तो पांच शताब्दियों पुराने कठिनतम स्वप्न भी कानून की मर्यादा के भीतर रहकर पूर्ण किए जा सकते हैं।

पर्यटन और 'मंदिर अर्थव्यवस्था' (Temple Economy)

अयोध्या की इस आध्यात्मिक क्रांति ने उत्तर प्रदेश और भारत में 'धार्मिक पर्यटन' (Religious Tourism) को एक नई आर्थिक शक्ति प्रदान की है :

पर्यटकों का सैलाब : अयोध्या में पर्यटकों की संख्या 2017 के 2.84 लाख से बढ़कर 2025 में 29.95 करोड़ तक पहुंच गई।

आर्थिक क्रांति : आईएम (IIM) लखनऊ के अध्ययन के अनुसार, अयोध्या की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल आया है। छोटे दुकानदारों की दैनिक आय जो 500 थी, वह अब 2,500 रुपये से अधिक हो गई है।

रोजगार सृजन : अकेले अयोध्या में आने वाले वर्षों में 1.2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश अब एक "Graveyard Economy" से निकलकर "Temple and Festival Economy" का वैश्विक हब बन गया है, जो राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

नैतिक दृष्टिकोण : 'NAITIK' ढांचा और विभीषण गीता का संदेश

विकसित भारत के इस रोडमैप को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में प्रस्तुत एक विशेष नैतिक ढांचे (NAITIK Framework) के साथ जोड़ा है। उनके अनुसार, विकसित भारत केवल ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि उच्च नैतिक मूल्यों से बनेगा। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने "विभीषण गीता" के उन शाश्वत दोहों का उल्लेख किया, जो आज के शासन और नागरिक जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस के इस अंश में भगवान राम विभीषण को बताते हैं कि विजय शस्त्रों से नहीं, बल्कि चरित्र से मिलती है :

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका॥

यहां 'सौरज' (शौर्य) और 'धीरज' (धैर्य) विकास के उस रथ के पहिए हैं, जबकि 'सत्य' और 'शील' (उत्कृष्ट आचरण) उसकी ध्वजा और पताका हैं।

यह नैतिक ढांचा आधुनिक भारत को एक सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता (Empathetic Mindset) की ओर ले जाता है। राम मंदिर के माध्यम से समाज में करुणा, कर्तव्यपरायणता और 'सबका साथ' जैसे मूल्यों को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह विचार कि "राम केवल हमारे नहीं, राम सबके हैं," भारत की धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संस्कृति को और अधिक गहराई प्रदान करता है।



भारत के इस विकास पथ पर अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक मुक्ति का क्षण है। 22 जनवरी, 2024 को हुई प्राण-प्रतिष्ठा और 25 नवंबर, 2025 को मंदिर के पूर्ण होने पर किया गया 'ध्वजारोहण' भारतीय जनमानस के लिए 500 वर्षों के संघर्ष और अटूट आस्था की विजय का प्रतीक है।

संकट में सामर्थ्य : कोविड-19 का प्रबंधन और सामाजिक सहयोग

विकसित राष्ट्र की असली पहचान संकट के समय उसकी दृढ़ता से होती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने जिस प्रकार का प्रबंधन दिखाया, उसने दुनिया को अचंभित कर दिया। जहां विकसित देशों की स्वास्थ्य प्रणालियां चरमरा रही थीं, वहीं भारत ने तकनीक और सामाजिक सहयोग के समन्वय से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान (200 करोड़ से अधिक खुराक) सफलतापूर्वक चलाया।

सामाजिक एकजुटता की सीख

महामारी के दौरान 'जनता कफ्यू' से लेकर 'दीपक जलाने' तक के आह्वानों ने भारतीयों के भीतर उस 'सामूहिक शक्ति' (Collective Might) को जगाया, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर करोड़ों लोगों का अनुशासन में रहना और 'स्वयंसेवी' समूहों द्वारा जरूरतमंदों की सेवा करना, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज अब एक "राष्ट्र-प्रथम" (Nation First) की मानसिकता से ओतप्रोत है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म 'Co-WIN' और आरोग्य सेतु ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत तकनीक के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। इस संकट ने भारत को 'Vishwa Bandhu' (विश्व का मित्र) के रूप में भी स्थापित किया, जब 'वैक्सीन मैत्री' के तहत हमने 99 देशों को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें प्रदान कीं।

संवैधानिक निर्णय : राष्ट्रीय एकीकरण का महायज्ञ

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन केवल एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर के पूर्ण भावनात्मक और संवैधानिक एकीकरण का ऐतिहासिक क्षण था। अगस्त 2025 में इस निर्णय के छह वर्ष पूर्ण होने पर कश्मीर का बदला हुआ परिदृश्य भारत की प्रशासनिक सफलता की

कहानी कह रहा है।

हिंसा में भारी कमी (2001 के 4,011 हताहतों की तुलना में 2024 में मात्र 127) और 2024 में कश्मीर में 2.35 करोड़ पर्यटकों का आना शांति और समृद्धि की नई शुरुआत है। चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण और श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक ने घाटी को देश के अन्य हिस्सों से स्थायी रूप से जोड़ दिया है। 2024 के विधानसभा चुनावों में हुआ भारी मतदान यह सिद्ध करता है कि अलगाववाद का अंत अब विकास और लोकतंत्र के माध्यम से हो चुका है।

समावेशी विकास: ग्रामीण-शहरी संतुलन और सामाजिक न्याय

विकसित भारत की यात्रा में कोई भी वर्ग पीछे न छूटे, इसके लिए सरकार ने 'संतृप्ति का सिद्धांत' (Principle of Saturation) अपनाया है।

महिला सशक्तिकरण : 'लखपति दीदी' योजना के माध्यम से तीन करोड़ महिलाओं को सशक्त उद्यमी बनाया जा रहा है। 'ड्रोन दीदी' पहल कृषि में महिलाओं के नेतृत्व को नई दिशा दे रही है।

अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग : सरकारी योजनाओं का लाभ धर्म या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता के आधार पर मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 52.77 करोड़ ऋणों में से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँचा है।

एरिपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स : देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों के विकास के लिए 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' ने क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया है, जहां चंबा जैसे जिलों ने 'हर घर जल' में रिकॉर्ड सफलता प्राप्त की है।

चुनौतियां : एक यथार्थवादी दृष्टि

हालांकि विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ते हुए इस मार्ग में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राष्ट्र के सामने बेरोजगारी, युवाओं के लिए आधुनिक कौशल विकास (एआई और रोबोटिक्स), आय की असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। सरकार इन चुनौतियों के प्रति सजग है और 'मिशन कर्मयोगी' के माध्यम से नौकरशाही को और अधिक संवेदनशील और भविष्योन्मुख बना रही है। पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत ने 'नेट जीरो 2070' का लक्ष्य रखा है और नवीकरणीय ऊर्जा में 505 GW की क्षमता स्थापित कर दुनिया को राह दिखा रहा है।

भविष्य की राह : जनभागीदारी का महाआंदोलन

विकास का रोडमैप तभी सफल होता है जब वह सरकारी कार्यक्रम से हटकर एक 'जन-आंदोलन' बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का 'अमृत काल' के लिए आह्वान हर नागरिक के 'कर्तव्य' पर आधारित है। विकसित भारत का निर्माण केवल मंत्रालयों के बजट से नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा और अटूट अनुशासन से होगा।

आधुनिक तकनीक (एआई, सेमीकंडक्टर) और प्राचीन ज्ञान (पांडुलिपियों का संरक्षण—Gyan Bharatam Mission) का संगम ही भारत को पुनः "विश्व गुरु" के पद पर आसीन करेगा। 'मिशन सुदर्शन चक्र' जैसे रक्षा कवच और 'गगनयान' जैसे अंतरिक्ष मिशन भारत के बढ़ते सामरिक और वैज्ञानिक कद के परिचायक हैं।



संभावनाओं का भारत, संकल्पों का सिद्धि काल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह वर्षों की यह यात्रा मात्र सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह 'भारतीय मन' के रूपांतरण की कहानी है। 2014 का वह भारत जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करता था, आज 2026 में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, कोविड-19 का सफल प्रबंधन, और डिजिटल क्रांति-इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा अनुशासित और प्रतिबद्ध भारतीय समाज तैयार किया है, जो अब छोटे लक्ष्यों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। विकसित भारत @ 2047 का रोडमैप तैयार है। इसकी नींव हमारे नैतिक मूल्यों (NAITIK) पर रखी गई है और इसका ढांचा आधुनिक तकनीक से निर्मित हो रहा है।

जैसाकि अयोध्या में ध्वजारोहण के समय प्रधानमंत्री ने कहा था—"यह समय भारत के उदय का साक्षी है"। यह एक ऐसी साझा यात्रा है, जहां हर नागरिक एक 'कर्मयोगी' है। आइए, हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक यात्रा के हमसफर बनें, क्योंकि विकसित भारत की ओर बढ़ता यह राष्ट्र अब रुकने वाला नहीं है। यह यात्रा एक गौरवशाली, आत्मनिर्भर और मानवीय भारत की ओर बढ़ता हुआ वह कदम है, जो आने वाली कई सदियों तक संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाश पुंज बनेगा।



(लेखक अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के निदेशक हैं। वे सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी पहलों में भी सक्रिय हैं। IC Centre for Governance तथा PRAYAS Juvenile Aid Centre के साथ भी कार्यरत हैं। उन्हें ट्विटर (@_KumarRohit) और इंस्टाग्राम (@write2kumarrohit) या ईमेल write2kumarrohit@outlook.com पर संदेश भेजा जा सकता है।)



विकसित भारत



डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी
एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू, नई दिल्ली

राजनीति-प्रशासन का कौशल युक्त प्रबंधन

भारत के समकालीन राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं, जिनका मूल्यांकन केवल चुनावी सफलता से नहीं, बल्कि उनकी प्रशासनिक शैली, निर्णय लेने की क्षमता, योजनाओं के क्रियान्वयन, संकट-प्रबंधन, विदेश नीति की सक्रियता और राजनीतिक नियंत्रण के व्यापक ढांचे में किया जाता है। वर्ष 2014 के बाद भारत में शासन की भाषा, सरकारी योजनाओं की प्रस्तुति, प्रशासनिक निगरानी, तकनीक के उपयोग, लाभार्थी-आधारित कल्याण, वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज और सत्ता-संचालन की राजनीतिक शैली—इन सभी में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है। इस बदलाव के केंद्र में नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व है।

वर्ष 2014 के बाद भारत की प्रशासनिक संस्कृति, नीति-निर्माण की गति, योजनाओं के क्रियान्वयन की शैली, विदेश नीति की सक्रियता और राजनीतिक प्रबंधन के तौर-तरीकों में स्पष्ट परिवर्तन का श्रेय निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा सकता है। उन्होंने शासन को केवल सरकारी प्रक्रियाओं तक सीमित न रखकर उसे परिणामोन्मुख, तकनीक-संचालित, जन-केंद्रित



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शासन को केवल सरकारी प्रक्रियाओं तक सीमित न रखकर उसे परिणामोन्मुख, तकनीक-संचालित, जन-केंद्रित और राजनीतिक रूप से संवाद-सक्षम बनाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि उनके प्रशासनिक कौशल का अध्ययन केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रबंधक के रूप में भी किया जाना चाहिए, जिसने शासन, संगठन, जनविश्वास और वैश्विक छवि—इन सभी को एक साथ साधने का प्रयास किया।

और राजनीतिक रूप से संवाद-सक्षम बनाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि उनके प्रशासनिक कौशल का अध्ययन केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रबंधक के रूप में भी किया जाना चाहिए, जिसने शासन, संगठन, जनविश्वास और वैश्विक छवि—इन सभी को एक साथ साधने का प्रयास किया। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की विशेषता यह रही है कि उन्होंने प्रशासन को पारंपरिक ढर्रे से निकालकर मिशन मोड में बदलने की कोशिश की। शासन, कूटनीति और राजनीतिक प्रबंधन के इस त्रिकोण ने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक शैली की सबसे बड़ी विशेषता निर्णय की स्पष्टता, कार्यान्वयन की केंद्रीकृत निगरानी, तकनीक-आधारित शासन, परिणामों की दृश्यता और राजनीतिक संदेश के साथ प्रशासनिक लक्ष्य का संयोजन है।

शासन-प्रशासन : “डिलीवरी स्टेट” की रचना

मोदी सरकार की प्रशासनिक पहचान का पहला स्तंभ है—डिलीवरी। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने अपने शासन मॉडल को कल्याणकारी वादों से आगे बढ़ाकर लाभार्थी-केंद्रित डिलीवरी तंत्र में बदला। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे और इनमें लगभग 2.68 लाख करोड़ जमा थे। इनमें 55 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं और लगभग दो-तिहाई खाते ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। इससे वित्तीय समावेशन को आधार मिला, जो आगे चलकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बीमा, पेंशन और डिजिटल भुगतान के विस्तार का आधार बना।

जनधन, आधार और मोबाइल के त्रिकोण ने शासन को “रिसाव-प्रधान” से “प्रमाण-प्रधान” बनाने की कोशिश की। डीबीटी पोर्टल के अनुसार मार्च 2024 तक विभिन्न योजनाओं में अनुमानित बचत/लाभ का संचयी आंकड़ा लाखों करोड़ रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया, जिसमें पहल जैसी योजनाओं में फर्जी/डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान से बड़े पैमाने पर बचत हुई। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मोदी प्रशासन ने कल्याणकारी राज्य को डिजिटल सत्यापन और बैंक खातों से जोड़कर एक नए प्रशासनिक अनुशासन में बदला।

डिजिटल गवर्नंस का दूसरा बड़ा आधार यूपीआई है। एनपीसीआई के अनुसार फरवरी 2026

में यूपीआई पर 20.39 बिलियन से अधिक लेनदेन और 26.84 लाख करोड़ से अधिक मूल्य का भुगतान दर्ज हुआ। यह केवल तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक डिजिटल व्यवहार में बदलने का उदाहरण है। मोदी सरकार ने इसे राज्य-समर्थित सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के रूप में आगे बढ़ाया।

जीएसटी के मामले में भी मोदी प्रशासन का कौशल नीति-निर्माण से अधिक क्रियान्वयन के क्रमिक सुधार में दिखाई देता है। प्रारंभिक अव्यवस्था, अनुपालन बोझ और दर-संरचना की जटिलता के बावजूद 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2025 के बीच सकल जीएसटी संग्रह 17.4 लाख करोड़ रहा और करदाताओं की संख्या 2017 के लगभग 60 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से अधिक हो गई। इससे यह संकेत मिलता है कि शासन का उद्देश्य केवल कर संग्रह नहीं, बल्कि आर्थिक औपचारिककरण भी था।

इसी प्रकार अवसंरचना निर्माण में मोदी सरकार की कार्यशैली “घोषणा” के बजाय “मापनीय विस्तार” पर टिकी दिखती है। 2014 के लगभग 91,287 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की तुलना में 2025 के अंत तक यह बढ़कर लगभग 1,46,560 किमी. हो गया। राजमार्ग निर्माण की गति 2014-15 के लगभग 12 किमी. प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में लगभग 33.8 किमी प्रतिदिन तक पहुंची। हाई-स्पीड कॉरिडोर और 4-लेन से ऊपर के राजमार्गों में भी तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। यह प्रशासनिक रूप से बताता है कि मोदी मॉडल में निर्णय, वित्त पोषण, भूमि-समन्वय, मॉनिटरिंग और दृश्य परिणाम-इन सभी को प्रधानमंत्री-केंद्रित प्राथमिकता में रखा गया।

स्वास्थ्य प्रशासन में भी यही शैली दिखती है। अक्टूबर 2025 तक 42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके थे; जुलाई 2025 तक 9.84 करोड़ से अधिक अस्पताल-प्रवेश अधिकृत हुए, जिनकी स्वीकृत राशि 1.40 लाख करोड़ से अधिक थी। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह प्रगति बताती है कि मोदी प्रशासन ने कल्याणकारी योजनाओं को केवल घोषणापत्र का हिस्सा नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें डेटा-समर्थित प्रशासनिक कार्यक्रमों में बदला।

प्रशासनिक शैली : केंद्रीकरण, निगरानी और “मिशन मोड”

प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासनिक कौशल की सबसे बड़ी ताकत उनकी मिशन मोड कार्यशैली है। वे योजनाओं को विभागीय खानों में नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें समयबद्ध राष्ट्रीय मिशन का रूप देते हैं—चाहे वह स्वच्छ भारत हो, जल जीवन मिशन, कोविड टीकाकरण, गति शक्ति, पीएम आवास या डिजिटल भुगतान। कोविड टीकाकरण के दौरान भारत ने 2022 तक 218 करोड़ से अधिक खुराकें देने का रिकॉर्ड बनाया। यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की उपलब्धि नहीं थी; यह आपूर्ति शृंखला, डिजिटल प्रमाणन, राज्यों के समन्वय और राजनीतिक संदेश—इन सभी का संयुक्त प्रशासनिक प्रदर्शन था।



संकट-प्रबंधन के स्तर पर भी विदेश नीति का प्रशासनिक पक्ष मजबूत दिखता है। ‘ऑपरेशन गंगा’ के तहत मार्च 2022 तक लगभग 23,000 भारतीय नागरिकों तथा 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया। ऐसे अभियानों में केवल दूतावासीय औपचारिकता नहीं होती; इसमें उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्णय, सैन्य और नागरिक उद्धारण समन्वय, पड़ोसी देशों से सहयोग, और लगातार निगरानी शामिल होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी की प्रशासनिक दक्षता का एक हिस्सा संकट-प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया में भी निहित है।



यहां मोदी मॉडल की दूसरी विशेषता दिखती है-प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) आधारित उच्च-स्तरीय निगरानी। भारत में पहले भी योजनाएं बनती थीं, परंतु मोदी युग में समीक्षा की संस्कृति अधिक प्रत्यक्ष और सार्वजनिक हुई। 'प्रगति' जैसी व्यवस्थाएं, जिलों तक योजनाओं की मॉनिटरिंग, लक्ष्य-आधारित मंत्रालयीय संस्कृति और "डेडलाइन गवर्नेंस" ने नौकरशाही को यह संदेश दिया कि राजनीतिक नेतृत्व केवल नीति घोषित नहीं करेगा, बल्कि प्रगति भी पूछेगा। इसने प्रशासन में गति लाई, हालांकि आलोचक यह कहने से नहीं चूके कि इससे मंत्रालयों और कैबिनेट समितियों की स्वायत्तता तुलनात्मक रूप से सीमित हुई है।

मोदी का प्रशासनिक कौशल इस बात में है कि उन्होंने भारतीय नौकरशाही की जड़ता को समझा और उसके ऊपर राजनीतिक दबाव + तकनीकी ट्रेकिंग + सार्वजनिक लक्ष्य का त्रिकोण बैठाया। भारत जैसा विशाल और बहुस्तरीय लोकतंत्र सामान्यतः प्रक्रियाओं में उलझता है; मोदी ने उसी प्रक्रिया को "परिणाम" की भाषा में पुनःपरिभाषित किया।

आर्थिक प्रबंधन : निवेश, औपचारिककरण और राज्य की सक्रिय भूमिका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक शैली का तीसरा प्रमुख पक्ष आर्थिक प्रबंधन है। उनके शासन में राज्य ने स्वयं को "न्यूनतम सरकार" के नारे से आगे बढ़ाकर कई क्षेत्रों में सक्रिय सक्षमकर्ता और प्लेटफॉर्म निर्माता के रूप में स्थापित किया। सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन, पूंजीगत व्यय, लॉजिस्टिक्स और औपचारिककरण-ये इस मॉडल के प्रमुख घटक हैं।

केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय 12.21 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह लगभग 10.96 लाख करोड़ रुपये था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और बजट दस्तावेजों में यह भी रेखांकित है कि बुनियादी ढांचे और प्रभावी पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर बना हुआ है।

लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार भी इसी प्रशासनिक सोच का हिस्सा है। विश्व बैंक के LPI 2023 में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुंचा, जो 2018 की तुलना में छह स्थान बेहतर था; पीआईबी ने यह भी रेखांकित किया कि 2014 की तुलना में भारत की स्थिति 16 स्थान सुधरी। इसका अर्थ यह है कि मोदी सरकार ने अवसंरचना को केवल सड़क या पुल नहीं माना, बल्कि व्यापार सुगमता, आपूर्ति

शृंखला, बंदरगाह, माल ढुलाई और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के व्यापक ढांचे में रखा।

विदेश नीति और कूटनीति : व्यक्तित्व-आधारित सक्रियता

मोदी की विदेश नीति शैली पारंपरिक भारतीय कूटनीति से कई मायनों में अलग है। इसमें एक ओर रणनीतिक स्वायत्तता की निरंतरता है, तो दूसरी ओर उच्च दृश्यता, व्यक्तिगत नेतृत्व, प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव, बहुपक्षीय मंचों पर आक्रामक प्रस्तुति और भू-राजनीतिक संतुलन की नई शैली है। भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनी, जबकि उस समय रूस-यूक्रेन युद्ध पर वैश्विक मतभेद बहुत तीखे थे। भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को उभारा और अफ्रीकन यूनियन को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। यह मोदी सरकार की कूटनीतिक प्रबंधन क्षमता को दर्शाता है-विशेषतः वहां, जहां सहमति बनाना लगभग असंभव माना जा रहा था।

संकट-प्रबंधन के स्तर पर भी विदेश नीति का प्रशासनिक पक्ष मजबूत दिखता है। 'ऑपरेशन गंगा' के तहत मार्च 2022 तक लगभग 23,000 भारतीय नागरिकों तथा 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया। ऐसे अभियानों में केवल दूतावासीय औपचारिकता नहीं होती; इसमें उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्णय, सैन्य और नागरिक उड्डयन समन्वय, पड़ोसी देशों से सहयोग, और लगातार निगरानी शामिल होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रशासनिक दक्षता का एक हिस्सा संकट-प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया में भी निहित है।

पीएम मोदी की विदेश नीति का एक और पक्ष है-बहुध्रुवीय समायोजन। अमेरिका, यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक, सभी दिशाओं में संबंध बनाए रखना आसान नहीं था। यह संतुलन मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक ऊर्जा और भारतीय विदेश सेवा की संस्थागत क्षमता, दोनों का परिणाम है। इस कसौटी पर भारत ने प्रगति की है, पर चुनौतियां शेष हैं, विशेषकर चीन के साथ सीमा तनाव, पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता, और वैश्विक व्यापार तनावों के दौर में।

राजनीतिक प्रबंधन : संगठन, संदेश और सत्ता-संचालन

प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासनिक कौशल की पूर्ण समझ राजनीतिक प्रबंधन के बिना संभव नहीं है। वे शायद स्वतंत्र भारत के उन विरले प्रधानमंत्रियों में हैं, जिन्होंने शासन और राजनीति को परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि परस्पर पोषक उपकरणों में बदल दिया। उनकी शैली में योजना केवल मंत्रालय की फाइल नहीं रहती; वह चुनावी संवाद, जन-अपील, सामाजिक मीडिया संदेश, लाभार्थी संपर्क और राष्ट्रवादी आख्यान का हिस्सा बन जाती है।

पीएम मोदी का राजनीतिक प्रबंधन तीन स्तरों पर काम करता है। पहला, संदेश की सरलता, जैसे-स्वच्छता, उज्ज्वला, जनधन, घर, शौचालय, नल, मुफ्त राशन, आयुष्मान आदि। दूसरा, लाभार्थी का



प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासनिक कौशल केवल सचिवालयों में नहीं, बल्कि चुनावी भूगोल में भी दिखाई देता है। वे प्रशासनिक निर्णयों को राजनीतिक पूंजी में बदलने की कला जानते हैं। यह कौशल भारतीय लोकतंत्र में नया नहीं है, पर इसकी तीव्रता और तकनीकी दक्षता मोदी काल में असाधारण है। बूथ-स्तर संगठन, डेटा-आधारित चुनावी रणनीति, सामाजिक समूहों का सूक्ष्म प्रबंधन, और राष्ट्रीय नेतृत्व की केंद्रीकृत छवि-इन सबने मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें शासन राजनीतिक वैधता को मजबूत करता है, और राजनीतिक वैधता शासन को और निर्णायक बनाती है।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का
प्रशासनिक कौशल भारत में
शासन के एक ऐसे मॉडल का
प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें
नेतृत्व, प्रबंधन, तकनीक, कूटनीति
और राजनीति का सशक्त समन्वय
दिखाई देता है। उन्होंने प्रशासन
को अधिक गतिशील, अधिक
दृश्यमान और अधिक जन-केंद्रित
बनाने का प्रयास किया।



निजीकरण, मतदाता को यह महसूस कराना कि योजना “सरकार” ने नहीं, “नेतृत्व” ने दी है। तीसरा, संगठन और चुनावी मशीनरी का अभूतपूर्व समन्वय, जहां शासन की उपलब्धियां सीधे राजनीतिक अभियान की सामग्री बन जाती हैं।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासनिक कौशल केवल सचिवालयों में नहीं, बल्कि चुनावी भूगोल में भी दिखाई देता है। वे प्रशासनिक निर्णयों को राजनीतिक पूंजी में बदलने की कला जानते हैं। यह कौशल भारतीय लोकतंत्र में नया नहीं है, पर इसकी तीव्रता और तकनीकी दक्षता मोदी काल में असाधारण है। बूथ-स्तर संगठन, डेटा-आधारित चुनावी रणनीति, सामाजिक समूहों का सूक्ष्म प्रबंधन, और राष्ट्रीय नेतृत्व की केंद्रीकृत छवि-इन सबने मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें शासन राजनीतिक वैधता को मजबूत करता है, और राजनीतिक वैधता शासन को और निर्णायक बनाती है।

प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी शक्ति यह रही है कि उन्होंने भारतीय राज्य को “धीमा”, “प्रतिक्रियाशील” और “फाइल-प्रधान” छवि से निकालकर “सक्रिय”, “दृश्यमान” और “परिणामोन्मुख” रूप देने की कोशिश की। उन्होंने प्रशासन में तकनीक, प्रत्यक्ष निगरानी, अभियान-आधारित क्रियान्वयन और व्यक्तिगत नेतृत्व की ऊर्जा डाली। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें केवल सफल राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि एक कुशल प्रबंधक भी मानते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रशासनिक कौशल भारत में शासन के एक ऐसे मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें नेतृत्व, प्रबंधन, तकनीक, कूटनीति और राजनीति का सशक्त समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने प्रशासन को अधिक गतिशील, अधिक दृश्यमान और अधिक जन-केंद्रित बनाने का प्रयास किया। हालांकि उनके आलोचकों के अनुसार, उनकी प्रशासनिक शैली की सीमाएं भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासनिक कौशल का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन इस स्वीकारोक्ति में है कि उन्होंने भारत के शासन को तेज, अधिक तकनीकी, अधिक राजनीतिक और अधिक दृश्य बनाया-पर अब यह देखना शेष है कि यह मॉडल भारत को कितना अधिक संस्थागत, समावेशी और दीर्घकालीन रूप से सशक्त बना पाता है। इतिहास में उनकी अंतिम पहचान इसी संतुलन से तय होगी।

(लेखक नियमित स्तंभकार और नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)



विकसित भारत



डॉ. नागेश्वर राव
पूर्व कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

क्रांतिकारी बदलाव की ओर

दूरस्थ-ऑनलाइन शिक्षा

भारत में दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा का विकास केवल तकनीकी परिवर्तन का प्रसंग नहीं है, बल्कि यह अवसर, समता और शैक्षिक न्याय को व्यापक बनाने का एक राष्ट्रीय प्रयास है। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने का महत्वपूर्ण संसाधन है।

पिछले एक दशक में जिस तेजी से डिजिटल मंचों, मुक्त संसाधनों, टेली प्रसारण और विनियमित ऑनलाइन कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है, उसने उच्च शिक्षा की प्रकृति ही बदल दी है। अब शिक्षा किसी एक परिसर, किसी एक समय या किसी एक माध्यम की परिधि में बंधी नहीं रह गई है। इस क्षेत्र में जो नीतिगत, संस्थागत और डिजिटल परिवर्तन हुए हैं, इसने उच्च शिक्षा के स्वरूप को अधिक लचीला, अधिक समावेशी और अधिक जनोन्मुख बना दिया है। इनमें से 10 प्रमुख परिवर्तनों की संक्षिप्त नीति आधारित रूपरेखा प्रस्तुत करना इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है :



नई शिक्षा नीति में नीति के स्तर पर एक खुलापन है और छात्रों के लिए उपलब्ध विकल्पों में भी खुलापन दिखता है। एक से ज्यादा एंट्री और एग्जिट जैसे विकल्प छात्रों को एक कक्षा और एक पाठ्यक्रम में रहने के बंधन से आजाद करेंगे। इसी तरह आधुनिक तकनीक आधारित क्रेडिट सिस्टम का एकेडमिक बैंक एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। इससे छात्रों में अपने स्ट्रीम और विषयों का चुनाव करने को लेकर आत्मविश्वास आएगा। 'सफल' (लर्निंग लेवल के विश्लेषण के लिए स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट) परीक्षा का डर दूर करेगा। इन नए कार्यक्रमों में भारत का भाग्य बदलने की क्षमता है।

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

1. स्वयम् (SWAYAM)

स्वयम् भारत का प्रमुख स्वदेशी 'मूक' (MOOC) मंच है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया। इस व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ सात जुलाई, 2017 को हुआ था। इस व्यवस्था में अधिकतर विषयों में प्रवेश की कोई अर्हता नहीं है। यह व्यवस्था किसी भी अभ्यर्थी को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने को बाध्य नहीं करती। केवल संबंधित विषय के इच्छित प्रश्नपत्र को पढ़ना पड़ता है। वर्ष में दो बार प्रवेश होता है, जुलाई-अगस्त और जनवरी-फरवरी। जनवरी 2026 तक इस मंच पर 18500 से अधिक पाठ्यक्रम विकसित किए जा चुके थे और इसमें 6.1 करोड़ नामांकन हुए। इसी प्रकार 53.7 लाख से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए। वर्तमान में 1930 पाठ्यक्रम और लगभग 52.1 लाख से अधिक वर्तमान नामांकन का उल्लेख है। स्वयम् (SWAYAM) की सबसे बड़ी शक्ति इसकी बहुस्तरीय पहुंच है, जिसमें विद्यालय स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के विषय शामिल हैं। इसमें वीडियो व्याख्यान, ई-सामग्री, चर्चा मंच, स्वमूल्यांकन, अंतिम परीक्षा एवं क्रेडिट अर्जन जैसी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं। यह मंच किसी भी आयु, पृष्ठभूमि या भौगोलिक स्थिति के शिक्षार्थी को अपनी गति से सीखने का अवसर देता है। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रबंधन, वाणिज्य, विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान और शिक्षक शिक्षा जैसे विविध अनुशासनों के पाठ्यक्रमों में निहित विभिन्न विषयों को उपलब्ध कराकर इसने गुणवत्तापूर्ण ज्ञान को विश्वविद्यालय के परिसरों की परिधि से बाहर निकाला है। कई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे भाषायी न्याय का प्रश्न भी आंशिक रूप से संबोधित हुआ है। यह मंच यूजीसी, एआईसीटीई, सीईसी, इग्नू, आईआईएमबी, एनपीटीईएल, एनसीईआरटी, एनआईओएस आदि राष्ट्रीय समन्वयकों के सहयोग से संचालित होता है। इसकी व्यापकता ने दूरस्थ शिक्षा को केवल सहायक विकल्प नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के मुख्य प्रवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। स्वयम् कोर्सेज निःशुल्क हैं, जबकि प्रमाणपत्र के लिए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। यह संरचना केवल पहुंच नहीं, बल्कि शैक्षिक उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करती है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नाम व ईमेल आवश्यक होता

है। स्वयम् पोर्टल पर ही वीडियो, पाठ्यसामग्री उपलब्ध होने के साथ चर्चा भी होती है। परीक्षा राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कराती है। हाल ही में यह कार्य संबंधित शैक्षिक संस्थानों को सौंपा गया है। जब हजारों विषयों में पाठ्यक्रम उपलब्ध हों, तब विद्यार्थी अपनी रुचि, समय और लक्ष्य के अनुसार अध्ययन का रास्ता चुन सकता है।

2. सीधे घर पर चैनल (Direct to Home Channel)

टी.वी. के माध्यम से शिक्षा के प्रसारण हेतु आज 280 चैनल उपलब्ध हैं। इसमें से 40 चैनल उच्च शिक्षा के लिए हैं, जिन्हें 'स्वयम् प्रभा' के नाम से सात जुलाई, 2017 को प्रारंभ किया गया। शेष 240 चैनल में 'पीएम ईविद्या (PM eVidya) के नाम से 200 एवं साथी के नाम से 40 चैनल कार्यरत हैं। आईआईटी कानपुर के सहयोग से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 40 चैनलों (SATHEE) का प्रसारण किया जाता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 200 चैनल (PM eVidya) का प्रयोग होता है। इन्हें डी.टी.एच. (Direct to Home) चैनल के नाम से भी जानते हैं। इन चैनलों द्वारा शिक्षा प्रसारण से शिक्षार्थी घर पर बैठकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इस प्रक्रिया में यूजीसी, एआईसीटीई, सीईसी, आईआईटी, इग्नू एवं कुछ बड़े विश्वविद्यालय समन्वय का कार्य करते हैं। यह इन्फ्लिबनेट (Inflibnet) अहमदाबाद द्वारा परिचालित की जाती है। 'स्वयम् प्रभा' नाम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 40 डीटीएच चैनलों का एक समूह कार्यरत है, जो चौबीसों घंटे उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है। उच्च शिक्षा के लिए समर्पित चैनलों पर पाठ्यक्रम आधारित व्याख्यान, पुनरावृत्ति, विषय विशेष कार्यक्रम, परीक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम आदि का प्रसारण होता है। यह पहल विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है, जिनके पास स्थिर इंटरनेट, महंगे उपकरण या निरंतर डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। 'स्वयम् प्रभा' ने इस रूप में डिजिटल समावेशन को एक व्यावहारिक धरातल प्रदान किया है, जहां उपग्रह प्रसारण और वेबकास्ट मिलकर शिक्षा का बहु-माध्यमी वितरण सुनिश्चित करते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह प्रसारण जीसैट-15 उपग्रह के माध्यम से होता है और यह प्रसारण प्रतिदिन लगभग चार घंटे नयी तथा शेष समय में पुनर्प्रसारित होती है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी सुविधा अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। प्रस्तुतीकरण में उच्च शिक्षा खंड के लिए लगभग 1,20,600 शीर्षकों के वीडियो, तीन लाख से अधिक मासिक डीटीएच दर्शकों और 7.4 करोड़ से अधिक यूट्यूब व्युअर्स का उल्लेख किया गया है। यह मॉडल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां वे नियमित शिक्षा संस्थानों के द्वारा उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

3. स्वयम् प्लस (SWAYAM Plus)

कौशल, उद्योग संबद्धता और रोजगारपरक अधिगम के मंच स्वयम् प्लस का शुभारंभ 27 फरवरी, 2024 को किया गया था। यह मंच विद्यार्थियों, कामकाजी पेशेवरों, गृहिणियों और आजीवन शिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम प्रदान करना नहीं, बल्कि उद्योग की वास्तविक जरूरतों से शिक्षा को जोड़ना है। इसमें 100 से अधिक सझेदार संस्थान और उद्योग सहयोगी जुड़े हुए हैं, जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें विनिर्माण, ऊर्जा, आईटी, प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, वित्त तथा कौशल-आधारित प्रशिक्षण जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। मंच की विशेषता यह है कि इनके पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। इसके तहत अपनी सुविधानुसार सीखने की व्यवस्था प्रदान की जाती है। इससे उच्च शिक्षा और कार्यक्षेत्र के बीच की दूरी कम होती है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से शिक्षण पथ निश्चित किया जाता है। केपीएमजी, लार्सन एंड टब्रो, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, टिस, आईकेएस, जीयूवीआई, इंग्लिश हेलपर, आईसीएसआई, अर्थ निर्मिति, इंटरनेटशाला, इंटेल आदि संस्थान इस शिक्षण व्यवस्था में सहयोग करते हैं। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों की



स्कूल का पहला दिन केवल एक शुरुआत नहीं है, बल्कि यह छात्रों के बीच एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है जिसे उनके भीतर गहराई से समाहित करने की आवश्यकता है। एनईपी 2020 के तहत भारत बुनियादी साक्षरता और तनावमुक्त शिक्षण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हुए जिज्ञासा और समग्र विकास को निरंतर बढ़ावा दे रहा है।
-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अवधि 30 से 90 घंटे की होती है। इससे एकाउंटिंग, पीपीटी डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया प्रबंधन, काल सेंटर आदि के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। स्वयम्प्लस की एक और विशेषता यह है कि यह उद्योगों से जुड़े डिजाइन पर आधारित है, इसलिए इसके पाठ्यक्रम न केवल कौशल सिखाते हैं, बल्कि कार्यस्थल की अपेक्षाएं, डिजिटल आत्मविश्वास और अनुपयुक्त अधिगम को भी साथ लाते हैं।

4. दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था की मान्यता

2017 से पूर्व दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था की मान्यता का कार्य इग्नू देखा करता था। 2017 में पहली बार यूजीसी ने दूरस्थ शिक्षा संस्थान एवं उसके कार्यक्रमों की मान्यता के संबंध में एक नियमन तैयार किया, जिसे एक जुलाई, 2018 से पूरे देश में लागू किया गया। 2020 में इस नियमन को पुनः संशोधित एवं परिमार्जित किया गया। इस नियमन के अंतर्गत वे सभी विश्वविद्यालय जो पहले दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाते थे, उनके कार्यक्रमों की मान्यता की विस्तृत रूपरेखा तय की गयी। अध्ययन केंद्र की अर्हतायें, पाठ्य-सामग्री के निर्माण के दिशा निर्देश, शिक्षक संख्या, प्रशासनिक व तकनीक तंत्र, परीक्षाएँ, परामर्श सत्र आदि के संबंध में उपयुक्त व्यवस्थाएँ की गईं। 2020 के विनियमन में पहली बार इन मान्य कार्यक्रमों की उपाधि को शैक्षिक संस्थाओं के परंपरागत/नियमित (रेगुलर) कार्यक्रमों की उपाधि के समतुल्य माना गया है। दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों को भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति की व्यवस्था इस विनियमन में भी की गई है। शैक्षिक संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने की वैधानिक मान्यता शिक्षार्थियों के लिए लाभकारी होती है। परंपरागत विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए निर्धारित अर्हताएँ होना आवश्यक है। इस विनियमन के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यक्रमों (फार्मसी, विधि, कृषि, अभियांत्रिकी आदि) को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से चलाने की अनुमति नहीं है।

5. ऑनलाइन पाठ्यक्रम

2018 में पहली बार उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाने की वैधानिक व्यवस्था के लिए यूजीसी ने विनियमन किया। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चार सितंबर, 2020

को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम, 2020 को अधिसूचित किया। इनके माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक तय किए गए। विनियमन के अनुसार जिन संस्थानों का नैक स्कोर 3.26 या उससे अधिक है अथवा जो एनआईआरएफ (NIRF) में शीर्ष 100 में आते हैं, वे यूजीसी में सिर्फ शपथपत्र देकर ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। जिन संस्थानों का नैक स्कोर 3.01 से 3.26 के बीच है, उन्हें यूजीसी में समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर एवं प्रस्तुत होकर विशिष्ट अनुमति लेनी होती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य गुणवत्ता और पहुंच के बीच संतुलन बनाना है। साथ ही, एलएमएस, ई-सामग्री, स्व-अध्ययन सामग्री, वचुअल कक्षाएं और चार-चतुर्थांश वितरण प्रणाली जैसे घटकों को अनिवार्य रूप में रखा गया है। यह व्यवस्था ऑनलाइन शिक्षा को अनियंत्रित विस्तार से बचाकर मानकीकृत दिशा देती है। अब तक लगभग 300 से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान एवं 200 से ज्यादा ऑनलाइन स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ हो चुके हैं। विज्ञान के कार्यक्रमों में लैब आधारित पाठ्यक्रमों के लिए कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर के आधार पर प्रैक्टिकल परीक्षाएँ लेने की व्यवस्था है। विनियम में पूर्णकालिक निदेशक, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्वविनियम तंत्र, ई-शिक्षण सामग्री, चार चतुर्थांश पद्धति और 2024 से एबीसी आधारित डीईबी आईडी जैसी व्यवस्थाएं इस तंत्र को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बना रही हैं।

6. भारत की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी

एनडीएलआई (NDLI) भारत के डिजिटल ज्ञान तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे आईआईटी खड़गपुर में विकसित किया गया है और यह 24x7 निःशुल्क उपलब्ध ज्ञान मंच के रूप में कार्य करता है। प्रस्तुतीकरण में 10 करोड़ से अधिक पुस्तकों, लगभग 100 से ज्यादा देशी एवं विदेशी भाषाओं में उपलब्ध 11.5 करोड़ की पाठ्य-सामग्री और 5,400 एनडीएलआई क्लब्स का उल्लेख है। एनडीएलआई में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित, विधि, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों की व्यापक सामग्री उपलब्ध है। यह मंच विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की पुस्तकें व पत्रिकाओं का विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराता है। एनडीएलआई क्लब्स के माध्यम से संस्थानों में अध्ययन संस्कृति और डिजिटल सहभागिता को भी प्रोत्साहन मिलता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2024 के आसपास 5,800 से अधिक संस्थानों तथा लगभग 17 लाख सदस्यों की सहभागिता का उल्लेख मिलता है। एनडीएलआई की विशालता केवल किताबों और आलेखों की संख्या में नहीं, बल्कि उसकी विविधता में भी है। जब एक ही मंच पर स्कूल स्तर, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, पेटेंट और मानक, सांस्कृतिक अभिलेखागार और समाचार पत्र उपलब्ध हों, तब यह मंच





राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 21वीं सदी के भारत के निर्माण का आधार और एक "बौद्धिक पुनर्जागरण" (Intellectual Renaissance) है। इसका उद्देश्य शिक्षा को रटने के बजाय "कैसे सोचें" (How to think) पर केंद्रित करना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, कौशल विकास और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

एक बड़े राष्ट्रीय ज्ञान संसाधन के रूप में व्यवहार करता है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक कोश के रूप में भी देखा जा सकता है।

7. प्रत्यायन (Accreditation)

दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन यानी एक्रिटेशन की प्रक्रिया 2018 के फरवरी में प्रारंभ की गई थी। परंपरागत विश्वविद्यालयों की भांति नैक से एक्रिटेशन की सात सुस्पष्ट मानकों के आधार पर दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में 2021 से इसको लागू कर दिया गया। सारे मुक्त विश्वविद्यालयों ने प्रत्यायन व्यवस्था का पूर्ण पालन किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि पाठ्यक्रम विवरण, शिक्षण-सीखना प्रक्रिया, भौतिक एवं शैक्षिक अधोसंरचना, प्रशासन, श्रेष्ठ परंपराएं, शिक्षक सहायता, शिक्षार्थी सहायता आदि का स्तर सुनिश्चित रहे। प्रत्यायन केवल औपचारिक स्वीकृति नहीं, बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता का आधार है। जब संस्थान मानक प्रक्रिया और सतत मूल्यांकन से गुजरते हैं, तब उनकी ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत बनती है।

8. दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग

(NIRF Ranking of Distance Education Institutions)

एनआईआरएफ (National Institutional Ranking Framework) को भारत सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों की तुलनात्मक गुणवत्ता के लिए अपनाया है। इसके माध्यम से भारत में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के साथ-साथ अभियांत्रिकी, प्रबंधन, चिकित्सा, विधि, वास्तुकला, फार्मेसी, दंत, शोध आदि के संस्थानों की भी राष्ट्रीय रैंकिंग प्रकाशित की जाती है। दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता का परीक्षण करने एवं विभिन्न दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों की तुलनात्मक स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार ने परंपरागत शिक्षण संस्थानों के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों की एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 से प्रारंभ कर दी है। इससे इस क्षेत्र को समान मूल्यांकन का मंच मिलता है और गुणवत्ता के प्रति प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनता है।

9. क्रेडिट अंतरण (Credit Transfer)

क्रेडिट अंतरण ने दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा को वास्तविक लचीलापन दिया है। यूजीसी ने स्वयम्

आधारित पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अर्जन और अंतरण की व्यवस्था को व्यापक बनाया, जिससे विद्यार्थी अपने कार्यक्रम का 40 प्रतिशत तक ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर अपना क्रेडिट अंतरण कर सकते हैं। वर्ष 2021 से यह सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला। अकादमिक क्रेडिट बैंक के माध्यम से विद्यार्थी अपना अर्जित क्रेडिट सुरक्षित रख सकते हैं और आगे के अध्ययन में उनका उपयोग कर सकते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो ऐसी नौकरी में हैं, जो स्थानांतरित होते रहते हैं या अपने अध्ययन की प्रक्रिया को लचीला बनाना चाहते हैं। क्रेडिट अंतरण व्यवस्था परंपरागत विश्वविद्यालयों के विषयों का दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षण संस्थाओं के विषयों के साथ भी जोड़ी जा सकती है। इससे विद्यार्थी अब एक ही संस्थान या एक ही शिक्षण प्रारूप तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे अपनी शैक्षिक यात्रा को अधिक लचीला, बहु-स्रोत और आवश्यकता आधारित बना सकते हैं।

10. मातृभाषा में दूरस्थ शिक्षा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल और प्रोत्साहन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा में पाठ्य-सामग्री, शिक्षण व परीक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। दूरस्थ शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों ने अपने-अपने राज्य में मातृभाषा में पाठ्य-सामग्री का निर्माण किया है, परीक्षाओं के उत्तर भी मातृभाषा में लिखे जा रहे हैं। परामर्श सत्र भी मातृभाषा में हो रहे हैं। 'स्वयम् प्रभा' के माध्यम से भी पूरे देश में मातृभाषा में परामर्श सत्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। मातृभाषा आधारित ओडीएल शिक्षा का सबसे मानवीय और समावेशी पहलू है। जब पाठ्य सामग्री, शिक्षण और परीक्षा विद्यार्थी की अपनी भाषा में उपलब्ध होती है, तब समझ, सहभागिता और आत्मविश्वास तीनों बढ़ते हैं। स्वयम्, स्वयम् प्रभा और एनडीएलआई जैसे मंचों पर क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह केवल भाषायी सुविधा का प्रश्न नहीं, बल्कि बौद्धिक न्याय का प्रश्न है। मातृभाषा में शिक्षा से ग्रामीण, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी और कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी भी अधिक सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के भी अनुरूप है, जो मातृभाषा को अवरोध नहीं, अवसर मानती है।

समग्र रूप से देखा जाए तो भारत में दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा का परिदृश्य एक गहन संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर चुका है। स्वयम् ने ज्ञान की पहुंच को जनतांत्रिक बनाया, स्वयम् ने डिजिटल विषमता के बीच वैकल्पिक वितरण तंत्र दिया, स्वयम् प्लस ने उद्योग और रोजगार से



‘स्वयम् प्रभा’ के तहत उपग्रह प्रसारण और वेबकास्ट सुनिश्चित किया गया है। यह प्रसारण जीसैट-15 उपग्रह के माध्यम से होता है और प्रतिदिन चार घंटे नया तथा शेष समय में पुनर्प्रसारित होता है, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा अनुसार सीखने का अवसर मिलता है।



शिक्षा के माध्यम के रूप में
मातृभाषा पर जोर देने से गरीब,
ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि
के छात्रों में आत्मविश्वास पैदा
होगा। यहां तक कि प्राथमिक
शिक्षा में भी मातृभाषा को बढ़ावा
दिया जा रहा है और 'विद्या प्रवेश
कार्यक्रम' इसमें बड़ी भूमिका
निभाएगा।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



जोड़कर शिक्षण को अधिक परिणाममुखी बनाया, यूजीसी के विनियमों ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता की रूपरेखा गढ़ी, क्रेडिट ट्रांसफर ने शिक्षण को लचीला बनाया, और एनडीएलआई ने ज्ञान संसाधनों को एक विस्तृत राष्ट्रीय भंडार में रूपांतरित किया। दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के लिए नैक व एनआईआरएफ का गुणवत्ता तंत्र, मातृभाषा में पाठ्य-सामग्री, परामर्श व परीक्षा ने इस शिक्षण व्यवस्था को प्रभावपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण बनाया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा ने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को केवल विस्तृत ही नहीं किया, बल्कि उसे अधिक समावेशी, उत्तरदायी, बहुभाषिक, प्रौद्योगिकी समर्थ और भविष्य उन्मुख भी बनाया है। आने वाले वर्षों में यदि इन पहलुओं को भाषायी गहराई, स्थानीय संदर्भ, बेहतर डिजिटल अधोसंरचना और संस्थागत नवाचार के साथ आगे बढ़ाया गया, तो यह परिवर्तन सचमुच शैक्षिक पुनर्जागरण का रूप ले सकता है। इस प्रकार की पहल से उपलब्ध शिक्षा की अधोसंरचना भारत के प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों को अभिप्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।



(लेखक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के भी कुलपति रह चुके हैं। वे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली के निदेशक भी रहे हैं।)



विकसित भारत



सौरभ श्रीवास्तव

वरिष्ठ पत्रकार, मेट्रो एडिटर-दैनिक
जागरण, दिल्ली-एनसीआर

संवाद में प्रभाव भी और प्रेरणा भी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व जितना प्रभावी नजर आता है, उनके भाषण भी उतने ही प्रभावी और दूर तक असर छोड़ने वाले होते हैं। जब वे संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलते हैं तो उनके भाषण को दुनिया गौर से सुनती है। विदेश में भारतीयों को संबोधित करते हैं तो देश से हजारों किलोमीटर दूर मोदी मोदी के नारे लगते हैं, जो देश के बाहर भी उनके प्रभाव को दर्शाता है। वैश्विक समुदाय को वह दुनिया के प्रति भारत की वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि भारत का लक्ष्य सिर्फ अपना विकास नहीं, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण है। वहीं, सख्त लहजे में और स्पष्ट शब्दों में वे आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा खतरा बताते हैं और इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए दुनिया का आह्वान करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को संबोधित करते हुए मोदी कहते हैं कि भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज इस वैश्विक मंच पर मानवता के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। हमारा देश 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना में विश्वास करता है यानी पूरा विश्व एक परिवार है। आपसी



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पारंपरिक संबोधनों और चुनावी भाषणों के अलावा 'मन की बात' और 'परीक्षा पर चर्चा' जैसे कार्यक्रमों के जरिये भी जनता से लगातार संवाद करते रहते हैं। ये संवाद प्रभावी तो होते ही हैं, प्रेरणाप्रद भी होते हैं और लोगों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी का अहसास भी कराते हैं।

सहयोग पर जोर देते हुए वे कहते हैं कि आज दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और महामारी। इन समस्याओं का समाधान केवल सहयोग और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। भारत ने हमेशा शांति, सह-अस्तित्व और विकास के मार्ग को अपनाया है। हमने कोरोना के कठिन समय में भी अनेक देशों को दवाएं और टीके उपलब्ध कराए। यह हमारी 'मानवता पहले' की सोच को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन की जटिल समस्या पर मोदी दुनिया को आगाह करते हुए जवाबदेह बनने का अनुरोध करते हैं, साथ ही इसे लेकर वह भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। वे कहते हैं कि विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती है। भारत ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह, आतंकवाद को मोदी पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। उनके अनुसार, आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति और कोई सीमा नहीं होती। इसे किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि 'अच्छा आतंकवाद' और 'बुरा आतंकवाद' जैसी कोई अवधारणा नहीं हो सकती। भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है। हमने अपने अनेक निर्दोष नागरिकों को इस हिंसा में खोया है, इसलिए हम इस पीड़ा को गहराई से समझते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि हमें आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया है कि पूरा विश्व एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या उसे शरण देते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराना होगा। हमें आतंकवाद के खिलाफ एक साझा रणनीति बनानी होगी, सूचनाएं साझा करना, वित्तीय सहायता रोकना और कठोर अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करना आवश्यक है। इस सबके बीच वे संयुक्त राष्ट्र को समय के साथ बदलने के साथ ही और अधिक प्रभावी बनाने की भी वकालत करते हैं। मोदी कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह 21वीं सदी की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। वे विश्व समुदाय से आग्रह करते हैं कि आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जो सुरक्षित, समृद्ध और शांतिपूर्ण हो।

विदेश में मोदी जब भारतीयों को संबोधित करते हैं तो वे उन्हें भारत की मिट्टी से जोड़ते और भारत की बदलती तस्वीर दिखाते हुए गौरवान्वित महसूस कराते नजर आते हैं। मोदी कहते हैं कि आप सभी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से यहां अपनी पहचान बनाई है, और साथ ही भारत का नाम

भी रोशन किया है। आज भारत तेजी से बदल रहा है। 130 करोड़ भारतीय एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। हमारा देश विकास के नए आयाम छू रहा है, चाहे वह डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। आज का भारत निर्णायक सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, पारदर्शिता बढ़ाई है और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मैं आप सभी भारतीयों से कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को आगे बढ़ाते रहें। आप भारत के सच्चे ब्रांड एंबेसडर हैं। साथ ही वे विदेश में बसे भारतीयों से आग्रह करते हैं कि आइए, हम सब मिलकर एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें।

देश में जब मोदी योग की बात करते हैं तो उनकी बात का प्रभाव ऐसा होता है कि देश ही नहीं, पूरा विश्व योग की मुद्रा में खड़ा नजर आता है। आज की तेज भागती ज़िंदगी में योग का महत्व बताते हुए वे कहते हैं कि योग केवल व्यायाम नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक अद्भुत माध्यम है। योग हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बनाकर जीवन जी सकते हैं। यह हमें तनाव से मुक्ति देता है, शांति और संतुलन प्रदान करता है। मोदी कहते हैं कि आज के समय में जब पूरी दुनिया भागदौड़ और तनाव से जूझ रही है, योग एक समाधान बनकर उभरा है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। वह सभी से आग्रह करते हैं कि लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। सब मिलकर 'योग से निरोग' का संकल्प लें और एक स्वस्थ, सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दें। उनकी बात का यह असर होता है कि देश में योग की लहर नजर आती है, वहीं भारतीय संस्कृति की यह अमूल्य निधि भारत के बाहर विभिन्न देशों में भी तेजी से अपना स्थान लेने लगती है।

जब वे स्वच्छता की बात करते हैं, तो देश में स्वच्छता को लेकर जागरूकता आती है और लोग उनकी प्रेरणा से स्वच्छता के प्रयासों में जुटते हैं। मोदी कहते हैं कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं है, यह एक संस्कार है, एक जिम्मेदारी है। जब हमारा घर साफ होता है तो हमें अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब हमारा देश साफ-सुथरा होगा तभी हम एक सशक्त और विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं, बल्कि लोगों की सोच को बदलना है। जब तक हर नागरिक यह न ठान ले कि वह गंदगी नहीं फैलाएगा, तब तक यह अभियान सफल नहीं हो सकता। वह आग्रह करते हैं कि सभी लोग अपने आसपास सफाई रखें, कचरा इधर-उधर न फैलाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह छोटा-सा प्रयास देश को एक नई दिशा दे सकता है। पीएम मोदी कहते हैं कि आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे। उनके इस प्रेरक भाषण का परिणाम यह निकलता है कि देश में स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता आती है और घर-घर इसकी चर्चा शुरू होती है, स्वच्छता की नई राह खुलती है।

कोरोना काल में मोदी जब चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों के योगदान के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए एक नियत समय पर ताली व थाली बजाने की अपील करते हैं तो पूरे देश में लोग अपने घर के दरवाजों या बॉलकनी में खड़े होकर ताली और थाली बजाकर कृतज्ञता दर्शाते हैं। लोगों को संबोधित करते हुए मोदी कहते हैं कि आज पूरा विश्व एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। कोरोना ने मानव जीवन को चुनौती दी है। ऐसे समय में हमारे देश के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग दिन-रात हमारी सेवा में जुटे हुए हैं। ये सभी लोग अपने परिवारों से दूर रहकर, अपनी जान की परवाह किए बिना, देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं। उनका यह त्याग और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं आप सभी से एक विशेष आग्रह करता हूँ कि आने वाले रविवार को, शाम पांच बजे, अपने-अपने घरों के दरवाजे, बॉलकनी या खिड़कियों पर खड़े होकर, पांच मिनट तक ताली, थाली, घंटी या शंख बजाकर इन



हमारे किसान देश के
अन्नदाता हैं। वे कठिन
परिस्थितियों में भी मेहनत
करते हैं और पूरे देश का पेट
भरते हैं। हमें उनके योगदान
का सम्मान करना चाहिए
और उन्हें आधुनिक तकनीक
और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध
कराने के लिए निरंतर प्रयास
करना चाहिए।
—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करें। यह केवल धन्यवाद देने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे सामूहिक संकल्प और एकजुटता का प्रतीक भी होगा। इससे उन सभी लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो इस कठिन समय में देश की सेवा कर रहे हैं। वह आग्रह करते हैं कि आइए, हम सब मिलकर इस संकट की घड़ी में एकजुटता का परिचय दें और अपने कर्तव्य का पालन करें। इसके बाद जो होता है वो सिर्फ भारत ने ही नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह उस रविवार को शाम पांच बजे पूरे देश के लोगों ने अपने घरों की बालकनी, दरवाजे व खिड़कियों पर खड़े होकर पांच मिनट तक ताली, थाली, घंटी और शंख बजाए।

ऐसा नहीं है कि पूर्व में ऐसे उदाहरण नहीं हैं। 1965 में खाद्य संकट से जूझ रहे भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर देशवासियों ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखकर एकता और अनुशासन का अभूतपूर्व परिचय दिया था। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषण ने जनता को संयम और साहस बनाए रखने की प्रेरणा दी थी, साथ ही सेना के मनोबल को भी मजबूत किया था। दूसरी ओर, इस युद्ध को मानवता व न्याय के लिए लड़ाई बताते हुए बांग्लादेश के लोगों के अधिकारों का समर्थन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके प्रभावी भाषणों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इन नेताओं का जनता से संवाद मुख्यतया पारंपरिक अवसरों पर ही हुआ करता था, लेकिन मोदी पारंपरिक संबोधनों और चुनावी भाषणों से इतर 'मन की बात' और 'परीक्षा पर चर्चा' जैसे कार्यक्रमों के जरिये भी जनता से लगातार संवाद करते रहते हैं। ये संवाद प्रभावी तो होते ही हैं, प्रेरणाप्रद भी होते हैं और लोगों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी का अहसास भी कराते हैं। 'मन की बात' श्रृंखला के प्रत्येक कार्यक्रम में मोदी किसी न किसी व्यक्ति की सफलता की कहानी अवश्य सुनाते हैं। आमतौर पर वह व्यक्ति हमारे आपके बीच से निकला हुआ एक सामान्य इंसान होता है जो अपनी सोच, अपनी मेहनत व लगन से एक ऐसा कार्य करता है, जो छोटा ही सही, लेकिन राष्ट्र सेवा में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे छोटे-छोटे उदाहरणों से वे बताते हैं और आम लोगों को प्रेरित करते हैं कि कोई बड़ा काम करना ही राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र निर्माण में योगदान देना नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति सीमित संसाधनों के साथ भी यदि कोई ऐसा काम करता है, जो उसके क्षेत्र या आसपास के लोगों का जीवन आसान करने या बेहतर करने में मददगार साबित हो तो ये भी राष्ट्र निर्माण में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। मोदी

'मन की बात' में देश के किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को भारत की असली ताकत बताकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वे जनता से अपील करते हैं कि इनका सम्मान करें और इन्हें पूरा सहयोग दें। पीएम मोदी कहते हैं कि आज मैं उन लोगों की चर्चा करना चाहता हूँ जो हमारे देश की असली ताकत हैं, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई-बहन और हमारे छोटे व्यापारी। हमारे किसान देश के अन्नदाता हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। हमें उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आधुनिक तकनीक व बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

हमारे श्रमिक, जो अपने पसीने से देश के निर्माण में लगे हैं, वे भारत की प्रगति के असली शिल्पकार हैं। चाहे वह सड़कें बनाना हो, घर बनाना हो या उद्योगों में काम करना, उनका योगदान अमूल्य है। छोटे कारोबारी और उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और नवाचार से लाखों लोगों को रोजगार दिया है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई नीतियों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम इन तीनों वर्गों, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का सम्मान करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इनके विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। आइए, हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इनकी ताकत को और बढ़ाएं।

मन की बात में मोदी युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं, ताकि भारत दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले में आकर खड़ा हो सके। वे कहते हैं कि आज का भारत अवसरों से भरा हुआ है। हमारे युवाओं में प्रतिभा है, ऊर्जा है और कुछ नया करने का जुनून है। यही शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आज दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि वे केवल नौकरी ढूँढने वाले न बनें, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।

स्टार्टअप के माध्यम से आप अपनी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। छोटे-छोटे विचार भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है, सरकार भी हर संभव सहायता दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हर युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया है। आप गांव में रहकर भी दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, अपने उत्पाद और सेवाएं वैश्विक स्तर पर पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे नए विचारों पर काम करें, जोखिम उठाने से न डरें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। वे कहते हैं कि याद रखिए, नवाचार ही भविष्य है और आप सभी उस भविष्य के निर्माता हैं। आइए, हम सब मिलकर एक नवाचार-प्रधान, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें।

हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने जा रहे छात्रों के बीच पहुंचकर मोदी का 'परीक्षा पर चर्चा'





‘आज का भारत अवसरों से भरा हुआ है। हमारे युवाओं में प्रतिभा है, ऊर्जा है और कुछ नया करने का जुनून है। यही शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आज दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि वे केवल नौकरी ढूँढने वाले न बनें, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।’

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



कार्यक्रम के जरिये उनसे सीधे संवाद करना न सिर्फ छात्रों को परीक्षा में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि परीक्षा को लेकर उनका तनाव भी कम करता है। पीएम मोदी छात्रों से कहते हैं कि सिर्फ अंक पर ध्यान नहीं दें, सीखने पर ध्यान दें। वे कहते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि परीक्षा को लेकर एक अनावश्यक दबाव बना दिया गया है। अंकों की होड़ में बच्चे अपनी असली प्रतिभा और खुशी को भूल जाते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जीवन केवल अंकों से नहीं चलता। आपके अंक आपके जीवन का अंतिम सत्य नहीं हैं। यह केवल एक पड़ाव है, न कि आपकी क्षमता का पूरा मापदंड। हमें खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। अगर आप हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, तो यही सबसे बड़ी सफलता है। माता-पिता और शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। हर बच्चे की अपनी अलग प्रतिभा होती है, उसे पहचानना और प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। आइए, हम सब मिलकर अंकों की इस होड़ से बाहर निकलें और सीखने को अपना असली लक्ष्य बनाएं। उनकी ये बातें न सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के महत्व को रेखांकित करती हैं, अपितु छात्रों के साथ ही अभिभावकों में भी लगी अंकों की होड़ को हतोत्साहित करती है।

प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह लें, डर के रूप में नहीं। जब आप तनावमुक्त होकर परीक्षा देंगे, तो परिणाम भी बेहतर आएंगे। याद रखिए, असफलता भी हमें कुछ सिखाती है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब वे छात्रों को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए मोबाइल फोन व सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने को कहते हैं तो वे न सिर्फ छात्रों को अपितु, देश के समस्त किशोरों और युवाओं को विचारशील बनने को प्रेरित करते हैं। परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं या दूसरों से नहीं खुद से प्रतिस्पर्धा करें, ये उनके कुछ ऐसे प्रेरक विचार हैं जो सिर्फ परीक्षा में ही नहीं, बल्कि छात्रों को जीवन भर किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएंगे।



(लेखक पिछले करीब तीन दशक से मुख्यधारा की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उन्हें लंबा अनुभव है। संप्रति दैनिक जागरण में दिल्ली एनसीआर के मेट्रो एडिटर हैं।)



विकसित भारत



विवेक शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक

गुलामी की मानसिकता

से मुक्ति का अभियान

केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद राजधानी दिल्ली में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की कई प्रतीकात्मक इमारतों को आधुनिक भारतीय पहचान से जोड़ने की एक व्यवस्थित और दूरदर्शी प्रक्रिया शुरू हुई। यह सिर्फ ईंट-पत्थर का खेल नहीं, बल्कि सदियों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का ऐतिहासिक अभियान है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि से सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने दिल्ली के दिल को नया स्वरूप दिया है। संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं के आसपास नई इमारतें खड़ी की गईं, पुरानी इमारतों को संरक्षित रखते हुए उन्हें संग्रहालय या सार्वजनिक उपयोग में बदल दिया गया। राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित कर और औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर मोदी सरकार ने साबित किया कि भारत अब गुलामी की जंजीरों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। यह परियोजना मात्र निर्माण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वाधीनता, आधुनिक प्रशासनिक दक्षता और विकसित भारत@2047 की दिशा में एक स्वर्णिम कदम है। यह बदलाव



‘राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित कर और औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर मोदी सरकार ने साबित किया कि भारत अब गुलामी की जंजीरों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। सेंट्रल विस्टा परियोजना मात्र निर्माण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वाधीनता, आधुनिक प्रशासनिक दक्षता और विकसित भारत@2047 की दिशा में एक स्वर्णिम कदम है।’



न केवल भौतिक है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जहां पुरानी गुलामी की छाया से मुक्ति मिल रही है और भारतीय सभ्यता की गौरवशाली विरासत को केंद्र में लाया जा रहा है।

विरासत और औपनिवेशिक प्रतीक

दिल्ली की सेंट्रल विस्टा ब्रिटिश राज की सबसे प्रमुख उपलब्धि थी। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के फैसले के बाद ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने 1912-1931 के बीच इस क्षेत्र को डिजाइन किया। राजपथ (तब किंग्स वे) राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबा था, जो ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। संसद भवन (1927 में उद्घाटन) गोलाकार था, जो ब्रिटिश ‘काउंसिल हाउस’ के रूप में बनाया गया था। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ब्रिटिश सचिवालय था, जहां से भारत पर शासन होता था। इन इमारतों में रोमन, ग्रीक और भारतीय मुगल तत्वों का मिश्रण था, लेकिन मूल उद्देश्य ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करना था। यह डिजाइन साम्राज्य की भव्यता दिखाने के लिए था, जहां हर ईंट और मेहराब में विदेशी शासन की यादें बसी थीं।

स्वतंत्रता के बाद भी ये इमारतें अपरिवर्तित रहीं। लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित 552 तक सीमित रहीं, जबकि जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ हो गई। पुरानी इमारत में भूकंप प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी (दिल्ली जोन-IV/V में है), आग की सुरक्षा कमजोर थी और एसी, सीसीटीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ने से संरचना क्षतिग्रस्त हो रही थी। मोदी सरकार ने 2014 से ही नाम परिवर्तन शुरू किए-रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा, लेकिन सेंट्रल विस्टा का व्यापक पुनर्विकास 2019 में शुरू हुआ। यह ‘अमृत काल’ और पंच प्राण (पांच प्रण) का हिस्सा था, जिसमें औपनिवेशिक मानसिकता हटाना दूसरा प्रण था। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा कि “किंग्स- वे या राजपथ, गुलामी का प्रतीक, आज इतिहास बन गया है।” यह परियोजना 20,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली है (कुछ हिस्सों का टेंडर आधारित)।

उद्देश्य और समयरेखा

सितंबर 2019 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य था :

- संसद की क्षमता का विस्तार (2029 के बाद लोकसभा सीटें बढ़ने पर 900+ सदस्यों के लिए जगह)।
- सभी मंत्रालयों को एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में लाना।
- पुरानी इमारतों को संग्रहालय बनाना।
- कर्तव्य पथ को पैदल यात्री-अनुकूल बनाना।
- पर्यावरण अनुकूल, भूकंपरोधी और भारतीय सांस्कृतिक तत्वों वाली इमारतें।

परियोजना 2020-2026 में पूरी होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण कुछ हिस्से 2028 तक विस्तारित हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में 2:1 फैसले से मंजूरी दी। एचसीपी डिजाइन (अहमदाबाद) ने मास्टर प्लान बनाया। प्रमुख घटक : नया संसद भवन, कर्तव्य भवन (10 इमारतें), एकजीक्यूटिव एनक्लेव (सेवा तीर्थ), वीपी एनक्लेव, नॉर्थ-साउथ ब्लॉक को युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। मार्च 2026 तक नया संसद भवन, कर्तव्य पथ, वीपी एनक्लेव, सेवा तीर्थ और कई कर्तव्य भवन (जैसे CCS-1,2,3) तैयार हो चुके थे, जबकि अन्य (CCS-6,7,10) अंतिम चरण में हैं।

नया संसद भवन : आधुनिक भारत का प्रतीक

नया संसद भवन पुराने के बगल में (प्लॉट 118) त्रिभुजाकार बनाया गया, जो 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। 28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें लोकसभा (मोर पंख थीम), राज्यसभा (कमल थीम) और बरगद वृक्ष थीम वाली आंतरिक सज्जा है—ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। छत पर अशोक स्तंभ का सिंह राजसी मुकुट है। भूकंपरोधी, ईको-फ्रेंडली (बिजली खपत 30% कम), 1,272 सीटें (लोकसभा 888, राज्यसभा 384)। सबसे महत्वपूर्ण-संगोल की स्थापना। यह चोल वंश का राजदंड है, जो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, लेकिन भुला दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया और कहा, “यह नया संसद भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का आह्वान करेगा।” निर्माण रिकॉर्ड 28 महीने के समय में हुआ। पुराना संसद अब म्यूजियम बनेगा। संसद की नई इमारत औपनिवेशिक ‘काउंसिल हाउस’ की जगह आधुनिक होने के साथ भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है।





संसद भवन का त्रिकोणीय रूप श्रीयंत्र और त्रिदेव (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) की पवित्र ज्यामिति से प्रेरित है, जो वास्तु में शुभ माना जाता है। इससे स्थिर शासन, बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए ऊर्जा मिलेगी। भवन के छह प्रवेश द्वारों पर वास्तु शास्त्र के अनुसार रक्षक पशु मूर्तियां स्थापित की गई हैं।



वास्तुशास्त्र का भी इस्तेमाल

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बन रही नई इमारतों, खासकर नए संसद भवन में वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखा गया है। वास्तुशास्त्र प्राचीन भारतीय वास्तुकला का विज्ञान है, जो दिशाओं, ऊर्जा प्रवाह (पंच महाभूत- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश), ज्यामिति और स्थान व्यवस्था पर आधारित है। इसका उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा (प्राण शक्ति) का संतुलन बनाना, नकारात्मक प्रभाव दूर करना और समृद्धि, स्थिरता तथा सद्भाव सुनिश्चित करना है। सरकारी दस्तावेजों और विशेषज्ञों के अनुसार, नई इमारतों का डिजाइन इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि शासन व्यवस्था मजबूत और सकारात्मक रहे। प्रख्यात वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ डॉ. जे.पी. शर्मा लालधारेवाले कहते हैं कि नए संसद भवन (त्रिकोणीय आकार की) में वास्तु का सबसे प्रमुख उपयोग दिखाई देता है। पुरानी गोलाकार संसद त्रिकोणीय प्लॉट पर बनी थी, जिसे लालधारेवाले जी ने प्रमुख दोष (ऊर्जा संघर्ष) बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि नया भवन त्रिकोणीय होना चाहिए ताकि ऊर्जा संतुलित हो। भवन का त्रिकोणीय रूप श्रीयंत्र और त्रिदेव (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) की पवित्र ज्यामिति से प्रेरित है, जो वास्तु में शुभ माना जाता है। इससे स्थिर शासन, बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए ऊर्जा मिलेगी। भवन के छह प्रवेश द्वारों पर वास्तु शास्त्र के अनुसार रक्षक पशु मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये मूर्तियां भारतीय संस्कृति, वास्तु और गुणों (बुद्धि, विजय, शक्ति, सफलता) के आधार पर चुनी गई हैं। उत्तर दिशा (बुध ग्रह से जुड़ी, बुद्धि के लिए) पर गज (हाथी) – बुद्धि, धन और स्मृति का प्रतीक। दक्षिण में अश्व (घोड़ा) – सहनशीलता, शक्ति और शासन की गति। पूर्व (सूर्योदय, विजय) में गरुड़ (ईगल) – जन आकांक्षाओं का प्रतीक। उत्तर-पूर्व में हंस (स्वान) – विवेक और ज्ञान। शेष द्वारों पर मकर (एकता में विविधता) और शार्दूल (जन शक्ति)। ये मूर्तियां सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और भवन की रक्षा करती हैं।

लगभग 5,000 कलाकृतियां (चित्र, पैनल, मूर्तियां, धातु कला) पूरे भवन (65,000 वर्ग मीटर) में वास्तु शास्त्र और सनातन परंपरा के अनुरूप लगाई गई हैं। आधिकारिक विजन डॉक्यूमेंट में स्पष्ट लिखा है: “कलाकृतियां और उनकी स्थापना सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही, समग्र थीम वास्तुशास्त्र के अध्ययन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।” कलाकृतियां 5,000 वर्ष की भारतीय सभ्यता, आदिवासी-महिला योगदान, ज्ञान परंपरा, भक्ति, विज्ञान और स्मारकों को दर्शाती

हैं। बरगद का वृक्ष (राष्ट्रीय वृक्ष) वाले खुले क्षेत्र, लोकसभा में मोर और राज्यसभा में कमल थीम भी वास्तु अनुरूप हैं।

अन्य नई इमारतों, जैसे-कर्तव्य भवन (सामान्य सचिवालय), प्रधानमंत्री आवास और कार्यकारी एन्क्लेव में भी परियोजना की समग्र थीम में पारंपरिक भारतीय ज्यामिति और समरसता शामिल है। हालांकि इनमें वास्तु का स्पष्ट उल्लेख कम है, फिर भी उत्तर-दक्षिण अक्ष, सूर्योन्मुखी डिजाइन और हरित क्षेत्र वास्तु के मूल सिद्धांतों (दिशा संतुलन, प्राकृतिक तत्वों का समावेश) से मेल खाते हैं। आर्किटेक्ट बिमल पटेल (HCP Design) ने डिजाइन में ज्यामिति और भारतीय शैलियों को प्राथमिकता दी है, जो वास्तु से प्रेरित है।

वास्तु का यह इस्तेमाल केवल सौंदर्य या परंपरा तक सीमित नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शासन में स्थिरता, बौद्धिक विकास, जन कल्याण और भारत को महाशक्ति बनाने वाली चार प्रमुख वास्तु अवधारणाएं सक्रिय होंगी। ऊर्जा संतुलन के साथ नई इमारतें सकारात्मक वातावरण बनाएंगी। यह परियोजना पर्यावरण अनुकूल भी है—पौधारोपण, सस्टेनेबल मटेरियल और यमुना तक विस्तार।

राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास न केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि वास्तुशास्त्र के माध्यम से भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को भविष्य से जोड़ने का उदाहरण है। इससे राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा, शासन सुचारु होगा और नई पीढ़ी में सनातन मूल्यों का संचार होगा।

संरक्षण से पुनरुत्थान

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के स्थान पर नई इमारतें नहीं खड़ी की गईं, बल्कि उन्हें संरक्षित रखते हुए नई इमारतें आसपास बनाई गईं। ब्रिटिश काल के ये ब्लॉक अब 'युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम' बनेंगे। 80,000 वर्ग मीटर में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थानांतरित होगा (पुराने से तीन गुना बड़ा)। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने 'सेवा तीर्थ' (नया पीएमओ कॉम्प्लेक्स) का उद्घाटन किया, जहां पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्थानांतरित हो गए। साउथ ब्लॉक से पीएमओ सेवा तीर्थ में स्थानांतरित हो गया। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के तहत कर्तव्य भवन-1,2,3 आदि (10 इमारतें) बन रही हैं। अगस्त 2025 में कर्तव्य भवन के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। अप्रैल 2026 तक कई पूरी हो जाएंगी। ये सभी केंद्रीय मंत्रालयों को एक जगह लाएंगी, दक्षता बढ़ाएंगी। पुरानी इमारतों की हेरिटेज संरचना बरकरार रहेगी।




प्रधानमंत्री मोदी ने
'सेवा तीर्थ' (नया
पीएमओ कॉम्प्लेक्स)
का उद्घाटन किया,
जहां पीएमओ, कैबिनेट
सचिवालय और नेशनल
सिक्योरिटी काउंसिल
स्थानांतरित हो गए।
पीएमओ भी सेवा तीर्थ में
स्थानांतरित हो गया।



आठ सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा और इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काली ग्रेनाइट से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। यहां पूर्वस्थापित किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटा दी गई।



कर्तव्य पथ : गुलामी से कर्तव्य की ओर

आठ सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा और इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काली ग्रेनाइट से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। यहां पूर्वस्थापित किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटा दी गई। यहां के रास्तों को लाल ग्रेनाइट वॉकवे, हरित क्षेत्र, पैदल अंडरपास, बेंच और राज्यवार फूड स्टॉल से सजाया गया। पीएम मोदी ने कहा, “किंग्स-वे या राजपथ गुलामी का प्रतीक था, जो अब इतिहास बन गया है। नया इतिहास रचा गया है।”

वास्तुशिल्पीय नवाचार और भारतीय पहचान

नई इमारतों में भारतीय तत्व प्रमुख रूप से शामिल हैं : कमल (ज्ञान), मोर (सौंदर्य) तथा बरगद (स्थिरता)। 1,753 वृक्षों को काटे बिना उनका प्रत्यारोपण किया गया है। यहां सोलर एनर्जी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है। यह लुटियंस-बेकर की औपनिवेशिक शैली से अलग आत्मनिर्भर भारत की वास्तुकला है। वास्तुशास्त्रीय डिजाइन से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जो प्रशासन में दक्षता लाता है।

लुटियंस दिल्ली का इतिहास

लुटियंस दिल्ली का इलाका 1911 के बाद बनना शुरू हुआ, जब तत्कालीन ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में घोषणा की कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट होगी। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसे मुख्य रूप से डिजाइन किया। उन्होंने एक ग्रैंड प्लान बनाया – रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन (तब वायसराय हाउस), संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, और राजपथ (अब कर्तव्य पथ) जो इंडिया गेट तक जाता है। ये सब 1931 तक बनकर तैयार हुए। यह इलाका तीन किलोमीटर लंबा है। इसमें हरे-भरे लॉन, चौड़ी सड़कें आदि हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत दिखाते थे। यह इलाका भारत की सत्ता और शान का प्रतीक रहा है। आप लुटियंस दिल्ली को भारत का सबसे प्रतिष्ठित, सुंदर और शक्तिशाली आवासीय-प्रशासनिक क्षेत्र मान सकते हैं। यह नई दिल्ली का केंद्रीय हिस्सा है, जो ब्रिटिश काल में साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक बनकर उभरा और आज भी देश की सत्ता, समृद्धि और वास्तुकला की शान का केंद्र बना हुआ

है। इसका नाम ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1912 से 1931 के बीच इस क्षेत्र की योजना और अधिकांश प्रमुख इमारतों का डिजाइन तैयार किया।

भारत की राजधानी कलकत्ता (कोलकाता) से दिल्ली स्थानांतरित करने के ऐतिहासिक फैसले का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व को भव्य रूप में प्रदर्शित करना था। इसके लिए दिल्ली को इसलिए चुना गया क्योंकि यह प्राचीन काल से ही भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा है।

ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने क्लासिकल यूरोपीय वास्तुकला को भारतीय तत्वों के साथ अनूठा मेल किया। उन्होंने इंडो-सरैसेनिक और क्लासिकल शैली का संयोजन किया, जिसमें मौर्य-बौद्ध स्तंभ, मुगल गुंबद, जालीदार काम और विशाल मेहराबों का इस्तेमाल किया गया। रायसीना हिल पर बना राष्ट्रपति भवन (पूर्व में वायसराय हाउस) इसका सबसे शानदार उदाहरण है। यह दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष आवासों में से एक रहा है, जिसकी 340 कमरों वाली इमारत 320 एकड़ में फैली है। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर राजपथ (अब कर्तव्य पथ) के दोनों ओर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक (सचिवालय) खड़े हैं, जो समरूपता और भव्यता के प्रतीक हैं। राजपथ का अंत इंडिया गेट पर होता है।

इस क्षेत्र की खासियत केवल इमारतों ही नहीं, बल्कि इसकी शहर नियोजन कला भी है। लुटियंस ने 'गार्डन सिटी' कॉन्सेप्ट को अपनाया। उन्होंने एक-तिहाई हिस्सा हरे-भरे बगीचों, वृक्षों और खुले मैदानों के लिए सुरक्षित रखा। चौड़ी सड़कें, समरूप बंगले, बड़े प्लॉट और शांत माहौल ने इसे अन्य शहरों से अलग स्वरूप दिया। पृथ्वीराज रोड, अकबर रोड, सफदरजंग रोड, चाणक्यपुरी जैसे इलाके आज भी सबसे महंगे आवासीय क्षेत्रों में शुमार हैं, जहां एक बंगले की कीमत 300-400 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है।

भव्यता से लोकतंत्र की शक्ति तक

आजादी के बाद भी यह इलाका सत्ता के केंद्र के रूप में बना रहा। प्रधानमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह, सैन्य अधिकारी और राजनयिक—सबका ठिकाना लंबे समय तक यही क्षेत्र रहा। संसद

लुटियंस दिल्ली में बदलाव केवल भौतिक ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक परिवर्तन का भी संकेत देता है। यह बदलाव सत्ता के उस नए दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो औपनिवेशिक अतीत से दूरी बनाकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों को केंद्र में लाना चाहता है।





भवन में लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होने लगीं। लेकिन समय के साथ ये पुरानी इमारतें जर्जर हो गईं। बिजली की पुरानी वायरिंग, पानी की लीकेज, और भूकंप से सुरक्षा की कमी – ये सब समस्याएं आने लगी थीं। दिल्ली के 1962 के मास्टर प्लान में इसे हेरिटेज इलाका घोषित किया गया, लेकिन रखरखाव की कमी से दिक्कतें बढ़ती गईं। आज भारत की आबादी बढ़ रही है, सांसदों की संख्या भी 2029 के बाद बढ़ सकती है। इसी वजह से बदलाव की जरूरत पड़ी।

यह जान लें कि नई दिल्ली न सिर्फ देश की राजनीति का केंद्र है, बल्कि यह भारत की पहचान है। यहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है, लोग पिकनिक मनाते हैं। लेकिन अब यह बदल रहा है – नई इमारतें, नए डिजाइन, जो भारत की आधुनिक महत्वाकांक्षा दिखाते हैं। प्रख्यात वास्तुशास्त्री डॉ. जे.पी. शर्मा कहते हैं कि यह सुखद है कि नई दिल्ली की सरकारी इमारतें, खासकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत और सचिवालय भवन, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। वास्तु के अनुसार सही दिशा, संतुलित ऊर्जा और शुभ प्रतीकों (जैसे-हाथी, घोड़ा, गरुड़ आदि) का प्रयोग होने से भवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इससे प्रशासन में दक्षता, निर्णय लेने की क्षमता, शांति और समृद्धि बढ़ने की मान्यता है।

सत्ता व एक खास वर्ग का प्रतीक

समय के साथ “लुटियंस दिल्ली” केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक मानसिकता और सत्ता-संरचना का प्रतीक बन गई। “लुटियंस जमात” या “लुटियंस इकोसिस्टम” जैसे शब्द प्रचलन में आए, जिनका प्रयोग अक्सर एक खास राजनीतिक, बौद्धिक और मीडिया वर्ग के लिए किया जाने लगा। यह वर्ग सत्ता के गलियारों के करीब माना जाता था और नीतियों, विमर्श और राय-निर्माण में इसकी अहम भूमिका रही, लेकिन 2014 के बाद इस स्थापित व्यवस्था को खुली चुनौती मिलने लगी। राजग सरकार के रूप में राजनीतिक सत्ता में बदलाव के साथ ही यह धारणा मजबूत हुई कि लुटियंस दिल्ली की पारंपरिक प्रभुता कमजोर हो रही है।

हरियाली भी रही खास पहचान

ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने जब नई दिल्ली की योजना बनाई, तो उन्होंने शहरी विकास के साथ-साथ हरियाली को भी विशेष महत्व दिया। चौड़ी सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने की

अवधारणा उसी सोच का परिणाम थी। जामुन, नीम, पीपल, बरगद, अमलतास, अर्जुन और शीशम जैसे देसी वृक्षों के साथ-साथ गुलमोहर और जैकरांडा जैसे विदेशी पौधे भी लगाए गए। इन पेड़ों ने समय के साथ दिल्ली की कठोर जलवायु में खुद को ढाल लिया और आज वे इस क्षेत्र की पहचान बन चुके हैं। इधर के पेड़ों का सौंदर्य ऋतुओं के साथ बदलता रहता है। गर्मियों में अमलतास के पीले फूल और गुलमोहर की लाल छटा सड़कों को रंगीन बना देती है, जबकि वसंत में नई पत्तियां और फूल पूरे क्षेत्र में जीवन का संचार कर देते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी नई दिल्ली के ये वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये वायु प्रदूषण को कम करने, तापमान नियंत्रित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में, जहां प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, ये पुराने वृक्ष प्राकृतिक रक्षक की तरह काम करते हैं।

सफदरजंग रोड, सुनहरी बाग, राजाजी मार्ग, कुशक रोड, त्यागराज मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग के किनारे जामुन के पेड़ हैं। अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग पर इमली के पेड़ हैं। अकबर रोड के पीछे कुछ अमलतास भी हैं। पृथ्वीराज रोड, औरंगजेब रोड (अब डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड), तीस जनवरी मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग पर नीम हैं। तो बाबा खड़क सिंह मार्ग, तिलक मार्ग, फिरोज शाह रोड, तीन मूर्ति मार्ग इमली के पेड़ों से लबरेज है।

दरअसल, नई दिल्ली के मुख्य मार्गों में कौन-कौन से प्रजाति के पौधे लगेंगे इस लिहाज से मिट्टी का परीक्षण किया गया था। उसके बाद ये भी तय हुआ कि पतझड़ी पेड़ों को लगाने से बचा जाए। ये सिलसिला अब भी कायम है। 1920 के बाद पौधे लगने शुरू हुए यानी यहां के वृक्ष अब 100 बरस से ज्यादा के हो चुके हैं। कहने वाले तो दावा करते हैं कि इन पेड़ों का ही कमाल है कि ये जिधर मौजूद हैं, वहां पर तापमान चार डिग्री कम ही रहता है हरियाली के चलते। हालांकि हर साल तेज आंधी में कई पेड़ धराशायी हो जाते हैं। ये लुटियंस दिल्ली के अटूट हिस्सा हैं।

क्यों शुरू हुई सेंट्रल विस्टा परियोजना

सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ। सरकार ने कहा कि पुरानी इमारतें अब आधुनिक जरूरतों के लिए फिट नहीं हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है— सरकार की दक्षता बढ़ाना, सभी मंत्रालयों को एक जगह लाना, संसद परिसर को बड़ा बनाना, और इलाके





को पर्यटक-अनुकूल बनाना। प्रोजेक्ट का डिजाइन एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मिला और टाटा प्रोजेक्ट्स को नई संसद का कॉन्ट्रैक्ट। कुल लागत है करीब 20,000 करोड़ रुपये। 2026 तक आते-आते कई हिस्से पूरे हो चुके हैं।

इसमें संसद की नई इमारत का आकार त्रिकोणीय है, जो चार मंजिला है। इसके भीतर लोकसभा की 888 सीटें, राज्यसभा की 384, और जॉइंट सेशन के लिए 1272 सीटें हैं। पुराने संसद भवन की इमारत सर्कुलर थी, जो 1927 में बनी थी। नई इमारत में में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, बेहतर लाइटिंग और रेस्ट रूम हैं। इसका मई 2023 में उद्घाटन हो चुका है।

कर्तव्य पथ (राजपथ) का रीडेवलपमेंट सितंबर 2022 में पूरा हुआ। इसमें नए ब्रिज, पैदल अंडरपास, चौड़े फुटपाथ, पार्किंग, हरे इलाके, बेंच आदि हैं। ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट (10 डोनट-शेप बिल्डिंग्स) का हिस्सा है, जहां सभी 51 मंत्रालय आएंगे। यहीं वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नए एन्क्लेव – 15 एकेड में, नए ऑफिस और रेजिडेंस भी हैं। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बनाया जाएगा। पुरानी इमारतें, जैसे-शास्त्री भवन, कृषि भवन गिराए जाएंगे।

इसके अलावा, इस योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का विस्तार, सेंट्रल विस्टा मेट्रो लूप लाइन (अंडरग्राउंड, चार स्टेशन) और यमुना के पास न्यू इंडिया गार्डन भी शामिल हैं। ये सब मिलकर इलाके को आधुनिक बनाएंगे।

औपनिवेशिक प्रतीकों से दूरी

लुटियंस दिल्ली में बदलाव केवल भौतिक ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक परिवर्तन का भी संकेत देता है। यह बदलाव सत्ता के उस नए दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो औपनिवेशिक अतीत से दूरी बनाकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों को केंद्र में लाना चाहता है। समर्थकों के लिए यह मानसिक गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है, जबकि आलोचक इसे इतिहास को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश मानते हैं।

विमर्श का बदलाव

एक समय था जब लुटियंस दिल्ली देश के बौद्धिक और मीडिया विमर्श का मुख्य केंद्र मानी जाती थी। बड़े अखबारों के दफ्तर, थिंक टैंक, सेमिनार और बंद कमरे की चर्चाएं यहीं केंद्रित रहती थीं,

लेकिन डिजिटल और सोशल मीडिया के विस्तार ने इस एकाधिकार को तोड़ा है। अब विमर्श केवल लुटियंस दिल्ली तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों, क्षेत्रीय आवाजों और वैकल्पिक मंचों को अधिक स्थान मिल रहा है। इससे लुटियंस दिल्ली की वैचारिक केंद्रीयता कमजोर हुई है।

प्रतीकात्मक सत्ता से आगे

लुटियंस दिल्ली का बदलता चेहरा यह संकेत देता है कि भारत की राजधानी अब केवल प्रतीकात्मक सत्ता का केंद्र नहीं रहना चाहती, बल्कि एक अधिक कार्यात्मक, कुशल और आधुनिक प्रशासनिक शहर बनना चाहती है। पुराने औपनिवेशिक ढांचे की जगह नई जरूरतों के अनुसार स्थान और संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। यह बदलाव सहज नहीं है और इसमें टकराव, बहस और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी शहर समय के साथ बदले बिना जीवित नहीं रह सकता।

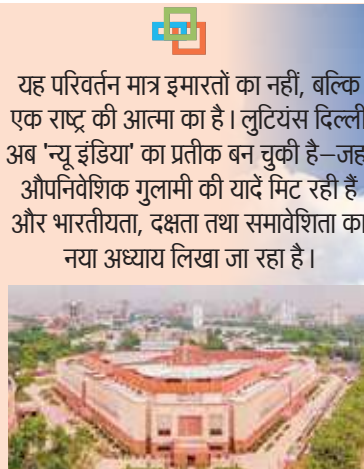
समावेशिता का नया अध्याय

लुटियंस दिल्ली आज एक संक्रमण काल से गुजर रही है। एक ओर उसकी ऐतिहासिक विरासत है, दूसरी ओर आधुनिक भारत की आकांक्षाएं। यह संघर्ष केवल इमारतों का नहीं, बल्कि विचारों, पहचान और सत्ता की प्रकृति का है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि यह बदलाव संतुलन बना पाता है या नहीं—क्या लुटियंस दिल्ली अपनी आत्मा को बचाते हुए नए भारत की जरूरतों के अनुरूप खुद को ढाल पाएगी? इतना तय है कि लुटियंस दिल्ली अब वैसी नहीं रही जैसी वह पिछले करीब सौ वर्षों में थी, और यही परिवर्तन उसकी सबसे बड़ी कहानी है। लुटियंस दिल्ली का बदलना भारत के विकास का प्रतीक है। पुरानी इमारतें अब फिट नहीं, तो नई बननी चाहिए।

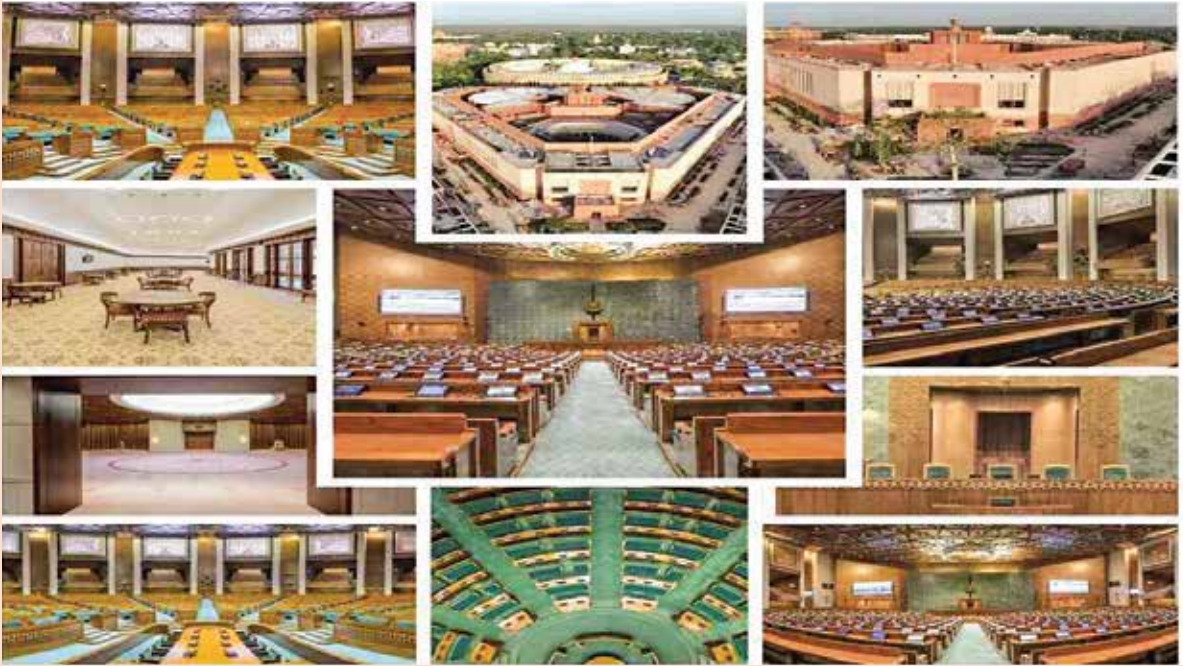
यह परिवर्तन मात्र इमारतों का नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का है। लुटियंस दिल्ली अब 'न्यू इंडिया' का प्रतीक बन चुकी है—जहां औपनिवेशिक गुलामी की यादें मिट रही हैं और भारतीयता, दक्षता तथा समावेशिता का नया अध्याय लिखा जा रहा है।

दूरदर्शिता का प्रमाण

सेंट्रल विस्टा परियोजना मोदी सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है। संसद भवन, नॉर्थ-साउथ ब्लॉक के आसपास नई इमारतें और औपनिवेशिक प्रतीकों का उन्मूलन मात्र निर्माण नहीं, बल्कि मानसिक



यह परिवर्तन मात्र इमारतों का नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का है। लुटियंस दिल्ली अब 'न्यू इंडिया' का प्रतीक बन चुकी है—जहां औपनिवेशिक गुलामी की यादें मिट रही हैं और भारतीयता, दक्षता तथा समावेशिता का नया अध्याय लिखा जा रहा है।



स्वाधीनता है। 140 करोड़ भारतीयों का यह सपना 'विकसित भारत 2047' की ओर ले जाएगा। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'नया संसद भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।' यह परियोजना इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी—गुलामी से कर्तव्य की यात्रा। यह बदलाव भारत की आत्मा का परिवर्तन है, जहां पुरानी विरासत को संरक्षित रखते हुए नई आकांक्षाएं उभर रही हैं। लुटियंस दिल्ली अब 'न्यू इंडिया' का प्रतीक बन चुकी है—जहां औपनिवेशिक गुलामी की यादें मिट रही हैं और भारतीयता, दक्षता तथा समावेशिता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। वास्तु, हरियाली, आधुनिक सुविधाएं और जन-केंद्रित डिजाइन मिलकर एक ऐसा पावर कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार एवं दिल्ली की ऐतिहासिक विरासतों के जानकार हैं और करीब चार दशकों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। हिंदी और अंग्रेजी में उनके 11 हजार से अधिक आलेख देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वे अटल बिहार वाजपेयी, चंद्रशेखर, इंदु कुमार गुजराल, जॉन मेजर, इमरान खान, श्रीश्री रविशंकर, बेन किंमसले, इंद्रा न्यूयी जैसी देश-विदेश की जानी-मानी शख्सियतों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी ले चुके हैं।)



विकसित भारत



कुमार पंकज

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

दूरदर्शी सोच के अप्रतिम नायक

नरेन्द्र मोदी का नाम आते ही हर किसी के जेहन में ऐसी तस्वीर बनती है कि वह सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर इस व्यक्तित्व में ऐसी क्या खासियत है तो दूसरों से अलग बनाती है। भारतीय राजनीति में कई ऐसे चेहरे हुए हैं जिनके व्यक्तित्व की छाप दूर-दूर तक सुनाई पड़ती है लेकिन समय के साथ व्यक्ति के बारे में लोगों का नजरिया बदलता जाता है। नरेन्द्र मोदी एक ऐसा नाम है जो वर्तमान समय में सत्ता और विपक्ष दोनों ही लोगों को सोचने पर विवश कर देता है कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हर किसी को सोचने पर विवश कर देती हैं कि आखिर जो फैसला लिया गया, उसके पीछे क्या कारण रहे।

नरेन्द्र मोदी संगठन और सरकार के ऐसे चेहरे हैं जो अपने काम को लेकर सुखियों में रहे हैं। वह भाजपा के संगठन में थे तब भी सुखियां बटोरते थे। यह अलग बात है कि उस दौर में न तो सोशल मीडिया का जमाना था और ना ही मीडिया का इतना विस्तार हुआ था, लेकिन 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन केवल जरूरतमंदों को छत देना भर नहीं है, उन्होंने सुनिश्चित किया कि घर के साथ शौचालय (स्वच्छ भारत), बिजली (सौभाग्य), गैस कनेक्शन (उज्ज्वला) और पानी (जल जीवन मिशन) भी मिले। यह एक 'समग्र जीवन शैली' प्रदान करने की दूरगामी दृष्टि है।



बने तो सबकी जुबान पर नरेन्द्र मोदी का नाम सामने आने लगा। 2002 का गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ मोदी और मुखर होकर सत्ता की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद 2007 का गुजरात विधानसभा चुनाव फिर मोदी और मुखरता के साथ सत्ता की कुर्सी पर बैठे। 2012 का भी विधानसभा चुनाव उसी मुखरता और निडरता के साथ जीते और एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब तक मोदी एक ब्रांड बन चुके थे। उस समय उनके व्यक्तित्व को लेकर कई तरह की विरोधाभासी बातें भी हुआ करती थीं, लेकिन उनकी उन्हें परवाह कहां। वे अपने काम में तल्लीन रहे।

संयोग से नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मुझे उनके कार्यकाल को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। 2001 से 2007 के बीच जो उनका व्यक्तित्व गुजरात में मैंने देखा कि हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही नाम आता था चुनाव हो तो 'आएगा तो मोदी ही'। यह एक चुनावी नारा नहीं बल्कि लोगों को एक विश्वास भी था कि कुछ भी कर लीजिए समाज का एक बड़ा वर्ग मोदी के साथ खड़ा है। बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी मोदी जी के व्यक्तित्व को सही तरीके से आंक पाने में असफल थे। मोदी के व्यक्तित्व को पहचानना हर किसी के वश की बात भी नहीं थी। जब गुजरात का डंका विश्व पटल पर बजने लगा तो इसके साथ मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। मुझे याद है कि 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद 2009 में देश में आम चुनाव होने थे, तब गुजरात में अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मैंने उनसे दिल्ली की राजनीति में भूमिका को लेकर एक सवाल पूछा था जिसका उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया था कि पार्टी में कई और बड़े नेता हैं जो 2009 की तैयारी में हैं। मेरे पास अभी समय है। आशय साफ था कि 2009 के आम चुनाव के बाद जो अगला चुनाव होगा नरेन्द्र मोदी उसकी तैयारी में जुटे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा की जीत के बाद नरेन्द्र मोदी का कद बढ़ता गया और वे 2014 के आम चुनाव की तैयारी में जुट गए।

2014 के आम चुनाव से पहले मोदी एक ब्रांड बन चुके थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर किताबें लिखी जाने लगी थीं। संयोग से इन पंक्तियों के लेखक ने साल 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 'दूरदर्शी नरेन्द्र मोदी' शीर्षक से किताब लिखी थी। किताब लिखने का आशय केवल यह था कि एक व्यक्ति अपनी दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और देशहित के लिए लगातार चिंतन मनन कर रहा है। तो क्यों न कुछ ऐसा लिखा जाए कि लोगों को भी उनके व्यक्तित्व का पता चले। राजनीति में कामकाज को लेकर मतभेद हो सकते हैं। विचारों से सहमति असहमति हो सकती



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता का सार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' में निहित है। उन्होंने यह विश्वास जगाया है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आने वाला इतिहास उन्हें एक ऐसे निर्माता के रूप में याद रखेगा, जिसने खंडित सपनों को जोड़कर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'विकसित भारत 2047' की नींव रखी।



कल्याण ही सर्वोपरि है। उनकी दूरदर्शिता का सार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' में निहित है। उन्होंने भारतीयों के मन में यह विश्वास जगाया है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आने वाला इतिहास उन्हें एक ऐसे निर्माता के रूप में याद रखेगा, जिसने खंडित सपनों को जोड़कर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'विकसित भारत 2047' की नींव रखी।

नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता का सबसे सशक्त प्रमाण उनकी वे योजनाएं हैं, जिन्होंने भारत के सामाजिक ढांचे की बुनियादी समस्याओं पर प्रहार किया। वे जानते थे कि एक बीमार और बेघर नागरिक कभी भी राष्ट्र निर्माण में पूर्ण योगदान नहीं दे सकता। उन्होंने महसूस किया कि मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों की जीवन भर की कमाई अक्सर किसी गंभीर बीमारी के इलाज में खर्च हो जाती है। इसी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' की नींव रखी। यह केवल पांच लाख रुपये की मुफ्त इलाज योजना नहीं है, बल्कि यह गरीब को 'सम्मान के साथ इलाज' का अधिकार देती है। आज करोड़ों लोग बिना कर्ज लिए बड़े अस्पतालों में इलाज-सर्जरी करा पा रहे हैं। इसके साथ ही 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के जरिए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ दिया है, जिससे भविष्य में इलाज की प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सुलभ होगी।

'सबके लिए आवास' का संकल्प उनकी उस दूरदर्शी सोच का हिस्सा है जो मानती है कि घर केवल ईंट-गारे की दीवारें नहीं, बल्कि एक परिवार की सुरक्षा और गरिमा का आधार होता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घरों का स्वामित्व मुख्य रूप से महिलाओं को दिया गया है। इसने ग्रामीण और शहरी भारत में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को रातों-रात बदल दिया। नरेन्द्र मोदी का विजन केवल छत देना नहीं था, उन्होंने सुनिश्चित किया कि घर के साथ शौचालय (स्वच्छ भारत), बिजली (सौभाग्य), गैस कनेक्शन (उज्ज्वला) और पानी (जल जीवन मिशन) भी मिले। यह एक 'समग्र जीवन शैली' प्रदान करने की दूरगामी दृष्टि है।

अगर हम अंतरराष्ट्रीय पटल की बात करें तो नरेन्द्र मोदी ने भारत को एक 'याचक' की भूमिका से निकालकर एक 'प्रदाता' और 'विश्व मित्र' की भूमिका में ला खड़ा किया है। कोरोना काल में दुनिया के सौ से अधिक देशों को वैक्सीन पहुंचाकर उन्होंने भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को चरितार्थ किया। यह उनकी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज भारत अमेरिका, रूस और खाड़ी देशों के साथ अपने हितों के आधार पर स्वतंत्र संबंध रखता है। 'योग' और 'मिलेट्स' (बाजरा)

को वैश्विक मान्यता दिलाना उनकी सांस्कृतिक कूटनीति की बड़ी जीत है।

नरेन्द्र मोदी का विजन वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ 2047 के विकसित भारत की नींव रखना है। उनकी नीतियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करे, तब वह न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ दुनिया का नेतृत्व भी कर रहा हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी एक ऐसे वास्तुकार हैं जो आज की धूल में कल के चमकते भारत का नक्शा देख रहे हैं। नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता का एक सिरा जहां 'अंतिम व्यक्ति' यानी अंत्योदय से जुड़ा है, वहीं दूसरा सिरा 'आधुनिकतम भारत' के निर्माण से जुड़ा है। उन्होंने महसूस किया कि भारत की प्रगति की रफ्तार तब तक तेज नहीं हो सकती, जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 'साइलो' (टुकड़ों) में काम करेगा और हमारी शिक्षा पद्धति औपनिवेशिक मानसिकता से दबी रहेगी। इसके लिए मोदी ने ठोस योजनाओं पर काम करना शुरू किया। अतीत में भारत की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सड़कें बनती थीं तो पानी की पाइपलाइन के लिए उसे खोद दिया जाता था। इस समन्वय की कमी को खत्म करने के लिए मोदी ने 'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' पेश किया। यह केवल सड़कों या रेलवे का जाल नहीं है, बल्कि 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे परियोजनाओं की लागत कम हुई है और काम की गति कई गुना बढ़ गई है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए भारत को ग्लोबल सप्लाय चैन का केंद्र बनाना उनकी उस आर्थिक दूरदर्शिता का हिस्सा है, जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है।

पीएम नरेन्द्र मोदी जानते हैं कि 21वीं सदी 'ज्ञान की सदी' है। 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति उनकी उस सोच का परिणाम है जो रटने वाली शिक्षा के बजाय 'कौशल' और 'क्रिटिकल थिंकिंग' पर जोर देती है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में शुरू करना उनकी एक बड़ी सांस्कृतिक और व्यावहारिक जीत है। इससे प्रतिभा अब भाषा की मोहताज नहीं रहेगी। शोध पर जोर देकर वे भारत को केवल 'उपभोक्ता' नहीं, बल्कि 'खोजकर्ता' बनाना चाहते हैं। 'अटल टिकरिंग लैब्स' के जरिए स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना इसी दूरगामी योजना का हिस्सा है।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखता, बल्कि दुनिया भारत के समाधानों (जैसे कोविन प्लेटफॉर्म, सौर गठबंधन) को अपना रही है। 'पंच प्रण' के संकल्प के साथ वे एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो अपनी विरासत पर गर्व करता है और आधुनिकता के शिखर को छूने का साहस रखता है। नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व में एक तपस्वी का धैर्य और एक आधुनिक सीईओ की कार्यकुशलता का मेल है। उनकी दूरदर्शी सोच ने भारत को 'मजबूर' राष्ट्र से 'मजबूत' राष्ट्र बना दिया है।

नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता केवल पृथ्वी की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों और धरती की रक्षा के बीच एक अनूठा संतुलन साधते हैं। उनकी सोच का आधार है,



चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। अब 'गगनयान' के जरिए अंतरिक्ष में भारतीय मानव को भेजने का सपना उनकी उस वैज्ञानिक दूरदर्शिता को दर्शाता है, जहां भारत दुनिया की बराबरी नहीं, बल्कि नेतृत्व करना चाहता है।



'विकास भी और विरासत भी', जिसमें पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक उत्कर्ष दोनों शामिल हैं। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन पर केवल बड़े सम्मेलनों में चर्चा कर रही थी, तब मोदी ने 'मिशन लाइफ' का विचार दिया। उन्होंने संदेश दिया कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि जन-भागीदारी और हमारी दैनिक आदतों को बदलने से होगी। फ्रांस के साथ मिलकर 'इंटरनेशनल सोलर एलायंस' की स्थापना करना उनकी उस दूरगामी सोच का प्रमाण है, जिसने भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 'विश्व गुरु' के रूप में स्थापित कर दिया। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर रहे हैं।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने 'इसरो' के वैज्ञानिकों के हौसलों को नई उड़ान दी। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। अब 'गगनयान' के जरिए अंतरिक्ष में भारतीय मानव को भेजने का सपना उनकी उस वैज्ञानिक दूरदर्शिता को दर्शाता है, जहां भारत दुनिया की बराबरी नहीं, बल्कि नेतृत्व करना चाहता है।

उनकी दूरदर्शिता का सार उनकी इन पंक्तियों में झलकता है, "यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है।" एक लेखक के रूप में, मैंने प्रधानमंत्री के कार्यों को बहुत करीब से देखा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी दूरदर्शी सोच ने भारत के इतिहास और राजनीति का एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है।



(करीब ढाई दशक से मुख्यधारा की पत्रकारिता में सक्रिय लेखक वरिष्ठ पत्रकार और 'देशबंधु' समाचार पत्र के नेशनल ब्यूरो चीफ हैं। उनकी चर्चित पुस्तक 'दूरदृष्टा नरेन्द्र मोदी' का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी अन्य पुस्तकों में युवा सांसदों पर आधारित 'देश का युवा नेतृत्व' और 'देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल' शामिल हैं। सामाजिक विषयों पर लेखन के लिए उन्हें यूनिफेम मीडिया अवॉर्ड, शहीद शंकर गुहा नियोगी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें शोधपरक कार्य के लिए एक्शन एड, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की फेलोशिप भी मिल चुकी है।)



विकसित भारत



मिलन सिन्हा

मोटिवेशनल लेखक एवं लाइफ कोच

स्वदेशी और

आत्मनिर्भरता की राह

आजादी के लगभग 67 साल बाद 26 मई, 2014 को नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। कहने को तो 2014 में हमारा देश दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी और हमारे जीडीपी का आकार 1.86 ट्रिलियन डॉलर था, लेकिन देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अनेक कारण थे, जिससे देशवासी परिचित, परेशान व चिंतित थे। ऐसे समय में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला और केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार का गठन हुआ। मोदी सरकार को यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार से विरासत में विभिन्न विकट समस्याओं से ग्रसित विशाल देश मिला।

नई सरकार ने उन तमाम आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का योजनाबद्ध तरीके से सामना करने का संकल्प लिया और पूरी स्थिति का सम्यक विश्लेषण किया। आयल बांड जैसी भारी-भरकम वित्तीय देनदारियों, बैंकों के गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए), सरकारी एयरलाइंस सहित अनेक अन्य सरकारी उपक्रमों के बढ़ते घाटों जैसी वित्तीय समस्याओं को चिह्नित कर उनमें



सुधार हेतु ठोस नीति और कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। लक्ष्य एकदम स्पष्ट था कि विविधताओं से भरे इस विशाल देश को जनोन्मुख और पूर्णतः जनसमावेशी योजनाओं के माध्यम से विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाना है और इस कार्य में हर स्तर पर जनसहयोग और जनभागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसी सोच का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया जिसमें आगे चलकर सबका प्रयास और सबका विश्वास भी शामिल हुआ।

इन मूल मानवीय भावनाओं से प्रेरित योजनाओं को वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए धरातल पर उतारना और उन्हें अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के दर्शन को मूर्त रूप देना आवश्यक था। कहते हैं न कि एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम लोगों को सक्रिय रूप से जोड़ना पहली शर्त है और यह भी उतना ही सत्य है कि कामयाब लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे तो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। लिहाजा नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों से संवाद करने का नायाब तरीका निकाला। तीन अक्टूबर, 2014 को प्रसारित इस मासिक कार्यक्रम के पहले ही एपिसोड में उन्होंने देशवासियों से न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया, बल्कि खादी के कपड़ों का उपयोग करने का अनुरोध भी किया। अगर आप 25 सितंबर, 2014 से प्रारंभ हुए ‘मेक इन इंडिया’ इनिशिएटिव के साथ-साथ ‘मन की बात’ कार्यक्रम के पहले पंद्रह एपिसोड पर ही गौर करें तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के साफ संकेत मिल जाएंगे।

दरअसल, स्वदेशी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम देश में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्कि जैसा मोदी ने कहा है कि हर वह वस्तु स्वदेशी है जिसमें किसी-न-किसी भारतीय की मेहनत और पसीना शामिल है। इसी संदर्भ में उन्होंने एकाधिक बार देशवासियों से यह आग्रह किया है कि उनके घर में उपयोग की जाने वाली हर चीज स्वदेशी होनी चाहिए। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने विक्रेताओं का भी आह्वान किया है कि वे स्वदेशी सामानों को बेचने का संकल्प लें, जिससे कि हमारे उद्यमियों, कारीगरों, श्रमिकों आदि को प्रोत्साहन मिले, घरेलू उत्पादन बढ़े, कई

वस्तुओं का आयात कम हो और इसके साथ ही इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो।

इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पद ग्रहण करने के छह माह के भीतर ही आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने हेतु सितंबर 2014 में ही 'मेक इन इंडिया' पहल को प्राथमिकता दी। दरअसल, वर्ष 2013 के अंत तक यह साफ हो चुका था कि देश की विकास यात्रा कठिन दौर से गुजर रही है और यूपीए सरकार पर एकाधिक घोटालों के आरोप के कारण देश की छवि भी खराब हो रही है। लिहाजा लक्ष्य यह था कि भारत को हर दृष्टि से आंतरिक रूप से मजबूत किया जाए और विश्व पटल पर 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप देश में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई और सरकार के सम्यक् प्रयास और लोगों को इस प्रयास में सक्रिय भगीदार बनाने की नीति व नीयत ने इस पहल को अपेक्षित गति प्रदान की। इसी तरह कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के घोर संकटपूर्ण दौर में 'आपदा को अवसर' बनाने के संकल्प के साथ अनेक साहसिक कदम उठाये गए जिनमें आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शामिल है। वर्ष 2020 में घोषित इस अभियान का लक्ष्य देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ-साथ घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने, आयात पर निर्भरता घटाने, निर्यात बढ़ाने, आम जनता को जागरूक और समर्थ करने का था, जिससे कि वर्ष 2047 यानी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके। इसके पीछे मोदी सरकार का विराट दर्शन यह था कि स्वदेशी, अंत्योदय, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव आदि की भावना से ओतप्रोत भारत समावेशी विकास के रास्ते विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेज गति से आगे बढ़े। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड को पांच स्तंभों के रूप में चिह्नित किया गया। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' एवं 'ईज ऑफ लिविंग' का समावेशी एवं संतुलित विकास का विचार इस सबके केंद्र में था, जिससे कि देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने और आम लोगों के जीवन को उन्नत करने में बहुत मदद मिले। इसके साथ ही सरकार ने हर घर शौचालय योजना, नल जल योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी कई जनोपयोगी योजनाओं से आम लोगों की जिंदगी को सुगम बनाने का प्रयास किया।

यह सच है कि विकसित भारत की राह को आसान बनाने के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की सोच ने बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। मोबाइल विनिर्माण, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुए गुणात्मक सुधार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट मिशन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास, पर्यावरण संरक्षण से लेकर सेमी कंडक्टर चिप के उत्पादन तक पिछले करीब बारह वर्षों में मोदी सरकार ने जो अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और जिनके परिणामस्वरूप आज देश 10वीं से विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करना स्वाभाविक है।



केंद्र की मोदी सरकार ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया कि युद्ध स्तर पर सभी योग्य गरीब लोगों का शून्य बैलेंस वाला बचत बैंक खाता खोला जाए। इस अभियान के तहत अगले कुछ महीनों में कई करोड़ नए खाते खोले गए। इसका नतीजा यह हुआ कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए चयनित लाभार्थियों को मिलने वाली राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके खातों में जमा होने लगी। इससे सही लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलने लगा और भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई।

जरूरत के हिसाब से टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में उपयोग की जा सकती है। इस योजना में ब्याज दर कम होती है। महिलाओं को तो ब्याज दर में छूट भी हासिल है। इस योजना के तहत अब तक लाखों लोगों ने न केवल अपना रोजगार शुरू किया है, बल्कि वे अब बड़ी संख्या में रोजगार भी दे रहे हैं। इस योजना की सफलता से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है।

डिजिटल इंडिया अभियान : क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में आज सबसे ज्यादा कैशलेस डिजिटल लेनदेन होता है—हर महीने 20 अरब से ज्यादा लेनदेन या इसके माध्यम से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से अधिक पेमेंट होता है या अब यह विश्व का सबसे बड़ा और तेज खुदरा भुगतान सिस्टम है? दरअसल, केंद्र सरकार ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने, कैशलेस इकोनॉमी की अवधारणा को गति प्रदान करने, रोजमर्रा के लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इस विचार को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया। तदनुसार, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) ने 11 अप्रैल, 2016 को यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस की शुरुआत की। इसकी बुनियाद में जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल डाटा की अहम भूमिका थी। आज यह डिजिटल क्रांति के रूप में विश्वभर में चर्चा का विषय है। आखिर हो भी क्यों नहीं। कुछ महीने पहले ही यूपीआई ने विश्व प्रसिद्ध वीजा पेमेंट सिस्टम को भी पीछे छोड़ दिया। आम लोगों के जीवन को यूपीआई ने इस तरह प्रभावित किया है कि अब तो कंधी से लेकर कार खरीदने तक में इसका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल फुटकर भुगतान से लेकर बड़े भुगतान तीव्र गति और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रहे हैं, बल्कि इससे कानून-व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स कंप्लायंस में भी इसकी भूमिका को सराहा जा रहा है। इसके इनोवेटिव सिस्टम की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) सहित विश्व के कई उन्नत देशों और वित्तीय संस्थाओं ने खुलकर प्रशंसा की है। यूपीआई की विकास यात्रा को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) ने 15 सितंबर, 2025 से इसके तहत लेनदेन की सीमा में संशोधन करते हुए इसे प्रति दिन दस लाख रुपया कर दिया है। जाहिर है कि इससे उच्च मूल्य के लेनदेन में लोगों को बहुत सुविधा होगी। दिलचस्प बात है कि मार्च 2026 के एक महीने में यूपीआई के मार्फ़त लेनदेन 29.53 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया यानी हर दिन करीब एक लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ।

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता : पिछले साल मई (2025) में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन डिफेंस फोर्स ने जिस तरह पाकिस्तान को चार दिन के भीतर घुटनों पर ला दिया, उसमें भारतीय सेना के तीनों अंगों का अभूतपूर्व एकीकृत प्रयास और आत्मविश्वास तो स्पष्ट था ही, उसके साथ ही



वैश्विक महामारी कोविड-19 के कठिन दौर में जब विश्व भर में जल्द-से-जल्द वैक्सीन बनाने पर जोर दिया जा रहा था और कुछ विकसित देश इसका गलत फायदा भी उठाने की चेष्टा करते नजर आ रहे थे, उस समय भारत के फार्मा वैज्ञानिकों ने जल्द ही एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन बनाने का गौरव हासिल किया। इस प्रशंसनीय कार्य के कारण देश में करोड़ों लोगों का सफल टीकाकरण संभव हो पाया। इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। भारत ने न केवल अपने लोगों को व्यापक टीकाकरण के माध्यम से कोविड-19 के कहर से बचा कर रखा, बल्कि दुनिया भर के अनेक देशों को इसका मुफ्त निर्यात किया, जिससे वहां भी करोड़ों लोगों को इस वैश्विक महामारी से बचाया जा सका।



पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय को नारों से निकालकर 'वास्तविकता' तक पहुंचाया है। उनके विकसित भारत के मॉडल में देश की स्त्रियों की अग्रणी भूमिका है। इसका प्रमाण उनकी योजनाओं और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में भी दिखता है। उज्ज्वला योजना द्वारा 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शनों ने ग्रामीण महिलाओं को न केवल धुएं से मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके समय की बचत की, जिसे वे उत्पादक कार्यों में लगा रही हैं।



दुनिया भर में भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों—मिसाइल, ड्रोन, रडार प्रणाली, एयरक्राफ्ट आदि की खूब चर्चा हुई। यह सर्वविदित है कि 2014 तक हमारा देश मोटे तौर पर आयात पर निर्भर था। अभी भी हम राफेल सहित कई रक्षा सामग्रियों के मामले में आयात पर निर्भर हैं, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ही रक्षा सामग्री के आयात के मामले में बदलाव के संकेत मिलने लगे। पिछले एक दशक में रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है। यह सिलसिला आगे और जोर पकड़ेगा। संप्रति भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों के लिहाज से अनेक उपकरणों का विनिर्माण कर रहा है, बल्कि विश्व के कई देशों को इसका निर्यात भी कर रहा है। इस मामले में हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) जैसी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का योगदान अहम रहा है। अच्छी बात है कि सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण निजी क्षेत्र की कंपनियां, जिनमें कई स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, रक्षा उपकरण विनिर्माण कार्य में अपनी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तो ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल, पिनाका राकेट लॉन्चर, तेजस लड़ाकू विमान आदि की मांग में इजाफा हुआ है। नौसैनिक जहाजों के विनिर्माण के मामले में भी देश की शिप बिल्डिंग कंपनियां आत्मनिर्भरता के अभियान को सुदृढ़ कर रही हैं। कोचीन शिपयार्ड में स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रान्त का निर्माण इसका बड़ा उदाहरण है।

फार्मा सेक्टर और वैक्सीन निर्माण : वैसे तो देश के निर्यात में फार्मा सेक्टर का योगदान पहले से रहा है, लेकिन इस सेक्टर में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर उसे निर्यात का एक अहम सेक्टर बनाने की संभावना को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाने की पहल की। फार्मा इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर इसे उत्पादन और निर्यात के मामले में एक नई ऊंचाई तक ले जाने का निर्णय लिया गया। यहां भी पीएलआई (प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव) स्कीम के तहत प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ जोड़ा गया। यही कारण था कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कठिन दौर में जब विश्व भर में जल्द-से-जल्द वैक्सीन बनाने पर जोर दिया जा रहा था और कुछ विकसित देश इसका गलत फायदा भी उठाने की चेष्टा करते नजर आ रहे थे, उस समय भारत के फार्मा वैज्ञानिकों ने जल्द ही एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन बनाने का गौरव हासिल किया। इस प्रशंसनीय कार्य के कारण देश में करोड़ों लोगों का सफल टीकाकरण संभव हो पाया। इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। भारत ने न केवल अपने लोगों को व्यापक टीकाकरण के माध्यम से कोविड-19 के कहर से बचा कर रखा,

बल्कि दुनिया भर के अनेक देशों को इसका मुफ्त निर्यात किया, जिससे वहां भी करोड़ों लोगों को इस वैश्विक महामारी से बचाया जा सका।

कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन में आत्मनिर्भरता : भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है और हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों से होने वाली आय पर निर्भर है। 1960-70 के दशक में हरित क्रांति के जरिए देश में गेहूं व चावल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसके फलस्वरूप देश में अनाज की किल्लत कम होती गई। लेकिन किसानों को फसल की सही कीमत न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) निर्धारित करने और उसे लागू करने पर बातें और वादे तो बहुत हुए, परंतु उस पर प्रभावी रूप से अमल नहीं हो पाया। बड़ा सवाल यह था कि देश के अन्नदाता को समर्थ और आत्मनिर्भर बनाए बिना आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे साकार होगा। पिछले करीब 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने इस दिशा में समेकित प्रयास शुरू किए। हर खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों को नई टेक्नोलॉजी और उन्नत पद्धति अपनाने हेतु वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जैसी योजनाओं के जरिये देश के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने का सिलसिला जारी है। इतना ही नहीं, आजकल ग्रामीण इलाकों में हजारों महिलायें नमो ड्रोन दीदी के रूप में कृषि क्षेत्र में नवाचार की सोच को आगे बढ़ाते हुए खाद और कीटनाशक के उपयोग में आधुनिक विधियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ इसका नेतृत्व भी कर रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसानों की आय को दोगुना करने, एमएसपी का सही लाभ देने, कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने, जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों को और गति मिलेगी।

जीएसटी सुधार : आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में सारे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहमति से देशभर में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी सिस्टम एक जुलाई, 2017 से लागू किया गया। लक्ष्य यह था कि पुराने दसाधिक टैक्स और सेस को समाप्त कर एक सरल और प्रभावी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एकरूपता से पूरे देश में लागू हो, जिससे कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं को आसानी हो तथा जिससे 'इज ऑफ़ ड्रूइंग बिजनेस' के साथ-साथ आर्थिक विकास को अपेक्षित प्रोत्साहन मिले। आठ वर्षों के बाद जीएसटी 2.0 सुधार के माध्यम से व्यापक स्तर पर टैक्स रेट को काफी कम करते हुए इसे 22 सितंबर, 2025 से देशभर में लागू किया गया। वित्तीय एवं कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस विकास उन्मुख सुधार से भारत तेजी



भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों के लिहाज से अनेक उपकरणों का विनिर्माण कर रहा है, बल्कि विश्व के कई देशों को इसका निर्यात भी कर रहा है। इस मामले में हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) जैसी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का योगदान अहम रहा है। अच्छी बात है कि सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण निजी क्षेत्र की कंपनियां, जिनमें कई स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, रक्षा उपकरण विनिर्माण कार्य में अपनी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तो ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल, पिनाका राकेट लॉन्चर, तेजस लड़ाकू विमान आदि की मांग में इजाफा हुआ है।



से आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाएगा।

कहने की जरूरत नहीं कि मध्य-पूर्व एशिया में चल रहे भीषण युद्ध से देश में उत्पन्न तेल और गैस समस्या की बात किए बिना यह चर्चा अधूरी मानी जाएगी। सच्चाई यह है कि इस युद्ध के परिणामस्वरूप विश्व के ज्यादातर देशों में जहां ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, वहीं हमारे देश में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई को छोड़कर कहीं भी तेल और गैस की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई। हां, कुछेक स्थानों पर अफवाह, मुनाफाखोरी, जमाखोरी और घबराहट के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन की हिलाई के कारण कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इन अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। तथ्य यह है कि देश में फिलहाल तेल और गैस की किल्लत नहीं है। इसके पीछे सरकार की आत्मनिर्भरता की नीति और दूरगामी सोच एवं कार्ययोजना तो है ही, मोदी सरकार की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इस समय भी अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा रही है। दरअसल, मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही विदेश से तेल आयात को कम करने, तेल रिफाइनरीज की तेल शोधन क्षमता और भंडारण में वृद्धि आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने का प्रयास किया। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो रेल का बढ़ता दायरा, इलेक्ट्रिक कार, बस, स्कूटर आदि का बढ़ता उत्पादन और उपयोग, पीएम सूर्य घर योजना आदि इसके कुछ उदाहरण हैं।

अंत में एक अहम बात, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के सामने चुनौतियां और समस्याएं कम आई या राजनीतिक विरोधियों ने सरकार को घेरने का कम प्रयास किया या उनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी नहीं रही या इतने विशाल देश में उनके लिए हर जगह-हर समय सब कुछ अनुकूल रहा। दरअसल, जब किसी भी सरकार की नीति, नीयत और नियम स्पष्ट, पारदर्शी और जन केंद्रित होती है और जिसमें समय-समय पर समीक्षा और सुधार के प्रावधान भी निहित होते हैं, तो ऐसे में उस सरकार को सफलता भी ज्यादा मिलती है और जन समर्थन भी।



(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार, मोटिविशनल लेखक और लाइफ कोच हैं, जिनके देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेख प्रकाशित होते रहे हैं। उनसे hellomilansinha@gmail.com के जरिए संपर्क किया जा सकता है।)



विकसित भारत



जितेंद्र तिवारी
वरिष्ठ पत्रकार, संपादक-हिन्दुस्थान समाचार
(बहुभाषी न्यूज एजेंसी)

दुनिया में बढ़ाया

भारत का मान

भारत दुनिया का प्राचीनतम देश है। भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। आदिकाल से ही दुनिया को देखने की एक भारतीय दृष्टि है। उस दृष्टि का घोष वाक्य 'वसुधैव कुटुंबकम्' कहा जा सकता है। अर्थ बहुत साफ है। हम इस वसुधा अर्थात् धरती पर रहने वाले सभी जीवों को अपना परिवार मानकर चलते आए हैं। इसी महान विचार के साथ भारत दुनिया भर के देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध चलाता आ रहा था। प्राचीन भारत काल में भी और अब स्वतंत्रता के बाद भी। लंबे कालखंड के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आने से इसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। कूटनीति तो नहीं बदली पर इस विचार को विश्व मंच तक पहुंचाने और स्थापित करने का तरीका बदला। उसी का परिणाम है कि यह विचार स्थापित होता जा रहा है कि भारत संकटग्रस्त दुनिया में शांतिदूत बनकर उभरेगा। भारत महाशक्ति बनता है तो वह विश्व के कल्याण के लिए कार्य करेगा। भारत की इस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक सोच को अपने मन-वचन-वाणी और कर्म से वैश्विक जगत में स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह भारत



के अब तक सबसे चर्चित और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही हैं।

शांतिदूत भारत

आज दुनिया फिर संकटग्रस्त है। चारों तरफ अफरा-तफरी है। बार-बार तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देती है। अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच जारी संघर्ष पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। तेल के लिए किए जा रहे इस युद्धक खेल के चलते दुनिया भर में घरेलू ईंधन (गैस) से लेकर पेट्रोल-डीजल का संकट पैदा हो गया है। इसका असर हर चीज पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में हो रहे इस संघर्ष के चलते रूस-यूक्रेन में जारी जंग और पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जारी गोलाबारी की बातें दब-सी गई हैं। कुल मिलाकर वैश्विक व्यवस्था जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। कूटनीति की मर्यादा का बड़े और ताकतवर देश पालन नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से निकलकर एक उद्यमी और फिर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बने डोनाल्ड ट्रंप न केवल अप्रत्याशित बातें और दावे कर रहे हैं बल्कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में अमर्यादित टिप्पणियां तक कर रहे हैं। ऐसे में कुछ प्रमुख देश ही ऐसे हैं जो उथल पुथल के दौर में भी बहुत संयमित और गरिमापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इनमें चीन और भारत का नाम पहले पायदान पर है। हालांकि चीन भी लंबे समय से लाल आंखों से ताइवान को घूर रहा है। उसकी विस्तारवादी नीति से उसके सभी पड़ोसी देश चौकन्ने रहते हैं। तब एक भारत ही है जो सक्षम देश होने के बावजूद संतुलित रवैया अपनाता रहा है। यह किसी कमजोरी का नहीं बल्कि परिपक्वता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 12 साल के अपने शासनकाल में इसी परिपक्वता से विश्व गगन में अपनी एक अलग, विशिष्ट और प्रभावी पहचान बनाई है।

भारत सबका, भारतीय सबके

प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई, 2014 को अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में ही नरेन्द्र मोदी ने विदेश नीति के मामले में अपनी दूरदृष्टि का परिचय दे दिया था। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के

शपथ ग्रहण में विदेशी मेहमान न आए और न बुलाए गए थे। नरेन्द्र मोदी की पहल पर उनके शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रण दिया गया। इसमें भारत के सभी पड़ोसी देश आ जाते हैं। बड़ी बात यह रही कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान के प्रमुख तो शामिल हुए ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उनके देश में हो रहे विरोध को दरकिनार कर नई दिल्ली पहुंचे थे। नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति का यह पहला आयाम था-पड़ोसी पहले। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान जैसे एक छोटे से देश को चुना और दूसरी यात्रा नेपाल की रही। स्पष्ट था कि वह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय विचार के निकट देशों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने विकसित देशों में शुमार जापान के प्रमुख शिंजो अबे के साथ अपनी निकटता बढ़ाई। जापान भी भारत में जन्मे भगवान बुद्ध को मानने वाला देश है। इसी विचार से सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के सबसे प्रमुख नगर और अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को क्वोटो की तर्ज पर विकसित करने के सपने का जन्म हुआ।

तब से अब तक, पिछले बारह वर्ष के मोदी शासन में विदेश नीति एक आजमाए तरीके से चलती रही है। भारत सबका है और भारतीय सबके साथ हैं, यह आदर्श वाक्य हमारी विदेश नीति का आधार रहा। पाकिस्तान का राग छोड़ दें तो दुनिया भर में बढ़ते और मजबूत होते भारत के नेतृत्व को काफी सराहा गया। भारत की सोच दुनिया को अपने अनुसार बदलने और दुनिया को अपने तौर पर चलाने की कभी नहीं रही, पर नरेन्द्र मोदी आवश्यकता पड़ने पर 'ग्लोबल लीडर' की भूमिका निभाते रहे। यह अब स्थापित हो चुका है कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक नेतृत्व में भारत का किरदार और बड़ा हुआ। भारत ने जोर जबर्दस्ती का रास्ता कभी नहीं अपनाया, पर समझाने बुझाने की हमारी शैली बेजोड़ रही। दुनिया इसे महसूस करती है और जहां भी भारतीय बसे हैं वे भी अब खुद पर गर्व करते हैं। यही नहीं, विदेश में बसे भारतीयों के बारे में वहां के लोगों का नजरिया बदला है। एक समय में पिछड़े और गरीब देश के रूप के नागरिक के रूप में कुछ सकुचाए से रहने वाले भारतवंशी अब गर्व के साथ अपने भारतीय होने का परिचय देते हैं। इंस्टाग्राम पर दुनिया भर में सबसे





प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अमूल्य धरोहरों को अपनी वैश्विक कूटनीति का आयाम बनाया। वे जिस भी देश में जाते हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्षों या प्रमुखों के लिए भारत के अलग-अलग राज्यों से कुछ विशिष्ट पहचान की वस्तुएं ले जाते हैं, पर साथ ही साथ गीता और गंगा जल भी ले जाते हैं।

ज्यादा, 100 मिलियन से अधिक, और दुनिया भर में कराए जाने वाले अनेक सर्वेक्षणों में बार-बार यदि किसी राजनेता को सबसे प्रभावशाली माना गया है तो वे नरेन्द्र मोदी ही हैं।

दुनिया के एक भाग के लोगों में भारत के बारे में एक आदरयुक्त छवि पहले से भी रही है। यह छवि मोक्षदायिनी गंगा और दुनिया को मार्ग दिखाने वाले महान ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता के चलते थी। दुर्भाग्य से देश के हालात ऐसे बने कि वह छवि दरक गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इन्हीं दोनों अमूल्य धरोहरों को अपनी वैश्विक कूटनीति का आयाम बनाया। वे जिस भी देश में जाते हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्षों या प्रमुखों के लिए भारत के अलग-अलग राज्यों से कुछ विशिष्ट पहचान की वस्तुएं ले जाते हैं, पर साथ ही साथ गीता और गंगा जल भी ले जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत में जी-20 सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने एक घोष वाक्य दिया- 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'। सीधा-सपाट और साफ तौर पर सबकी समझ में आने वाला। भारत के विचार और भारतीय जीवन दर्शन को अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट करने के चलते ही नरेन्द्र मोदी न केवल भारतवर्षियों के हृदय में अजीज बन गए बल्कि वैश्विक जगत में उन्हें सम्मान के नजरिये से देखा जाना लगा। तभी तो पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर एयरपोर्ट पर स्वागत करने आए उस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मोराबे ने नरेन्द्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वह दृश्य देखकर हर देशभक्त भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कम बोलते हैं। हां, उनका काम ज्यादा बोलता है। भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थात् आधारभूत संरचनाओं में जिस तेजी से परिवर्तन हुआ, सड़कों से लेकर रेलवे के ट्रैक और कश्मीर की घाटी में वंदे भारत की पहुंच हो या सैन्य सामग्री का भारत में निर्माण या फिर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे भारत की बात... बस काम ही तो बोल रहा है। जहां तक वैश्विक स्तर पर मोदी-मोदी की गूंज सुनाई देने की बात है तो पहली विदेश मंत्री (स्वर्गीय) सुषमा स्वराज और अब एस. जयशंकर ने अपनी वाक्पटुता और कूटनीति से दुनियाभर में जो जमीन तैयार की, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं से वहां-वहां भारत का परचम फहराने का काम किया।

याद कीजिए कि योग न जाने कब से भारतीय जीवन में रचा-बसा है। पर इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर भारत के नाम का डंका बजाने का विचार किसके मन में आया। वह मोदी ही तो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा प्रस्ताव रखा, जिसके सह प्रायोजक दुनिया के 177 देश बने और

यह सबसे कम समय में पास होने वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव था। वह साल था 2014, अपने शपथ के छह महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह करिश्मा कर दिखाया था। और 2015 के बाद से 21 जून को कभी बुर्ज खलीफा पर योग मुद्राएं दिखती हैं तो कभी अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर। दुनिया भर में तिरंगे के साथ योग को जोड़कर प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीयों को गर्व करने का अवसर दिलाया।

जिम्मेदार भी आक्रामक भी

भारत के तटस्थ और गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति में किसी सीमा को किसी अवरोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अपने दो चिरपरिचित प्रतिद्वंद्वी पड़ोसियों, पाकिस्तान और चीन की तरफ भी उन्होंने पहले विनम्रता और बड़े मन से हाथ बढ़ाया। अफगानिस्तान से लौटते समय नवाज शरीफ के बुलावे पर अचानक पाकिस्तान चले जाना, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से ही उनके घर तक जाना एक दुस्साहस कहा जा सकता है। पर उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की निर्भीकता और ईमानदार कोशिश थी। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भारत हमेशा से प्राथमिकता देता है। यही संदेश देने तो नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक गुरु अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे। पर जब कारगिल में घुसपैठ हुई तो भारत की सीमा के भीतर ही रहकर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की पिटाई की, वह उन्हें आज भी याद होगी। पाकिस्तान में तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इतना भय पैदा कर दिया जो 47, 65 और 71 के युद्ध में भी नहीं किया जा सका था।

ठीक इसी प्रकार चीन से रिश्ते सुधारने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनिपिंग के साथ एक ही झूले पर झूला झूलकर संदेश देने का काम किया कि इसी में सबका आनंद है। पर चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आया, पहले डोकलाम और फिर गलवान में घुसपैठ कर उसने चुनौती दी। सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया बल्कि चीनी सैनिकों को आखिरकार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।



अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पहल करके ह्यूस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई। ट्रंप तो नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत के चुनावी माहौल में गुंजे नारे 'अबकी बार मोदी सरकार' की तर्ज पर उस सभा में खुद ही बोला-अबकी बार ट्रंप सरकार।



रखेगा। यह भी बहुत हास्यास्पद दिखता है, जब विपक्ष के लोग इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंधों को पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और टीका टिप्पणी करते हैं। पाकिस्तान और तुर्किए को छोड़ दें तो अधिकतर मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध अब तक के सर्वाधिक मधुर एवं परस्पर विश्वास के स्तर पर हैं, जबकि पाकिस्तान को लेकर अरब देशों में शंका बनी रहती है। कभी पाकिस्तान के हुक्मरान कर्ज को लेकर परेशान करते हैं तो कभी पाकिस्तान के भिखारी। दूसरी ओर भारत, अरब देशों का भरोसेमंद रणनीतिक साझीदार बना हुआ है। अरब के सभी देश और उनके शासक प्रधानमंत्री मोदी को 'बड़े भाई' कहकर संबोधित करते हैं। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' (ओआईसी) की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत को पहली बार 'विशिष्ट अतिथि' के रूप में 2019 में आमंत्रित किया गया था। यह प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह इस्लामी जगत में भारत के योगदान का प्रभाव नहीं है तो और क्या है।

भारतीय होने पर गर्व

यह सब एकाएक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को विशेष प्रमुखता दी। विदेश मंत्रालय का प्रभार उसे दिया गया, जो वैश्विक व्यवस्था को समझने का अनुभव रखता था और जिसकी अपनी खुद की अंतरराष्ट्रीय पहचान भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार में विदेश मंत्री की पहली जिम्मेदारी सुषमा स्वराज को दी। उनकी भारतीय राजनीति में एक गंभीर नेता और ओजस्वी वक्ता की पहचान थी। स्वर्णीय सुषमा स्वराज की वाकपटुता का आनंद देश की जनता और नेता ने तो लिया ही, विदेश के लोग और कूटनीतिज्ञों ने भी उनकी वाणी का लोहा माना। सुषमा स्वराज के कार्यकाल में वैश्विक जगत में भारत की पहचान सुधरने लगी तो विदेश में रह रहे भारतीयों की भी चिंता की जाने लगी। ध्यान रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ही पहली बार प्रवासी भारतीयों की सुध ली गई थी। आजादी के बाद से पहली बार हुआ जब 9 जनवरी, 2003 को भारत में पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी उसके केंद्र में थे और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ही उसकी मुख्य यजमान थीं। वही सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री बनीं तो यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री जनरल (से.नि.) वी.के.सिंह ने वहीं कैम्प किया और युद्ध के बीच से भारतीयों



अरब के सभी देश और उनके शासक प्रधानमंत्री मोदी को 'बड़े भाई' कहकर संबोधित करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' (ओआईसी) की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत को पहली बार 'विशिष्ट अतिथि' के रूप में 2019 में आमंत्रित किया गया।



की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई। उसके बाद कोरोना काल में दुनिया भर में फंसे भारतीयों को मिशन वन्दे मातरम् चलाकर स्वदेश लाया गया। लोग भूलें नहीं होंगे कि रूस के आक्रमण से ध्वस्त हो रहे यूक्रेन से सुरक्षित निकासी के लिए भारत का तिरंगा ही सबसे प्रभावी था। इतना कि वहां फंसे पाकिस्तानी भी भारतीय तिरंगा लहराते हुए वहां से बच निकले। लीबिया, इराक, आस्ट्रेलिया, लुगन्स्क और यूक्रेन के बाद अब ईरान से भी जो लोग अपने देश वापस आना चाहते थे, अजरबैजान के रास्ते भारत ने सुरक्षित वापसी कराकर अपना सिक्का जमाया। यह सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम ही है।

बढ़ा भरोसा भारत का

नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब देश की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह होने की स्थिति में थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी, आरबीआई एक्ट और सेबी एक्ट में सुधार कर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के सारे जतन किए। खुद ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं कर दुनिया के बड़े कॉरपोरेट के साथ नजदीकी रिश्ते बनाए। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भारत एक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में खड़ा हुआ। दुनिया के पचास से अधिक देशों के लोगों को वैक्सीन देकर जीवन बचाने की पहल की। श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भरपूर मदद कर उनको दिवालिया होने से बचाया। और जब जरूरत पड़ी तो चीन और पाकिस्तान को एक साथ रगड़ कर भी दिखाया।

इस समय भारत दुनिया भर के देशों के लिए आदर्श अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जिन-जिन देशों को ट्रंप प्रशासन ने घुड़की दी, उन सबने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। जापान, ब्रिटेन, यूरोप और अफ्रीका के देशों के लिए भारत एकमात्र ऐसा गंतव्य है जहां व्यापार की प्रचुर संभावनाएं हैं। जहां नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है, जहां निवेश पूरी तरह सुरक्षित है और जहां रिश्तों की अहमियत है।

नए दौर का भारत

याद करिए, जिस अमेरिका ने मुख्यमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी को एक समय वीसा देने से इंकार

कर दिया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हीं मोदी की गूंज जब सब तरफ से सुनाई देने लगी, जिस देश में मोदी जाते वहां वहां भारतवंशियों के बड़े-बड़े सम्मेलन होने लगे, हजारों हजार लोग जुटने लगे, तब 2019 के अपने दूसरे चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पहल करके ह्यूस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई। ट्रंप तो नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत के चुनावी माहौल में गूंजे नारे 'अबकी बार मोदी सरकार' की तर्ज पर उस सभा में खुद ही बोला- अबकी बार ट्रंप सरकार।

दरअसल, अमेरिका के साथ हमारा संबंध अलग-अलग समय पर बदलता रहा है। अमेरिकी प्रशासन अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाता रहा है। भारत भी अमेरिका से संबंध अपनी रणनीतिक जरूरतों के अनुसार ही चलाता रहा है। चाहे कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति हो, भारत को रूस और चीन के मुकाबले ज्यादा प्राथमिकता मिली। अमेरिकी कॉरपोरेट भी सबसे ज्यादा भारतीय समुदाय को ही पसंद करते हैं। भारतीय अमेरिकी व्यवस्था के न सिर्फ अनिवार्य अंग बन गए हैं, बल्कि सबसे सफल समुदायों में से एक हैं।

मोदी और ट्रंप की मित्रता और निकटता की चर्चा कर कई बार लोग आलोचना भी करते हैं। इसका कारण बहुत हद तक ट्रंप का रवैया और हर बात का क्रेडिट लेने की होड़ में देखा जा सकता है। पर मोदी बहुत परिपक्व, संतुलित और सावधान बने रहे। अमेरिका से व्यापार और अमेरिका में बसे भारतवंशियों की चिंता करते हुए भी उन्होंने रूस के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों पर आंच नहीं आने दी। ट्रंप की बार-बार की धमकियों के बाद भी यूक्रेन से जंग के दौरान भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर रूस से तेल खरीदता रहा। ट्रंप टैरिफ की धमकियों के सामने नहीं झुका। यहां तक कि 'ऑपरेशन सिंदूर' रुकवाने की ट्रंप द्वारा बार-बार किए गए दावों को मोदी ने अपने मौन से खारिज कर दिया। संसद में अधिकृत रूप से उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी का भारतीय सैन्य अधिकारी को किए गए फोन और गोलीबारी रोकने की याचना के बाद ही 'ऑपरेशन सिंदूर' को स्थगित किया गया है, अगर पड़ोसी मुल्क की ओर से फिर से कोई



अमेरिका के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों पर आंच नहीं आने दी। ट्रंप की बार-बार की धमकियों के बाद भी यूक्रेन से जंग के दौरान भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर रूस से तेल खरीदता रहा।



चीन से रिश्ते सुधारने के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक ही झूले पर झूला झूलकर संदेश देने का काम किया किया, पर चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आया, पहले डोकलाम और फिर गलवान में घुसपैठ कर उसने चुनौती दी। सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब ही नहीं दिया बल्कि चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।



दुस्साहस किया गया तो यह ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत पर किसी भी हमले के बाद हम किसी अमेरिका या अन्य देश के पास सुबूत लेकर नहीं जाएंगे। किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। दुनिया हमारी सदाशयता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना और वसुधैव कुटुंबकम के विचार का सम्मान करे, इसे हमारी कमजोरी न माने। क्योंकि इस सब विचार के बाद भी हमारा राष्ट्र और उसकी रक्षा सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम हमारा संकल्प है। भारत पर सीमा पार से किसी भी तरह का आक्रमण या देश के भीतर भी किसी भी आतंकवाद के कृत्य को हम युद्ध के तौर पर देखेंगे। और...यह नए दौर का भारत है, जो घर में घुसकर मारने की कूवत रखता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और बहुभाषी न्यूज एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के संपादक हैं।)



विकसित भारत



मनीष त्रिपाठी

वरिष्ठ पत्रकार-लेखक, वरिष्ठ समाचार
संपादक-दैनिक जागरण

योग का वैश्विक

पुनर्जागरण

यो

ग भारत की हजारों साल पुरानी वह धरोहर है, जिसे भारतीय ऋषियों ने 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन' के सिद्धांत पर विकसित किया था लेकिन समय के साथ यह अमूल्य विद्या केवल व्यक्तिगत साधना या योगशालाओं तक सीमित रह गई थी। 21वीं सदी के दूसरे दशक में, जब पूरी दुनिया जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों, मानसिक तनाव और वैश्विक अशांति से जूझ रही थी, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को एक वैश्विक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने योग को धर्म या देश-काल के दायरे से बाहर निकालकर एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित किया।

संयुक्त राष्ट्र में नए युग की आहट

27 सितंबर, 2014 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने पहले ही संबोधन में वह प्रस्ताव रखा, जिसने दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने किसी सैन्य गठबंधन या आर्थिक पैकेज की बात नहीं की, बल्कि

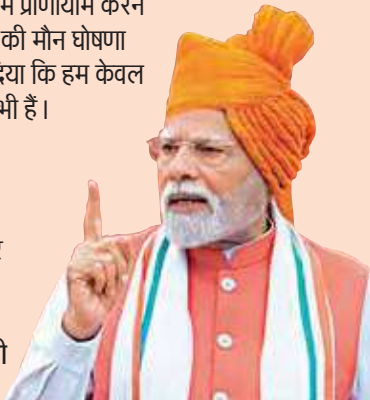


जो काम करोड़ों डॉलर के विज्ञापन नहीं कर सकते थे, वह योग ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सांस्कृतिक कूटनीति का केंद्र बनाया। जब दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय योग गुरुओं के सान्निध्य में प्राणायाम करने लगे, तो यह भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता की मौन घोषणा थी। योग के माध्यम से भारत ने यह संदेश दिया कि हम केवल लोकतंत्र नहीं हैं, बल्कि ज्ञानतंत्र भी हैं।



योग केवल कसरत नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, दुनिया के साथ और प्रकृति के साथ एकात्मता खोजने का माध्यम है।

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



योग की बात की। नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं को याद दिलाया कि "योग केवल कसरत नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, दुनिया के साथ और प्रकृति के साथ एकात्मता खोजने का माध्यम है।" उन्होंने तर्क दिया कि बदलती जलवायु और बढ़ती बीमारियों के दौर में योग ही वह समग्र दृष्टिकोण है जो संतुलन ला सकता है। इस प्रस्ताव की स्वीकार्यता इतनी अभूतपूर्व थी कि इसे 177 सदस्य देशों ने सह-प्रायोजित किया। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा समर्थन था। मात्र 75 दिनों के भीतर इस संकल्प को पारित कर दिया गया। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुनना भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक प्रतीकात्मक निर्णय था, क्योंकि यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन (ग्रीष्म संक्रांति) होता है, जो प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है।

रोजगार और समृद्धि का नया द्वार

प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के अपने संबोधन में पहली बार 'योग इकोनॉमी' का जिक्र किया था। 2025 तक यह शब्द एक ठोस आर्थिक हकीकत बन गया। यह केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक बहु-अरब डॉलर का उद्योग बन गया है जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है। एक अनुमान के अनुसार, 2025 तक वैश्विक योग बाजार 120 बिलियन डॉलर (करीब 10 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत की है। योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश पर आयुष मंत्रालय ने योग शिक्षकों के लिए गुणवत्ता मानक तय किए। आज भारतीय योग शिक्षकों के पास प्रमाणित डिग्री है, जिससे उन्हें अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में ऊंचे वेतन वाली नौकरियां मिल रही हैं। यह 'ब्रेन ट्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रणनीति का हिस्सा है।

सांस्कृतिक श्रेष्ठता की मौन घोषणा

राजनीति विज्ञान में सॉफ्ट पावर का अर्थ है—अपनी संस्कृति और मूल्यों के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करना। जो काम करोड़ों डॉलर के विज्ञापन नहीं कर सकते थे, वह योग ने कर दिखाया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सांस्कृतिक कूटनीति का केंद्र बनाया। जब दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय योग गुरुओं के सान्निध्य में प्राणायाम करने लगे, तो यह भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता की मौन घोषणा थी। योग के माध्यम से भारत ने यह संदेश दिया कि हम केवल लोकतंत्र नहीं हैं, बल्कि ज्ञानतंत्र भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जोड़ने वाली शक्ति (एकात्मता बल) के रूप में प्रचारित किया, जिसने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता की सीमाओं को तोड़ दिया।

राजपथ से वैश्विक मंच तक

प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने योग दिवस को केवल सरकारी औपचारिकता नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक जन-उत्सव बना दिया। 2015 में पहले योग दिवस पर नई दिल्ली में राजपथ (अब कर्तव्य पथ) का नजारा अद्भुत था। प्रधानमंत्री ने स्वयं हज़ारों नागरिकों के साथ जमीन पर बैठकर योग किया। इस आयोजन ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। इसने दुनिया को संदेश भी दिया कि भारत अपने नेतृत्व के साथ मिलकर चलने को तैयार है। इसके बाद 2016 से 2018 के वर्षों में प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़, लखनऊ और देहरादून जैसे शहरों को चुना। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में योग करके उन्होंने योग और पर्यावरण के संबंध को मजबूती से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक है, वह प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

स्वास्थ्य प्रणालियों में संरचनात्मक एकीकरण

भविष्य के भारत में योग केवल एक वैकल्पिक पद्धति नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री के 'आयुष्मान भारत' विजन के तहत, देशभर के 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग को मुख्य चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों (जैसे-बीपी, शुगर और तनाव) के बोझ को कम करना है। इससे भारत के स्वास्थ्य बजट में अरबों रुपये की बचत होगी, जिसे अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा।

तकनीक और परंपरा का संगम

प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत, योग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। 2025 के आयोजनों में हमने देखा कि कैसे एआई-आधारित





ऐप्स व्यक्ति की मुद्रा को लाइव ट्रैक करके उसे ठीक करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि भविष्य में हर व्यक्ति के पास उसका डिजिटल योग गुरु हो, जो उसे उसकी शारीरिक ज़रूरत के अनुसार अभ्यास कराए।

कोरोना काल में सुरक्षा का कवच

वर्ष 2020 और 2021 में जब कोविड-19 महामारी ने दुनिया को घुटनों पर ला दिया, तब प्रधानमंत्री मोदी का 'योग विजन' एक सुरक्षा कवच बनकर उभरा। उन्होंने योग@होम (घर पर योग) का संदेश दिया। उस दौर में योग केवल शारीरिक रूप से फिट रहने का साधन नहीं, बल्कि एकांत और डर से लड़ने की मानसिक शक्ति बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर 'एमयोगा एप' लॉन्च किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने योग की प्राचीन शिक्षाओं को मोबाइल तकनीक के माध्यम से दुनिया के करोड़ों लोगों की जेब तक पहुंचा दिया। यह डिजिटल इंडिया और प्राचीन योग का वह संगम था जिसने आधुनिक भारत की तस्वीर पेश की।

शिक्षा और कॉरपोरेट संस्कृति का हिस्सा

प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर नई शिक्षा नीति में योग को स्कूल से ही बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाने का खाका तैयार किया गया है। साथ ही, 'कॉरपोरेट योग' के माध्यम से कार्यस्थलों पर तनाव कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष वाई ब्रेक-मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। यह एक नए, ऊर्जावान और शांत कार्यबल का निर्माण करेगा।

वैश्विक मानक और प्रमाणन

भारत का लक्ष्य योग के लिए विश्व मानक स्थापित करना है। गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि योग की हर विधा का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण भारत से ही हो, ताकि दुनिया को शुद्ध और प्रामाणिक योग मिल सके।

2047 के विकसित भारत का आधार

प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य योग को केवल एक वार्षिक उत्सव या 21 जून की तस्वीर तक सीमित रखना नहीं है। उन्होंने इसे 'विकसित भारत @2047' के संकल्प का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया है। उनका मानना है कि एक समृद्ध देश वही हो सकता है जिसके नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों।

एक पृथ्वी-एक स्वास्थ्य का दर्शन

वर्ष 2025 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज हुआ। यह केवल 11वां योग दिवस नहीं था, बल्कि यह उस योग क्रांति के दस सफल वर्षों का उत्सव था जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में शुरू किया था। आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापत्तनम को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए चुनना एक गहरी रणनीतिक सोच का हिस्सा था। प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम को इसलिए चुना क्योंकि यह शहर भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और समुद्री सुरक्षा का मुख्य केंद्र है। समुद्र की लहरों के बीच हजारों योग साधकों के साथ योग करना इस बात का प्रतीक था कि योग की शक्ति असीम और अनंत है। यहां प्रधानमंत्री ने "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य" (वन अर्थ-वन हेल्थ) के सिद्धांत को वैश्विक मंच पर और अधिक प्रखरता से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव स्वास्थ्य को पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य से अलग नहीं किया जा सकता।

जन-भागीदारी का महासंगम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का एक दशक पूरा होने पर आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 10 विशेष कार्यक्रम शुरू किए। इसके अंतर्गत 'योग संगम' एक विशाल सामुदायिक भागीदारी थी। विशाखापत्तनम के रामकृष्ण बीच पर तीन लाख से अधिक लोगों ने योग किया, जो अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। पूरे भारत में 3.5 लाख स्थानों पर करोड़ों लोग इस अभियान का हिस्सा बने। युवाओं में बढ़ते डिजिटल तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 'योग अनप्लग्ड' की पहल पर ज़ोर दिया। इसका उद्देश्य तकनीक की दुनिया से कुछ समय के लिए डिटॉक्स होकर स्वयं के साथ





2023 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के लॉन में 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करना इस बात का प्रमाण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग को ग्लोबल डिप्लोमेसी के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया है। यह भारत की वह शक्ति है जो बिना किसी सैन्य संघर्ष के दुनिया के दिलों पर राज करती है।

जुड़ना था। इसी प्रकार हरित योग अभियान के तहत योग सत्रों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया, जिससे योग को पर्यावरण संरक्षण का एक साधन बनाया गया।

सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर तक

प्रधानमंत्री मोदी ने योग को केवल सांस्कृतिक निर्यात के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे भारत की स्मार्ट पावर का हिस्सा बनाया। आज जब दुनिया भर के दूतावासों में विदेशी नागरिक भारतीय तिरंगे के नीचे योग करते हैं, तो यह भारत की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के लॉन में 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करना इस बात का प्रमाण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग को ग्लोबल डिप्लोमेसी के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया है। यह भारत की वह शक्ति है जो बिना किसी सैन्य संघर्ष के दुनिया के दिलों पर राज करती है।

सियाचिन से महासागर तक योगशक्ति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को केवल शहरों के पार्कों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतीकों से भी जोड़ दिया। उनके विजन ने योग को एक ऐसी शक्ति के रूप में पेश किया जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहती है। भारतीय सेना के जवान सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में, जहां तापमान -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहां योग का अभ्यास करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं कई बार सैनिकों के बीच जाकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। कड़कड़ाती ठंड में 'प्राणायाम' और 'सूर्य नमस्कार' न केवल सैनिकों की शारीरिक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें उस एकांत और कठोर वातावरण में मानसिक दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार समुद्र में तैनात नौसैनिकों के लिए प्रधानमंत्री के सुझाव पर 'ओशन रिंग' का आयोजन किया गया। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर हजारों मील दूर तैनात नौसैनिक सूर्योदय के साथ योग करते हैं। यह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का वह वैश्विक संदेश है जिसे भारत की नौसेना दुनिया के बंदरगाहों तक पहुंचाती है। यह दृश्य दुनिया को दिखाता है कि भारत की शक्ति आक्रामक नहीं, बल्कि संतुलित है।

पूरी मानवता की साझा विरासत

स्पष्ट है कि जैसे-जैसे हम 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, योग आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य, शांति और एकता का सबसे बड़ा मंत्र होगा। यदि हम पिछले एक दशक का विश्लेषण करें, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को 'भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण' का चेहरा बना दिया है। उन्होंने इसे किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से ऊपर उठाकर मानवता से जोड़ा। उनकी व्यक्तिगत पहल और निरंतर प्रयास के कारण ही आज योग को यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' की सूची में स्थान मिला है। योग दिवस की सफलता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति का भी हिस्सा है, जिसने दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर पश्चिम तक भारत के प्रभाव को बढ़ाया है। उन्होंने इसे एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा बना दिया है जिसे बिना बोले पूरी दुनिया समझती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल और प्रयास से यह 1.4 अरब से अधिक भारतीयों की उस गौरवशाली संस्कृति की पुनर्स्थापना है, जो अब पूरी मानवता की साझा विरासत बन चुकी है।

वेलनेस टूरिज्म का उदय

भारत आज दुनिया के लिए 'वेलनेस कैपिटल' बन चुका है। ऋषिकेश, मैसूर, केरलम और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में योग टूरिज्म में 40% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। विदेशी पर्यटक अब केवल ताजमहल देखने नहीं आते, बल्कि हफ्तों और महीनों तक भारत के आश्रमों में रुककर योग और आयुर्वेद का लाभ लेते हैं। इससे स्थानीय होटल, परिवहन और कुटीर उद्योगों को भारी आर्थिक लाभ मिल रहा है।

आत्मनिर्भर भारत और योग सामग्री

प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत पहल का असर योग क्षेत्र में भी स्पष्ट है। पहले योग मैट और उपकरण चीन और अन्य देशों से आते थे। अब भारत में निर्मित इको-फ्रेंडली सूती और प्राकृतिक रबड़ की मैट, खादी के योग परिधान और जड़ी-बूटियों से बने उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। यह ग्रामीण भारत के शिल्पकारों और बुनकरों के लिए समृद्धि का नया रास्ता है।





डिजिटल योग और स्टार्टअप्स

प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान ने योग को भी हाई-टेक बना दिया है। आज भारत में सैकड़ों ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो एआई और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से योग सिखा रहे हैं। इन स्टार्टअप्स ने हजारों युवाओं को तकनीकी और योग प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया है।

योग और समावेशी विकास

प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा योग को समावेशी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने दिव्यांगजन के लिए विशेष योग मॉड्यूल तैयार करवाए, जिससे साबित हुआ कि योग हर शरीर के लिए है। साथ ही, 2024 की थीम 'महिला सशक्तिकरण के लिए योग' के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को योग प्रशिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक जागरण में सीनियर न्यूज एडिटर हैं।)



विकसित भारत



डॉ. राजेंद्र नाथ त्रिपाठी

वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक,
महामंत्री-वंगीय हिंदी परिषद, कोलकाता

आध्यात्मिक-वैज्ञानिक

चेतना के विरल साधक

21

वीं सदी का वैश्विक परिदृश्य तीव्र तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक द्वंद्व और नैतिक संकटों से परिपूर्ण है। ऐसे समय में नेतृत्व के लिए केवल प्रशासनिक दक्षता पर्याप्त नहीं रह जाती, बल्कि उसे वैचारिक गहराई और नैतिक आधार की भी आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व एक विशिष्ट अध्ययन का विषय बनता है।

भारतीय परंपरा में आध्यात्मिकता और ज्ञान का संबंध सदैव घनिष्ठ रहा है। आधुनिक काल में जब विज्ञान और आस्था को प्रायः परस्पर विरोधी माना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण इन दोनों के समन्वय की संभावना को पुनर्स्थापित करता है। आज के बदलते वैश्विक संदर्भों में, जबकि हमारी समूची वैज्ञानिक प्रगति मानव के विनाश की ओर अग्रसर हो चुकी है और उससे बाहर निकलने का कोई उपाय शेष नहीं बचा है, हमें विश्व कल्याण के अन्य विकल्पों की ओर देखना होगा। भारत भूमि निश्चित रूप से इस दिशा में हमारा समुचित मार्गदर्शन कर पाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उसी भारतीय मनीषा का मूर्त स्वरूप हैं, जिनकी ओर आज समूचा विश्व समुदाय



संघर्ष नरेन्द्र मोदी को घुट्टी में प्राप्त हुआ था, इसीलिए चुनौतियां उन्हें आज भी डिगा नहीं पाती हैं। बचपन से ही उनकी आध्यात्मिक सोच उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों की ओर उन्मुख करती रही और वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हिमालय की ओर चल पड़े थे। युवावस्था में हिमालय की ओर उनका झुकाव भारतीय तप और आत्मबोध की परंपरा से उनके आंतरिक संबंध को दर्शाता है।

आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के मूल में उसकी निरंतर प्रगतिशील सोच और वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अवधारणा को रेखांकित किया जा सकता है, जिनके आलोक में हम विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर पाने में सक्षम हो सके हैं। पीएम मोदी की वैचारिक सोच की जड़ें भारतीय मनीषा के बहुआयामी दृष्टिकोण से ऊर्जा ग्रहण करती हैं।

वैचारिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

नरेन्द्र मोदी का प्रारंभिक जीवन साधारण परिस्थितियों में व्यतीत हुआ, जिसने उनके व्यक्तित्व को व्यावहारिकता और अनुशासन प्रदान किया। वे प्रायः बाल्यकाल की अपनी स्मृतियों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उनका बचपन कठिन चुनौतियों से भरा हुआ था, जहां जीवित बचे रहना ही उनकी जीवन यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। वे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय भी बेचते थे और अपने परिवार के भरण-पोषण में अपना योगदान देते थे। उनकी माता घरों में काम करके आजीविका चलाने को विवश थीं। संघर्ष नरेन्द्र मोदी को घुट्टी में प्राप्त हुआ था, इसीलिए चुनौतियां उन्हें आज भी डिगा नहीं पाती हैं। बचपन से ही उनकी आध्यात्मिक सोच उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों की ओर उन्मुख करती रही और वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हिमालय की ओर चल पड़े थे। युवावस्था में हिमालय की ओर उनका झुकाव भारतीय तप और आत्मबोध की परंपरा से उनके आंतरिक संबंध को दर्शाता है।

उनका संगठनात्मक विकास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन और राष्ट्रवादी चिंतन से प्रभावित रहा। इस पृष्ठभूमि ने उनके भीतर सामूहिकता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को सुदृढ़ किया। संघ की कार्यशैली ने उनकी आध्यात्मिक चेतना को और अधिक समृद्ध किया और वे पूरी तरह राष्ट्र के प्रति समर्पित होते गए। परिजनों ने उन्हें गृहस्थ जीवन की जंजीरों में जकड़ना चाहा और अल्प वय में ही उनका विवाह भी कर दिया गया, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित इस चिर साधक को गृहस्थ जीवन बांध नहीं सका। भारत माता उन्हें पुकार रही थीं, यही कारण है कि वे सबकुछ छोड़कर मातृभूमि की सेवा के लिए चल पड़े। राजनीति उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र नहीं

था लेकिन जब राष्ट्र के समक्ष कुशल राजनैतिक नेतृत्व की आवश्यकता आन पड़ी, तब मोदी जी ने राष्ट्रीय दायित्व से मुंह नहीं मोड़ा। वे एक अनासक्त योगी की तरह एक राजनेता के रूप में राष्ट्र की सेवा करते रहे। प्रबल विरोध के उपरांत भी उनकी कार्यक्षमता में कभी कोई शैथिल्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ। विरोध के क्रोड़ से वे शक्ति अर्जित करते रहे।

आध्यात्मिकता का दार्शनिक आधार

पीएम नरेन्द्र मोदी की आध्यात्मिकता किसी संकीर्ण धार्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण का रूप लेती है। उनका सूत्र-“सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास”-भारतीय दर्शन के ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ सिद्धांत के अनुरूप है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की परंपरा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिन्होंने आध्यात्मिकता को सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन का आधार बनाया। पीएम मोदी के भाषणों में भगवद्गीता के कर्मयोग सिद्धांत का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है-विशेषतः निष्काम कर्म, कर्तव्यपरायणता और आत्मसंयम। गीता भारतीय चिंतन का नवनीत है। हर कर्मयोगी गीता से निश्चित रूप से प्रभावित होता है। गीता सांसारिकता और अध्यात्म को एक साथ लेकर मानव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की जो त्रिवेणी गीता के माध्यम से प्रवाहित होती है। वह भारतीय मनीषा का प्राण तत्व है। योगेश्वर श्रीकृष्ण से लेकर समस्त ज्ञानी ध्यानी महापुरुष गीता को ही प्रस्थान बिंदु के रूप में स्वीकार करते हैं। महात्मा गांधी की तरह पीएम मोदी की आंतरिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत गीता ही है।

योग, ध्यान और वैज्ञानिकता

मोदी के जीवन में योग और ध्यान का विशेष स्थान है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत अनुशासन के साथ-साथ वैश्विक स्वास्थ्य विमर्श का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा इस सांस्कृतिक कूटनीति की सफलता का प्रमाण है।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मोदी योग को केवल आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य-आधारित प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इसके “evidence-based validation” पर बल देते हैं। महर्षि पतंजलि ने सदियों पहले जिस योग दर्शन को प्रतिपादित किया था, उसे भारतीय चिंतन परंपरा ने दैनंदिन जीवन प्रक्रिया से जोड़ा और इस



पीएम नरेन्द्र मोदी की आध्यात्मिकता किसी संकीर्ण धार्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण का रूप लेती है। उनका सूत्र-“सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास”-भारतीय दर्शन के ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ सिद्धांत के अनुरूप है।



दिशा में मोदी का योगदान सर्वोपरि माना जाएगा। उन्होंने योग को व्यावहारिक धरातल प्रदान किया और इसे जनक्रांति के रूप में समूचे विश्व में प्रसारित कर दिया।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नीतिगत पहल

भारतीय संविधान में 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' को नागरिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। पीएम मोदी ने इसे शासन के केंद्र में रखने का प्रयास किया है। उन्हें यह ज्ञात था कि केवल अध्यात्म के मार्ग पर चलकर हम वैश्विक दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते। विश्व की व्यावहारिक आवश्यकताओं के लिए एक समृद्ध वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने भारतीय चेतना को नवीनतम वैज्ञानिक संकल्पों से जोड़ा और जन-जन में उसका प्रचार-प्रसार किया।

डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी नवाचार, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा (आयुर्वेद, योग) और आधुनिक चिकित्सा के एकीकृत मॉडल को प्रोत्साहित किया। आज भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से समूचा विश्व हैरान है। इतने कम समय में भारत ने डिजिटल इंडिया में महारत हासिल कर ली है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आज हम विश्व का मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। स्टार्टअप के द्वारा करोड़ों भारतीय युवा दुनिया को आज नई दिशा दे रहे हैं।

विज्ञान व आध्यात्मिकता का समन्वय

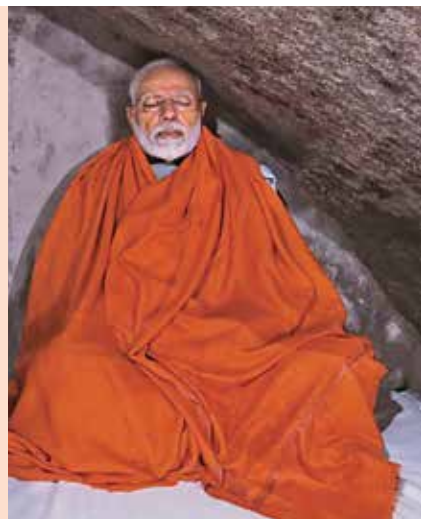
पीएम नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण यह मानता है कि विज्ञान बाह्य जगत का विश्लेषण करता है और आध्यात्मिकता आंतरिक चेतना का विकास करती है। दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य और पूरक हैं। यह विचार भारतीय ज्ञान परंपरा-विशेषकर उपनिषदों-की उस अवधारणा से मेल खाता है, जहां आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है। यह समन्वय आधुनिक युग में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि

यह मनुष्य के समग्र विकास की दिशा में एक समुचित मार्ग प्रशस्त करता है।

स्वच्छ भारत अभियान बाह्य स्वच्छता के साथ आंतरिक शुद्धता का भी प्रतीक है। फिट इंडिया मूवमेंट शारीरिक सक्रियता और मानसिक संतुलन दोनों पर बल देता है। सौर ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की पहल वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से वैश्विक समस्याओं के समाधान का संकेत देती है।

दीर्घकालिक योजना, आत्मसंयम, संकट प्रबंधन क्षमता और जन-संपर्क कौशल का समन्वय पीएम मोदी को एक प्रभावी और विशिष्ट नेता के रूप में स्थापित करता है। भारत और समूचा विश्व जब भी विकट चुनौतियों से ग्रस्त हुआ, तब मोदी की दूर दृष्टि ने समाधान की नई दिशाएं खोज लीं। कोरोना के वैश्विक संकट को हम कैसे भूल सकते हैं! जब सारी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी, पीएम मोदी चुनौतियों-प्रतिकूलताओं के बावजूद कोरोना की वैक्सीन के लिए अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। विश्व ने उसका सुखद परिणाम देखा। भारत ने न केवल अपने देशवासियों की रक्षा की, बल्कि विश्व के न जाने कितने असहाय देशों और लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की।

यह स्वीकार करना होगा कि विविधता से भरे भारत में संतुलन स्थापित करना एक जटिल कार्य है। हालांकि लगभग पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा रहता है, पर अपने कार्यकाल के आरंभिक दिनों से ही उन्हें कतिपय अवांछित विरोध का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि विरोधों और विरोधियों से विचलित हुए बिना वह देश हित में कठिन और चुनौतीपूर्ण निर्णय लेते रहे हैं। चाहे वह नोट बंदी का मामला हो या फिर कश्मीर के बारे में लिया गया उनका साहसिक निर्णय या फिर तीन तलाक कानून। कोई भी राजनेता प्रबल इच्छाशक्ति के बिना ऐसे कठोर फैसले नहीं ले सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने हार नहीं मानी। आलोचनाएं होती रहीं और राष्ट्रहित में निर्णय लिए जाते रहे। आज कश्मीर में पहले से अधिक शांति है। पहलगाम आतंकी हमले से उपजे तात्कालिक भय के माहौल के बावजूद पूरे कश्मीर में पर्यटक बेखौफ घूम रहे हैं। तीन तलाक बिल से मुस्लिम महिलाएं आज आजादी के वातावरण में सांस ले रही हैं। गुजरात में सामान नागरिक संहिता लागू करके पीएम मोदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्र हित और जनकल्याण ही उनके लिए सर्वोपरि है। एक स्वतंत्र, संप्रभु और पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक कानूनों को संविधान के ऊपर नहीं रखा जा सकता है।





नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक चेतना के समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक वैचारिक साधक के रूप में उभरते हैं। उनका दृष्टिकोण यह संकेत करता है कि भारत का भविष्य केवल तकनीकी विकास पर निर्भर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण पर भी आधारित है।



जब वैश्विक चुनौतियाँ हमारे संकल्प को चुनौती देती हैं तब अध्यात्म ही हमें रास्ता दिखलाता है। चुनौतियाँ आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन जब तक हम वसुधैव कुटुम्बकम् को अपना मूल मंत्र मानते रहेंगे और विश्वकल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे, तब तक चुनौतियाँ और प्रतिकूलताएँ कभी हमारा मार्ग बाधित नहीं कर सकती हैं। नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक चेतना के समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक वैचारिक साधक के रूप में उभरते हैं। उनका दृष्टिकोण यह संकेत करता है कि भारत का भविष्य केवल तकनीकी विकास पर निर्भर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण पर भी आधारित है। आज विश्व युद्ध की विभीषिका से ग्रस्त है। मानवता के संहार में आज कुछ लोग पूरी शक्ति के साथ अग्रसर हैं। किसी को मनुष्य की कोई चिंता नहीं है। मानवता से अधिक स्थान निजी स्वार्थ और अहंकार को मिलने लगा है, लेकिन भारत आज भी वैश्विक आपदा के बीच संयम और नैतिकता के साथ शांति के मार्ग तलाश रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर सब आशा के साथ देख रहे हैं। भीतर और बाहर हमारे शत्रु भी पूरी शक्ति के साथ नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हिमालय की तरह ही यह दृढ़ साधक विश्व कल्याण के प्रति सचेष्ट है और समूचा विश्व उसकी ओर आशा के साथ देख रहा है।



(लेखक संप्रति बंगीय हिंदी परिषद्, कोलकाता के महामंत्री हैं। कोलकाता स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में अध्यापन से जुड़े रहे हैं।)



विकसित भारत



प्रो. रामनारायण द्विवेदी
महामंत्री, श्रीकाशी विद्वत्
परिषद्, वाराणसी

मुझे मां गंगा ने बुलाया है

तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ अद्भुत् नेतृत्व, अदम्य साहस, विराट व्यक्तित्व के धनी, सर्वसमाज के हितैषी, लोकोपकारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जीवन में प्रथम बार जब लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो पतित-पावनी उत्तरवाहिनी मां भागीरथी गंगा को अपने संकल्प में जोड़ते हुए सर्वप्रकाशिका काशी भगवान विश्वनाथ की प्रियतमा नगरी को चुना। 2014 में जब नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से अपना नामांकन भरा था, तभी उन्होंने कहा था "...न मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो गंगा मां ने बुलाया है।" 2014 के इस संकल्प कि 'मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है' के साथ वे लगातार तीन बार वाराणसी से सांसद तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद उनके नेतृत्व में काशी का अद्भुत अप्रतिम चतुर्दिक विकास हुआ। साथ ही, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण सनातन हिंदुओं के विश्वास और आस्था का केंद्र बना। पहले जिन पतली गलियों में प्रवेश करते ही स्वच्छता-सुगमता का अभाव दिखता था, वहां आज भव्य-दिव्य मनोहारी तथा एक अद्भुत् वातावरण का



निर्माण एवं कोटि कोटि हिंदुओं सनातन धर्मावलंबियों को आकर्षित करता हुआ विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देश एवं दुनिया के हिंदुओं के लिए आस्था-विश्वास की साधनास्थली के रूप में विकसित हो चुका है। काशी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लगाव को इस बात से महसूस किया जा सकता है कि आज जब कभी दिल्ली में कोई काशीवासी उनसे मिलता है, तो वे उससे अवश्य पूछते हैं-‘मेरी काशी का क्या समाचार है? मेरे काशीवासी कैसे हैं?’ इस प्रकार के वाक्य काशी तथा काशीवासियों के प्रति उनका अद्भुत प्रेम दर्शाते हैं। इन सभी समीचीन उपलब्धियों से काशीवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं तथा उस आर्थिक-सामाजिक-आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र राष्ट्र के मानबिंदु विश्वनाथ धाम मंदिर सहित अनेक धरोहरों का संरक्षण, विरासतों का संवर्धन प्रत्येक काशीवासी के लिए आह्लादजनक तथा देश दुनिया को आश्चर्यचकित करने जैसा प्रयोग हुआ। असंभव कार्य को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संभव करके दिखाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दीर्घकालिक प्रशासनिक सेवाओं का पूर्ण लाभ समूचे भारत और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ काशी के लोगों को मिल रहा है। उनके कुशल नेतृत्व में विकास कार्यों को संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त हुआ है :

संकल्पसिद्धिस्तु सदैव जायताम्॥

सप्तैता मोक्षदायिका :

नगरी काशी अविनाशी सत्यार्थ की प्रकाशिका सर्वविद्या की राजधानी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान तीन खण्डों में स्थित है। तीनों खण्डों के अलग अलग माहात्म्य स्कन्ददिपुराणों में वर्णित हैं। दुनिया की सबसे प्राचीनतम आध्यात्मिक नगरी काशी है। सभी संप्रदायों के प्रायः पूज्य आचार्यों को काशी से प्रमाणीकरण हुआ है। यह काशी प्रमाणीकरण की भूमि है। लघु भारत के रूप में काशी को देखा जाता है। यह कहा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी राजनैतिक सर्वोच्चता का प्रमुख पद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अविनाशी काशी से ही चुने गए। राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारत सहित दुनिया का मार्गदर्शन करने वाली काशी सांस्कृतिक के साथ राजनैतिक नगरी के रूप में भी स्थापित हुई।

काशी में नवीन मंदिर या लिंग स्थापना से अधिक फल प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार से मिलता है। काशी में तिल तिल में लिंग हैं, इसलिये काशी में कहीं भी भूमि खोदना कठिन है। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इसीलिए नये तीर्थ का निर्माण या नये लिंग की स्थापना की अपेक्षा प्राचीन लिंग, कूप आदि के जीर्णोद्धार से दोगुना फल प्राप्त होता है :

काश्यां तिले तिले लिंगं काश्यां तीर्थं पदे पदे ।

खननं काशिभूमेस्तु दुर्घटं भाति पार्वति ॥

जीर्णोद्धारं च ये कुर्युर्निस्सन्देहा महाधिपः ।

स्वयं कृतं यद् वाप्यादि तदनन्तफलप्रदम् ॥

ततोऽप्यधिकधर्मादिजनकं जीर्णमुद्धृतम् ।

न तत्र लिंगपीडा स्यान्न तीर्थखननं भवेत् ॥

अतो जीर्णोद्धारः कार्या निरवद्या महाफला ।

जीर्णोद्धारं प्रकुर्वन्ति तेषां विश्वेश्वरः शिवः ॥ काशी रहस्य 7.56-58

काशी खण्ड में भी कहा गया है कि जीर्णोद्धार करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उस फल का प्रलय काल में भी नाश नहीं होता।

कालेन भंगमापन्नं जीर्णोद्धारं करोति यः ।

इह तस्य फलस्यान्तः प्रलयेऽपि न जायते ॥ - काशी खण्ड 21.116

भविष्य में जब भी काशी की समीक्षा इतिहास, पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के आधार पर की जाएगी, तो आध्यात्मिक चेतना के संवाहक के रूप में एक नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से अवश्य जुड़ेगा, जिसमें देवालयों से लेकर पंचक्रोशात्मक काशी का विकास, गंगा के घाटों का विकास, गंगा की घाटों की स्वच्छता सहित अकादमिक, संस्थानिक तथा सार्वभौमिक समरसतापूर्ण समाज के विकास हेतु अनेक कार्य हुए हैं।

2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीतने और पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी जब काशी आए थे, तो उस समय उनका संबोधन भावुक कर देने वाला था। उसी समय



500 वर्षों का कलंक अयोध्या धाम में जो लगा था, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ही नेतृत्व में उससे मुक्ति मिली है तथा भगवान श्रीराम के अद्भुत भव्य विग्रह के साथ दिव्य मंदिर का निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी को सजाने संवारने का सर्वविध प्रयास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अयोध्याधाम का प्राचीन वैभव जागृत हुआ है। 'रामो विग्रहवान् धर्मः' की छटा कोटि-कोटि हिंदुओं को अयोध्या धाम आने के लिए आकर्षित कर रही है। मां सरयू के घाट तथा पंचकोशी परिक्रमा मार्ग श्रीरामलला के जीवन दर्शन से ओतप्रोत होते हुए सनातन धर्मावलंबियों के लिए सुगम, सहज एवं सरल आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लाखों हिंदुओं का बलिदान, पूज्य संतों की आत्माहुतियां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज सफल प्रतीत हो रही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का मंदिर पूर्णतः हिंदुओं के लिए समर्पित हो चुका है।





उन्होंने काशी को विश्व पटल पर लाने, उसे साफ-सुथरा व विश्वस्तरीय शहर बनाने के साथ विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प जताया था। उन्होंने अपने संकल्प को सिद्ध करते हुए काशीवासियों को भारत सहित पूरी दुनिया में गौरवान्वित महसूस करने का सुअवसर दिया। जो कार्य आजादी के करीब सात दशकों बाद तक संभव नहीं हो सका था, उसे नरेन्द्र मोदी ने काशी का सांसद और प्रधानमंत्री बनने पर कुछ ही वर्षों में साकार कर दिया। आज देश और दुनिया के श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी में नव्य दिव्य बाबा विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाटों का दर्शन कर अभिभूत हो जाते हैं। उनका वहां से हटने का मन ही नहीं होता।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही यह विश्वास जताया था कि जब तक काशी फिर से देश का नेतृत्व नहीं करती, तब तक भारत दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। गुजराती होने के बावजूद देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव-जुड़ाव इतना गहरा है कि वे यहां आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इस बात को अब तक उनके यहां होने वाले 30 से अधिक दौरों से समझा और महसूस किया जा सकता है। खास बात यह है कि उनका यहां का दौरा अनायास ही नहीं होता। वे यहां के अपने हर दौर को खास बना लेते हैं और लगभग हर दौर में काशीवासियों को कोई न कोई बड़ी सौगात देते हैं, जिससे यहां के विकास को और पंख लग जाते हैं।

2014 के पहले की काशी और आज की काशी में जमीन-आसमान का फर्क आ गया है। इस बात को काशीवासी भी अच्छी तरह समझते हैं और इस आशातीत विकास का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही देते हैं, जिनकी पहल, प्रयास और संकल्प से काशी का आमूलचूल बदलाव संभव हो सका है। देश और दुनिया के जो श्रद्धालु या पर्यटक 2014 के पहले काशी जा चुके हैं, हाल के वर्षों में काशी आने के बाद इसके बेमिसाल बदलाव और सौंदर्यीकरण को देखकर उन्हें भी सुखद आश्चर्य होता है। हर किसी को लगता है कि काश, यह बदलाव पहले क्यों नहीं हुआ।

अपने पहले ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काशी को जापान के धार्मिक नगर क्योटो जैसा खूबसूरत बनाने का वादा किया था। इसके लिए पीएम मोदी जब जापान गए, तो उन्होंने वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे को बनारस आने का निमंत्रण दिया था। जापानी पीएम जब वाराणसी आए, तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने राजेंद्र प्रसाद घाट पर पंडित छन्नूलाल मिश्र के गायन के बीच गंगा आरती का आनंद उठाया। उसी दौरान काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। इसके बाद जापान से विशेषज्ञों की टीम का काशी दौरा हुआ। इस पहल से वाराणसी के घाटों के सौंदर्यीकरण की शुरुआत हुई।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम काफी तेजी से चल रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच 25,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में बन रहा है। इसके तहत फूड स्ट्रीट, रिवर फ्रंट समेत समेत काशी की तंग सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गंगा किनारे होकर 50 फीट चौड़ी सड़क से बाबा विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं।

वाराणसी क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से शिल्प-कला का बड़ा केंद्र रहा है। यही वजह है कि यहां के आठ उत्पादों को जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडीकेशन को बौद्धिक संपदा अधिकार का दर्जा हासिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी वादा किया था कि बनारस की बुनकरी और हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, पहचान दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए वाराणसी के बड़ा लालपुर में दीन दयाल हस्तकला संकुल यानी ट्रेड फैसिलिटी सेंटर खोला गया। प्रधानमंत्री की पहल और प्रोत्साहन से वाराणसी में 'काशी तमिल संगमम्' जैसे अनूठे सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक मेलजोल के नये युग की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल की शुरुआत 19 नवंबर, 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य उत्तर भारत (वाराणसी) और दक्षिण भारत (तमिलनाडु) के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और अकादमिक संबंधों को पुनर्जीवित करना और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को





मजबूत करना है।

देखा जाए, तो काशी आज केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र ही नहीं है, इस सांस्कृतिक नगरी को एक बार फिर अपना पुराना गौरव वापस मिल गया है। इसके साक्षी यहां के निवासियों के साथ-साथ देश और दुनिया से हर वर्ष यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भी बन रहे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में काशी का स्वरूप और निखरेगा। भगवान विश्वनाथ की यह नगरी अपने खूबसूरत गंगा तटों और नये स्वरूप की वजह से भी हर किसी को यहां आने के लिए विवश कर देगी।



(लेखक श्रीकाशी विद्वत् परिषद्, वाराणसी के राष्ट्रीय महामंत्री और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में प्रोफेसर हैं।)



विकसित भारत



प्रो. रवींद्र नाथ श्रीवास्तव 'परिचय दास'
प्रोफेसर, नव नालंदा महाविहार सम विश्वविद्यालय
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

सांस्कृतिक चेतना

और कवि मन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक सचेत राजनेता होने के साथ कवि हृदय भी रखते हैं। इसे उनके काव्य संग्रह “आंख ये धन्य है” से समझा जा सकता है। यह केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसे मन का सांस्कृतिक दस्तावेज है जो सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुँचने से पहले शब्दों की विनम्र ज़मीन पर अपने पदचिह्न बनाना चाहता था। नरेन्द्र मोदी की यह काव्य-चेष्टा उस परंपरा से संवाद करती प्रतीत होती है जहाँ कवि अपने समय का साक्षी होते हुए भी उससे थोड़ा अलग खड़ा रहता है—जैसे कोई व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी भीतर से एकांत में हो।

इन कविताओं में ‘आंख’ केवल देखने का साधन नहीं, बल्कि अनुभव का वह सूक्ष्म केंद्र बन जाती है जहाँ दृश्य और अदृश्य का संयोग होता है। यहाँ दृष्टि केवल बाहर की दुनिया को नहीं पकड़ती, बल्कि भीतर की कंपन को भी आकार देती है। इसीलिए “धन्य” होना यहाँ किसी चमत्कार का परिणाम नहीं बल्कि साधारण के भीतर असाधारण को पहचान लेने की क्षमता है। यह वही बिंदु है जहाँ कविता अपने सबसे शांत और सबसे प्रभावी स्वर में बोलती है।



यह धरती सुंदर है
 यह दृष्टि धन्य है
 हरी घास पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, भला
 यहां सूरज की रोशनी क्यों न पड़े?
 आकाश भव्य है
 और यह धरती सुंदर है
 इंद्रधनुष आकाश में खिल रहा है
 रंगों के घेरे बना रहा है
 जीवन का गुण क्या है?
 जीवन धन्य है, धन्य है
 सागर आकाश में बहुत ऊंचा उठता है
 कौन जाने बादलों की गहराई में क्या भरा है
 यह सब कुछ खाली है

यह धरती सुंदर है
 मैं मनुष्यों के समूह से मिलता रहा
 और दूसरों की संगति में, मैं खुद को पाता रहा
 यह सब अनोखा है
 और कुछ समझ से परे है
 धन्य है, धन्य है यह धरती
 मेरी धरती सुंदर है।



प्रधानमंत्री मोदी की कविताओं में प्रकृति का उपस्थित होना एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्स्मरण है। पेड़, नदी, आकाश—ये सब केवल दृश्य नहीं, बल्कि भारतीय संवेदना के स्थायी प्रतीक हैं। इनका प्रयोग किसी नवोन्मेषी चमत्कार के लिए नहीं बल्कि उस गहरे सांस्कृतिक ताने-बाने को छूने के लिए है जहां मनुष्य और प्रकृति का संबंध एक सहजीविता में बंधा रहता है। यह काव्य-दृष्टि कहीं-कहीं भक्ति काव्य की स्मृति भी जगाती है, जहां प्रकृति ईश्वर का विस्तार बन जाती है और मनुष्य उसका अनुगामी।

इन कविताओं का स्वर आत्मालाप का है पर वह आत्मालाप आत्ममुग्धता में नहीं फंसता। यहां एक प्रकार की सजगता है, जैसे कवि अपने ही शब्दों से थोड़ा सावधान हो। यह सावधानी शायद उस सार्वजनिक जीवन का परिणाम है, जहां हर अभिव्यक्ति अपने आप में एक संकेत बन जाती है। इसलिए इन कविताओं में जो भी कहा गया है, वह सीधे-सीधे कह देने के बजाय एक नियंत्रित लय में बहता है—जैसे नदी अपने किनारों को जानती हो।

सांस्कृतिक स्तर पर यह काव्य-संग्रह भारतीयता की एक विशेष छवि रचता है—जहां राष्ट्र केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। यहां देशभक्ति का स्वर ऊंचा नहीं, बल्कि भीतर से उठता हुआ एक धीमा कंपन है। यह कंपन कभी-कभी प्रार्थना जैसा लगता है, कभी स्मृति जैसा, और कभी भविष्य के प्रति एक मौन विश्वास जैसा।

फिर भी, यह कहना पड़ेगा कि इन कविताओं में जो लालित्य है, वह हमेशा स्वाभाविक नहीं लगता। कहीं-कहीं वह एक निर्मित सौंदर्य का आभास देता है—जैसे शब्दों को बहुत सावधानी से सजाया गया हो, ताकि वे अपनी सीमाओं से बाहर न निकल जाएं। यही वह स्थान है जहां पाठक को कविता और छवि-निर्माण के बीच की महीन रेखा दिखाई देने लगती है। और शायद यही इस संग्रह की सबसे दिलचस्प विशेषता है—यह कविता और व्यक्तित्व, निजी संवेदना और सार्वजनिक छवि, साधारण अनुभव और असाधारण स्थिति के बीच लगातार एक संतुलन साधने की कोशिश करता है। यह संतुलन कभी-कभी कविता को गहराई देता है, और कभी-कभी उसे सतह पर ही रोक देता है।

यहां कविता किसी क्रांति की घोषणा नहीं करती, न ही किसी गहरे विद्रोह का उद्घोष करती है। वह

बस धीरे से कहती है—देखो, यह दुनिया अभी भी देखने लायक है और अगर तुम्हारी आंख सच में ‘धन्य’ हो सके, तो हर साधारण दृश्य भी एक उत्सव बन सकता है।

कविता लिखना वैसे भी आसान काम नहीं और जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के इतने तीव्र प्रकाश में खड़ा हो, तब शब्दों को बचाकर रखना तो लगभग साधना जैसा हो जाता है। “आंख ये धन्य है” इसी की धीमी, संयत और भीतर तक उतरती हुई अभिव्यक्ति है। नरेन्द्र मोदी यहां कवि के रूप में प्रकट होते हैं और यह प्रकट होना किसी घोषणा की तरह नहीं, बल्कि एक शांत खुलती हुई खिड़की की तरह है।

इन कविताओं का सबसे बड़ा गुण उनकी दृष्टि है—वह दृष्टि जो देखने को एक साधना में बदल देती है। “आंख” यहां केवल दृश्य ग्रहण करने वाली इंद्रिय नहीं बल्कि संवेदना का केंद्र है। यह वही आंख है जो प्रकृति के साधारण दृश्यों में भी एक असाधारण अर्थ तलाश लेती है। पेड़ों की छाया, नदी का बहाव, आकाश की नीलिमा—ये सब यहां केवल बिंब नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे अनुभव में बदल जाते हैं जहां मनुष्य अपने भीतर लौटता है। यह लौटना किसी पलायन का संकेत नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व के साथ एक गहरे संवाद का आरंभ है।

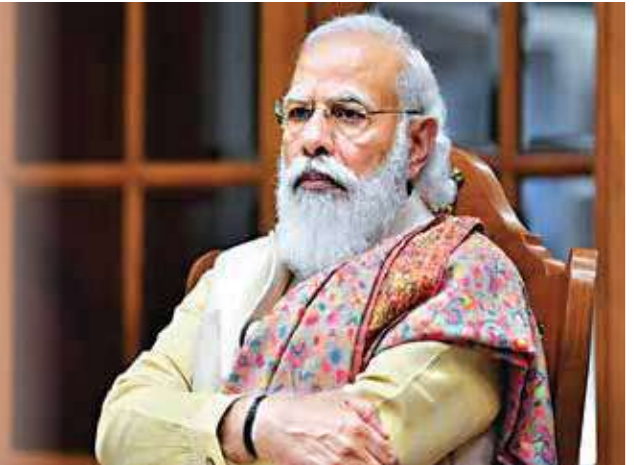
इस संग्रह की काव्य-भाषा में एक प्रकार की सादगी है, जो अपने भीतर लालित्य को छिपाए हुए चलती है। यह सादगी बनावटी नहीं लगती; उसमें एक स्वाभाविक प्रवाह है, जैसे कोई व्यक्ति बिना अलंकारों के भी सुंदर बोल सकता है। शब्दों की यह संयमता कविता को एक विशेष गरिमा देती है। यहां भाषा चक्राचौंध पैदा नहीं करती, बल्कि धीरे-धीरे पाठक के भीतर उतरती है और वहां एक स्थायी प्रतिध्वनि छोड़ जाती है।

प्रकृति का जो स्वर इन कविताओं में उभरता है, वह भारतीय सांस्कृतिक चेतना से गहरे जुड़ा हुआ है। यह वही परंपरा है जिसमें प्रकृति और मनुष्य का संबंध केवल उपयोगिता का नहीं, बल्कि आत्मीयता का होता है। कहीं-कहीं यह स्वर भक्ति काव्य की स्मृति को भी छूता है, जहां प्रकृति ईश्वर का रूप ले लेती है और मनुष्य उसके सामने एक विनम्र साधक बन जाता है। इस प्रकार, ये कविताएं केवल निजी अनुभव नहीं रह जातीं बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन जाती हैं।

इन रचनाओं में राष्ट्र का भाव उपस्थित है पर वह किसी ऊंचे उद्घोष के रूप में नहीं आता। वह एक शांत, भीतर से उठती हुई अनुभूति है—जैसे मिट्टी की गंध, जो बिना किसी घोषणा के मन को भर देती है। यह देशभक्ति का वह रूप है जिसमें शोर नहीं, बल्कि एक स्थिर विश्वास है। इस विश्वास में एक प्रकार की आध्यात्मिकता भी जुड़ जाती है, जो कविता को केवल राजनीतिक या



तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में
दूढ़ने की व्यर्थ कोशिश मत करो
मैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूँ
अपने आत्मविश्वास में
अपनी वाणी और कर्मक्षेत्र में।
तुम मुझे मेरे काम से ही जानो
तुम मुझे छवि में नहीं
लेकिन पसीने की महक में पाओ
योजना के विस्तार की महक में ठहरो
मेरी आवाज की गूंज से पहचानो
मेरी आंख में तुम्हारा ही प्रतिबिंब है।





‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का काव्य संग्रह “आंख ये धन्य है” केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसे मन का सांस्कृतिक दस्तावेज है जो सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले शब्दों की विनम्र जमीन पर अपने पदचिह्न बनाना चाहता था।’



सामाजिक संदर्भों से ऊपर उठाकर एक गहरे मानवीय स्तर पर ले जाती है।

इस संग्रह को पढ़ते हुए यह अनुभव होता है कि कविता यहां किसी प्रदर्शन की वस्तु नहीं, बल्कि एक आत्मिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कवि को भीतर से निर्मल करती है और पाठक को भी उस निर्मलता का स्पर्श देती है।

“आंख ये धन्य है” एक ऐसी काव्य-यात्रा बन जाती है, जिसमें दृष्टि, संवेदना और सांस्कृतिक स्मृति एक साथ चलती हैं। यह संग्रह हमें यह विश्वास दिलाता है कि शब्द, यदि वे सच्चे हों, तो किसी भी जीवन-परिस्थिति में अपना रास्ता बना सकते हैं—और तब एक साधारण-सी आंख भी सचमुच धन्य हो उठती है।

इस काव्य-संग्रह में एक संतुलन है, जैसे कोई धीमी नदी जो न तो उफनकर सब बहा ले जाती है, न ही ठहरकर दलदल बनती है। “आंख ये धन्य है” की काव्य-भूमि इसी मध्यवर्ती प्रदेश में आकार लेती है जहां अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों एक-दूसरे को परखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका पाठ करते हुए यह स्पष्ट होता है कि यहां कवि किसी जटिल वैचारिक जाल में पाठक को उलझाने की कोशिश नहीं करता। उसकी रुचि उस सरल बिंदु में है जहां अनुभव अपने सबसे स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है। यह सरलता, यदि सतही होती, तो कविता तुरंत निष्प्रभ हो जाती; लेकिन यहां वह एक प्रकार की साधना से निकली हुई लगती है। जैसे बहुत कुछ कह सकने की क्षमता होते हुए भी कम कहना चुना गया हो। नरेन्द्र मोदी के इस काव्य-स्वर में एक विशेष प्रकार की आत्म-निर्यंत्रित संवेदना दिखाई देती है। कवि के लिए अभिव्यक्ति केवल उच्छृंखल बहाव नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यहां कविता अपने आप में एक अनुशासन रचती है—एक ऐसा अनुशासन जिसमें भावनाएं नियंत्रित होते हुए भी अपनी ऊष्मा बनाए रखती हैं।

सांस्कृतिक स्तर पर यह संग्रह भारतीयता की एक अंतःसलिला को छूता है। यहां कोई आक्रामक सांस्कृतिक आग्रह नहीं है बल्कि एक स्वाभाविक उपस्थिति है—जैसे मिट्टी में नमी होती है पर वह स्वयं को घोषित नहीं करती। इस उपस्थिति में परंपरा की स्मृति भी है और आधुनिकता की हल्की छाया भी। परिणामतः कविता किसी एक समय या विचारधारा में सीमित नहीं रहती बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक निरंतरता का आभास देती है।

इन कविताओं का सौंदर्य उनके बिंबों की चमक में कम और उनकी लय की निरंतरता में अधिक है। यहां भाषा किसी अलंकारिक चकाचौंध का सहारा नहीं लेती; वह अपनी साधारणता में ही एक

प्रकार का दीर्घजीवी सौंदर्य रचती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कवि अपने ही व्यक्तित्व की व्यापक छवि के भीतर से बोल रहा है—जहां निजी अनुभव और सार्वजनिक जीवन एक-दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हो पाते। इस स्थिति में कविता एक दिलचस्प द्वंद्व रचती है: वह व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी। पाठक जब उसे पढ़ता है तो वह केवल कवि को नहीं बल्कि उस पूरे संदर्भ को भी महसूस करता है जिसमें यह कविता संभव हुई है।

इस संग्रह को पढ़ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संवेदनात्मक यात्रा है। इसमें सहमति या असहमति से अधिक महत्त्व उस अनुभव का है जो पाठक के भीतर धीरे-धीरे आकार लेता है। यह अनुभव कभी स्पष्ट होता है, कभी धुंधला, पर वह बना रहता है—जैसे कोई छवि, जो आंख से हटकर भी मन में बनी रहती है।

नरेन्द्र मोदी की काव्य-दृष्टि में जो एकांत है, वह किसी विरक्ति का एकांत नहीं बल्कि सक्रिय जीवन के बीच से निकला हुआ एक विराम है। यह विराम कवि को अपने ही भीतर लौटने की जगह देता है। इसलिए इन कविताओं में एक प्रकार की आत्मिक स्वच्छता दिखाई देती है—जैसे किसी ने अपने भीतर के शोर को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया हो ताकि शब्द साफ सुनाई दें। यहां स्मृति का स्वर उल्लेखनीय है। स्मृति इन कविताओं में बोझ नहीं बनती बल्कि एक हल्की छाया की तरह साथ चलती है। वह वर्तमान को ढकती नहीं बल्कि उसे एक गहराई देती है। इस प्रकार कविता केवल वर्तमान क्षण में सीमित नहीं रहती बल्कि समय के एक विस्तृत आयाम में फैल जाती है—जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक-दूसरे से संवाद करते हैं।

इन कविताओं का एक पक्ष है—उनकी आंतरिक लय। यह लय बाहरी छंदों या तुकों पर निर्भर नहीं करती बल्कि भावों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि इन्हें पढ़ते समय एक निरंतरता का अनुभव होता है जैसे कोई धीमी धुन चल रही हो। यह धुन कविता को एक विशिष्ट संगीतात्मकता प्रदान करती है। कभी-कभी कवि प्रश्नों को खुला छोड़ देता है, अनुभवों को अधूरा रहने देता है। यह अधूरापन ही कविता को जीवित रखता है क्योंकि पूर्णता अक्सर स्थिरता ले आती है जबकि अधूरापन गतिशीलता को बनाए रखता है।

सांस्कृतिक दृष्टि से यह संग्रह एक ऐसी भारतीयता को सामने लाता है जो किसी बाहरी प्रतीक या औपचारिकता में नहीं बल्कि संवेदना के स्तर पर मौजूद है। यह भारतीयता किसी आग्रह से नहीं बल्कि सहज अनुभव से उपजती है। इसी कारण वह पाठक पर थोपी हुई नहीं लगती बल्कि धीरे-धीरे उसके भीतर जगह बना लेती है। "आंख ये धन्य है" के भीतर बार-बार एक ऐसी संवेदना उभरती है जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही अपने को रोक लेती है। यह रुकना किसी हिचकिचाहट का

अभी तो मुझे आश्चर्य होता है
कि कहां से फूटता है यह शब्दों का झरना
कभी अन्याय के सामने
मेरी आवाज की आंख ऊंची होती है
तो कभी शब्दों की शांत नदी
शांति से बहती है
इतने सारे शब्दों के बीच
मैं बचाता हूँ अपना एकांत
तथा मौन के गर्भ में प्रवेश कर
लेता हूँ आनंद किसी सनातन मौसम का।





अगर कोई इमारत गिरती है,
तो मैं उसे सहारा देता हूँ।
मनुष्य के पीछे माधव
और राघव हैं।
मेरे पास शिव की बांसुरी
और धनुष है।
भगवान और शैतान के बीच
मुझे मनुष्य ही रहना है।
मनुष्य होना ही महान बात है।
मुझे धरती पर स्वर्ग दिखाई देता है।
यही मेरी विरासत है।
भीड़ को जाने दो।
मेले में मिलते हैं।

परिणाम नहीं बल्कि एक प्रकार की काव्य-सजगता है। जैसे कवि जानता हो कि हर अनुभव को शब्दों में बांध देना, उसकी संपूर्णता को सीमित कर देना होगा। इसीलिए वह कई बार संकेतों में बात करता है, और संकेतों की यही भाषा पाठक को सक्रिय बनाती है।

नरेन्द्र मोदी के इस काव्य-संसार में प्रकाश और छाया का एक निरंतर खेल चलता रहता है। प्रकाश वहां है, जहां अनुभूति स्पष्ट होकर सामने आती है; और छाया वहां, जहां वह धुंधली होकर भी अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। यह द्वंद्व कविता को एक आयामी होने से बचाता है। वह केवल उजाले की घोषणा नहीं करती बल्कि उस अंधेरे को भी स्वीकार करती है जो हर प्रकाश के पीछे अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। इन कविताओं की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अपने समय से संवाद करती हुई भी समयातीत होने की कोशिश करती हैं। यहां समकालीन जीवन की हल्की आहटें मिलती हैं पर वे कविता को किसी तात्कालिक संदर्भ में बांधती नहीं। इसके बजाय, वे एक व्यापक मानवीय अनुभव में बदल जाती हैं, जहां व्यक्ति अपने निजी क्षणों के साथ-साथ एक सामूहिक चेतना का हिस्सा भी बन जाता है।

भाषा के स्तर पर यह संग्रह किसी प्रयोगधर्मी जटिलता की ओर नहीं जाता पर उसकी सरलता को कमतर नहीं आंका जा सकता। यह वही सरलता है जो बार-बार पढ़े जाने पर अपने भीतर की परतें खोलती है। एक बार पढ़ने पर जो पंक्ति केवल एक विचार लगती है, वही दूसरी बार पढ़ने पर एक अनुभव बन जाती है और तीसरी बार वह एक स्मृति की तरह मन में बस जाती है। यही क्रम कविता को स्थायित्व प्रदान करता है। कहीं-कहीं यह भी महसूस होता है कि कवि अपने शब्दों के माध्यम से एक प्रकार की आत्म-प्रतिष्ठा नहीं बल्कि आत्म-परिचय की खोज में है। यह खोज उसे भीतर की ओर ले जाती है, और उसी भीतर से बाहर की दुनिया को देखने का एक नया कोण प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में कविता किसी उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि एक यात्रा का संकेत देती है—ऐसी यात्रा, जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं, केवल निरंतरता है।

"आंख ये धन्य है" के इस काव्य-प्रयास में एक निरंतरता है जो पाठक को बांधे रखने के लिए किसी बाहरी उत्तेजना का सहारा नहीं लेती। यहां कोई चौंकाने वाले मोड़ नहीं, कोई तीव्र नाटकीयता नहीं। इसके बजाय एक शांत, लगभग धैर्यपूर्ण गति है—जैसे कोई व्यक्ति बिना जल्दबाजी के, अपने ही विचारों के साथ चल रहा हो। यह गति आज के समय में थोड़ी असामान्य लग सकती है, जहां हर

चीज तुरंत प्रभाव चाहती है; पर यही असामान्यता इसे विशिष्ट भी बनाती है। इस संग्रह को पढ़ते समय पाठक अक्सर यह भूल जाता है कि वह किसी प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्तित्व की कविताएं पढ़ रहा है; वह केवल कविता के साथ रह जाता है और यह किसी भी काव्य-प्रयास के लिए कम उपलब्धि नहीं।

कभी-कभी महसूस होता है कि इन कविताओं में समय का एक धीमा, लगभग अदृश्य प्रवाह है। कोई स्पष्ट कालखंड सामने नहीं आता पर एक निरंतर परिवर्तन की अनुभूति बनी रहती है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं पर उनका परिवर्तन अचानक नहीं होता—धीरे-धीरे, लगभग अनजाने में। यही अनुभूति इस काव्य-संग्रह में भी उपस्थित है जो उसे एक प्रकार की जीवन-लय से जोड़ देती है। यह अपने पाठक को ज्ञान नहीं देता, कोई घोषणापत्र नहीं रचता, कोई अंतिम सत्य नहीं सुनाता। वह बस एक अनुभव देता है—धीरे-धीरे खुलने वाला, भीतर टिकने वाला, और समय के साथ अपने अर्थ बदलने वाला।

इस काव्य-संग्रह में एक हल्की-सी रिक्ति बची रह जाती है—वह जो किसी भी सच्ची काव्य-यात्रा का अनिवार्य अवशेष होती है। यह रिक्ति असंतोष की नहीं बल्कि उस जगह की है जहां पाठक और कविता के बीच अंतिम संवाद घटित होता है। “आंख ये धन्य है” इसी अंतिम संवाद की ओर धीरे-धीरे ले जाती है, बिना किसी शोर, बिना किसी आग्रह के।

नरेन्द्र मोदी के इस काव्य-प्रयास में जो तत्व सबसे अधिक ध्यान खींचता है वह है उसकी ‘संयमित आत्मीयता’। यह आत्मीयता पाठक को अपने भीतर खींचती है पर उस पर कोई बोझ नहीं डालती। वह आमंत्रित करती है, बाध्य नहीं करती। और यह भेद बहुत सूक्ष्म होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है—क्योंकि यहीं से कविता का नैतिक सौंदर्य निर्मित होता है।

इन कविताओं में जो ‘मौन’ बार-बार उपस्थित होता है, वह केवल शब्दों के बीच की खाली जगह नहीं बल्कि एक सक्रिय तत्त्व है। यह मौन ही वह जगह है जहां अर्थ अपने सबसे गहरे रूप में जन्म लेते हैं। शब्द वहां केवल संकेत बन जाते हैं और वास्तविक संवाद उस मौन में घटित होता है, जिसे पढ़ा नहीं, बल्कि महसूस किया जाता है। इस दृष्टि से यह काव्य-संग्रह एक प्रकार की ‘ध्यान-प्रक्रिया’ जैसा भी प्रतीत होता है—जहां पाठक धीरे-धीरे भीतर उतरता है और वहां उसे कोई शोर नहीं बल्कि एक सघन शांति मिलती है।

इस संग्रह से गुजरने के बाद कोई यह अपेक्षा करे कि कविता उसे कोई अंतिम सत्य सौंप देगी





तो यह उम्मीद थोड़ी अनुचित ही होगी। कविता का स्वभाव ही है—वह उत्तर नहीं देती, वह केवल प्रश्नों को अधिक संवेदनशील बना देती है। इस संग्रह की सफलता है कि यह हमें कुछ नया सिखाने का दावा नहीं करता पर हमें इस योग्य बना देता है कि हम पहले से मौजूद चीजों को थोड़ी अधिक गहराई से देख सकें। और मनुष्य के लिए जो अक्सर देखने की कला ही भूल जाता है, यह उपलब्धि कम नहीं मानी जानी चाहिए। नरेन्द्र मोदी का यह काव्य-स्वर अपनी सबसे प्रभावी स्थिति में तब पहुंचता है जब वह किसी विशेष पहचान से मुक्त होकर केवल 'कविता' बन जाता है। वहां न पद की ऊंचाई रहती है, न व्यक्तित्व का विस्तार—सिर्फ एक मनुष्य की संवेदना बचती है जो अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है। यही वह क्षण है जहां यह संग्रह अपनी सबसे सच्ची चमक प्राप्त करता है।

यह काव्य-यात्रा किसी तीव्र वैचारिक टकराव या प्रयोगधर्मिता की घोषणा नहीं करती। यह अपनी सीमाओं को जानती है और उन्हीं सीमाओं के भीतर एक सघनता रचती है। यह स्वीकार, यह आत्म-जागरूकता, इसे एक ईमानदार काव्य-प्रयास बनाती है। हर कविता यहां अपने पूरे दावे के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे संयम के साथ उपस्थित होती है। और शायद यही संयम इस संग्रह की सबसे बड़ी शक्ति है। यह पाठक को चकित करने की कोशिश नहीं करता; वह उसे धीरे-धीरे बदलता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि पहली नज़र में दिखाई नहीं देता पर समय के साथ उसका प्रभाव गहरा होता जाता है—जैसे कोई धीमी रोशनी जो अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे पूरे कमरे को भर देती है। यह संग्रह हमें यह नहीं सिखाता कि क्या देखना चाहिए बल्कि यह सिखाता है कि कैसे देखा जा सकता है और जब 'कैसे' बदल जाता है तो 'क्या' अपने आप बदल जाता है।



(लेखक नव नालंदा महाविहार सम विश्वविद्यालय (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार), नालंदा में प्रोफेसर हैं। हिंदी अकादमी, दिल्ली सरकार तथा मैथिली-भोजपुरी अकादमी, दिल्ली सरकार के सचिव रह चुके हैं। दर्जनों पुस्तकों के लेखक और साहित्य में 'सुगद्य' विधा के प्रवर्तक हैं।)



विकसित भारत

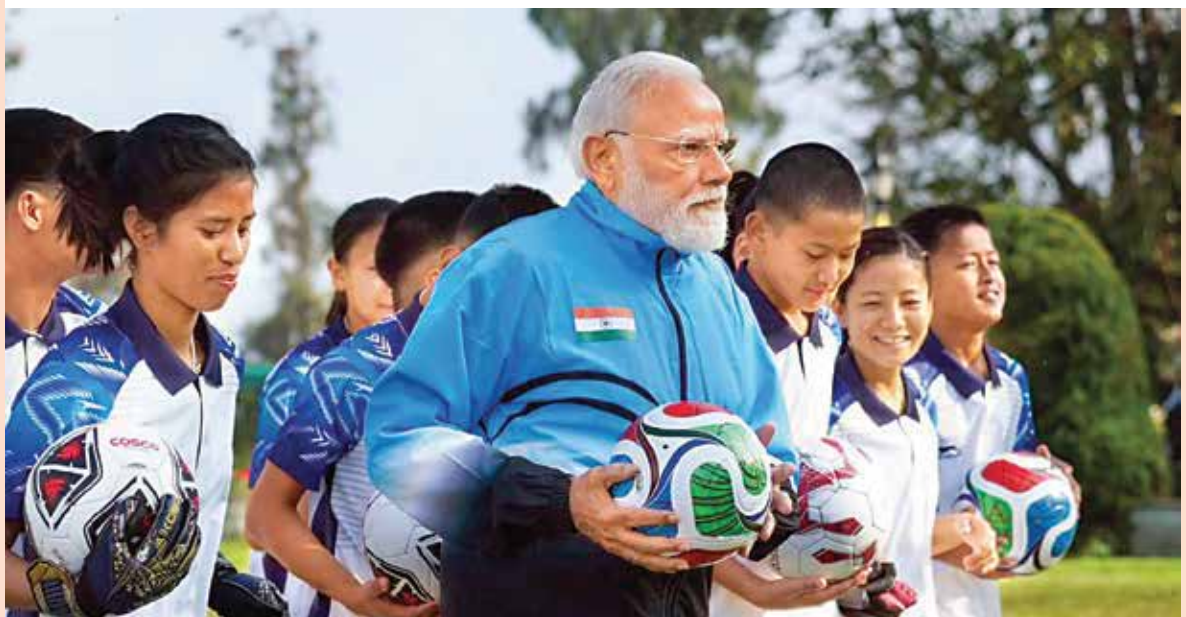


डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल
एमडी-एनआईडीटी ग्रुप, चेयरमैन-एनसीआर
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं
प्रेसिडेंट-मेरठ कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी

अनुशासन, कर्म व

ऊर्जा का संगम

मेरी उम्र इस समय बेशक करीब 84 वर्ष की हो गई है, पर मैं जब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन, उनकी दिनचर्या, सक्रियता, ऊर्जा और उत्साह को देखता हूँ तो मैं खुद को उनसे प्रेरित पाता हूँ। हालाँकि मेरा स्वयं का जीवन बेहद अनुशासित और सयमित रहा है, पर मैं प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में अनुशासन और कर्म का संतुलन देखकर बहुत प्रभावित होता हूँ। मुझे लगता है कि अगर देशवासी भारत को 2047 तक या उससे भी पहले विकसित भारत के पीएम मोदी के सपने को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री के निजी जीवन, खानपान के संतुलन, सक्रिय दिनचर्या, कर्मठता से जरूर सबक लेना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए जरूरी है, बल्कि इससे हमारे देश को भी दुनिया में अलग पहचान बनाने में मदद मिल सकेगी। मैं इस बात से हमेशा अभिभूत रहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी कदम से कभी यह झलक नहीं मिलती कि वह अपनी निजी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में घर परिवार छोड़ दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देश का खूब भ्रमण किया और उसे करीब से समझा। इस बात को इससे ही समझें कि जिस व्यक्ति ने देशसेवा के लिए



अपना घर-बार सब त्याग दिया हो, उसे भला किस चीज से मोह होगा। हालांकि पहले संघ के कार्यकर्ता, फिर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए कभी भी यह नहीं लगा कि वह जरा भी थके हैं या उनकी ऊर्जा में कोई कमी आई है। 75 की उम्र हो जाने के बावजूद वह बिना कोई छुट्टी लिए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुटे हैं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि सेहतमंद और फिट रहकर कोई समाज और देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि वह देशवासियों से अक्सर खुद को फिट रखने की अपील करते दिखते हैं। चाहे वह मोटापे पर नियंत्रण पाने की बात हो या फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में तेल का कम प्रयोग करने की बात। पीएम मोदी देशवासियों से बार-बार यह आग्रह करते हैं कि वे अपने रोज के जीवन में खाने के तेल की मात्रा में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाएं। जरा सोचें, इस तरह का आग्रह क्या पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया है? बिल्कुल नहीं। ये पीएम मोदी ही हैं, जो अपने देशवासियों की सेहत के लिए लगातार फिक्रमंद रहते हैं।

विकसित भारत के लिए संकल्प

मुझे प्रधानमंत्री मोदी की एक और खासियत बहुत बड़ी लगती है, वह यह कि वे हर समय देश के लिए चिंतित रहते हैं, उसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं और इसमें देशवासियों से भी सहयोग करने की अपील करते रहते हैं। पिछले दिनों कर्नाटक के मांड्या में आदिचुनचनगिरि महासंस्थान मठ में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करने के अवसर पर अपने भाषण में उन्होंने विकसित भारत के लिए नौ संकल्पों की चर्चा की और देशवासियों से इन संकल्पों को लेने और इन्हें सिद्धि तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, 'यदि हम ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इन नौ संकल्पों पर आगे बढ़ें, तो हम तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं।'

देश के लिए समर्पित जीवन

समकालीन भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व केवल उनके राजनीतिक निर्णयों या प्रशासनिक नीतियों तक सीमित नहीं है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में भी की

जाती है जिसकी जीवनशैली अत्यंत अनुशासित, सादगीपूर्ण और श्रमप्रधान है। यह प्रश्न अक्सर उठता है कि अत्यधिक व्यस्त और जिम्मेदार पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा, एकाग्रता और कार्यक्षमता को किस प्रकार बनाए रखता है। इस संदर्भ में नरेन्द्र मोदी की दैनिक दिनचर्या हर भारतवासी के लिए एक रोल मॉडल प्रस्तुत करती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीवनशैली में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, व्यक्तिगत अनुशासन, योग-साधना, समय-प्रबंधन और आधुनिक प्रशासनिक कार्यसंस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनके कई साक्षात्कारों, सार्वजनिक वक्तव्यों और निकट सहयोगियों के अनुभवों से यह पता चलता है कि उनका दिन अत्यंत सुव्यवस्थित होता है। उसमें समय के एक-एक क्षण का योजनाबद्ध ढंग से उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की व्यवस्थित-अनुशासित दिनचर्या से तुलना करते हुए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने खुद इसी तरह की अनुशासित दिनचर्या से इतना दीर्घ जीवन पाया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र वाक्य 'कर्म' है। मेरे लिए कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए कर्म किस तरह सबसे बढ़कर है, इसके असंख्य उदाहरण समय-समय पर सामने आते रहते हैं। इसमें मुझे वह क्षण सबसे अधिक हैरान करने वाला लगता है, जब अपनी मां हीराबेन के निधन पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। मां से प्रेरित एवं उनसे मन का जुड़ाव होने के कारण वह उस समय उनका अंतिम दर्शन करने जाने से खुद को रोक तो नहीं सके थे, पर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को सबसे ऊपर मानने के कारण ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और अगले दिन से प्रधानमंत्री पद के अपने दायित्व को निभाने में लग गए। क्या कोई और इस तरह का त्याग कर सकता है? आम लोगों से लेकर खास तक परिवार में शोक की कोई घटना होने पर कार्य से कुछ दिनों का अवकाश ले लेते हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने को राष्ट्र के प्रति कुछ इस तरह से समर्पित कर दिया है कि उनके लिए इससे बड़ा कोई नहीं है। वे बार-बार इस बात को कहते भी हैं कि उनके लिए 'राष्ट्र सबसे पहले' है। इसके लिए वे कोई समझौता नहीं कर सकते।

मैंने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी कभी आधी रात तक कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद सुबह-सुबह ही देश के सुदूर किसी इलाके में किसी सभा या परियोजना की शुरुआत करने के लिए पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, अक्सर यह भी देखा जाता है कि सुबह वह पूर्वोत्तर के किसी स्थान पर होते हैं, तो दोपहर बाद पश्चिम या दक्षिण में किसी योजना, परियोजना में शामिल दिखाई देते हैं। यह उनकी ऊर्जा, कर्मठता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रमाण नहीं तो और क्या है?

कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका अनुशासन है। वे सामान्यतः सुबह लगभग चार से पांच बजे के बीच जागते हैं। भारत की पारंपरिक जीवनशैली में



प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक छवि एक ऐसे नेता की है जो अत्यंत अनुशासित जीवनशैली, कठोर परिश्रम और उच्च कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी दिनचर्या केवल व्यक्तिगत जीवन का मामला नहीं है, बल्कि यह उनके प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय-प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है।



ब्रह्ममुहूर्त का समय मानसिक शांति, आध्यात्मिक अभ्यास और बौद्धिक कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। पीएम मोदी की दिनचर्या में इस परंपरा की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सुबह उठने के बाद वे कुछ समय ध्यान और मानसिक एकाग्रता के अभ्यास में बिताते हैं। ध्यान का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि मन को शांत और संतुलित बनाना भी होता है। राजनीतिक नेतृत्व में जहां लगातार निर्णय लेने पड़ते हैं और अनेक प्रकार के दबाव होते हैं, वहां मानसिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से ध्यान उनके लिए मानसिक स्थिरता का साधन माना जा सकता है। ध्यान के बाद प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। योग उनके जीवन का अभिन्न अंग है और वे इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक चेतना से भी जोड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार-प्रसार में उनकी भूमिका उल्लेखनीय मानी जाती है। उनके प्रयासों के चलते ही 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया, जिसे हर वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है।

पीएम मोदी के योगाभ्यास में सामान्यतः सूर्य नमस्कार, विभिन्न योगासन और श्वसन संबंधी अभ्यास शामिल होते हैं। योग के माध्यम से शरीर में लचीलापन, शारीरिक सक्रियता और मानसिक एकाग्रता बनी रहती है। प्रधानमंत्री स्वयं कई अवसरों पर कह चुके हैं कि योग उन्हें पूरे दिन कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। कभी-कभी योग के बाद वे हल्की सैर या प्रातः भ्रमण भी करते हैं। यह समय उनके लिए प्रकृति से जुड़ने और शारीरिक सक्रियता बनाए रखने का अवसर होता है। योग और व्यायाम के बाद प्रधानमंत्री अपने दिन का अगला चरण प्रारंभ करते हैं। इस समय वे देश-विदेश की प्रमुख खबरों का अध्ययन करते हैं, समाचार पत्र देखते हैं और डिजिटल माध्यमों से प्राप्त जन-प्रतिक्रियाओं पर भी नजर डालते हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि सुबह का समय वे समाचार पढ़ने, ई-मेल देखने और नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को समझने में भी लगाते हैं। यह आदत उनके प्रशासनिक निर्णयों को व्यापक जनमत से जोड़ने में सहायक मानी जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी के भोजन में भी अत्यधिक सादगी दिखाई देती है। वे सामान्यतः हल्का और पौष्टिक नाश्ता करते हैं, जिसमें फल, अंकुरित अनाज या पारंपरिक भारतीय व्यंजन जैसे पोहा, उपमा,

खाखरा आदि शामिल हो सकते हैं। उनका भोजन पूर्णतः शाकाहारी और संतुलित माना जाता है। दोपहर का भोजन भी अपेक्षाकृत हल्का होता है। वे भारी या अत्यधिक तैलीय भोजन से बचते हैं और घर का बना सरल भोजन पसंद करते हैं। कहा जाता है कि उन्हें खिचड़ी भी बहुत प्रिय है।

उनकी कार्यशैली के बारे में कहा जाता है कि वे दिन में कई घंटे लगातार काम करते हैं और प्रशासनिक कार्यों के प्रति अत्यंत सजग रहते हैं। राजधानी में रहने के दौरान वे आमतौर पर सुबह नौ बजे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पहुंच जाते हैं और देर रात तक वहां काम करते हैं। इस दौरान वे बैठकों, नीति-समीक्षाओं में व्यस्त हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की दिनचर्या यह दर्शाती है कि उनका अधिकांश समय राष्ट्र के प्रशासन और जनसंवाद में व्यतीत होता है। रात्रि भोजन के बाद भी उनका कार्य समाप्त नहीं होता। वे दिनभर प्राप्त दस्तावेजों, रिपोर्टों और फाइलों का अध्ययन करते हैं और अगले दिन की बैठकों तथा कार्यक्रमों की तैयारी करते हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि सोने से पहले वे दिनभर की फाइलें पढ़ते हैं और अगले दिन की योजनाओं पर विचार करते हैं। कई साक्षात्कारों में उन्होंने बताया है कि वे सामान्यतः लगभग चार से छह घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन गहरी नींद उन्हें पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिनचर्या केवल व्यक्तिगत अनुशासन का उदाहरण नहीं है, बल्कि वह आधुनिक सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व की एक विशिष्ट शैली को भी दर्शाती है। प्रातःकालीन योग और ध्यान से लेकर देर रात तक प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रहना उनकी कार्यनिष्ठा और समय-प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। उनकी जीवनशैली यह संकेत देती है कि नेतृत्व केवल राजनीतिक कौशल का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह निरंतर आत्मानुशासन, सादगी और श्रम की दीर्घकालिक साधना से निर्मित होता है।

प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक छवि एक ऐसे नेता की है जो अत्यंत अनुशासित जीवनशैली, कठोर परिश्रम और उच्च कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी दिनचर्या केवल व्यक्तिगत जीवन का मामला नहीं है, बल्कि यह उनके प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय-प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। राजनीतिक नेतृत्व के अध्ययन में अक्सर यह देखा जाता है कि उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की कार्यक्षमता का संबंध उनकी व्यक्तिगत आदतों, स्वास्थ्य अनुशासन और मानसिक संतुलन से होता है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की दैनिक दिनचर्या हमें यह समझने में सहायता करती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास आधुनिक प्रशासनिक नेतृत्व को प्रभावित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सामान्यतः लगभग चार से छह घंटे की नींद लेते हैं। यद्यपि यह अपेक्षाकृत कम समय प्रतीत होता है, लेकिन वे इसे पर्याप्त मानते हैं। नींद की गुणवत्ता और मानसिक संतुलन कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। इसलिए कम समय की नींद भी



मेरी देशवासियों से अपील है कि वे शुगर इनटेक कम करें और खाने के तेल में 10 प्रतिशत की कटौती करें। ये छोटे-छोटे बदलाव मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से बचाने में मददगार होंगे। फिटनेस केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे परिवार और समाज को भी लाभ मिलता है। इसके अलावा, रोजाना योग, व्यायाम और संतुलित खानपान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ('मन की बात' कार्यक्रम में)



"आइए हम
अगली पीढ़ी को
एक स्वस्थ राष्ट्र
उपहार में देने का
संकल्प लें, जहां
त्योहारों की तरह
ही फिटनेस को
भी महत्व दिया
जाता हो।"
-प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी



पर्याप्त हो सकती है यदि वह गहरी और संतोषजनक हो।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तिगत जीवन देशवासियों के लिए किस तरह रोल मॉडल हो सकता है, इसे उनकी दिनचर्या, स्वास्थ्य और खानपान को लेकर सावधानी से साफ समझा जा सकता है। इस उम्र में आयु संबंधी जटिलताएं और बीमारियां आम होती हैं, पर हमने शायद ही कभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बीमार, अस्पताल में भर्ती होने या छुट्टी लेकर स्वास्थ्य लाभ करने के बारे में कभी सुना हो या अखबारों-टीवी में पढ़ा-देखा होगा। चाहे वह देश में हों या विदेश में, वे हमेशा सक्रिय और ऊर्जावान नजर आते हैं। चुनावों के दौरान वे प्रधानमंत्री पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां भी करते नजर आ जाते हैं। उसी दौरान वे सुकून के पल भी निकाल लेते हैं, जैसे बंगाल चुनाव में जनसभा और रैली के दौरान उन्होंने हुगली नदी में नौकायन करते हुए फोटोग्राफी का वक्त निकाल लिया। उनकी यह तस्वीर और वीडियो समाचारों और सोशल मीडिया तक में खूब वायरल हुए। बंगाल चुनाव के तुरंत बाद सिक्किम के गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए पीएम मोदी की तस्वीर खूब वायरल हुई। आइए हम भारतवासी भी अपने प्रधानमंत्री के जीवन, उनकी ऊर्जा और कर्म के प्रति समर्पण से प्रेरणा लें। खुद को स्वस्थ और फिट रहने का प्रयास करते हुए जीवन का आनंद लेने के साथ देश को विकसित भारत बनाने की राह पर आगे बढ़ाने में हर सभंव योगदान दें। हम जब स्वस्थ और फिट रहेंगे, तभी नए कौशल सीखकर अपने साथ समाज और देश को आगे बढ़ा सकेंगे। यही हम सबके और देश के हित में है।



(वरिष्ठ चिकित्सक (प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ), शिक्षाविद और समाजसेवी के रूप में डॉक्टर ओमप्रकाश अग्रवाल एक जाने-पहचाने नाम हैं। वे मेरठ स्थित एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन और प्रतिष्ठित मेरठ कॉलेज की मैनेजमेंट कमिटी के प्रेसिडेंट हैं। वे सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल, मेरठ के अलावा ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (NIET) के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। पिछले करीब छह दशक से चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं और जरूरतमंदों के निःशुल्क उपचार एवं आर्थिक मदद के लिए जाने जाते हैं।)



विकसित भारत



अरुण श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार, मोटिवेशनल लेखक
एवं करियर काउंसलर

खाड़ी संकट

असर बेअसर

पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण दुनिया के तमाम देशों में मची अफरा-तफरी के बीच मार्च 2026 के आखिर में मेरे एक पत्रकार मित्र अयोध्या के किसी पेट्रोल पंप पर अपनी कार में तेल भरवाने पहुंचे। उन्हें यह आशंका थी कि पंप पर लंबी कतार होगी, पर इसके विपरीत उन्हें वहां सन्नाटा मिला। इस पर उन्होंने जब पेट्रोल पंप कर्मी से पूछा कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो इस पर उस कर्मी ने जो जवाब दिया, वह न केवल चौंकाने वाला बल्कि आंख खोलने वाला भी था। उसने कहा कि जब सब लोग अपनी गाड़ियों (कार, बाइक, ट्रैक्टर सहित) की टंकी फुल करा चुके हैं तो अब कौन यहां दिखाई देगा? तेल खत्म होने के बाद ही तो कोई यहां आएगा। ऐसा अनुभव खाड़ी संकट के दौरान पेट्रोल पंपों पर जाने वाले लगभग हर व्यक्ति का रहा। सवाल यह है कि जब पेट्रोल-डीजल का कोई संकट था ही नहीं, तो इस तरह की अफवाह किसने और क्यों फैलाई?

28 फरवरी, 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद जब होर्मुज जलडमरूमध्य बाधित हो गया, तो इस रास्ते आने वाले



पहले भारत में 27 देशों से कच्चे तेल और गैस का आयात किया जाता था, अब 41 देशों से ऊर्जा जरूरतों का आयात किया जाता है। भारत ने कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटिजिक रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन के रिजर्व पर काम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्ष में हमारी रिफाइनरिंग क्षमता भी बढ़ी है।

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



दुनिया के तकरीबन 20 फीसदी कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा आ गई। जाहिर है खाड़ी मुल्कों से दुनिया के तमाम देशों को निर्यात किए जाने वाले तेल व गैस की आपूर्ति लगभग पूरी तरह से बाधित हो गई। ऐसे में यूरोप सहित एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसे लेकर भारत में भी आशंकाओं और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार विरोधी दलों व लोगों ने खूब हवा दी। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक ऐसी खबरें और दृश्य दिखाए जाने लगे, जैसे कि पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के जबर्दस्त संकट के साथ भारत में भी लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इससे लोगों के बीच घबराहट का जो माहौल बना, उसमें देश के कुछ स्थानों पर अपने वाहनों की टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें दिखने लगीं। यही हाल गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी सिलेंडर के लिए लगी लंबी-लंबी लाइनों में भी दिखा। हालांकि वास्तविकता में जमीन पर ऐसा कोई संकट था ही नहीं। कुछ ही दिनों में पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा दिखने लगा, क्योंकि वाहनों की टंकी फुल करवा लेने और ड्रमों में पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक स्टॉक जमा कर लेने के कारण ऐसा करने वाले लोगों को अगले कई दिनों तक तेल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अनावश्यक रूप से जमा किया ईंधन खर्च ही नहीं हो पाया। हालांकि इस बीच जमाखोरी व कालाबाजारी की भी कोशिश हुई, जिस पर सरकार के सख्त रवैये के कारण अंकुश लगा।

इस घबराहट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में दिए गए अपने वक्तव्य में साफ कर दिया कि सरकार पश्चिम एशिया-होर्मुज संकट का अपने नागरिकों पर कोई असर न होने देने के लिए संकल्पित है। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग करके यह स्पष्ट किया जाता रहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। हमारे यहां पर्याप्त रणनीतिक भंडार है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देशों में जहां इस संकट के कारण पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में काफी बढ़ोत्तरी करने के साथ राशनिंग भी की गई, वहीं हमारे देश में पेट्रोल पंपों पर न केवल तेल का पर्याप्त स्टॉक रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम 70 डॉलर से बढ़कर 120 डॉलर के पार जाने के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। हां, आयातित एलपीजी के संकट को देखते हुए सिलेंडर की बुकिंग सीमा 15 से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई और व्यावसायिक सिलेंडरों पर तात्कालिक रोक लगा दी गई। हालांकि करीब डेढ़ महीने बाद ही व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति 70 फीसदी तक बहाल कर दी गई। हां, व्यावसायिक गैस सिलेंडरों सहित जेट फ्यूल और प्रीमियम पेट्रोल के दाम में कुछ बढ़ोत्तरी जरूर की गई, पर इसका आम आदमी

पर कोई असर नहीं पड़ा।

सवाल यह है कि आखिर देश में अफवाह और आशंका का माहौल कौन पैदा कर रहा था? जाहिर तौर पर इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है, जो राजग सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जले-भुने बैठे हैं, जिन्हें पीएम मोदी और सरकार को घेरने का कोई न कोई बहाना चाहिए। पर ऐसे नेताओं-दलों और आलोचकों की बोलती तब पूरी तरह से बंद हो गई, जब उन्हें एहसास हो गया कि वाकई सरकार ने भारत में पश्चिम एशिया संकट का कोई खास असर नहीं होने दिया है।

दरअसल, भारत में पेट्रोल-डीजल और गैस की खपत बहुत ज्यादा है। देश की कुल खपत का 85 से 90 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। चूंकि खाड़ी देशों (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इराक, ओमान, ईरान) से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया जाता है, ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट बाधित होने से हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल और प्रेरणा से विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी अपने कूटनीतिक संपर्कों-संबंधों का लाभ उठाते हुए चुपचाप काम करते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि होर्मुज के उस पार जहां विभिन्न देशों के ढाई-तीन सौ टैंकर और जहाज फंसे हुए थे, भारत के तकरीबन दस से अधिक टैंकर होर्मुज होकर भारत आने में सफल रहे। इसके अलावा, जिस रूस से सस्ता तेल लेने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक समय भारत पर 25 फीसदी का दंडात्मक शुल्क लगा दिया था, पश्चिम एशिया संकट के चलते उन्हें भारत को रूस से तेल लेने की छूट देनी पड़ी। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक विजय नहीं तो और क्या है? जहां हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि में तेल-गैस संकट के चलते आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई और कीमतों में बढ़ोतरी के साथ राशनिंग भी की जाती रही, वहीं हमारे देश में पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सामान्य रही। सबसे बड़ी बात आपूर्ति बनाए रखने की मुश्किल के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई वृद्धि न होना है, जो देश के आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात रही।

इस बारे में स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करते हुए सबका सहयोग मांगा। इस दौरान खाड़ी देशों में रहने और काम करने वाले लगभग एक करोड़ भारतीयों और उन जलक्षेत्रों में वाणिज्यिक जहाजों पर सवार बड़ी संख्या में भारतीय चालक दल के सदस्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वाभाविक रूप से भारत की चिंताएं कहीं अधिक हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इस संकट पर भारत की संसद से एकजुट और सर्वसम्मत आवाज विश्व के सामने रखी जाए। प्रधानमंत्री ने संसद में ऊर्जा आपूर्ति के गंभीर मुद्दे पर स्वीकार किया था कि बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुएं होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर भारत पहुंचती हैं, और युद्ध के बाद से जलडमरूमध्य से होकर माल ढुलाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार का मुख्य ध्यान आम परिवारों को कठिनाइयों से बचाने पर रहा। एलपीजी के घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देने और इसके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने जैसे उपायों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में अपनाई गई ऊर्जा विविधीकरण रणनीति वर्तमान संकट में काफी कारगर साबित हुई। भारत ने पिछले 12 वर्षों में ऊर्जा आयात के अपने स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है, जिससे किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भरता कम हो गई है। मोदी सरकार के इस दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण के चलते आज की परिस्थितियों में ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में पिछले 12 वर्षों में उठाए गए कदम और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। भारत के पास आज 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। तेल कंपनियों के अलग-अलग भंडारों के अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक का भंडार बनाने का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के निरंतर प्रयासों से पिछले 12 वर्षों में देश की शोधन क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।



इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण जो एक दशक पहले मात्र 1-1.5 प्रतिशत था, आज लगभग 20 प्रतिशत हो गया है। इससे तेल आयात में प्रति वर्ष लगभग साढ़े चार करोड़ बैरल की कमी आई है। रेलवे के विद्युतीकरण से भी प्रति वर्ष लगभग 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हुई है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 2014 में 250 किलोमीटर से कम से बढ़कर आज करीब 1,100 किलोमीटर हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह बात बिल्कुल सही है कि वैकल्पिक ईंधन के विभिन्न स्रोतों पर आज जिस स्तर पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और भी सुरक्षित होगा।

पश्चिम एशिया संकट का भारत की कृषि और किसानों पर भी कोई असर नहीं हुआ है। इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की कारगर नीति को श्रेय दिया जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी और उससे संबंधित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के दौरान भी जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यूरिया की कीमतें 3,000 रुपये प्रति बोरी तक पहुंच गई थीं, तब भी सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि भारतीय किसानों को वही बोरी 300 रुपये से कम में मिले। खाड़ी संकट के कारण उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में आई तेजी के बीच ही देश के किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। इसके तहत खरीफ सीजन से पहले केंद्र सरकार एक बार में 25 लाख टन यूरिया आयात करने का निर्णय लिया, जो देश के कुल सालाना आयात का करीब एक चौथाई है। बड़ी बात यह है कि कीमतों में भारी तेजी के चलते दो महीने पहले की तुलना में लगभग दोगुनी कीमत पर खरीदा जा रहा है, पर इसका बोझ किसानों पर नहीं डाला जाएगा। हालांकि देश में फिलहाल यूरिया का संकट नहीं है, पर किसानों तक आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आयात आवश्यक है। सरकार ने साफ कर दिया कि किसानों को अनुदानित दर पर मिलने वाली खाद की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 45 किलो का यूरिया बैग 266.50 रुपये और डीएपी का

50 किलो का बैग 1350 रुपये में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अप्रैल 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 41,533.81 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को स्वीकृति दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में चार हजार करोड़ रुपये अधिक है। आपूर्ति में निरंतरता के लिए रूस, मित्र, नाइजीरिया, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि से यूरिया खरीदा जाएगा। होर्मुज जैसे पारंपरिक समुद्री मार्गों में बाधा को देखते हुए यह यूरिया केप ऑफ गुड होप जैसे वैकल्पिक रास्तों से मंगाया जा सकता है।

भारतीय कृषि को बाहरी झटकों से बचाने के लिए उठाए गए संरचनात्मक कदमों के तहत पिछले एक दशक में छह नए यूरिया संयंत्र चालू किए गए हैं, जिससे वार्षिक उत्पादन क्षमता में 76 लाख मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि हुई है। डीएपी और एनपीकेएस उर्वरकों का घरेलू उत्पादन लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है और उर्वरक आयात के स्रोतों में विविधता लाई गई है। जिस तरह तेल और गैस आयात को विविधीकृत किया गया है, उसी प्रकार डीएपी और एनपीकेएस के आयात के विकल्पों का भी विस्तार किया गया है। मेड-इन-इंडिया नैनो यूरिया जैसे नवोन्मेषणों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और डीजल पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत 22 लाख से अधिक सौर पंपों के वितरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सराहनीय रही है।

पिछले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति से सरकार की तैयारियों को अत्यधिक मजबूती मिली है। भारत की कुल संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा अब नवीकरणीय स्रोतों से आता है और देश की कुल नवीकरणीय क्षमता 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है। अकेले सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 12 वर्षों में लगभग तीन गीगावाट से बढ़कर 140 गीगावाट हो गई है। लगभग 40 लाख रूफटॉप सौर पैनल लगाए गए हैं। गोबर्धन योजना के तहत 200 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र अब चालू हैं और परमाणु ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही एक नई स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना भी है जो अगले पांच वर्षों में 1,500 मेगावाट क्षमता जोड़ेगी। पश्चिम एशिया में युद्ध आरंभ होने के बाद से 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं, जिनमें अकेले ईरान से लगभग 1,000 भारतीय शामिल हैं, जिनमें से 700 से अधिक युवा मेडिकल छात्र हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ने 2,432



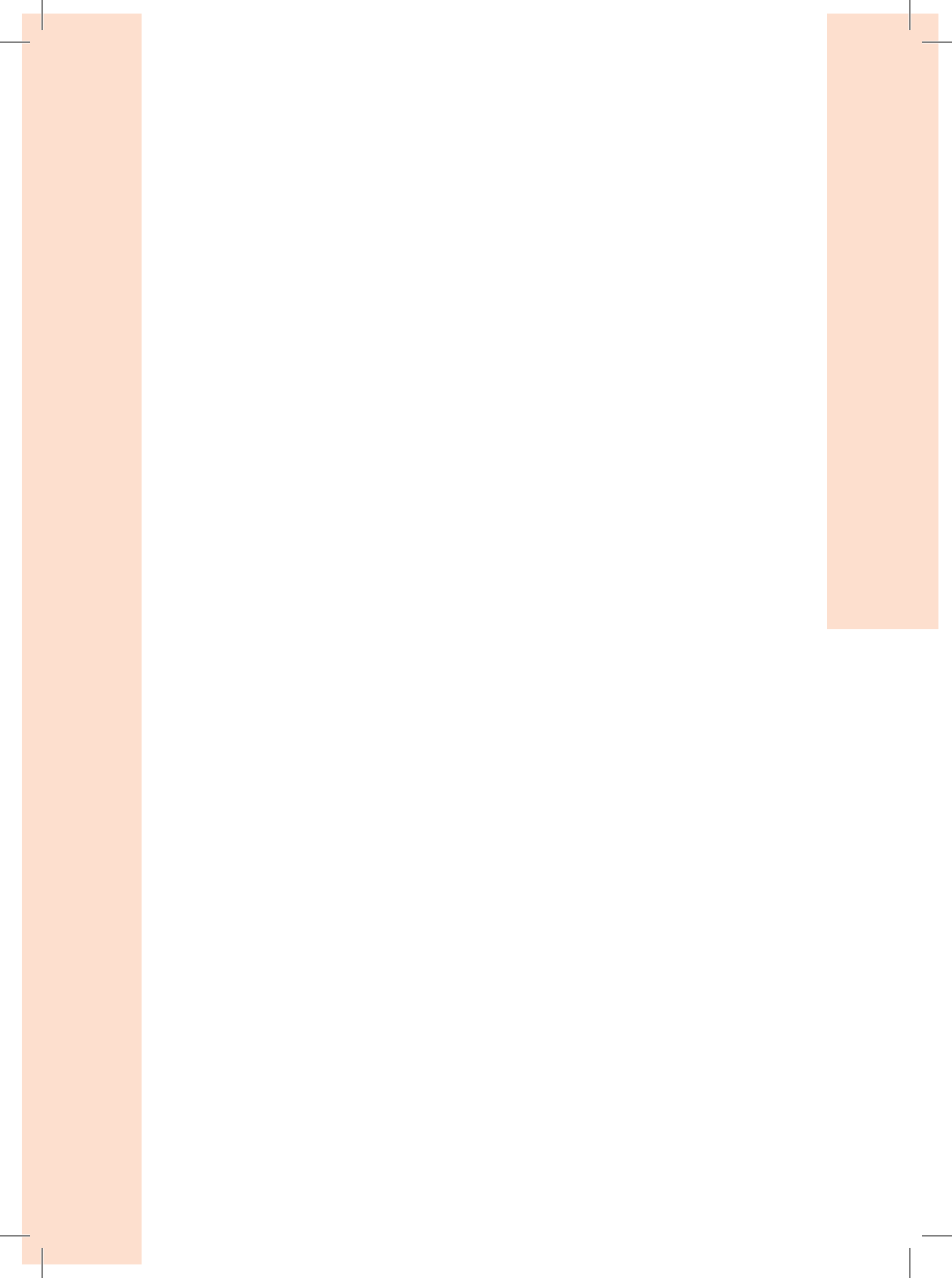


भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर निकालकर आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचाने में मदद की है। इनमें 1,096 भारतीय छात्र और 657 भारतीय मछुआरे शामिल हैं। 28 फरवरी से अब तक संकटग्रस्त खाड़ी क्षेत्र से 12 लाख से अधिक भारतीय देश लौट चुके हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट के असर को जिस बुद्धिमत्ता के साथ बेअसर किया है, वह हैरान करने वाला है। कोई और सरकार या नेता इस स्थिति को इतनी कुशलता व कूटनीति के साथ शायद ही संभाल पाता। भारत के अमेरिका, इजरायल, ईरान, रूस के साथ खाड़ी के अन्य सभी देशों के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने इस संकट के समय खुद को तटस्थ रखकर न केवल इन देशों के साथ अपने संबंधों का निर्वहन किया, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' की नीति पर चलते हुए देशवासियों को खाड़ी संकट के दुष्प्रभाव से भी बचाए रखा। आने वाले दिनों में जब इस संक्रमण समय का इतिहास लिखा जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार के सफल कूटनीतिक प्रयासों को ही दिया जाएगा।



(लेखक पिछले करीब 34 वर्षों से दिल्ली-एनसीआर में मुख्य धारा की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। दैनिक जागरण से करीब 20 वर्ष तक जुड़े रहे। वहीं फीचर संपादक भी रहे। सिविल सर्विसेज क्राॅनिकल, चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे और कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू के संपादक भी रहे। दैनिक जागरण सहित देश की अन्य प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में 1000 से अधिक आलेख प्रकाशित। लेखक और पत्रकार के साथ-साथ करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल लेखक के रूप में भी सक्रिय। दैनिक जागरण 'जोश' परिशिष्ट में 15 वर्ष तक लगातार 'काउंसलर' कॉलम प्रकाशित होने का रिकॉर्ड। अब तक 30 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं सहित उनके अभिभावकों का प्रेरक मार्गदर्शन।)



विशेष खंड
नारी-शक्ति वंदन





विकसित भारत



डॉ. सरोजिनी अग्रवाल

पूर्व एमएलसी-यूपी,
चेयरपरसन-एनआईडीटी ग्रुप

आधी आबादी

को पूरा अधिकार

नारी शक्ति वंदन विधेयक में संशोधन और लोकसभा व विधानसभा सीटों के परिसीमन के साथ महिलाओं के लिए 33 फीसदी स्थान सुरक्षित करने को लेकर 16 से 18 अप्रैल, 2026 तक बुलाए गए संसद के विशेष अधिवेशन को कई मामलों में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। अभूतपूर्व इसलिए, क्योंकि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। उन्होंने अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया से लेकर राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आहूत करके यह दिखा दिया कि वे आधी आबादी को उसका अधिकार दिलाने के अपने संकल्प को किस तरह सिद्धि तक पहुंचाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, संसद के विशेष सत्र के दौरान उन्होंने खुद इसके लिए सभी दलों का आह्वान किया कि वे इसके लिए राजनीति को परे रहकर इसका समर्थन करें, ताकि देश की महिला शक्ति उनका अभिनंदन करे।

भले ही लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका, पर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आजादी साढ़े सात



हम भ्रम में न रहें, हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। जी नहीं। यह उसका हक है। हमने कई दशकों से उसे रोका है। आज उसका प्रायश्चित्त कर के उस पाप से मुक्ति पाने का यह मौका है।
-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

दशक से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की नीयत पहले की सरकारों ने नहीं दिखाई। बेशक ग्राम पंचायतों में तो यह अधिकार मिल गया था, पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में इसे लागू करने में किसी न किसी बहाने हीला हवाली की जाती रही। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस उदासीनता और अनदेखी का जिक्र भी खास तौर पर अपने भाषण में किया और यह भी कहा कि यह निर्णय से कहीं ज्यादा नीयत की बात है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस विधेयक को लेकर कितने संजीदा रहे हैं, यह पिछले कुछ दिनों में उनके उत्साह और सक्रियता से साफ समझा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रधानमंत्री या सरकार ने इतनी गंभीरता से पहले कभी इस मुद्दे को उठाया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह नेक काम बहुत पहले हो गया होता। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर देश और राजनीतिक दलों में सर्व-सम्मति बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अखबारों में लेख लिखे। अपने भाषणों में बार-बार अपील की। इतना ही नहीं, देश भर से नारी-शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं का दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया। इसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी सहभागी बनीं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां अपने संबोधन में उनका भी खास तौर पर जिक्र किया।

नारी शक्ति वंदन विधेयक पर लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण का अंश



हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा और यह मंथन देश की दिशा और दशा तय करेगा। आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह 20-25 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, समय-समय पर इसमें सुधार होते रहते। सदन के सभी साथियों को यह अवसर मिला है।



राजनीतिक जीवन में जो लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25 से 30 वर्ष में ग्रासरूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर महिलाएं लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33 फीसदी का सामर्थ्य नहीं है, बल्कि वे आपके फैसलों को भी प्रभावित करने वाली हैं। इसलिए जो आज विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजनीतिक समझदारी इसी में है कि हम जमीनी स्तर पर महिलाओं की जो राजनीतिक लीडरशिप खड़ी हुई है, उसे संदर्भ में लें।

नारी शक्ति वंदन विधेयक पर लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण का अंश

 यह निर्णय भारत का कमिटमेंट है, सांस्कृतिक कमिटमेंट है। इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में यह व्यवस्था बनी। हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है। सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। वे अच्छा योगदान देंगी। जितनी हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम से सदन को समृद्ध किया है। देश में वर्तमान में 2700 ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं, जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। शहरों में मेयर हों या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली महिलाएं। जब यह अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तो यह अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद यह अवसर है कि हम पुरानी मर्यादाओं से बाहर निकलें और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और नारी शक्ति की सहभागिता को सुनिश्चित करें।

 यहां बैठकर हमारे संविधान ने किसी को टुकड़ों में सोचने का अधिकार नहीं दिया। एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम एक साथ सोच सकते हैं और एक साथ निर्णय ले सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं इस सदन से कहना चाहता हूँ कि चाहे दक्षिण हो या उत्तर, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य, परिसीमन प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ, वह अनुपात उनके समय से चला आ रहा है और उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर गारंटी कहिए तो मैं गारंटी देता हूँ, वादे की बात करें तो वादा करता हूँ। जब नीयत साफ है तो हमें शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है।

पहले यह अधिनियम नई जनगणना के बाद लागू किया जाना था, पर इसमें विलंब के चलते सरकार ने इसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही लागू करने का निर्णय किया, लेकिन इस पर विपक्षी दलों द्वारा आपत्ति जताई गई। अगर इस आपत्ति को महत्व दिया जाता है, तो 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ताजा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठित होने वाले परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगेगा। 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन को लेकर कुछ विपक्षी दलों और

 अगर इस आपत्ति को महत्व दिया जाता है, तो 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ताजा जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठित होने वाले परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगेगा।





राज्यों (खासकर दक्षिण के) को यह आशंका है कि उनकी सीटें उत्तर भारत के मुकाबले कम हो सकती हैं, लेकिन इस आशंका को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान निर्मूल बताते हुए आश्वस्त किया था कि परिसीमन में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यह मोदी की गारंटी है। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लक्षित करते हुए संसद में कहा था कि हमने पहले ही संसद की नई इमारत बनाकर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है जो संसद की पुरानी इमारत में संभव नहीं थी।

खास बात यह है कि 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए 131वें संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को लेकर जहां विपक्षी दल आपत्ति जता रहे थे, वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे ऐतिहासिक बताया था। बसपा प्रमुख मायावती ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था। देश की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं प्रतिभा पाटिल ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार के इस निर्णय का समर्थन और स्वागत किया था। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए यह भी लिखा कि यह संविधान संशोधन ऐसा परिवर्तनकारी कदम है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का मजबूत प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इसके बावजूद इस विधेयक का समर्थन न करना विपक्षी दलों की नीयत पर सवाल खड़े करता है।

मैंने स्वयं तीन कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए मैं अच्छी तरह महसूस करती हूं कि राजनीतिक रूप से आगे आने और नीतिगत निर्णयों में समुचित भागीदारी के लिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना कितना आवश्यक है। महिलाओं के आगे आने और उन्हें निर्णय का अधिकार मिलने से परिवार, समाज और

देश सभी को फायदा होता है। महिलाएं सभी को साथ लेकर चलना बखूबी जानती हैं। उनमें कोमल हृदय तो होता ही है, साथ ही देवी दुर्गा की तरह मजबूत इरादे और निर्णय लेने की अपार क्षमता भी होती है।

वैसे यह कोई आज की बात नहीं है। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही महिलाओं को पर्याप्त सम्मान और प्रतिनिधित्व देने की परंपरा रही है। वैदिक काल में लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, अपाला जैसी विदुषी नारियां इसकी साक्षात् उदाहरण रही हैं। आजादी के आंदोलन में भी हमारी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं को पूजनीय और शक्ति-रूपा बताने के बावजूद आजादी के सात दशक तक महिलाएं अपने हक से वंचित रही हैं। मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि अंततः इस बात का पूरा पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया जाना चाहिए, जिनकी पहल, परिश्रम और संकल्प से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) पारित कर लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित हुआ। इसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित होंगी। फिलहाल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 15 फीसदी से भी कम है। परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें बढ़ने से महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।

2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम तब लागू इसलिए नहीं हो सका था, क्योंकि इसके लिए महिलाओं के आरक्षण के अनुपात में लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें बढ़ाना आवश्यक था। यह कार्य बिना परिसीमन के नहीं हो सकता था। यही कारण है कि मोदी सरकार ने पहल करते हुए सर्व-सम्मति का माहौल बनाने के प्रयास के साथ इसके लिए संशोधन विधेयक का प्रावधान किया। इसे यथाशीघ्र लागू करने के लिए सरकार 2011 की जनगणना को ही आधार बनाना चाहती है और विधेयक में यही प्रावधान किया गया है, पर विपक्षी दलों की मांग इसे वर्तमान में चल रही जनगणना पर आधारित करने को लेकर था। चूंकि कोविड के कारण काफी देर से अब कहीं जाकर जनगणना आरंभ हो सकी है, इसलिए अगर वर्तमान जनगणना को आधार बनाने को लेकर अवरोध खड़ा किया जाएगा तो इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करना संभव नहीं होगा। हां, यदि 2011



2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम तब लागू इसलिए नहीं हो सका था, क्योंकि इसके लिए महिलाओं के आरक्षण के अनुपात में लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें बढ़ाना आवश्यक था। यह कार्य बिना परिसीमन के नहीं हो सकता था। यही कारण है कि मोदी सरकार ने पहल करते हुए सर्व-सम्मति का माहौल बनाने के प्रयास के साथ इसके लिए संशोधन विधेयक का प्रावधान किया। इसे यथाशीघ्र लागू करने के लिए सरकार 2011 की जनगणना को ही आधार बनाना चाहती है।



की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके सीटें तय भी कर दी जाती हैं और राजनीतिक दलों को लगता है कि सीटें आगे और बढ़ाई जानी चाहिए, तो इस बारे में भविष्य में राजनीतिक दल सहमति बनाकर संसद में फिर संशोधन विधेयक लाकर ऐसा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'नीयत' बिल्कुल साफ है कि प्रक्रियाओं में तेजी लाकर इसे 2029 से हर हाल में लागू कर दिया जाए। यही कारण है कि वे खुद संसद से लेकर हर मंच से इसके लिए अपील और आह्वान कर रहे थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी संकल्पों की तरह उनका यह संकल्प भी निःसंदेह सिद्धि को प्राप्त करेगा और आधी आबादी को उनका यथोचित अधिकार मिलेगा। जिस दिन संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएंगी, वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा और निश्चित रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाएगा।



(लेखिका वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो लगातार तीन बार उत्तर प्रदेश विधानपरिषद की सदस्य रह चुकी हैं। वे एनआईटी समूह की चेयरपरसन भी हैं।)



विकसित भारत



जया तारे

विंग कमांडर (से.नि.), भारतीय वायुसेना

सशस्त्र बलों में

नारी-शक्ति की उड़ान

कि

सी भी राष्ट्र की असली पहचान उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण से तय होती है और जब दृष्टिकोण बदलता है, तो संस्थाएं भी बदलती हैं, धीरे-धीरे, लेकिन स्थायी रूप से। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका का विस्तार इसी परिवर्तन की कहानी है, एक ऐसी कहानी, जहां विचार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि नीति बने, अवसर बने और अंततः उपलब्धियों में बदल गए। इस व्यापक परिवर्तन की नींव उस समय मजबूत हुई, जब देश में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी को एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। आगे बढ़ते हुए, यह दृष्टिकोण भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचा और अधिक समावेशी और दूरदर्शी होगा।

मेरे अपने अनुभवों में, जब भी मैं उड़ान भरती थी, तब केवल एक ही जिम्मेदारी होती थी, मिशन को पूरा करना। आकाश में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता,



2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के करीब एक साल बाद 2015 में जब महिलाओं को फाइटर स्ट्रीम में शामिल करने का निर्णय लिया गया, तब यह केवल एक नई भूमिका देने का कदम भर नहीं था, बल्कि एक मानसिकता को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास था।

केवल निर्णय और अनुशासन होते हैं, लेकिन इस अनुभव को व्यापक बनाने की दिशा में निर्णायक पहल तब शुरू हुई, जब महिलाओं को नीतिगत स्तर पर अधिक अवसर देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि आज अधिक से अधिक युवा महिलाएं इस क्षेत्र को एक संभावित करियर के रूप में देख रही हैं। भविष्य में यह प्रवाह केवल संख्या नहीं बढ़ाएगा, बल्कि गुणवत्ता और नेतृत्व के नए मानक भी स्थापित करेगा।

मानसिकता का उदय, आकाश का विस्तार

यूं तो भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की औपचारिक शुरुआत 1992 में हुई, लेकिन फाइटर स्ट्रीम तक पहुंचने में उन्हें लगभग 23 वर्षों का समय क्यों लगा? क्या यह केवल प्रक्रिया थी या धैर्य और विश्वास की एक लंबी परीक्षा? 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के करीब एक साल बाद 2015 में जब महिलाओं को फाइटर स्ट्रीम में शामिल करने का निर्णय लिया गया, तब यह केवल एक नई भूमिका देने का कदम भर नहीं था, बल्कि एक मानसिकता को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास था। इस निर्णय ने प्रशिक्षण संस्थानों से लेकर ऑपरेशनल बेस तक एक नई ऊर्जा उत्पन्न की। इसका प्रभाव यह हुआ कि महिलाओं की भागीदारी को अब प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि क्षमता के रूप में देखा जाने लगा। आगे के वर्षों में यह पहल भारत को एक ऐसे वायुसेना ढांचे की ओर ले जा रही है, जहां कौशल ही एकमात्र पहचान होगा।

स्थायित्व का अधिकार : करियर नहीं, एक यात्रा

2020 में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू किया गया, जिसने इस परिवर्तन को वास्तविक स्थायित्व प्रदान किया। यह निर्णय केवल सेवा की अवधि बढ़ाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अपने करियर को पूर्णता तक ले जा सकें और संगठन के भीतर अपनी पहचान को दीर्घकालिक रूप से स्थापित कर सकें। इसका प्रभाव यह हुआ कि सशस्त्र बलों के भीतर नेतृत्व की एक नई, निरंतर और सशक्त धारा विकसित होने लगी—जहां अनुभव, दृष्टि और

प्रतिबद्धता समय के साथ और गहराई पाते हैं।

इस परिवर्तन से आने वाले समय में हम अनेक उभरती हुई कमांडिंग ऑफिसर्स और फ्लाइट कमांडर्स को देखेंगे, जो केवल पद नहीं संभालेंगी, बल्कि दिशा भी तय करेंगी। इस निर्णय ने नेतृत्व के पैमाने को बदल दिया है—जहां अब नेतृत्व केवल अवसर का परिणाम नहीं, बल्कि निरंतरता, अनुभव और संस्थागत विश्वास का स्वाभाविक विस्तार होगा। आगे बढ़ते हुए, यह पहल सशस्त्र बलों को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगी, जहां नेतृत्व अधिक संतुलित, व्यापक और दूरदर्शी होगा।

प्रशिक्षण के द्वार : शुरुआत से समान अवसर

नेशनल डिफेंस अकादमी की स्थापना 1954 में हुई और 2021 तक यह एक ऑल-बॉयज संस्थान बना रहा, जबकि सशस्त्र बलों में महिलाओं की उपस्थिति इससे दशकों पहले ही शुरू हो चुकी थी। फिर प्रश्न उठता है—जब क्षमता पहले से सिद्ध थी, तो प्रशिक्षण के इस सर्वोच्च द्वार को खोलने में इतना समय क्यों लगा? उत्तर स्पष्ट है—यह कभी कौशल का प्रश्न नहीं था, यह इरादे का प्रश्न था।

मोदी सरकार की पहल पर 2022 में जब नेशनल डिफेंस अकादमी के द्वार महिलाओं के लिए खुले, तब पहली बार देश की हजारों बेटियों ने इसे एक वास्तविक अवसर के रूप में देखा। यह केवल एक संस्थान का विस्तार नहीं था, बल्कि नेतृत्व की परिभाषा को जड़ से बदलने का निर्णय था। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेतृत्व की नींव वहीं रखी जाती है, जहां प्रशिक्षण शुरू होता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब नेतृत्व की शुरुआत ही समान अवसरों के साथ हो रही है, जहां आत्मविश्वास किसी अपवाद से नहीं, बल्कि व्यवस्था से जन्म लेता है।

इस परिवर्तन से आने वाले समय में हम ऐसे अधिकारी देखेंगे, जिनकी सोच शुरुआत से ही संतुलित, समावेशी और व्यापक होगी। यह निर्णय सशस्त्र बलों को एक ऐसे नेतृत्व ढांचे की ओर ले जा रहा है, जहां विविधता कोई प्रयास नहीं, बल्कि स्वाभाविक विशेषता होगी—और यही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी।

समुद्र और सीमाएं : विस्तार का नया आयाम

भारतीय नौसेना में महिलाओं का पहला औपचारिक प्रवेश 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से हुआ, लेकिन 2022 तक उनकी भूमिका मुख्यतः शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल





2020 में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू किया गया, जिसने इस परिवर्तन को वास्तविक स्थायित्व प्रदान किया। यह निर्णय केवल सेवा की अवधि बढ़ाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अपने करियर को पूर्णता तक ले जा सकें और संगठन के भीतर अपनी पहचान को दीर्घकालिक रूप से स्थापित कर सकें। इसका प्रभाव यह हुआ कि सशस्त्र बलों के भीतर नेतृत्व की एक नई, निरंतर और सशक्त धारा विकसित होने लगी—जहां अनुभव, दृष्टि और प्रतिबद्धता समय के साथ और गहराई पाते हैं।



और कुछ सीमित तकनीकी शाखाओं तक ही केंद्रित रही। समुद्र पर तैनाती, युद्धपोतों पर दीर्घकालिक ऑपरेशनल भूमिकाएं और कई कोर शाखाएं अभी भी उनके लिए पूर्ण रूप से खुली नहीं थीं। प्रश्न वही था—क्या यह क्षमता की सीमा थी या अवसर की?

2022–23 के दौरान जब भारतीय नौसेना ने महिलाओं के लिए लगभग सभी प्रमुख शाखाएं खोलीं—जिनमें एजीक्यूटिव ब्रांच (नेविगेशन, ऑपरेशंस), एंविशन, टेक्निकल ब्रांचेज और युद्धपोतों पर तैनाती शामिल हैं—तब यह केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं था, बल्कि समुद्र की उस परंपरागत परिभाषा को बदलने का निर्णय था, जो अब तक सीमित थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि महिलाओं की उपस्थिति अब केवल तट तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे खुले समुद्र में, वास्तविक ऑपरेशनल भूमिकाओं में अपनी भागीदारी निभाने लगीं।

इस परिवर्तन से आने वाले समय में हम अधिक महिला अधिकारियों को युद्धपोतों का हिस्सा बनते, जटिल मिशनों का नेतृत्व करते और समुद्री सुरक्षा के हर आयाम में सक्रिय भूमिका निभाते देखेंगे। यह विस्तार भारतीय नौसेना को एक अधिक बहुआयामी, संतुलित और सक्षम बल के रूप में स्थापित करेगा—जहां समुद्र की अनिश्चितता का सामना करने के लिए हर योग्य नेतृत्व को समान अवसर मिलेगा।

जमीनी स्तर पर भागीदारी : व्यापक समावेशन

2022 में अग्निवीर योजना के माध्यम से महिलाओं को सैनिक स्तर पर शामिल किया गया, जिसने इस परिवर्तन को केवल विस्तार नहीं दिया, बल्कि उसे गहराई भी प्रदान की। अब तक यह भागीदारी मुख्यतः अधिकारी स्तर तक केंद्रित थी, लेकिन इस पहल ने उस आधार को छुआ, जहां से सशस्त्र बलों की वास्तविक शक्ति निर्मित होती है—जमीनी स्तर, जहां अनुशासन, साहस और सामूहिकता हर दिन परिभाषित होते हैं।

यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने समावेशन को प्रतीकात्मक नहीं रहने दिया, बल्कि उसे संरचनात्मक बना दिया। इससे न केवल संख्या बढ़ी, बल्कि समानता की भावना भी सशक्त हुई—अब महिलाएं केवल नेतृत्व की संभावनाओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, जो राष्ट्र की सुरक्षा का आधार है। यह बदलाव “quantity” और “equality”

दोनों को साथ लेकर आया जहां भागीदारी का विस्तार और अवसरों की समानता एक साथ आगे बढ़े।

प्रशिक्षण मैदानों से लेकर ऑपरेशनल यूनिट्स तक, यह उपस्थिति केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई सोच का संकेत है जहां क्षमता को पहचानने के लिए किसी अतिरिक्त परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। आने वाले वर्षों में यह पहल एक ऐसे सशस्त्र बल का निर्माण करेगी, जो केवल शक्ति में नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व में भी समृद्ध होगा। एक ऐसा बल, जहां हर वर्ग, हर पृष्ठभूमि और हर आकांक्षा को स्थान मिलेगा—और यही समावेशन भविष्य की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनेगा।

नेतृत्व की नई परिभाषा

हाल के वर्षों में महिलाओं का उच्च नेतृत्व पदों तक पहुंचना इस पूरी यात्रा का स्वाभाविक और सशक्त विस्तार है, एक ऐसा विस्तार, जिसकी शुरुआत वर्षों पहले लिए गए नीतिगत निर्णयों से हुई थी और जो आज ठोस परिणामों के रूप में दिखाई दे रहा है। जब 2020 में स्थायी कमीशन लागू हुआ और उसके बाद के वर्षों में कमांड व नेतृत्व भूमिकाओं के द्वार वास्तविक रूप से खुले, तब पहली बार यह सुनिश्चित हुआ कि यह यात्रा केवल भागीदारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नेतृत्व तक पहुंचेगी।

ये उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस संस्थागत बदलाव का संकेत हैं, जहां नेतृत्व अब एक पूर्वनिर्धारित संरचना नहीं, बल्कि एक विकसित होती हुई अवधारणा बन चुका है। जब एक महिला अधिकारी कमांड संभालती है—चाहे वह यूनिट हो, स्क्वाड्रन हो या कोई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल जिम्मेदारी, तो वह केवल एक पद नहीं ग्रहण करती, बल्कि उस सोच को स्थापित करती है कि नेतृत्व का आधार केवल अनुभव, निर्णय क्षमता और दृष्टि है।

इस परिवर्तन का सबसे गहरा प्रभाव निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में दिखाई देता है। विविध अनुभवों और दृष्टिकोणों के शामिल होने से निर्णय अधिक संतुलित, व्यावहारिक और व्यापक होते हैं। सशस्त्र बलों जैसे जटिल और गतिशील वातावरण में यह संतुलन केवल एक अतिरिक्त लाभ नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बन जाता है। मेरे अपने अनुभव में, नेतृत्व हमेशा पद से नहीं, बल्कि विश्वास से आता है—वह विश्वास जो आपकी टीम आपके निर्णयों में देखती है। आज जब मैं नई





पीएम मोदी की पहल उस राष्ट्रीय दृष्टि से जुड़ती है, जिसे 2047—भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष के लक्ष्य के रूप में परिकल्पित किया गया है, जहां विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण किया जा रहा है। इसमें नारी शक्ति केवल भागीदार नहीं, बल्कि परिवर्तन की अग्रणी शक्ति है। सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसी व्यापक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जहां सुरक्षा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका निर्णायक बनती जा रही है।



पीढ़ी की महिला अधिकारियों को इस भूमिका में देखती हूँ, तो स्पष्ट महसूस होता है कि यह बदलाव केवल अवसर मिलने का परिणाम नहीं है, बल्कि उस विश्वास के निर्माण का परिणाम है, जिसे अब संस्थागत समर्थन प्राप्त है।

आने वाले समय में हम एक ऐसे नेतृत्व ढांचे को और स्पष्ट रूप से उभरते देखेंगे, जहां विविधता केवल प्रतिनिधित्व नहीं होगी, बल्कि निर्णय की गुणवत्ता को परिभाषित करेगी। यह परिवर्तन सशस्त्र बलों को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है, जहां नेतृत्व अधिक समावेशी, अधिक उत्तरदायी और कहीं अधिक प्रभावी होगा और यही एक आधुनिक, सशक्त और दूरदर्शी राष्ट्र की पहचान है।

दिख रहा है बदलाव

मेरे अपने सफर में मैंने इस परिवर्तन को किसी एक क्षण में नहीं, बल्कि समय के साथ धीरे-धीरे आकार लेते हुए देखा है। एक समय था जब हर कदम मानो एक अनकहा परीक्षण होता था, जहां जिम्मेदारी के साथ-साथ यह अपेक्षा भी जुड़ी होती थी कि आपको अपनी उपस्थिति को बार-बार सिद्ध करना है, लेकिन पिछले एक दशक में जब नीतियों ने स्पष्ट रूप से अवसरों के द्वार खोले, तब यह अनुभव बदलने लगा। अब नई पीढ़ी उस स्थान पर खड़ी है, जहां उसे शुरुआत से ही अवसर मिलते हैं—संदेह से पहले विश्वास मिलता है।

इसका प्रभाव गहरा है। आत्मविश्वास अब व्यक्तिगत संघर्ष की उपज नहीं रहा, बल्कि संस्थागत समर्थन का स्वाभाविक परिणाम बन गया है। यह बदलाव केवल कार्यशैली में नहीं, बल्कि सोच में दिखाई देता है—जहां ध्यान “सिद्ध करने” से हटकर “श्रेष्ठ करने” पर केंद्रित हो गया है। आने वाले समय में, यही परिवर्तन एक ऐसी कार्यसंस्कृति को जन्म देगा, जहां क्षमता को पहचानने के लिए किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी—वह स्वयं अपने परिणामों से स्थापित होगी।

तेजी से बदल रही समाज की धारणा

जब इन नीतिगत परिवर्तनों को लागू किया गया, उसी समय से उनका प्रभाव वर्दी की सीमाओं से बाहर भी दिखने लगा। सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका ने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया—एक ऐसा दृष्टिकोण, जहां नेतृत्व और जिम्मेदारी को किसी पूर्व निर्धारित परिभाषा में नहीं बांधा गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि करियर, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व को देखने का नजरिया बदलने

लगा। अब यह सवाल कम होता जा रहा है कि “क्या संभव है”, और अधिक यह कि “अगला कदम क्या हो सकता है।” यह परिवर्तन घरों, स्कूलों और उन अनगिनत सपनों तक पहुंचा है, जो अब पहले से अधिक स्पष्ट और साहसिक हैं।

आने वाले समय में, यह प्रतिध्वनि और गहरी होगी—जहां नई पीढ़ी के लिए विकल्प सीमित नहीं, बल्कि असीमित होंगे। और यही वह बिंदु होगा, जहां सशस्त्र बलों का यह परिवर्तन समाज के व्यापक परिवर्तन का आधार बनेगा।

आगे की दिशा : निरंतर यात्रा

अब तक उठाए गए सभी कदम—चाहे वह स्थायी कमीशन हो, एनडीए का खुलना हो या जमीनी स्तर पर समावेशन—एक स्पष्ट और सुनियोजित दिशा का हिस्सा रहे हैं। इन पहलों ने यह सुनिश्चित किया है कि सशक्तिकरण कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया बने, जो समय के साथ और अधिक गहराई और व्यापकता प्राप्त करती जाए। इसका प्रभाव यह है कि अब यह यात्रा केवल भागीदारी तक सीमित नहीं है—यह गुणवत्ता, उत्कृष्टता और नवाचार की ओर अग्रसर हो चुकी है। सशस्त्र बलों का यह नया स्वरूप केवल अधिक समावेशी नहीं, बल्कि अधिक सक्षम, अधिक सजग और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है।

यह दिशा सीधे उस राष्ट्रीय दृष्टि से जुड़ती है, जिसे 2047—भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष के लक्ष्य के रूप में परिकल्पित किया गया है, जहां एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण किया जा रहा है। इस दृष्टि में नारी शक्ति केवल भागीदार नहीं, बल्कि परिवर्तन की अग्रणी शक्ति है। सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसी व्यापक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जहां सुरक्षा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका निर्णायक बनती जा रही है।

आने वाले वर्षों में, यह दिशा एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देगी, जहां हर अवसर एक नए मानक को स्थापित करेगा और हर उपलब्धि सीधे उस बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ी होगी, जो भारत को एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगा। यह केवल प्रगति नहीं होगी—यह एक सुनियोजित, समावेशी और निरंतर उत्कर्ष की यात्रा होगी, जो 2047 के भारत की नींव को और अधिक मजबूत बनाएगी।



आत्मविश्वास अब व्यक्तिगत
संघर्ष की उपज नहीं रहा,
बल्कि संस्थागत समर्थन का
स्वाभाविक परिणाम बन गया है।
यह बदलाव केवल कार्यशैली में
नहीं, बल्कि सोच में दिखाई देता
है—जहां ध्यान “सिद्ध करने” से
हटकर “श्रेष्ठ करने” पर केंद्रित
हो गया है।



जब मैं आज आकाश की ओर देखती हूँ, वह अब भी उतना ही असीम और विस्तृत है पर अब उसे देखने और छूने के बीच की दूरी समाप्त हो चुकी है।



अच्छी नीयत से असंभव हुआ संभव

जो कभी सात दशकों तक असंभव माना गया, वह कुछ ही वर्षों में संभव हुआ—यह इस बात का प्रमाण है कि बाधाएं परिस्थितियों में नहीं, मानसिकता में होती हैं। यह कहानी केवल सशस्त्र बलों की नहीं है, यह उस भारत की कहानी है, जिसने विचार को केवल व्यक्त नहीं किया, बल्कि उसे क्रियान्वयन में बदलकर दिखाया। पिछले एक दशक में लिए गए निर्णायक कदमों ने इस परिवर्तन को गति दी, और आज उसका प्रभाव हर स्तर पर स्पष्ट दिखाई देता है।

भविष्य की दिशा भी उतनी ही स्पष्ट है जहां हर सपना एक अवसर से जुड़ा होगा और हर अवसर एक उपलब्धि में बदलेगा। जब मैं आज आकाश की ओर देखती हूँ, वह अब भी उतना ही असीम और विस्तृत है पर अब उसे देखने और छूने के बीच की दूरी समाप्त हो चुकी है। आकाश हमेशा से वहीं था—बदला है वहां तक पहुंचने का हमारा इरादा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व और उसे सिद्ध करने का संकल्प...



(लेखिका भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) रही हैं। उन्हें 3500 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव है। वह एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर भी रही हैं। वह भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं, जिन्हें एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त है। Newrizon Space की सीईओ के रूप में अब वह युवाओं को आकाश से आगे बढ़कर अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 'मिशन शक्ति SAT' की एंबेसडर के रूप में वह देश के पहले पूर्णतः महिला लूनर ऑर्बिट मिशन का नेतृत्व कर रही हैं।)



विकसित भारत



डॉ. नीमा अग्रवाल
एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर-एनआईडीटी,
ग्रेटर नोएडा

मन के

जीते जीत

मैं

ने जब से होश संभाला है, हर प्रधानमंत्री को प्रतिवर्ष लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हुए देखा है, जिसमें वे अपनी सरकार की नीतियों-उपलब्धियों को साझा करते रहे हैं। लगभग हर प्रधानमंत्री किसी खास मौके पर ही आकाशवाणी से देश को संबोधित करते रहे हैं, पर 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह उसी साल से हर महीने के आखिरी रविवार को 'मन की बात' के माध्यम से रेडियो को जनता से जुड़ने का जोरदार जरिया बना दिया, उसे देख-सुनकर मुझे सुखद हैरानी होती है। आज के सोशल मीडिया, इंटरनेट और एआई के जमाने में प्रधानमंत्री मोदी ने हाशिये पर जा रहे रेडियो को फिर से जीवंत कर दिया, उससे रेडियो से जुड़ी बचपन की यादें ताजा हो गईं। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले के किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश की करोड़ों जनता से नियमित और जीवंत संवाद करने के लिए रेडियो को माध्यम बनाया होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। 'मन की बात' का पहला एपिसोड उसी साल तीन अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर



भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी हैं। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है – ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सबकी भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
(‘मन की बात’ में)



पर आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) से प्रसारित हुआ था। 14 मिनट के इस एपिसोड में उन्होंने देशवासियों से संवाद करते हुए उन्हें स्वच्छता के प्रति संदेश दिया था। बाद में यह कार्यक्रम आधे घंटे और उससे ज्यादा का हो गया और फिर इसके लिए हर महीने का आखिरी रविवार तय हो गया। ‘मन की बात’ की लोकप्रियता इसी बात से साबित होती है कि अप्रैल 2026 तक इसके कुल 133 एपिसोड हो चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी हों, उनका यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से प्रसारित होता है। रेडियो के इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए लगभग सभी सरकारी और निजी टीवी चैनल भी इसे प्रसारित करते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह यूट्यूब चैनल पर भी यह आसानी से उपलब्ध है।

आज के सोशल मीडिया के जमाने में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से संवाद के लिए रेडियो को चुनकर एक साथ कई संदेश दिए। उन्होंने आज की तेज तकनीकी प्रगति के बीच रेडियो जैसे पारंपरिक माध्यम को अपनाकर न केवल इसमें नई जान फूंक दी, बल्कि देश के लोगों को रेडियो से एक बार फिर जोड़ दिया। वे ‘मन की बात’ के जरिए लोगों से बातें करते हैं, उनकी उपलब्धियां और समस्याएं सुनते हैं और उनकी सराहना करते हुए उन्हें खूब प्रेरित भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ग के लोगों से जुड़ते हैं, चाहे वे महिलाएं हों, किसान हों, उद्यमी हों या फिर बच्चे और छात्र ही क्यों न हों।

‘मन की बात’ के माध्यम से जनभागीदारी और स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के अभियान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी सराहा गया। बीबीसी द्वारा इस कार्यक्रम को ‘रेडियो रिवाइवल’ यानी ‘रेडियो का पुनरुत्थान’ बताया गया। द इकोनॉमिस्ट ने इसे पीएम मोदी की ‘डायरेक्ट कनेक्ट स्ट्रेटेजी’ का हिस्सा बताया। द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा इसे ‘इनोवेटिव पॉलिटिकल कनेक्ट टूल’ बताया गया।

सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भी आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में पहले 15 एपिसोड में वेबसाइट पर 61,000 से अधिक सुझाव और 1.43 लाख से अधिक वॉयस रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई थीं। एक एपिसोड के दौरान 55,000 से अधिक फोन कॉल रिकॉर्ड किए गए थे। 30 अप्रैल, 2023 को 100वें एपिसोड के अवसर पर इस कार्यक्रम को 100 करोड़ से अधिक लोग कम से कम एक बार इसे सुन चुके थे।

स्वच्छता पर जोर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत के लोगों (140 करोड़ से अधिक) के लिए स्वस्थ और फिट रहना आवश्यक है, तभी वे देश को विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने में समग्रता के साथ योगदान दे सकते हैं। इसके लिए जीवन में स्वच्छता का पालन करना बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर अपने आसपास को साफ-सुथरा रखना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने अपने इस कार्यक्रम के जरिए बार-बार देश के लोगों को स्वच्छता के बारे में संदेश दिया है। इसके लिए वे शहरों से लेकर गांव-गांव तक शौचालय बनवाने और उसका इस्तेमाल करने पर बल देते रहे हैं। इसके लिए सरकारी स्तर पर सक्रिय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उनकी इस अपील का असर यह दिखा कि 2014 में शुरू 'स्वच्छ भारत मिशन' के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। पिछले 12 वर्षों में सवा दो लाख से अधिक सामुदायिक शौचालय बनवाए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 12 वर्षों में साढ़े पांच लाख से अधिक गांवों को 'खुले में शौच से मुक्त' (ओडीएफ) घोषित किया गया।

जल संरक्षण को बढ़ावा

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' के जरिए जल संरक्षण को भी लगातार प्रोत्साहित किया है, खासकर गर्मी के महीनों में जल बचाने को लेकर। पीएम मोदी ने जल शक्ति अभियानों और स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। पहले हमने देखा है कि राजस्थान के दुर्गम और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में कैसे लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसते थे। हम पहले ऐसे दृश्य अक्सर देखते थे कि लोग सूखे तालाब, जोहड़/गड्ढों में जमा गंदे पानी को पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होते थे। राजस्थान की महिलाओं को पानी के लिए दूर-दूर जाना पड़ता था। दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों तक में गर्मियों में पेयजल के लिए मारामारी होती रही है। अच्छी बात यह





‘मन की बात’ में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूँ, जो अदृश्य है, लेकिन, जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी ना चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन-शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है — ‘वायुर्वा इति व्यष्टिः, वायुरवै समष्टिः।’ अर्थात् वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है।

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
(‘मन की बात’ में)

है कि पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार से लेकर नागरिकों तक में पानी को बचाने के लिए जागरूकता काफी बढ़ी है। वर्षा जल संरक्षण और संचयन की दिशा में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में कई बार उन गांवों और वहां के निवासियों का जिक्र किया, जो जल संरक्षण और नए तालाब बनवाने या पुराने तालाबों के पुनरुत्थान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी ऐसे लोगों से ‘मन की बात’ में सीधा संवाद भी करते रहे हैं।

लोकल फॉर वोकल

‘मन की बात’ के माध्यम से पीएम मोदी स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल करने को लेकर देश के लोगों को लगातार प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने सरकार के स्तर पर प्रयास तो किए ही, साथ ही आम नागरिकों को भी स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने की नियमित रूप से अपील की। इस दिशा में काम कर रहे लोगों, खासकर महिला उद्यमियों से पीएम मोदी सीधे संवाद करते और उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में एमएसएमई सेक्टर को भी लगातार प्रोत्साहित किया है। इससे 2014 के बाद न केवल इस सेक्टर की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ी है, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की लोकप्रियता और बिक्री भी खूब बढ़ी है। पीएम मोदी के प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि एमएसएमई की संख्या जो 2014-15 में 6.3 करोड़ थी, वह 2025 तक 7.5 करोड़ से अधिक हो गई। खास बात यह है कि एमएसएमई के तहत महिला उद्यमियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत उद्यमों में 38% से अधिक महिलाओं का स्वामित्व है। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में बांस और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों की सराहना कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

संवाद का अनूठा अंदाज

‘मन की बात’ के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग-अलग इलाकों में अपने तरीके से काम करते हुए देश को बढ़ाने में योगदान करने वाले लोगों का उल्लेख करते हैं। उनसे सीधी बात करते हुए और देशवासियों को उनके काम से परिचित कराते हुए उन्हें भी कुछ अलग करने के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित करते हैं। चाहे वह ‘सेल्फी विद डॉक्टर’ की बात हो या फिर बिना संसाधनों या बेहद कम संसाधन में पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात हो।

पीएम मोदी इस लोकप्रिय कार्यक्रम में उन युवा उद्यमियों की कहानियां भी अक्सर साझा करते हैं, जो नवाचार से अपने सपनों को उड़ान देते हुए देश के बाकी युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। वे ऐसे दिव्यांगों की चर्चा भी करते हैं, जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके उदाहरण से उन्होंने कहा कि सीमा शरीर की होती है, मन की नहीं। कोरोना काल में उन्होंने उन डॉक्टरों, नर्सों, सफाईकर्मियों, पुलिसकर्मियों की कहानियां साझा कीं, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मुश्किल समय में मानव सेवा का अनुपम उदाहरण पेश किया।

प्रधानमंत्री मोदी अपने इस कार्यक्रम में अक्सर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी नेतृत्वकारी भूमिका की बात करते हैं। इस क्रम में वे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी उन महिलाओं की अक्सर चर्चा करते हैं, जो गांवों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। वे महिला उद्यमियों की भी लगातार बात करते और उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को सराहते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी नारी को एक दिव्य सत्ता के रूप में देखते हैं। अपने संबोधन में, वे भारतीय सभ्यता की शाश्वत अवधारणा “शक्ति” या नारी दिव्य ऊर्जा को प्रतिध्वनित करते हैं, जिसके अनुसार महिलाएं शक्ति, ज्ञान और संरक्षण की प्रतीक हैं। भारत में बालिकाओं के प्रति भेदभाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” के जनआंदोलन का आह्वान किया और ‘मन की बात’ के आठ एपिसोड में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी जैसी वैदिककालीन विदुषी नारियों का जिक्र किया, जिन्होंने वेदों की रचना की; अक्का महादेवी या मीराबाई जैसी महिला भक्तों की आध्यात्मिक विरासत से प्रेरणा ली; अहिल्याबाई होलकर के शासन



‘मन की बात’ के माध्यम से जनभागीदारी और स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के अभियान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी सराहा गया। बीबीसी द्वारा इस कार्यक्रम को ‘रेडियो रिवाइवल’ यानी ‘रेडियो का पुनरुत्थान’ बताया गया। द इकोनॉमिस्ट ने इसे पीएम मोदी की ‘डायरेक्ट कनेक्ट स्ट्रेटेजी’ का हिस्सा बताया। द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा इसे ‘इनोवेटिव पॉलिटिकल कनेक्ट टूल’ बताया गया।



प्रधानमंत्री मोदी
अपने कार्यक्रम में
अक्सर महिलाओं के
सशक्तिकरण और
उनकी नेतृत्वकारी
भूमिका की बात करते
हैं। इस क्रम में वे स्वयं
सहायता समूहों से
जुड़ी उन महिलाओं की
अक्सर चर्चा करते हैं,
जो गांवों की महिलाओं
को आर्थिक रूप से
सशक्त बना रही हैं।
वे महिला उद्यमियों
की भी लगातार बात
करते हैं।



या रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रेरणा ली। उन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ने वाली महिलाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि चोल काल में भी नौसेना के युद्धपोतों पर महिलाएं मौजूद थीं। भारतीय-अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की शक्ति की कोई सीमा नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारतीय महिलाओं के प्रदर्शन की सराहना की। 'मन की बात' के माध्यम से उन्होंने महिला लड़ाकू पायलटों, महिला लेफ्टिनेंटों और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत एक महिला प्लाटून का परिचय कराया और आईएनएसवी तारिणी पर 250 दिनों से अधिक समय तक विश्व का चक्कर लगाने वाली छह भारतीय महिला कमांडरों को बधाई दी।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से यह स्थापित किया कि आम नागरिक ही देश के असली नायक हैं, जिनके छोटे-छोटे प्रयासों से देश में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसके लिए हर किसी को सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। इससे समाज बदलता और आगे बढ़ता है। उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को इसी तरह प्रेरित-प्रोत्साहित करते रहेंगे।

(लेखिका एनआईटी, ग्रेटर नोएडा की
एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।)



विकसित भारत



यशा माथुर

वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका

नये भारत में नेतृत्व की राह पर नारी-शक्ति

‘नारी शक्ति सिर्फ विकास की भागीदार नहीं, बल्कि विकास की नेतृत्वकर्ता है।’ ऐसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक अवसरों पर कहा है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि अब महिलाओं के विकास नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व के साथ विकास ही नए भारत की पहचान बनेगा। उनकी यह सोच इस बात को रेखांकित करती है कि अब नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रही हैं। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में न केवल नारी सशक्तिकरण के लिए व्यापक पहल की गई है बल्कि महिलाओं को नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की यह सोच सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक नियुक्तियों और सामाजिक पहल में दिखाई भी देती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब सत्ता की बागडोर संभाली, तब उन्होंने महिलाओं को केवल सशक्त बनाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका में आगे लाने का लगातार प्रयास किया है। उनकी सरकार के पिछले करीब बारह वर्षों में नारी शक्ति को नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आने का अवसर मिला है। राजनीति,



अब केवल महिलाओं का विकास ही नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व के साथ विकास ही नए भारत की पहचान बनेगा।



जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वॉलिटी ऑफ गवर्नेंस में भी सुधार होता है।

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



स्थानीय निकायों, उद्यमिता और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं का बढ़ता नेतृत्व बदलाव की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। आज महिलाएं निर्णय लेने वाले स्तर पर हैं, योजनाओं को लागू करने वाली हैं, विकास की दिशा तय करने वाली नेतृत्वकर्ता हैं। यह भारत के बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण संकेत है।

मोदी जी के रिकॉर्ड कार्यकाल में यह सोच मजबूत हुई है कि जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी, तभी समाज और देश का समग्र विकास संभव होगा। उनके सबसे महत्वपूर्ण कदमों में द्रौपदी मुर्मु को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने और निर्मला सीतारमण को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाने का फैसला लेना रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो महिलाओं की सफल नेतृत्व क्षमता को साबित करते हैं और मोदी जी की सोच को सही ठहराते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो समाज अधिक संवेदनशील और संतुलित बनता है। इसी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने महिला नेतृत्व आधारित विकास को भारत की विकास नीति का महत्वपूर्ण आधार बताया। जब उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार की कमान अपने हाथों में ली, तब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी। 2014 के आसपास संसद में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित था। स्थानीय निकायों में आरक्षण के कारण महिलाएं जरूर थीं, लेकिन कई जगह वास्तविक निर्णय पुरुष ही लेते थे। उस समय महिलाओं को राजनीति में आने के लिए सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता था। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) को पारित किया गया, जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता खुला। यह कदम महिलाओं को राजनीति में नेतृत्व की भूमिका देने की दिशा में ऐतिहासिक माना गया।

इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर नारी शक्ति पर अपने विश्वास को वास्तविकता में बदला है। द्रौपदी मुर्मु को भारत का राष्ट्रपति बनाने के साथ उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर महिला नेतृत्व की नई मिसाल कायम की। उन्होंने

निर्मला सीतारमण को भारत की वित्त मंत्री का पद देकर अपने विश्वास को जीवंत किया। निर्मला सीतारमण ने बजट और आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे आर्थिक नीति निर्माण में महिला नेतृत्व की मजबूत उपस्थिति दिखाई देती है। राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी से दो बार लोकसभा चुनाव जीत इतिहास बनाने वाली स्मृति इरानी भी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के रूप में स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में सक्रिय भूमिका निभाई। इन महिलाओं की नियुक्तियां नीति निर्माण में महिलाओं की प्रमुखता को दर्शाती है। प्रशासन और कूटनीति के क्षेत्र में भी रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वह भारत की पहली महिला प्रतिनिधियों में शामिल रहीं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का नेतृत्व किया। तेलंगाना की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाणी राव भी पुलिस नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वह तेलंगाना में महिला सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनीं। मोहना सिंह भी फाइटर पायलट के रूप में वायुसेना को नई दिशा दे रही हैं। पीएम मोदी महिला नेतृत्व को कितनी महत्ता देते हैं यह इस बात से पता चलता है कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अब गणतंत्र दिवस की परेड की कमान महिला शक्ति ही संभालती नजर आती है।

आर्थिक नेतृत्व में भी आगे

मौजूदा मोदी सरकार में महिलाएं आर्थिक विकास की मजबूत धुरी बनती जा रही हैं। महिला उद्यमी स्टार्टअप और व्यवसाय चला रही हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। 'लखपति दीदी' जैसी पहल महिलाओं को आर्थिक नेतृत्व दे रही है। जब महिलाएं कमाती हैं, तो वह परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर अधिक निवेश करती हैं। इससे समग्र विकास की गति तेज होती है। जब 2014 में मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला, तब महिलाओं की नेतृत्व भूमिका उभर तो रही थी, लेकिन अभी शुरुआती चरण में थी। अवसर सीमित थे, सामाजिक बाधाएं अधिक थीं और नेतृत्व के शीर्ष स्तर पर महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप





आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उद्यम, सशस्त्र बलों और खेलों के साथ हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं-बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिलते हैं।

—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



इंडिया और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार सृजित करने वाली 'लीडर' भी बन रही हैं। इसके साथ ही 'मिशनशक्ति' और 'कौशल विकास' कार्यक्रमों ने महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के तहत तकनीकी साक्षरता बढ़ने से महिलाएं आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बना रही हैं और नए अवसरों का लाभ उठा रही हैं।

'लखपति दीदी' योजना ने तो महिलाओं को आर्थिक नेतृत्व की नई पहचान दी है। इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाएं डेयरी, कृषि आधारित कार्य, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, छोटे उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहार में तो स्वयं सहायता समूहों के विकास से महिलाओं की बदलती तस्वीर साफ नजर आ रही है। इस आंदोलन ने एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति को जन्म दिया है। आज बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। इस परिवर्तन की सबसे बड़ी पहचान है जीविका, जिसे बिहार सरकार ने शुरू किया और बाद में इसे विश्व बैंक का भी सहयोग मिला। इस पहल ने लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया।

जीविका कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इन समूहों में महिलाएं छोटी-छोटी बचत से शुरुआत करती हैं और फिर उसी बचत के आधार पर छोटे ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करती हैं। आज बिहार में महिलाएं डेयरी और पशुपालन, सब्जी उत्पादन, सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और छोटी दुकानों का संचालन जैसे कार्यों के माध्यम से आय अर्जित कर रही हैं। इन समूहों ने महिलाओं को आत्मविश्वास दिया और उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित की। उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद बिहार में स्वयं सहायता समूहों का तेजी से विस्तार हुआ। लाखों स्वयं सहायता समूह बने, उनसे करोड़ों महिलाएं जुड़ीं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इन गतिविधियों ने महिलाओं को

घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर आर्थिक नेतृत्व की भूमिका में ला खड़ा किया है। आज बिहार के कई गांवों में महिलाएं न केवल अपना व्यवसाय चला रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बना रही हैं। यह बदलाव सामाजिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है।

उद्यमिता में महिलाओं के बढ़ते कदम

‘महिलाओं को अवसर दीजिए, वे असंभव को संभव कर दिखाती हैं।’ प्रधानमंत्री मोदी की इस सोच के साथ उनकी सरकार की नीतियों ने भी महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया। आज महिलाएं ऑनलाइन व्यवसाय, घरेलू उद्योग, स्टार्टअप और सामाजिक उद्यम जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पाद देश-विदेश तक पहुंचा रही हैं। मोदी सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को ऋण दिए गए। स्टार्टअप इंडिया के जरिए नवाचार को बढ़ावा दिया गया। डिजिटल इंडिया से ऑनलाइन व्यवसाय के अवसर प्रदान किए गए। इन पहलों के चलते आज महिलाएं छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े स्टार्टअप तक का नेतृत्व कर रही हैं। सरकारी योजनाओं से मिला प्रोत्साहन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है।

मोदी सरकार की पहल ने महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण दिया है। आज ऐसा माहौल बना है कि शिक्षित और प्रशिक्षित महिलाएं सबसे पहले अपना स्टार्टअप या उद्यम ही स्थापित करने के बारे में सोचती हैं। कोई महिला किसानों की उपज को सीधे खपत वाले स्थानों पर पहुंचा रही है, तो कोई तकनीक के बल पर अपना उद्यम स्थापित कर रही हैं। उपासना टाकू ने डिजिटल पेमेंट सेक्टर में ‘मोबिक्विक’ नाम से सफल स्टार्टअप बनाकर फिनटेक क्षेत्र में महिला नेतृत्व को साबित किया। आज तकनीक के क्षेत्र में महिलाएं फिनटेक (डिजिटल पेमेंट), ई-कॉमर्स, हेल्थ टेक, एडटेक, एग्रीटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में निर्णय लेने वाली बनी हैं। इन क्षेत्रों में महिला उद्यमी नए समाधान दे रही हैं, नवाचार कर रही हैं और देश के डिजिटल विकास में योगदान दे रही हैं।

अगर वर्तमान की कुछ सफल व मशहूर महिला उद्यमियों की बात करें तो उन्हें किसी न किसी रूप में मोदी सरकार की नीतियों का फायदा मिला है, जिससे वे सफलता के शिखर पर हैं। उनके उत्पाद विश्व में पहचान बना रहे हैं। नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर का नाम कौन नहीं



पीएम मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल में यह सोच मजबूत हुई है कि जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी, तभी समाज और देश का समग्र विकास संभव होगा। उनके सबसे महत्वपूर्ण कदमों में द्रौपदी मुर्मु को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का फैसला लेना रहा है।



पिछले दशक में पंचायतों और नगर निकायों में पहले से लागू आरक्षण को और प्रभावी बनाने के प्रयास किए गए, जिससे गांवों और शहरों में महिलाएं आज सरपंच, पार्षद और मेयर जैसे पदों पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इससे जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है।



जानता। इन्होंने ब्यूटी और ई-कॉमर्स क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। विनीता सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक्स स्टार्टअप के जरिए महिला नेतृत्व का मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है।

जमीनी स्तर पर भी ले रहीं फैसले

प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से यह स्पष्ट किया है कि देश का विकास तभी संभव है, जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे आएँ। इसी सोच के साथ सरकार की योजनाओं को इस तरह तैयार किया गया कि महिलाएं केवल लाभार्थी न रहें, बल्कि बदलाव की नेतृत्वकर्ता बनें। यह बदलाव केवल नीतियों का नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी संकेत है। आज स्थानीय स्तर पर भी महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा मिला है। पंचायतों में महिला सरपंच गांवों के विकास को नई दिशा दे रही हैं। नगर निकायों में महिला नेतृत्व शहरी सुविधाओं को बेहतर बना रहा है। भारत में लोकतंत्र की असली ताकत गांव और शहरों के स्थानीय निकायों में दिखाई देती है। पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के माध्यम से विकास की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचती हैं। पिछले दशक में पंचायतों और नगर निकायों में पहले से लागू आरक्षण को और प्रभावी बनाने के प्रयास किए गए, जिससे गांवों और शहरों में महिलाएं आज सरपंच, पार्षद और मेयर जैसे पदों पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इससे जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। मोदी सरकार की महिला समर्थक नीतियों के कारण जमीनी स्तर पर नेतृत्व देने की दिशा में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। आज महिलाएं सिर्फ नाम की सरपंच नहीं हैं, जिनके नाम पर 'प्रधान पति' व्यवहार में सारी भूमिकाएं निभाते रहे हैं। बढ़ती जागरूकता के चलते अब महिला सरपंच स्वयं विकास योजनाओं का संचालन कर रही हैं। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रही हैं। महिला नेतृत्व की वजह से ही अब महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिल रही है।

अभी और भी हैं चुनौतियां

प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 'महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं, महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण ही नए भारत की पहचान है।' यह बदलाव उस नए भारत की मजबूत नींव तो रखता है जहां नारी शक्ति ही विकास की दिशा तय कर रही हो, लेकिन इस राह में मोदी सरकार के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं। इनका सामना करते हुए भी मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राह में सामाजिक मानसिकता सबसे बड़ी चुनौती है। वह सामाजिक सोच को बदलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आज भी कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना जाता है। उनके नेतृत्व को समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। आज भी हमारे समाज में बेटियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। जल्दी विवाह की परंपरा है, जिसके चलते कम उम्र में ही महिलाओं के सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। महिलाओं पर घर और करियर के बीच चुनाव का दबाव लगातार बना रहता है, जिससे उनकी प्रगति प्रभावित होती है। ये सभी बातें महिलाओं के आगे बढ़ने में बाधा बनती हैं। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक नारी सशक्तिकरण और नेतृत्व का अभियान अधूरा ही रहेगा।

हमारे देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आज भी महिलाओं की शिक्षा का स्तर कम है। उनमें डिजिटल शिक्षा की कमी है। कौशल प्रशिक्षण का अभाव है। साथ ही उनमें उनके इलाके में रोजगार के सीमित अवसर मिल पाते हैं। इन कारणों से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं और नेतृत्व की भूमिका में आने में कठिनाई होती है। आर्थिक स्वतंत्रता नारी सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर रहती हैं। उनमें बैंकिंग और वित्तीय जानकारी की कमी है, जिसके कारण वे व्यवसाय शुरू करने में कठिनाई महसूस करती हैं। सरकारी योजनाओं और बाजार की स्थिति की जानकारी नहीं होने के चलते संसाधनों तक उनकी सीमित पहुंच हो पाती है। आज के डिजिटल युग में भी तकनीक के बारे में महिलाओं की जानकारी सीमित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहां मोबाइल और इंटरनेट की सीमित उपलब्धता हो सकती है। डिजिटल साक्षरता की कमी और ऑनलाइन अवसरों से दूरी का अंतर महिलाओं के विकास की गति को धीमा करता




आर्थिक स्वतंत्रता नारी सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर रहती हैं। उनमें बैंकिंग और वित्तीय जानकारी की कमी है, जिसके कारण वे व्यवसाय शुरू करने में कठिनाई महसूस करती हैं।



नरेन्द्र मोदी समाज की सोच बदलने, महिलाओं में शिक्षा और कौशल विकास बढ़ाने, उन्हें आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने और उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि नारी में स्वयं सशक्त होने की ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र को दिशा देने की भी अपार शक्ति है।



है। महिलाओं के साथ सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी अहम हैं। उनकी सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। कार्यस्थल पर सुरक्षा, यात्रा के दौरान असुरक्षा का भाव उनमें डर की भावना को जन्म देता है। यह समस्या भी महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने से रोकती है। इनके अतिरिक्त घरेलू जिम्मेदारियों का अधिक बोझ, सहयोग की कमी और मातृत्व के दौरान करियर में रुकावट के कारण भी कई महिलाएं अपने करियर को बीच में ही छोड़ देती हैं। ऐसे में नरेन्द्र मोदी समाज की सोच बदलने, महिलाओं में शिक्षा और कौशल विकास बढ़ाने, उन्हें आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने और उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि नारी में स्वयं सशक्त होने की ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र को दिशा देने की भी अपार शक्ति है। तभी तो वह गर्व से कहते हैं कि आज भारत की बेटियां स्टार्टअप से लेकर सेना तक, हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। इस बात को हर किसी को समझने और इस पर अमल करने की जरूरत है।



(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका हैं। नारी सशक्तिकरण, सामाजिक विमर्श, फूड, ट्रैवेल, संस्कृति आदि से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी विशेषज्ञता है। इन विषयों पर उनके अब तक हजारों लेख राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। दैनिक जागरण के अलावा कश्मीर टाइम्स, दैनिक भास्कर, चंडीगढ़ दूरदर्शन से जुड़ी रही हैं। उनके लेख के बारे में अपनी राय mathur.yasha18@gmail.com पर दी जा सकती है।)



डॉ. ओमप्रकाश अग्रवाल

वरिष्ठ चिकित्सक (प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ), शिक्षाविद और समाजसेवी के रूप में डॉक्टर ओमप्रकाश अग्रवाल एक जाने-पहचाने नाम हैं। वे मेरठ स्थित एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन और प्रतिष्ठित मेरठ कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। वे सिटी वॉकेशनल पब्लिक स्कूल, मेरठ के अलावा ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (NIET) के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। पिछले करीब छह दशक से चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं और जरूरतमंदों के निःशुल्क उपचार एवं आर्थिक मदद के लिए जाने जाते हैं। चिकित्सा, शिक्षा और समाजसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।



अरुण श्रीवास्तव

पिछले करीब 34 वर्षों से दिल्ली-एनसीआर में मुख्य धारा की पत्रकारिता में सक्रिय। देश के अग्रणी समाचार पत्र दैनिक जागरण से करीब 20 वर्ष तक जुड़े रहे। वहीं फीचर संपादक भी रहे। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे और कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू के संपादक भी रहे। दैनिक जागरण सहित देश की अन्य प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में 1000 से अधिक आलेख प्रकाशित। लेखक और पत्रकार के साथ-साथ करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल लेखक के रूप में भी सक्रिय। दैनिक जागरण के सभी संस्करणों में 'जोश' पन्ने पर 15 वर्ष तक लगातार 'काउंसलर' कॉलम प्रकाशित होने का रिकॉर्ड। अब तक 30 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं सहित उनके अभिभावकों का प्रेरक मार्गदर्शन।